राष्ट्रीय संस्करण

पीएम मोदी के आठ शब्द बने 'गोल्डन ट्वीट' >>4

वर्ष 3 अंक 183

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 11 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

नागरिकता संशोधन विधेयक की अग्निपरीक्षा आज

खिंची तलवार ▶ लोकसभा की मंजूरी के बाद अब राज्यसभा में बिल होगा पेश, आंकड़ों के गणित में सरकार का पलड़ा भारी

शिवसेना के बदले रुख से विपक्ष को मिला हौसला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पर सरकार और विपक्ष के बीच खिंची तलवार से साफ है कि बुधवार को राज्यसभा में विधेयक की अग्निपरीक्षा होगी। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन में अपनी धारदार रणनीति की झलक दे चुकी सरकार राज्यसभा में आंकड़ों के अपने गणित को लगभग चाक-चौबंद कर चुकी है। हालांकि शिवसेना के विधेयक पर रुख बदलने के साफ संकेतों और टीआरएस के इस बार विपक्ष में खड़े होने से कुछ दबाव जरूर बढ़ा है। राज्यसभा में नंबर गणित का मामला नजदीकी होने के चलते ही विपक्षी खेमे के दलों ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने तो नागरिकता विधेयक के खिलाफ वोट करने के लिए अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है।

सोमवार को लोकसभा में 80 के मुकाबले सरकार ने 311 मतों से विधेयक पारित करा लिया था। लेकिन 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में फिलहाल 240 सदस्य हैं और थोड़े हेरफेर से ही स्थिति रोचक हो सकती है। दरअसल, शिवसेना खेमे से यह स्वर उभर रहे हैं कि वह सदन से वॉकआउट कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन यह संकेत भी दिया जा रहा है कि परिस्थिति को देखते हुए वह विपक्षी खेमे के साथ वोट भी कर सकती है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के रुख में बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि लोकसभा की तरह उनकी पार्टी राज्यसभा में विधेयक का समर्थन करे।

शिवसेना का कहना है कि श्रीलंकाई तमिल भाषी शरणार्थियों को भी इस विधेयक में शामिल करने और इस कानून के तहत नागरिक बनने वाले शरणार्थियों को 25 साल बाद ही मतदान का अधिकार देने के उसके प्रस्ताव को सरकार मानेगी तभी पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी। सरकार इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेगी यह तय है और ऐसे में शिवसेना भी राज्यसभा में विधेयक का समर्थन करने से परहेज करेगी। इस विधेयक पर सियासी सरगर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस ने शिवसेना के रुख बदलने के संकेतों का स्वागत करने में देर नहीं लगाई। लोकसभा में शिवसेना ने सोमवार को नागरिकता विधेयक के पक्ष में वोट दिया था। विपक्ष सरकार के सहयोगी दल जदयू के कुछ नेताओं की तरफ से उठाए गए सवालों से भी उत्साहित है। यह और बात है कि जदयू में आवाज उठा रहे प्रशांत किशोर और पवन वर्मा फिलहाल हाशिए पर हैं और संगठन में उनकी धमक नहीं है। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने ही इसकी पुष्टि की।

यह है राज्यसभा का गणित

103 राजग	
भाजपा	83
जदयू	6
शिअद	3
आरपीआइ	1
अन्य	10

62 संप्रग	
कांग्रेस	46
राजद	4
राकांपा	4
द्रमुक	5
अन्य	3

245 कुल सदस्य संख्या

240 प्रभावी सदस्य संख्या

121 बहुमत के लिए जरूरी

12 मनोनीत राज्यसभा सदस्यों में आठ भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जबकि चार अब भी मनोनीत श्रेणी में हैं।

- इन चार मनोनीत सदस्यों में तीन राजग के साथ और एक संप्रग के साथ जुड़े। इसलिए तीन राजग की सूची में और एक संप्रग की सूची में जोड़ दिया गया है।

गैर राजग और गैर संप्रग (विधेयक के विरोध में)	
तृणमूल	13
सपा	9
टीआरएस	6
माकपा	5
बसपा	4
आप	3
पीडीपी	2
भाकपा	1
जदएस	1

अन्य विपक्षी पार्टियां (विधेयक के समर्थन में)	
अन्नाद्रमुक	11
बीजद	7
शिवसेना*	3
वाईएसआरसीपी	2
तेदेपा	2
अन्य	3

*लोस में सरकार का साथ दिया, रास में रुख अस्पष्ट

राज्यसभा में राजग के पक्ष में हैं 128 सदस्य

विपक्ष की कोशिश के बावजूद राज्यसभा में आंकड़ों का गणित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के पक्ष में दिख रहा है। राज्यसभा में अभी 240 सदस्य हैं और नागरिकता विधेयक पर सरकार फिलहाल करीब 128 सांसदों का समर्थन जुटाती दिख रही है। इसमें शिवसेना के तीन सांसदों की संख्या शामिल नहीं है। जबकि विधेयक पारित कराने के लिए राजग को 121 के संख्या बल की जरूरत है। राजग के पास भाजपा के 83, जदयू के छह, लोजपा के एक, असम गण परिषद के एक, मनोनीत तीन सांसदों के साथ अन्नाद्रमुक के 11, बीजद के सात, वाईएसआर कांग्रेस के दो सदस्यों के अलावा टीडीपी के भी दो सांसदों का समर्थन है।

शिवसेना साथ दे तो विपक्ष को 112 सदस्यों का समर्थन

राज्यसभा में कांग्रेस के 46, तृणमूल कांग्रेस के 13, सपा के नौ, द्रमुक के पांच, माकपा के पांच, राजद के चार, राकांपा के चार, बसपा के चार, पीडीपी के दो, एमडीएमके और जदएस का एक-एक समेत विपक्षी खेमे का यह आंकड़ा 109 तक ही पहुंचता है। शिवसेना यदि राज्यसभा में बिल के खिलाफ मतदान करती है तो भी विपक्षी खेमे का आंकड़ा 112 तक ही पहुंच पाएगा। इसमें टीआरएस के छह सांसद भी शामिल हैं। अब तक राजग को हर मुद्दे पर साथ देती रही टीआरएस नागरिकता बिल पर उसका विरोध कर रही है। ऐसे में विधेयक पारित कराने से रोकने या इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजने में विपक्ष को कामयाबी मिल पाएगी, इसकी गुंजाइश नहीं है।

कांग्रेस बोली, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने बांटा था देश

नई दिल्ली : धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने के अमित शाह के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर द्वि-राष्ट्र बनाने का सिद्धांत हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का था। (पेज-3)

कैब से असम में बंगालियों का वर्चस्व नहीं होगा : केंद्र

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि कैब से असम में बंगाली भाषियों का वर्चस्व नहीं हो जाएगा और न ही यह राज्य के मूल लोगों के हितों के विरुद्ध है। (पेज-3)

सरोकार

पहाड़ से पलायन रोकेगी हिमालयी उपज कुटकी

बागेश्वर : पलायन के चलते खाली हो रहे पहाड़ के गांवों के लिए हिमालयी उपज

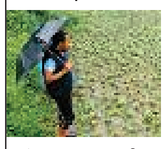

कुटकी बड़ी उम्मीद ला रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कुटकी की खूब पैदावर हो रही है। भेषज संघ कुटकी का उत्पादन करा रहा है। बाजार में उपज की कीमत 500 से 800 रुपया प्रति किलो तक है। (पेज-11)

जागरण विशेष

दानिश संग कदमताल करते नए कश्मीर के जवां ख्वाब

श्रीनगर : 'कश्मीर का रोनाल्डो' नाम से मशहूर स्टार फुटबॉलर दानिश भट एक बार

फिर घरेलू दर्शकों के सामने जलवा बिखेरने को तैयार हैं। आइ-लीग में दानिश की टीम 'रियल कश्मीर' का एक मुकाबला इसी सप्ताह श्रीनगर में होना है। (पेज-11)

न्यूज गैलरी

नेशनल कैपिटल ▶ पृष्ठ 2

निर्भया के दोषी अक्षय ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को चुनौती दी है। याचिका में उसने कोर्ट से उसे फांसी की सजा देने के पांच मई, 2017 के आदेश को रद करने की मांग की है। दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले मे चार दोषियों को फांसी की सजा हुई है।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

चुनावी बांड जारी करने में रिजर्व बैंक को नहीं थी आपत्ति : निर्मला

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव बांड को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच सरकार ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के माध्यम से चुनावी बांड जारी किए जाने में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार की ओर से इस मामले में फैसला लेने के हर कदम के बारे में आरबीआइ को पता था।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पहली बार सीसीपीआइ में शीर्ष 10 देशों में भारत शामिल

मैड्रिड : भारत पहली बार जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन से उबरने के लिए किए गए भगीरथ प्रयासों का ही नतीजा है। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। कोयला आधारित उद्योगों पर अब भी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब भी अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हैं।

तीसरा टी-20
भारत vs वेस्टइंडीज
शाम 7:00 बजे से
स्थान : मुंबई
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

कश्मीर घाटी में बहाल हो गई एसएमएस सेवा

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- 40 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगी ओटीपी की सुविधा
- आम उपभोक्ता अभी नहीं कर सकेंगे एसएमएस सेवा का प्रयोग

कश्मीर में स्थानीय लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने मंगलवार को मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवा बहाल कर दी है। इससे घाटी में करीब 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, बैंक, रेल प्रशासन, एयरलाइंस और बीमा कंपनियों की ओर से भेजे जाने वाले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) व अन्य एसएमएस की सुविधा मिल सकेगी। फिलहाल, आम उपभोक्ता एसएमएस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट और प्री-पेड मोबाइल फोन सेवा को भी अभी बंद रखा गया है।

पोस्टपेड सेवा हो चुकी है शुरू : कश्मीर में चार अगस्त की मध्यरात्रि को प्रशासन ने एहतियातन सभी प्रकार की फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं। गत 14 अक्टूबर को वादी में पोस्टपेड सेवा में एसएमएस सुविधा बहाल कर दी गई थी, लेकिन एसएमएस सेवा को उसी दिन कुछ समय बाद फिर बंद कर दिया गया था।

एसएमएस पर ओटीपी न आने से हो रही थी दिक्कत : इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक होने से वादी में व्यापारियों, सरकारी कर्मियों, ठेकेदारों, छात्रों, ट्रैवल एजेंटों के साथ आम लोगों को भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था। हालांकि इंटरनेट सुविधा अगस्त के अंतिम पखवाड़े के दौरान ही आम लोगों के लिए सरकार ने विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कड़ी निगरानी के बीच सीमित आधार पर उपलब्ध कराना शुरू कर दी थी, लेकिन आम लोग इसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे थे।

ऑनलाइन फार्म भरने से लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने तक आम लोगों को अपने मोबाइल फोन का नंबर देकर उस पर ओटीपी प्राप्त करना होता था। ओटीपी नंबर के आधार पर ही वह

प्रतीकात्मक

इंटरनेट पर अपने काम कर पाते थे। एजाज अहमद ने एसएमएस सेवा बहाली पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेशक आंशिक रूप से एसएमएस सेवा बहाल हुई है, लेकिन इससे बहुत राहत मिलेगी। उम्मीद है आम लोगों को भी एसएमएस भेजने की सुविधा जल्द मिलेगी।

सलीम वानी नामक एक व्यक्ति ने कहा कि एसएमएस सेवा न होने से हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे बैंक खाते में क्या जमा हुआ है और क्या निकासी हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी आधार पर सब्सिडी पाने वालों को भी पता नहीं चलता था कि उन्हें धनराशि मिली है या नहीं। हम लोग ऑनलाइन लेन-देन भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ओटीपी नहीं मिलता था, क्योंकि कई बैंक और अन्य संस्थान ईमेल पर ओटीपी नहीं देते हैं। इम्तियाज नामक छात्र ने कहा, मुझे अपना सिम कार्ड रामबन में अपने दोस्त के पास भेजना पड़ा, ताकि उस पर ओटीपी प्राप्त कर वह मेरे लिए आनलाइन परीक्षा फार्म जमा कर सके।

राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर स्थानीय प्रशासन लेगा फैसला पेज>>6

पक्षपातपूर्ण है कैब पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नागरिकता संशोधन विधेयक की अमेरिकी आयोग ने की है निंदा
- आयोग की टिप्पणी भेदभावपूर्ण, कैब हमारा आंतरिक मामला : विदेश मंत्रालय

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (फाइल फोटो)

पहले कश्मीर से अनुच्छेद-370 का हटना और अब नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब)। अमेरिकी एजेंसियों की भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणी करने की आदत जाने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को लोकसभा में पारित कैब पर स्वायत्त अमेरिकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआइआरएफ) ने बेहद तल्ख टिप्पणी। अमेरिकी आयोग ने यहां तक कहा है कि अगर राज्यसभा में यह बिल पारित होता है तो अमेरिकी सरकार को भारत के गृह मंत्री और अन्य राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ पाबंदी लगानी चाहिए। भारत ने आयोग की टिप्पणी को बेहद पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने आयोग पर बगैर वस्तुस्थिति की जानकारी के ही टिप्पणी करने की बात कही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मंगलवार को कहा, 'यूएससीआइआरएफ की तरफ से कैब पर टिप्पणी अवांछित है। यह बिल सिर्फ कुछ देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। यह उनकी मौजूदा समस्याओं को दूर करता है और मानवाधिकार के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करता है। जो लोग सही मायने में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं उन्हें इस तरह के कदम का स्वागत करना चाहिए। यह विधेयक दूसरे समुदायों को भारतीय नागरिकता देने के मौजूदा प्रावधानों में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने जिस तरह से नागरिकता प्रदान की है, वह इस संदर्भ में उसके रिकार्ड को बताता है।' उन्होंने कहा है कि कैब या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की प्रक्रिया किसी भी धर्म के नागरिक की मौजूदा नागरिकता को छीनने की कोशिश नहीं है। ऐसी बात करना किसी गलत भावना से प्रेरित है और अन्यायपूर्ण भी है। अमेरिका समेत हर देश को अपने नागरिकों के हितों का ख्याल रखने और उसे तय करने का अधिकार है। कुमार ने यूएससीआइआरएफ को घेरते हुए कहा कि उसके पुराने रुख को देखते हुए उसकी टिप्पणी को समझा जा सकता है। लेकिन यह दुखद है कि अमेरिकी एजेंसी ने उस पूरे मुद्दे पर पूर्वाग्रह व दुर्भावना से भरी टिप्पणी की है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है।

मंगलवार को सुबह यूएससीआइआरएफ की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत में इस विधेयक के जरिए धर्म के आधार पर नागरिकता देने का रास्ता बनाया जा रहा है। यह खतरनाक है और गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। यह भारत के पंथनिरपेक्ष बहुवादी व्यवस्था के बेहद गौरवपूर्ण इतिहास और भारतीय संविधान के खिलाफ है। एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए भारत सरकार लाखों मुस्लिमों से नागरिकता छीन लेगी।

बिल पर पाकिस्तान ने टांग अड़ाई पेज>>3

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में ट्रस्ट बना देगी सरकार

- गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा को दी जानकारी
- कहा, केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध

लोकसभा में मंगलवार को राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के बारे में जानकारी देते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में योजना बनाने, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ ट्रस्ट बनाने या कोई अन्य निकाय बनाने, ट्रस्ट के कामकाज, ट्रस्टियों के अधिकार, ट्रस्ट को भूमि हस्तांतरण जैसी तमाम आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और दी गई समय सीमा के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि एक सदी से ज्यादा समय से चले आ रहे विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसने अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने और मस्जिद के लिए किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में प्रमुख स्थान पर जमीन दी जाए और मंदिर का निर्माण उस जगह पर किया जाए, जहां हिंदू मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ था।

कोलेजियम की सिफारिश के छह माह में हो जजों की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलेजियम की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के छह माह के भीतर जज की नियुक्ति हाई कोर्ट में हो जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट में जजों के 1,079 स्वीकृत पदों के मुकाबले 410 पद रिक्त होने को गंभीरता से लेते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने आदेश में कहा, 'ऐसे मामलों में जिनमें हाई कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम व सरकार की मंजूरी मिलती है, कम से कम उनमें नियुक्तियां छह माह के भीतर होनी चाहिए।' 'आंकड़ों से पता चलता है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की 1079 मंजूर संख्या के मुकाबले कार्यरत संख्या 669 है। 213 सिफारिशों के सरकार या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास प्रक्रिया में होने की बात कही गई है जबकि 197 रिक्तियों के लिए हाई कोर्ट कोलेजियम से सिफारिशें प्राप्त होनी बाकी हैं।'

बदलेगा नाम

विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठक में बनी सहमति, मीरजापुर के बरकछा में 2700 एकड़ में फैला है दक्षिणी परिसर

बीएचयू के दक्षिणी परिसर से हटेगा राजीव गांधी का नाम

जागरण संवाददाता, वाराणसी

बरकछा स्थित काशी हिंदू विवि का दक्षिणी परिसर। जागरण

नाम बदलने के क्रम में अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी जुट गई है। मीरजापुर स्थित बीएचयू (काशी हिंदू विश्वविद्याल) के दक्षिणी परिसर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर 13 वर्ष पूर्व हुआ है। बीएचयू कोर्ट की बैठक में आए प्रस्ताव में सहमति बनी कि परिसर के नाम से राजीव गांधी का नाम हटा दिया जाए। हालांकि दो-तीन सदस्यों ने इस प्रस्ताव को लेकर सहमति नहीं जताई है। विदित हो कि बीएचयू कोर्ट में कुल 48 सदस्य हैं जिनमें से करीब 35 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

विश्वविद्यालय के कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में बीएचयू कोर्ट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे अहम विवि के नए दक्षिणी परिसर को लेकर था। जब सदस्यों ने परिसर से राजीव गांधी का नाम हटाकर सिर्फ बीएचयू दक्षिणी परिसर रखने का प्रस्ताव रखा। दो तीन सदस्यों को छोड़ कर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।

नाम बदलने की प्रक्रिया : यदि बीएचयू के दक्षिणी परिसर से राजीव गांधी का नाम हटाने का प्रयास होगा तो इसके पहले विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद से प्रस्ताव पास करना होगा। प्रस्ताव को कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लाकर हरी झंडी लेनी होगी।

2006 में हुआ था भूमि पूजन : मीरजापुर के बरकछा स्थित बीएचयू दक्षिणी परिसर का कुल क्षेत्रफल 2700 एकड़ है। बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विवि है। दोनों परिसरों को मिलाकर छात्रावासों की संख्या 75 है। 30 मई 2005 को पहली बार तत्कालीन कुलपति प्रो. पंजाब सिंह परिसर पहुंचे थे। 2006 में इसका भूमि पूजन किया गया। उसी समय इसका नाम राजीव गांधी दक्षिणी परिसर किया गया। छह पाठ्यक्रम के साथ शुरू दक्षिणी परिसर में वर्तमान में 26 पाठ्यक्रम संचालित हैं। 2500 छात्र-छात्राएं वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या 100-100 है। दक्षिणी परिसर में दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के अलावा स्नातक व परास्नातक के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। पूर्वांचल का यह पहला संस्थान है जहां पशु विज्ञान व पशु चिकित्सा संकाय के तहत बीएससी वेटेनरी साइंस की पढ़ाई की जाती है।

बीएचयू के दक्षिणी परिसर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटने नहीं देंगे। संस्थाओं के राजनीतिकरण के मंसूबे को कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। देश के विकास में राजीव गांधी का बड़ा योगदान है। उनके नाम को मिटाने का यह प्रयास निंदनीय है।

– अजय राय, सदस्य, अनुशासन व सलाहकार समिति-प्रदेश कांग्रेस

बीएचयू में खत्म हुआ डॉ. फिरोज प्रकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में नियुक्ति के बाद से ही विरोध झेल रहे डॉ. फिरोज खान ने इस्तीफा देकर विश्वविद्यालय के ही कला संकाय स्थित संस्कृत विभाग में पदभार संभाल लिया है। फिरोज का संस्कृत विभाग के अलावा आयुर्वेद संकाय में भी चयन हुआ था। उन्होंने मंगलवार को विभाग में पहली हाजिरी लगाई। हालांकि परीक्षा के चलते उनको कक्षाएं नहीं मिल पाई। उधर, छात्रों ने फिरोज के इस्तीफे के बाद धरना समाप्त कर दिया है।

(विस्तृत खबर पेज-7 पर)

डेरा समर्थकों ने तीन दिन तक पंचकूला को कैसे बंदी बनाए रखा : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पूछा, डेरा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने से पहले समर्थकों को बैठने की इजाजत किसने दी
- दंगों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर जल्द ही फैसला सुनाएगी पूर्ण पीठ

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पूछा है कि पंचकूला हिंसा प्रकरण में तीन दिन तक पंचकूला में डेरे के समर्थकों को बैठने की इजाजत क्यों और किसने दी? मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस आरके जैन व जस्टिस एजी मसीह की पूर्ण पीठ ने कहा कि पंचकूला स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत पर फैसला आना था, उसके लिए ये कौन सी कौन सी मांग को लेकर आए थे। जस्टिस जैन ने कहा कि मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन यह स्पष्ट किया जाए कि तीन दिन तक पूरे पंचकूला को डेरा समर्थकों ने कैसे बंदी बनाए रखा। बाद में पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा और 40 लोगों की जान चली गई। उनके परिवारों को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? पीठ ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इस पर हम जल्द ही फैसला देंगे।

डेरा सच्चा सौदा की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि दंगों और तोड़फोड़ की भरपाई डेरे से नहीं की जा सकती है। इसमें डेरे का कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में यह तय कर चुका है कि ऐसे मामले में नुकसान के आकलन के लिए एक कमेटी गठित की जा सकती है। वह पूरा आकलन कर उसकी भरपाई करा सकती है। हाई कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। इस पर पीठ ने कहा कि वह इस पर सुनवाई कर सकते हैं और निर्देश भी दे सकते हैं।

7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मंगलवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान। यह इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले चार और पांच दिसंबर को न्यूनतम तापमान क्रमश: 7.9 और 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 दिसंबर 2019

आरआरटीएस कॉरिडोर से जुड़ेंगी अन्य मेट्रो लाइनें

महेश कुमार वैद्य, रेवाड़ी

- दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर रूट के दूसरे चरण की बाधाओं को दूर करने के लिए हुई कार्यशाला
- भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी सुगम कनेक्टिविटी
- जयपुर में हुई एसएनबी-सोतानाला आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए स्टेकहोल्डर वर्कशॉप

आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) के दिल्ली-गुरुग्राम-रेवाड़ी-अलवर कॉरिडोर के दूसरे चरण का काम भी तेजी से पूरा होगा। मंगलवार को दूसरे चरण में प्रस्तावित 35 किमी लंबे 'एसएनबी-सोतानाला कॉरिडोर' के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर में स्टेक होल्डर वर्कशाप आयोजित की गई। स्टेक होल्डर से अभिप्राय उन विभागों से है जिन पर रूट को जोखिम रहित करने की जिम्मेदारी है। बैठक में दो चीजें पूरी तरह स्पष्ट हो गईं। आरआरटीएस कॉरिडोर से दिल्ली व अन्य मेट्रो लाइनों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरे-भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा (बीटीके) जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को सुगम कनेक्टिविटी दी जाएगी।

कार्यशाला में राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता व दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस वर्कशाप में कॉरिडोर से संबंधित विभिन्न स्टेक होल्डर जैसे आवास एवं शहरी कार्य विकास मंत्रालय (एमओएचयू), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी), दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआइसीडी), नगर सुधार न्यास (यूआइटी), शहरी विकास एवं हाउसिंग विभाग (यूडीएच), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेलवे व दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर विकास निगम (डीएमआइसीडीसी) सहित कई विभागों के अधिकारी थे। कार्यशाला में दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर रूट के दूसरे चरण की बाधाओं को दूर करने के लिए विस्तार से चर्चा हुई।

परियोजना व कार्यशाला की अहम बातें

- आरआरटीएस का पहला चरण दिल्ली से एसएनबी स्टेशन तक पूरा होगा। एसएनबी रेवाड़ी जिले की सीमा समाप्त होते ही अलवर की सीमा में बनेगा।
- दूसरे चरण में एसएनबी से सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र तक ट्रैक बिछेगा। एसएनबी से शाहजहांपुर, नीमराणा व बहरोड़ क्षेत्रों को दिल्ली, गुड़गांव व रेवाड़ी से सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। सोतानाला से वाया एसएनबी दिल्ली तक सफर आसान होगा।
- कार्यशाला में प्रोजेक्टर के माध्यम से एसएनबी-सोतानाला कॉरिडोर की विशेषताएं व लाभ दर्शाए गए।
- कॉरिडोर का परिचालन शुरू होने के बाद दिल्ली से सोतानाला की 141 किमी की दूरी महज 90 मिनट में तय होगी।
- तीसरे चरण में एसएनबी से खैरथल के रास्ते अलवर तक ट्रैक बिछाया जाएगा। तीनों चरणों को मिलाकर कॉरिडोर की कुल लंबाई 199 किमी होगी। इसमें कुल 22 आरआरटीएस स्टेशन होंगे।
- सराय काले खां, जोर बाग, मुनीरका, एयरोसिटी, उद्योग विहार गुरुग्राम, खेड़की दौला, पचगांव व बावल आरआरटीएस स्टेशनों पर प्रमुख स्थानों के लिए सामान्य मेट्रो व परिवहन के अन्य बेहतर साधनों की सुगम उपलब्धता रहेगी।

देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। इस मामले में राजस्थान भी अग्रणी राज्य है। आरआरटीएस न केवल शहरीकरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान करने में मदद करेगा बल्कि इससे प्रदूषण को भी काफी कम करेगा।
-डीबी गुप्ता, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर क्षेत्र में परिवहन के लिए एक गेमचेंजर होगा। यह न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास का कारक होगा, बल्कि एनसीआर के लोगों और स्थानों को और करीब लाएगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी की परिकल्पना पूरी की जाएगी। भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा (बीटीके) जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आधुनिक ट्रेन के अनुकूल परिवहन समाधान विकसित होगा। बीटीके क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाले ट्रॉली बस कोचों की व्यवहार्यता भी तलाशी जाएगी।
-विनय कुमार सिंह, एमडी, एनसीआरटीसी

रीजनल प्लान 2041 से बदलेगी दिल्ली-एनसीआर की सूरत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड तैयार कर रहा है रीजनल प्लान 2041
- कार्यशाला आयोजित कर विशेषज्ञों से लिए जा रहे सुझाव

दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चरमराते ढांचे को संवारने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने रीजनल प्लान 2041 तैयारी शुरू कर दी है। प्लानिंग बोर्ड कार्यशाला आयोजित कर रीजनल प्लान के लिए क्षेत्र में रहने वालों व विशेषज्ञों से सुझाव ले रहा है। इन सुझावों को सम्मिलित करते हुए रीजनल प्लान 2041 को अंतिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आबादी के बढ़ते दबाव की वजह से क्षेत्र का मास्टर प्लान गड़बड़ा गया है। क्षेत्र में ढांचागत विकास प्रभावित होने से समस्याएं बढ़ रही हैं। मास्टर प्लान का क्रियान्वयन भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। नए मास्टर प्लान में पर्यावरण से लेकर आर्थिक विकास, शिक्षा, खेती किसान तक को जगह दी जाएगी।

इसे देखते हुए प्लानिंग बोर्ड मास्टर प्लान 2041 के लिए विशेषज्ञों के सुझाव व उनकी जरूरतों का आकलन करने में जुटा है। पिछले माह बोर्ड ने दिल्ली में कॉन्क्लेव आयोजित किया था। दिसंबर में प्लानिंग बोर्ड विभिन्न विषयों पर कार्यशाला आयोजित कर रहा है जिसमें विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में ट्रांसपोर्ट एवं मोबिलिटी, ऊर्जा, जल एवं ड्रेन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, कृषि, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन एवं विरासत, आर्थिक विकास, आय बढ़ोतरी, खेल, सुरक्षा, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि विषयों को शामिल किया गया है। ताकि मास्टर प्लान 2041 को समग्र रूप से तैयार किया जा सके, जो क्षेत्र के आने वाले वर्षों की जरूरतों को पूरा करे।

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर चलाए जा रहे संपर्क अभियान के तहत आयोजित हो रहे बूथ संवाद कार्यक्रम की समीक्षा की। इस मौके पर चुनाव लड़ने के लिए फंड की कमी का मुद्दा उठा। जिस पर आप के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने फंड एकत्रित करने के लिए अलग से अभियान चलाने की बात कही। बैठक में सभी सांसद, मंत्री, विधायक, लोकसभा प्रभारी, पार्षद व जिला प्रभारी शामिल थे। सभी ने बूथ संवाद कार्यक्रम की सफलता से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि अब पार्टी के लोग चुनाव के लिए फंड जुटाने के काम में जुटेंगे।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सबसे पहले बूथ संवाद कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के लोगों की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज को लेकर आ रही प्रतिक्रिया जानी। पार्टी के नेताओं व विधायकों ने अब तक आयोजित बूथ संवाद में आई लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को बताया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के पांच वर्ष में किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताने के लिए कहा। साथ ही आगामी चुनाव के लिए जनता के बीच जाकर फंड एकत्र करने पर भी जोर दिया। जिसके बाद प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि फंड एकत्र करने के लिए भी पार्टी अभियान चलाकर काम करेगी।

निर्भया के दोषी ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका

वसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म कांड ▶ सुप्रीम कोर्ट में दी फांसी की सजा को चुनौती, याचिका में दी अजीबोगरीब दलीलें

कहा-दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण से उम्र कम होती जा रही है, फिर फांसी की क्या जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी की सजा को चुनौती दी है। याचिका में उसने सुप्रीम कोर्ट से उसे फांसी की सजा देने के पांच मई, 2017 के आदेश पर पुनर्विचार कर उसे रद करने की मांग की है।

दिल्ली के वसंत विहार में 16 दिसंबर, 2012 को चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस दौरान छात्रा को गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तीन अभियुक्तों मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट गत वर्ष नौ जुलाई को खारिज कर चुका है। लेकिन अक्षय ने अभी तक पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी।

अक्षय ने वकील एपी सिंह के जरिये दाखिल पुनर्विचार याचिका में फांसी की सजा का विरोध करते हुए कहा है कि यह सजा

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि दोषी में क्रमवार सुधार किया जाना चाहिए। फांसी देकर सिर्फ अपराधी को मारा जा सकता है, अपराध को नहीं। याचिका में मृत्युदंड समाप्त किए जाने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। यहां का पानी जहरीला हो चुका है। प्रदूषित हवा और पानी के चलते पहले ही लोगों की उम्र कम हो रही है। तो फिर फांसी की सजा की क्या जरूरत है।

याचिका में वेद, पुराण और उपनिषद आदि का भी हवाला दिया गया है। कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, सतयुग में लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे। त्रेता युग में भी एक व्यक्ति हजार वर्ष तक जीता था। लेकिन, कलयुग में आदमी की उम्र 50-60 वर्ष तक सीमित रह गई है। ऐसे में फांसी की सजा देने की जरूरत नहीं है।

बक्सर से तिहाड़ जेल पहुंचे फांसी के 10 फंदे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ जेल अधिकारियों ने कहा, प्रशासन सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर तैयारी करे

निर्भया मामले को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुरोध पर बिहार की बक्सर जेल में बने फांसी के 10 फंदे तिहाड़ पहुंच चुके हैं। जेल अधिकारियों का कहना है कि निर्भया मामले में अंतिम निर्णय जो भी हो, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से सभी विकल्पों को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है। यदि निर्भया के दोषियों को फांसी देने का अंतिम फैसला कायम रहेगा तो जेल प्रशासन इसके लिए तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। जेल सूत्रों का कहना है कि फंदा लेकर जेल का ही एक कर्मचारी यहां सोमवार को पहुंचा। जरूरत पड़ी तो आने वाले कुछ दिनों में और भी फंदे वहां से मंगाए जा सकते हैं। साथ ही फांसी देने के लिए जल्लाद की तलाश जल्द पूरी हो जाएगी। अलग-अलग इलाकों में रहने वाले तीन जल्लादों से जेल प्रशासन की बात हो रही है। बातचीत तय होने पर उन्हें जल्द ही जेल बुलाया जाएगा।

पहली बार चार को एक ही दिन फांसी : जेल सूत्रों का कहना है कि यदि फांसी से जुड़ा निर्णय बरकरार रहता है तो इस बार चार कैदियों को एक ही दिन फांसी दी जाएगी। तिहाड़ में पिछले चार दशक में एक ही दिन में चार दोषियों को फांसी नहीं दी गई है। ऐसे में

तिहाड़ जेल फाइल फोटो

केवल एक जल्लाद के भरोसे जेल प्रशासन नहीं रहना चाहता। जेल कर्मचारी पर प्रशासन इस बार इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस बार मामला एक नहीं, बल्कि चार दोषियों का है। यदि फांसी के दौरान कोई गड़बड़ी सामने आई तो इससे जेल प्रशासन की किरकिरी हो सकती है।

खबरों पर निर्भया के दोषियों की नजर : निर्भया मामले में फांसी की सजा पाए दोषी अभी कानूनी विकल्पों की तलाश में जुटे हैं। जेल सूत्रों की मानें तो इस मामले में चारों दोषी टेलीविजन पर खुद से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद देश भर में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग से जुड़ी खबरें देखकर ये सहमे हुए हैं। हालांकि इनके माथे पर चिंता की लकीरें तभी उभरनी शुरू हो गई थी, जब जेल प्रशासन की ओर से दोषियों को दया याचिका दायर करने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था। जेल प्रशासन चारों दोषियों पर नजर जमाए हुए है।

जेल सूत्रों का कहना है कि पवन को मंडोली जेल से यहां लाने के बाद अक्षय व मुकेश को यह बात अटपटी लगी। उन्होंने सोचा आखिर पवन को यहां क्यों लाया गया। तब जेल में यह अफवाह उड़ गई कि चारों को जल्द ही फांसी होनी वाली है। इसके बाद सभी दोषी घबरा गए। अभी अक्षय, मुकेश व पवन जेल नंबर-दो में अलग-अलग जगहों पर बंद हैं। तीनों की मुलाकात नहीं होती है। तीनों को इनके हमउम्र कैदियों के साथ रखा गया है। जेल प्रशासन की ओर से सभी पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जेल प्रशासन उनके साथ रह रहे दो अन्य कैदियों से भी इनके बारे में पूरी जानकारी ले रहा है। अभी इन्हें किसी अन्य कैदी से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

दिल्लीवासियों को मिलीं 100 और नई बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को राजघाट डिपो से 100 नई बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। 37 सीटों वाली इन बसों में हाईड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे एवं जीपीएस जैसी सुविधाएं व सुरक्षा के इंतजाम हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 अक्टूबर को भी 104 नई बसों को द्वारका सेक्टर 22 डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसके बाद गत सात नवंबर को भी नई 100 बसें सड़कों पर उतारी गई थीं। बीते चार माह में सार्वजनिक परिवहन बेड़े में कुल 429 नई बसें शामिल की गई हैं।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है। हमें 100 नई अल्ट्रा मॉडर्न बसें मिली हैं। इन नई बसों के आने से दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। मेट्रो स्टेशनों, अस्पतालों और ट्रैफिक इंटरचेंज हब के लिए कश्मीरी गेट, आनंद विहार टर्मिनल और सराय काले खां में मेट्रो स्टेशनों, कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले अतिरिक्त मार्गों को इन बसों द्वारा सेवा दी जाएगी।

इन रूटों पर चलेंगी ये बसें

- उत्तम नगर से एयरपोर्ट टर्मिनल 2 – 20
- एयरपोर्ट के आइजीएल से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन – 20
- तिलकनगर से दौराला बॉर्डर – 16
- लामपुर बॉर्डर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 19
- नरेला टर्मिनल से दिल्ली सचिवालय – 10
- होलांकी कलां जेजे कालोनी से शिवाजी स्टेडियम – 8
- केतवारा गांव से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन 7

सिरसपुर में बनेगा 1100 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1100 बेड का मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। यह अस्पताल उत्तरी दिल्ली के सिरसपुर में बनेगा। अस्पताल की इमारत 10 मंजिला होगी। अस्पताल पूरी तरह वातानुकूलित होगा। यह अस्पताल 15 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसके निर्माण पर 487 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसका निर्माण 36 माह में पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार की यह पहली योजना होगी। जिसे ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) के तहत काम किया किया जाएगा। जिसमें विभिन्न एजेंसियों से निर्माण के लिए स्वीकृति लेना व निर्माण कराना कंपनी का ही कार्य होगा। दरअसल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया के लिए नए नियमों को जारी किया है जिनके अनुसार अब कंपनियों को काम देने के मामले में बदलाव किया गया है।

550 बेड का होगा हेडगेवार अस्पताल : वहीं यमुनापार के डॉ. हेडगेवार अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक बनाया जाएगा। इसका निर्माण 33 माह में पूरा किया जाएगा। इसके

सिरसपुर में बनने वाले 100 बेड के अस्पताल की इमारत का डिजाइन।

निर्माण पर 221 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। यह अस्पताल अभी 200 बेड का है जिसे 550 बेड का किया जाएगा। यह अस्पताल 1996 में बनना शुरू हुआ था। आबादी के हिसाब से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इन दोनों अस्पतालों को लेकर मंगलवार को दिल्ली सरकार की खर्च एवं वित्त समिति (ईएफसी) में चर्चा हुई। समिति ने इन योजनाओं के लिए मंजूरी देने की संस्तुति दे दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार के तहत लोक निर्माण विभाग ने आठ अस्पतालों में री-मॉडलिंग (पुनर्विकसित) करने का काम शुरू कर दिया है। जबकि 4 अन्य अस्पतालों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। इनमें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार की खर्च एवं वित्त समिति (ईएफसी) ने तीन अस्पतालों को तीन सप्ताह पहले मंजूरी दी थी। इनमें से प्रत्येक अस्पताल की क्षमता 650 बेड होगी। ये अस्पताल मादीपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में बनाए जाएंगे।

बिना फास्टैग लगे वाहनों का नहीं हो सकेगा इंश्योरेंस

अर्पित त्रिपाठी, नोएडा : 15 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा फास्टैग लेन घोषित हो जाएंगे। इसे लगाने वालों की संख्या बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार फास्टैग से ईंधन भरने, पार्किंग का शुल्क भरने आदि की सुविधा शुरू करने जा रही है। अगले वर्ष से केंद्र सरकार नई व्यवस्था शुरू करेगी। इसके तहत उन्हीं वाहनों का इंश्योरेंस हो सकेगा, जिन पर फास्टैग लगा होगा। इसका मकसद सभी वाहनों पर फास्टैग लगाना है।

परिवहन मंत्रालय ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तहत देशभर के राजमार्गों पर टोल बूथ पर बिना रुके यातायात संचालित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी (आरएफआइडी) को लागू किया है। नवंबर में परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 70 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। इसे लगाने वाले वाहनों की संख्या और बढ़े, इसके लिए सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फास्टैग 2.0 शुरू किया है। इसकी शुरुआत हैदराबाद एयरपोर्ट से हुई है। इसके तहत फास्टैग से पार्किंग शुल्क भरने की सुविधा दी जा रही है। आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर तेल भराने जैसी अन्य सुविधा भी शुरू होगी। इसी कड़ी में अब सरकार इस तैयारी में जुट गई है कि आने वाले दिनों में उन्हीं वाहनों का इंश्योरेंस किया जाएगा, जिन पर फास्टैग लगा होगा।

12 लोग हो सकते हैं गिरफ्तार

अनाज मंडी अग्निकांड

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

फिल्मिस्तान स्थित अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में आग लगने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच से साफ हो गया है कि इमारत में कई तरह के अवैध धंधे चल रहे थे। रिहान कुछ हिस्से में अवैध फैक्ट्री चलाता था, शेष बचे हिस्से को उसने करीब 12 लोगों को किराए पर दे रखा था। किराए पर कमरे लेकर ठेकेदार वहां अवैध रूप से फैक्ट्रियां चलाते थे। छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर वहीं रहते भी थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक फैक्ट्री के मालिक रिहान व उसके मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार किया है। उक्त दोनों से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने उन 12 लोगों की सूची तैयार की है, जो वहां बगैर संबंधित विभागों से लाइसेंस व अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए कारोबार कर रहे थे।

मंगलवार को क्राइम ब्रांच फुरकान को लेकर मौके पर पहुंची। उससे सभी चार मंजिलों पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ की गई। फुरकान से सभी किराएदारों के मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं। किराया वसूलने से लेकर रिहान के हर कारोबार का वही हिसाब रखता था। दरसअल किराए पर कमरे लेकर लोग वहां अवैध धंधे कर रहे

अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में हुए अग्निकांड के बाद फैक्ट्री के प्रबंधक फुरकान (दाएं से दूसरे) को लेकर पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारी पूछताछ के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। ध्रुव कुमार

थे। ठेकेदार खुद वहां नहीं रहते थे। घटना के बाद से सभी फरार हैं। क्राइम ब्रांच फुरकान से मिले मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी तलाश कर रही है।

सदर बाजार थाना पुलिस ने रिहान व उसके मैनेजर फुरकान को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड पर लिया है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आशीष दूबे व अजय कुमार की टीम फुरकान को लेकर अनाज मंडी गई थी। क्राइम ब्रांच ने क्राइम रिकॉर्ड अफसर के जरिये पूरी बिल्डिंग की फोटोग्राफी कराई है।

प्रारंभिक जांच से भी पता चला है कि घटना वाले दिन तड़के द्वितीय मंजिल पर बिजली के मीटर के पास शार्ट सर्किट से चिंगारी निकली थी। इससे नीचे रखे गत्ते में आग लग गई थी। आग फैलकर वहीं पास में रखे ज्वलनशील पदार्थ के डिब्बे तक जा पहुंची, इसके बाद सीढियों के पास आग तेजी से फैलती चली गई। धुआं व आग फैलने से दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल के कमरों में सो रहे लोगों की नींद तो खुल गई थी, लेकिन उन्हें जान बचाने के लिए छत पर भागने का मौका नहीं मिल पाया। सीढ़ी के दरवाजे में फुरकान ने ताला लगा रखा था।

कड़वा सच

प्रजा फाउंडेशन और हंसा रिसर्च के सर्वेक्षण में पाया गया कि बात चाहे अपराध के शिकार होने वाले लोगों की हो या फिर अपराध के प्रत्यक्षदर्शियों की, सभी पुलिस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं

राजधानी में लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में रहने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है। बात चाहे अपराध के शिकार होने वाले लोगों की हो या फिर अपराध के प्रत्यक्षदर्शियों की, सभी पुलिस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। यही नहीं पुलिस के रवैये को देखते हुए लोग अपने या दूसरों के साथ होने वाले अपराध की सूचनाएं देने से भी कतराते हैं। यह बात सर्वे में सामने आई है। इसमें राजधानी के 72 फीसद लोग पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट थे।

प्रजा फाउंडेशन ने हंसा रिसर्च के साथ मिलकर राजधानी में सर्वे किया है। इसमें पुलिस व कानून व्यवस्था की स्थिति पर लोगों की राय ली गई। प्रजा फाउंडेशन के निदेशक मिलिंद म्हस्के ने बताया कि दिल्ली में रहने वाले 27,121 परिवारों को सर्वे में शामिल किया गया। इनमें से दस फीसद लोगों ने अपराध होते हुए देखा था, लेकिन इनमें 57 फीसद ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी, जबकि 35 फीसद ने अपराध का सामना किया और 26 फीसद ने पुलिस को मामले की जानकारी ही नहीं दी। अपराध होते देखने वाले सिर्फ चार फीसद लोगों ने ही पुलिस थाने में जाकर एफआइआर दर्ज कराई। वहीं, अपराध का सामना करने वाले पांच फीसद लोगों ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस को अपराध की सूचना देने वाले 72 फीसद लोग पुलिस की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं थे। अपराध का सामना करने वाले और प्रत्यक्षदर्शियों में से 26 फीसद लोगों ने इसलिए पुलिस को सूचना नहीं दी, क्योंकि उन्हें पुलिस और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है।

दुष्कर्म के 63 फीसद पीड़ित मासूम बच्चे : रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरटीआइ के जरिये ली गई जानकारी में पता लगा कि राजधानी में दुष्कर्म के मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए मामलों में से 63 फीसद पीड़ित मासूम बच्चे थे। दुष्कर्म के दर्ज कुल 1965 मामलों में 1237 में दरिंदों ने मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं वर्ष 2018-19 में अपहरण कर और बहला-फुसलाकर भगाने के मामलों में 94 फीसद मामले बच्चों के अपहरण के थे। इनकी संख्या 5555 थी। इनमें से 70 फीसद मामलों में पीड़ित लड़की थी।

छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में आई है कमी : आरटीआइ से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में दिल्ली में दर्ज किए गए दुष्कर्म के मामलों में छह फीसद की कमी आई है। जबकि, छेड़छाड़ की घटनाओं में 30 फीसद की कमी आई है। वहीं चोरी के मामलों की बात की जाए तो यह संख्या करीब दोगुनी हो गई है। वर्ष 2014-15 में चोरी के 52 हजार 211 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2018-19 में चोरी के एक लाख आठ हजार 406 मामले दर्ज किए गए।

हजारों मामलों की जांच है बाकी : सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में दिल्ली में आइपीसी के तहत चार लाख दो हजार 512 मामलों की जांच की जानी थी। इनमें से 35 फीसद मामलों की जांच वर्ष के अंत तक पूरी नहीं हो सकी थी। वहीं 2017 में दो लाख 42 हजार 125 मामलों की अदालतों में कानूनी जांच की जानी थी। इनमें से 89 फीसद मामलों में 2017 के अंत तक ट्रायल पूरा नहीं सका था।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने को भाजपा ने बनाई समिति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनाज मंडी अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों व घायलों को मुआवजा देने के लिए भाजपा ने समन्वय समिति गठित की है। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष अभय वर्मा व योगिता सिंह, प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मुहम्मद हारून, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष मनीष सिंह व भाजपा नेता डॉ. सरदार खान शामिल किए गए हैं।

हादसे वाले दिन भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिहं पुरी की उपस्थिति में मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख तथा घायलों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा देने का एलान किया था। पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा राशि मिल सके, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है।

निगमों ने भूरेलाल से कहा, नेता नहीं करने दे रहे फैक्ट्रियां सील

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

महज तीन दिन पहले फिल्मिस्तान अग्निकांड में हुई 43 मौतों को लेकर जांच कमेटियां कुछ भी कहें, लेकिन हादसों की रोकथाम को लेकर गंभीरता अभी भी कहीं नजर नहीं आती। आलम यह है कि जो जन प्रतिनिधि घटनास्थल एवं अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, वही अवैध गतिविधियों को संरक्षण भी देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) भी इन हालातों से परेशान है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अपनी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक रविवार को हुए हादसे के बाद ईपीसीए अध्यक्ष और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य डॉ. भूरेलाल ने तीनों नगर निगमों के आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इसमें अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियों को सील करने के स्पष्ट निर्देश दिए। लेकिन, निगम अधिकारियों ने यह कहकर बेबसी जाहिर की कि जहां भी सीलिंग करने जाते हैं, वहां के विधायक और पार्षद समर्थकों के साथ आ जाते हैं। इस बीच यह भी बताया कि अकेले शाहदरा साउथ जोन में 1,072 अवैध फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जन प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप की वजह से उन्हें सील कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस पर भूरेलाल ने निगम अधिकारियों से लिखित में रिपोर्ट देने को कहा है।

1930 में मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता इकबाल ने पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कही थी।

क्या नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता का परिणाम है नागरिकता कानून

8 अप्रैल, 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू (बाएं) और पाक पीएम लियाकत अली (दाएं) ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ● फाइल फोटो

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक को सही ठहराते हुए सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने नेहरू-लियाकत समझौते का उल्लेख किया था। उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते को 'कैब' की वजह बताते हुए कहा, यदि पाकिस्तान द्वारा संधि का पालन किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। 1950 में दिल्ली में तत्कालीन पीएम नेहरू और पाक पीएम लियाकत अली खान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे नेहरू-लियाकत समझौता नाम दिया गया। आइए जानते हैं क्या है यह समझौता और यह क्यों किया गया था:

इसलिए किया गया था समझौता

दोनों देशों के बीच अल्पसंख्यक समुदायों के बड़े पैमाने पर प्रवासन की पृष्ठभूमि में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बड़ी चिंता पूर्वी पाकिस्तान (जो बाद में बांग्लादेश बना) से हिंदुओं और पश्चिम बंगाल से मुसलमानों का पलायन था। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ के साथ दोनों देशों के बीच के रिश्ते पहले ही तनावपूर्ण हो चुके थे। पाकिस्तान से अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों के पलायन और भारत में मुसलमानों को गंभीर शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। इसे रोकने के लिए दोनों देशों के बीच अप्रैल 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ।

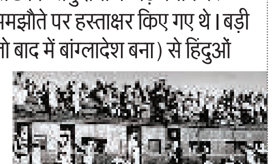

क्या है समझौता

इस समझौते के तहत शरणार्थी अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत-पाकिस्तान आ जा सकते थे।

- अगवा की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाना था।
- जबरन धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी गई थी।
- दोनों देशों ने अपने-अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था विरोध

दिल्ली पैक्ट के नाम से भी मशहूर इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने समझौते को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला बताया था।

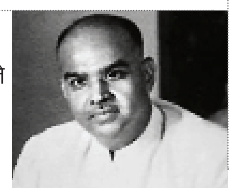

समझौता सफल या विफल बना बहस का विषय

नेहरू-लियाकत समझौते ने अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल किया या नहीं, यह बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि, नेहरू-लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद महीनों तक पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं का पलायन भारत के पश्चिम बंगाल में जारी रहा। अगस्त 1966 में, जनसंघ के नेता निरंजन वर्मा ने तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से तीन प्रश्न पूछे।

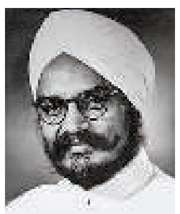

पहला सवाल : नेहरू-लियाकत समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है?
दूसरा सवाल : क्या दोनों देश अभी भी समझौते की शर्तों के अनुसार कार्य कर रहे हैं?
तीसरा सवाल : वह साल कौन सा है, जब से पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन कर रहा है?

स्वर्ण सिंह ने अपने जवाब में कहा, 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी समझौता है। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों को भी नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हों।

दूसरे सवाल पर, स्वर्ण सिंह ने जवाब दिया, हालांकि भारत में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लगातार और प्रभावी रूप से संरक्षित किया गया है, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लगातार उपेक्षा और उत्पीड़न करके समझौते का लगातार उल्लंघन किया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता के बारे में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए दावे को परिलक्षित करता है। स्वर्ण सिंह ने कहा, इस तरह के उल्लंघनों के उदाहरण समझौते होने के तुरंत बाद ही सामने आने लगे थे।

क्या बोले अमित शाह

नागरिकता संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश विभाजन के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक गलती को सही कर रही है।

राज्यसभा से होना है पारित

नागरिकता संशोधन विधेयक को सत्ताधारी भाजपा ने लोकसभा से आसानी से पारित करवा लिया है। अब राज्यसभा में इस विधेयक को रखा जाना है, जहां से पारित होने बाद यह कानून की शक्ल लेगा।

कांग्रेस बोली, हिंदू महासभा-मुस्लिम लीग ने बांटा देश

दावा ▶ मनीष तिवारी ने गृह मंत्री के लोकसभा में बयान को बताया गलत, कहा-इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश न करें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों से तिलमिलाई कांग्रेस ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर द्वि-राष्ट्र बनाने का सिद्धांत हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का था। शाह के बयान को आपत्तिजनक करार देते हुए पार्टी ने उन्हें इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं करने की नसीहत दी।

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने धर्म के नाम पर बंटवारा न किया होता तो नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर दो अलग-अलग राष्ट्र का सिद्धांत रखकर देश का बंटवारा कराया। महान स्वाधीनता सेनानी और हिंदू महासभा के नेता लाला लाजपतराय के 1924 में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए तिवारी ने कहा कि इसमें उन्होंने देश को दो हिस्सों मुस्लिम भारत और हिंदू भारत में विभाजित करने की बात कही थी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू महासभा के बाद 1930 में मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता इकबाल ने पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध ओर बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कही थी। इसके बाद 1937 में हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने अहमदाबाद में साफ कहा था कि भारत एक समरूप लोगों का राष्ट्र नहीं बल्कि इसके उलट इसमें दो राष्ट्र हैं हिंदू और मुसलमान। इसके बाद मोहम्मद अली

मनीष तिवारी फाइल फोटो

जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची सम्मेलन में 1940 में साफ कहा था कि देश में हिंदू और मुसलमान एक समान नागरिक होंगे यह एक सपना है। जिन्ना ने इसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि धर्म, संस्कृति, साहित्य और परंपरा के हिसाब से हिंदू और मुसलमान बिल्कुल अलग हैं। ये दोनों न साथ खा सकते हैं और न ही आपसी वैवाहिक संबंध कर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसी तरह सावरकर ने 1943 में बिल्कुल साफ कर दिया था कि जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से उनका कोई विरोध नहीं है।

मनीष तिवारी ने कहा, हकीकत यह भी है कि जब भारत की मर्जी के खिलाफ अंग्रेजों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में उसे शामिल किया तो कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आजादी के आंदोलन को तेज कर दिया था। इस दौरान तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर प्रांतों में सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस के नेता स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जा रहे थे। तिवारी ने कहा कि इतिहास की यह सच्चाई झुठलाई नहीं जा सकती और गृह मंत्री का इतिहास को इस तरह तोड़-मरोड़ कर पेश करना आपत्तिजनक है।

कैब से असम में बंगालियों का वर्चस्व नहीं होगा : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्वोत्तर में व्यापक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि नागरिकता संशोधन बिल (कैब) से असम में बंगाली भाषियों का वर्चस्व नहीं हो जाएगा और न ही यह राज्य के मूल लोगों के हितों के विरुद्ध है।'मिथक तोड़ो' हैशटैग से प्रेस सूचना कार्यालय (पीआइबी) ने कहा कि कैब बंगाली हिंदुओं को स्वत: ही भारतीय नागरिकता नहीं देगा बल्कि यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लिए समर्थकारी कानून है। यह पूरी तरह मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर अत्याचार होने के कारण इन देशों से भागे हैं। ट्वीट में कहा गया है, 'ज्यादातर हिंदू बंगाली असम की बराक घाटी में बसे हुए हैं जहां बंगाली दूसरी राजकीय भाषा घोषित है। ब्रह्मपुत्र घाटी में हिंदू बंगाली छिटपुट स्थानों पर बसे हैं और उन्होंने असमी भाषा को अपना लिया है।' पीआइबी ने कहा, मिथक है कि कैब हिंदू बंगालियों को बसाकर आदिवासी जमीन हथियाने की चाल है, लेकिन तथ्य यह है कि हिंदू बंगाली ज्यादातर बराक घाटी में बसे हैं और वे जनजातीय क्षेत्रों से दूर हैं। कैब जनजातीय जमीनों की रक्षा से जुड़े कानूनों और विनियमों का उल्लंघन नहीं करता और यह उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां इनर लाइन परमिट और छठी अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधान हैं। कैब असम से अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन से संबंधित असम संधि को शिथिल बनाता है यह बात भी बिल्कुल गलत है।

बिल पर पाकिस्तान ने टांग अड़ाई

- ▶ इमरान बोले-विधेयक संघ की हिंदू राष्ट्र की विस्तारवादी योजना का हिस्सा
- ▶ धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का स्वागत हो : भारत

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपनी टांग अड़ाई है। भारत के आंतरिक मामले में दखल देते हुए पड़ोसी मुल्क ने विधेयक को पक्षपातपूर्ण बताया है। साथ ही इसे भारत का पड़ोसी देशों के मामलों में 'दखल' का 'दुर्भावनापूर्ण इरादा' करार दिया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को ट्वीट किया कि नागरिकता बिल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के सभी नियमों और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करता है। 'यह आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विस्तारवादी योजना का हिस्सा है।' इससे पहले पाक के विदेश मंत्रालय ने मध्य रात्रि के बाद एक बयान जारी किया। उसमें कहा,'हम इस विधेयक की निंदा करते हैं। यह प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण है और सभी संबद्ध अंतरराष्ट्रीय संधियों व मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह पड़ोसी देशों में दखल का भारत का दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।' इस कानून का आधार झूठ है और यह धर्म या आस्था के आधार पर भेदभाव को हर रूप में खत्म करने संबंधी मानवाधिकारों की वैश्विक उद्घोषणा व अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है।

वक्तव्य के मुताबिक, 'लोकसभा में लाया गया बिल पाक और भारत के बीच हुए दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े समझौते समेत विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों का भी पूर्ण रूप से विरोधाभासी है।' हालांकि पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार का यह विधेयक 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक प्रमुख कदम है, जिस अवधारणा को कई दशकों से दक्षिणपंथी हिंदू नेताओं ने पाला पोसा। यह विधेयक क्षेत्र में कट्टरपंथी 'हिंदुत्व विचारधारा और प्रभावी वर्ग की महत्वकांक्षाओं' का विषैला मेल है और धर्म के आधार पर पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में दखल की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पाकिस्तान इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि विधेयक के पीछे बहुसंख्यक एजेंडा है और इसने आरएसएस-भाजपा की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को विश्व के समक्ष ला दिया है।'

इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस विधेयक में भारत में पहले से ही रह रहे कुछ विशिष्ट देशों के धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शीघ्र नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यह उनकी वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने और उनके बुनियादी मानवाधिकारों को पूरा करने का प्रयास करता है। इस तरह की पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, उन लोगों को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं।' मंत्रालय के अनुसार कैब, नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक सभी समुदायों के लिए उपलब्ध मौजूदा रास्तों को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह की नागरिकता देने का हालिया रिकॉर्ड भारत सरकार की निष्पक्षता को प्रदर्शित करता है।

संसद प्रश्नोत्तर

आयुष्मान योजना में इस साल हुआ 65 लाख मरीजों का इलाज

- ▶ दिल्ली, प. बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के लोगों को नहीं मिल पा रहा योजना का लाभ : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत इस साल पांच दिसंबर तक 65 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। इनके इलाज पर 9,549 करोड़ रुपये का खर्च आया। जबकि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के गरीब परिवारों को अभी भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि उक्त चारों राज्यों ने एबी-पीएमजेएवाई को लागू नहीं किया है। पश्चिम बंगाल ने तो इसे लागू करने के बाद वापस ले लिया। वहीं, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत 65,45,733 मरीजों में से 35,34,695 मरीजों का इलाज निजी अस्पतालों में किया गया और उनके इलाज पर 6,133 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक सवाल के लिखित जवाब में चौबे ने इलाज की कीमतों को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच किसी तरह की खींचतान से इन्कार किया। बता दें कि एबी-पीएमजेएवाई के तहत 1,392 स्वास्थ्य पैकेज हैं और उनकी

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन फाइल फोटो

दरें पूर्व निर्धारित हैं। इनके अलावा एक सर्जिकल पैकेज भी है।

2022 तक 1.2 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति : अश्विनी चौबे ने बताया कि इस योजना के तहत 2022 तक देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों (एचडब्लूसी) की स्थापना की जानी है। लिहाजा 2022 तक उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) स्तरीय एचडब्लूसी पर 1.2 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के 84 प्रयास

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगस्त से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से घुसपैठ के कम से कम 84 प्रयास हुए। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि 59 आतंकियों के घाटी में प्रवेश करने की आशंका है।

सदन में तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए रेड्डी ने कहा कि एलओसी से जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित है। उन्होंने कहा, 'सीमा पार से 84 ऐसे प्रयास हुए हैं और अनुमान है कि 59 आतंकी प्रवेश कर गए होंगे।'गृह राज्यमंत्री ने कहा कि 2005 से 21 अक्टूबर 2019 तक 1110 आतंकियों को मार गिराया गया, 42 को पकड़ा गया और 2253 को पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। सुरक्षा बलों की प्रभावी निगरानी से यह संभव हुआ है।

जेके और लद्दाख के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग से भत्ता : गृह राज्यमंत्री ने एक लिखित उत्तर में बताया कि दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुके जम्मू-कश्मीर के 4.5 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों के लिए 4,800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक बच्चों की शिक्षा भत्ता, छात्रावास भत्ता, परिवहन भत्ता, एलटीसी, तय चिकित्सा भत्ता देना इसमें शामिल है। इससे पहले कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं दिए जा रहे थे। 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए।

अरावली की पहाड़ियों को बचाने की मांग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाणा में घटते वन क्षेत्र को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में चिंता जताई गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद व गुरुग्राम के बीच अरावली की पहाड़ियों के 47 फीसद वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है, जिन्हें 'ग्रीन लंग्स' माना जाता है।

इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाते हुए कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा देश में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। यहां वन क्षेत्र में बढ़ोतरी की सख्त जरूरत है। राज्य सरकार ने 27 फरवरी 2019 को पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर पूर्व के कानून को कमजोर बना दिया है। इस क्रम में राज्य के 130 गांवों के पहाड़ी क्षेत्रों की 74 हजार एकड़ भूमि को वन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। सैलजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को हर कीमत पर बचाने की बात कही है। दिल्ली-एनसीआर के लिए अरावली की पहाड़ियों को बचाना बहुत जरूरी है। इससे राजस्थान के बढ़ते आ रहे रेगिस्तान को रोकने में मदद मिल रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से एक टास्क फोर्स के गठन की मांग की, जो वन क्षेत्र को वर्ष 2024 तक कम से कम पांच फीसद और वर्ष 2030 तक 10 फीसद तक बढ़ाने में मदद करे।

राज्यसभा में उठा अध्यापकों की पेंशन स्कीम का मुद्दा

- ▶ नई पेंशन योजना में पैसे को लेकर पारदर्शिता का अभाव
- ▶ शून्यकाल के दौरान सपा नेता रामगोपाल यादव ने उठाया मामला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा में सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज के अध्यापकों तक की पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का मुद्दा मंगलवार को उठा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए नई पेंशन स्कीम में पारदर्शिता के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक हड़ताल पर थे। इनमें सरकारी कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेजों और महाविद्यालयों के अध्यापक शामिल थे। रामगोपाल ने कहा, पुरानी पेंशन योजना को 2005 में बदल दिया गया। नई पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन का 10 फीसद काटकर पेंशन स्कीम में डाल दिया जाता है। इसकी गवर्निंग एजेंसी भारतीय स्टेट बैंक, यूटीआइ और एलआइसी हैं। नया सिस्टम लागू होने के बाद कर्मचारियों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनका पैसा कहां जा रहा है? कहां निवेश किया जा रहा है?

यादव ने कहा, 'दरअसल यह सारा धन 169 निजी कंपनियों में जमा किया गया है, जो दिवालिया होने के कगार पर हैं। ये कंपनियां दिवालिया हो गईं तो इन कर्मचारियों की पेंशन का क्या होगा?' सपा नेता ने सरकार से पुरानी

राज्यसभा में मंगलवार को बोलते सपा नेता रामगोपाल यादव। प्रेट्र

पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में सारे अध्यापक उद्वेलित हैं। उनकी आशंका निर्मूल नहीं है। सरकार सिस्टम ठीक करके प्रॉविडेंट फंड की तर्ज पर कर्मियों को उनकी पेंशन की राशि की रसीद और पासबुक जारी करे। उन्होंने कहा,देश में इतनी ज्यादा संख्या में कर्मचारी हैं, जिनका पैसा पेंशन मद में काटा जा रहा है। सरकार उन्हें उनके पैसे सुरक्षित होने का भरोसा दे। सदन में कई सदस्यों ने खुद को इससे संबद्ध किया।

शस्त्र कानून संशोधन बिल पर रास की भी मुहर, अब हर गोली पर रहेगी नजर

नीलू रंजन, नई दिल्ली

बंदूक, पिस्तौल या फिर राइफल की गोलियों का गलत इस्तेमाल आने वाले दिनों में महंगा साबित हो सकता है। हर गोली पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि यह गोली मूल रूप से किसकी है। शस्त्र कानून पर चर्चा के दौरान गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। बाद में राज्यसभा ने शस्त्र कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। लोकसभा में यह विधेयक सोमवार को पारित हो चुका है।

जी कृष्ण रेड्डी ने उच्च सदन में बताया कि गोलियों पर सीरियल नंबर के साथ ही सरकार नेशनल डाटाबेस ऑन आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) और आर्म्स लाइसेंस इश्यूएंस सिस्टम (एएलआइएस) का पोर्टल भी लांच करने की योजना बना रही है। इस पोर्टल पर एक ही जगह आर्म्स लाइसेंस जारी किए जाने, इसके धारकों और उपयोग किए गए गोलियों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। जाहिर है सरकार के पास पूरा ब्योरा होगा कि किस नंबर की गोली किसके नाम पर जारी की गई है। ऐसे में गोलियों की अवैध खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाना संभव हो सकेगा। दोनों सदनों से मुहर लगने के बाद अब नए शस्त्र कानून के अनुसार प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद रखने की अवस्था में पांच से सात साल की जगह सात से 14 साल का कारावास हो सकता है। इसी तरह सेना के जवानों या पुलिस बल से हथियार छिनने की स्थिति में आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अवैध हथियार बनाने वालों, संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने वालों को भी आजीवन कारावास की सजा होगी।

इसमें हर्ष फायरिंग में होने वाली मौतों पर कठोर सजा का प्रावधान है। इसी तरह विधेयक के पास होने के बाद प्रतिबंधित विदेशी अत्याधुनिक हथियारों को लाने, बेचने और उपयोग करने वालों के लिए कड़ी सजा का रास्ता साफ हो गया है। नए संशोधनों के अनुसार अब लाइसेंसधारी को हर तीन साल में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना होगा। इसकी सीमा बढ़ाकर पांच साल किया गया है।

नए कानून से खिलाड़ियों, पूर्व सैनिकों व मौजूदा सैनिकों को मिलने वाले हथियारों के लाइसेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही नहीं, खिलाड़ियों की जरूरत को देखते हुए इसमें उन्हें और अधिक हथियार देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह सैन्यबल के अवकाश प्राप्त अधिकारी की शस्त्र की पूर्व संख्या को भी उसी तरह से रख गया है।

35 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं देश में

13 लाख वैध शस्त्र अकेले उत्तर प्रदेश में हैं

3.7 लाख लाइसेंस जम्मू-कश्मीर में लोगों के पास हैं

- ▶ शस्त्र कानून में संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह राज्यमंत्री ने दी जानकारी
- ▶ कानून में संशोधनों को मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत ही बाकी

किशन रेड्डी फाइल फोटो

कह के रहेंगे — माधव जोशी

वित्त मंत्री बोलीं

निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी, वित्त मंत्री ने इस संबंध में विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को निर्मूल बताया

चुनावी बांड से आरबीआइ को नहीं थी आपत्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव बांड को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बीच सरकार ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के माध्यम से चुनावी बांड जारी किए जाने में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को कोई आपत्ति नहीं थी।

प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देती हुई वित्त मंत्री ने कहा कि एक हितधारक के तौर पर आरबीआइ इसकी परिकल्पना के समय से ही सरकार के साथ विचार-विमर्श में शामिल था। सीतारमण ने कहा, 'परामर्श की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने सवाल किया था कि इस बांड को कौन जारी करने जा रहा है और इसे किस प्रारूप में जारी किया जाएगा।' उन्होंने कहा, 'समस्त बातचीत रिकॉर्ड में है। अंत में जब एसबीआइ के माध्यम से बांड जारी किए जाने वाले थे तो आरबीआइ ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।'

वित्त मंत्री ने कहा कि 11 अक्टूबर 2017 को एसबीआइ की तरफ से चुनावी बांड जारी किए जाने के मुद्दे पर आरबीआइ की कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड (सीसीबी) अप्रत्यक्ष रूप से सहमत थी। सीसीबी के साथ बैठक में बैंक व अन्य हितधारकों ने योजना को लेकर विमर्श किया था। उन्होंने बताया, 'सीसीबी ने बैंक के उस कदम का समर्थन किया था कि चुनावी बांड विभाजित रूप में जारी नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन उसने कहा कि अगर सरकार एसबीआइ के माध्यम से चुनावी बांड विभाजित रूप में जारी करना चाहती है तो बैंक को ऐसा करने देना चाहिए।' सीतारमण ने कहा कि चुनावी बांड को बीयरर प्रारूप में जारी करने का उद्देश्य राजनीतिक प्रणाली में चंदे को पारदर्शी बनाना था। उन्होंने कहा, इस संबंध में विपक्ष की ओर से जो भी बातें कहीं जा रही हैं, वह निराधार हैं।

राज्यसभा में एक अन्य पूरक सवाल का जवाब देती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,सरकार गुमनाम दाताओं के बारे में जानकारी नहीं पा सकती है, क्योंकि योजना की अधिसूचना के समय ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जारी करने वाला प्राधिकार इसकी गोपनीयता बरकरार रखेगा। दानकर्ता के बारे में जानकारी सिर्फ अदालत के आदेश पर दी जा सकती है। वह भी तब जब सीबीआइ या कोई भी अन्य जांच एजेंसी किसी मुकदमे में आरोपपत्र के लिए इसकी मांग करती है।

राज्यसभा में मंगलवार को चुनाव बांड पर सवाल का जवाब देतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCHES
(Optional) राजनीति विज्ञान
भारत तथा विश्व से कक्षा प्रारम्भ... 18 DEC 2019 3:00 PM 5:30 PM
सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा) सामाजिक न्याय से कक्षा प्रारम्भ... 18 DEC 2019 11:30 AM 2:00 PM
GS-IV मुख्य परीक्षा नीतिशास्त्र (ETHICS) 18 DEC 2019 9:00 AM 11:00 AM
OFFLINE / ONLINE CLASSES
B-11, 1st FLOOR, IN FRONT OF MEERUT SWEETS, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

DR. RAMASWAMY IAS ACADEMY
FREE COACHING
IAS, SSC, JUDICIARY AND GROUP-A, B & C
SC/ST/EWS/OBC DELHI RESIDENCE ONLY
9350933144, 9958589406
1418, Dr. Mukherjee Nagar, 4th Floor, Main Road, New Delhi-09
4-A/17, Old Rajendra Nagar Main Market, New Delhi-110060

275 से अधिक उम्मीदवार झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में ऐसे हैं, जो पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। इस चरण में धनवार, रांची, हटिया, बरही और सिल्ली सबसे हॉट सीटें की मानी जा रही हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 दिसंबर 2019

एससी–एसटी जनप्रतिनिधियों के आरक्षण को लोकसभा से मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- संशोधन विधेयक के समर्थन में 352 और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा
- एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटों पर संशय, वर्तमान विधेयक में नहीं था प्रावधान
- एंग्लो इंडियन के बारे में रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, हम विचार करेंगे : रविशंकर प्रसाद

लोकसभा में मंगलवार को एससी–एसटी जनप्रतिनिधियों के आरक्षण को अगले दस साल तक बढ़ाने से जुड़े विधेयक पर बोलते कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। एएनआइ

लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आरक्षण को अगले दस साल तक बढ़ाने के लिए लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मिलने वाले मनोनयन को नहीं बढ़ाया गया है। यानी 25 जनवरी, 2020 के बाद से लोकसभा और विधानसभाओं में उन्हें मिला आरक्षित प्रतिनिधित्व खत्म हो सकता है। यह संभावना इसलिए बनी है क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कई बार दोहराया कि अभी यह आरक्षण खत्म नहीं किया गया है। विचार चल रहा है। विपक्ष की ओर से एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को नहीं बढ़ाने का विरोध किया गया। प्रधानमंत्री ने विधेयक के पारित होने पर खुशी जताई है।

लोकसभा और विधानसभाओं में एससी-एसटी वर्ग के लिए लगभग एक हजार सीटें आरक्षित हैं। शुरुआत में यह आरक्षण सिर्फ दस साल के लिए लागू किया गया था लेकिन उसके बाद हर दस साल में इसे बढ़ाया जाता रहा है। यह आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को खत्म हो रहा है। इसको बढ़ाने के लिए पेश 126वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में 352 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। जाहिर है कि इस आरक्षण पर तो कोई विरोध हो नहीं सकता था इसीलिए लोकसभा में चर्चा छिड़ी तो विपक्ष की ओर से सरकार पर एससी-एसटी के साथ भेदभाव की बात की गई। इस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से याद दिलाया गया कि भाजपा की सरकार में ही भीमराव आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ स्थान का दर्जा दिया गया। अवसर मिला तो राष्ट्रपति के पद पर भी दलित वर्ग के राजनेता को बिठाया गया है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में सदन ने इस संविधान संशोधन को पारित कर दिया। राज्यसभा में पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों से भी पारित कराया जाएगा उसके बाद यह प्रभावी होगा। बहरहाल पूरी चर्चा में विपक्ष के भाषणों में एंग्लो इंडियन का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में दो और विधानसभाओं में आरक्षित 13 सीटों को खत्म करना अनुचित है। तिवारी ने कहा कि सरकार इस हद तक उतर आई है कि देश के सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय एंग्लो इंडियन की लोकसभा में नामित कर भरे जानेवाली दो सीटों को खत्म कर रही है। दूसरे विपक्षी दलों ने भी कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा किया। देश के निर्माण में एंग्लो इंडियन के योगदान और वर्तमान हालात में उनकी खराब हालत का हवाला देते हुए आरक्षण जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने याद दिलाया कि एंग्लो इंडियन को शुरुआत में पोस्टल और रेलवे में भी आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसका विस्तार नहीं किया। रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र सबको पता है। जब सत्ता में थे तो एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म कर दिया और आज जब सरकार रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के सहारे बता रही है कि उनकी संख्या केवल 296 रह गई तो सवाल खड़े कर रही है। तृणमूल के सांसद सौगत राय ने इस संख्या पर सवाल खड़ा किया तो रविशंकर ने कुछ राज्यों में इसका ब्योरा रख दिया और बताया कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ नौ है, महाराष्ट्र में 16, केरल में सबसे ज्यादा 125, कर्नाटक में 62 आदि। रविशंकर ने बताया कि संविधान में भी एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात कही गई है जबकि एंग्लो इंडियन के लिए मनोनयन की बात है। यह परिस्थिति के अनुसार तय किया जाता है। रकार देखेगी।

प्रोन्नति में एससी–एसटी कोटे पर 28 जनवरी को सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नति में आरक्षण देने से संबंधित सभी पहलुओं पर अगले महीने विचार करेगा। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार, मप्र और त्रिपुरा सरकार के वकीलों की इस दलील पर संज्ञान लिया कि यथास्थिति बनाए रखने के शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश से इस वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के प्रोन्नत में बाधा आ रही है। इस पर पीठ ने कहा, 'हम 28 जनवरी को सभी आवेदनों पर सुनवाई करेंगे।' केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह एससी–एसटी समुदाय के कोटे से क्रीमी लेयर को अलग करने के अपने पिछले साल के फैसले को सात सदस्यीय पीठ के सामने पुनर्विचार के लिए भेज दे। पिछले साल पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि एससी–एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। मंगलवार की संक्षिप्त सुनवाई में इन राज्यों की तरफ से बताया गया कि शीर्ष अदालत के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के चलते उनके यहां सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं, जिन्हें प्रोन्नति के जरिये ही भरा जाना है।

मप्र के भाजपा विधायक लोधी की सदस्यता समाप्ति का आदेश निरस्त

नईदुनिया, भोपाल : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त करने के आदेश को विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी गई, जिसमें सदस्यता समाप्ति की अधिसूचना निरस्त करने की जानकारी दी गई है। लोधी को दो नवंबर से नौ दिसंबर के बीच की अवधि का वेतन-भत्ता लेने की भी पात्रता होगी। विशेष न्यायालय ने एक मामले में लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस पर मप्र हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर को हाई कोर्ट के फैसले को सही करार दिया था। सोमवार को विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बीच गोटेगांव में चर्चा हुई थी तथा दोनों पक्षों के बीच लोधी की सदस्यता समाप्ति का आदेश निरस्त करने पर सहमति बनी थी। गोटेगांव में ही विस अध्यक्ष प्रजापति ने सदस्यता समाप्ति के आदेश को निरस्त करने की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

छग में सरकार खोज रही पाकिस्तानियों की संपत्ति

मृगेंद्र पाण्डेय, रायपुर : देश में एनआरसी के मुद्दे के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने पाकिस्तान से आकर संपत्ति खरीदने वालों की खोज शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दिया जाए। बताया जा रहा है कि जो संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में छह लाख विदेशी शरणार्थी हैं। इसमें से 40 फीसद वापस पाकिस्तान और बांग्लादेश लौट गए हैं। केंद्र ने पाकिस्तान लौटने वालों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया है और उसका रिकार्ड राज्यों से मंगाया है। केंद्र के फरमान के बाद राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति की पड़ताल शुरू हुई है। पूर्व राजस्व सचिव एके खाखा ने बताया कि केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति का ब्योरा मांगा था। प्रदेश में कुछ जगहों से जानकारी मिली है। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति का भी ब्योरा आया है। अब उन जिलों के कलेक्टरों को इस संपत्ति पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। खाखा ने बताया कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की संपत्ति का उपयोग कैसे करना है, इसकी गाइडलाइन भी जारी की है।

इसमें शत्रु संपत्ति को किराए पर देने के साथ अन्य तरीके बताए गए हैं। इसमें लावारिस हालत में पड़ी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का भी प्रावधान है। एनके खाखा हाल ही में रिटायर हुए हैं और उनके स्थान पर राजस्व सचिव सुबोध कुमार को बनाया गया। सुबोध ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। पुलिस मुख्यालय के खुफिया विंग के आला अधिकारियें ने बताया कि हर वर्ष बड़ी संख्या में पाकिस्तानी यहां पर्यटक के रूप में आते हैं। इनमें से कुछ वीजा का समय बढ़वाकर तो कुछ अवैध रूप से यहीं रुक जाते हैं। धीरे-धीरे कारोबार शुरू करते हैं और फिर प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं।

बंगाल के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के अधिकार सीमित

बदलाव ▸ विस में नया नियम पारित, शिक्षा विभाग के जरिये ही विवि से संपर्क कर सकेंगे गर्वनर

नए नियमों के तहत मानद उपाधि की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे राज्यपाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के अधिकारों को सीमित करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। मंगलवार को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सह शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने गैजेट अधिसूचना के जरिये वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटीज रूल्स 2019 को सदन में रखा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। नए नियम के अनुसार राज्यपाल जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, उन्हें अब किसी भी काम के लिए शिक्षा विभाग के जरिये विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित करना होगा। इस नए नियम से विश्वविद्यालयों में राज्यपाल का अधिकार सीमित हो जाएगा। नए नियम के अनुसार, विश्वविद्यालय सेनेट या किसी अन्य मीटिंग के लिए राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति से तारीख व कार्यसूची जाननी होगी इसके बाद ही राज्यपाल बैठक बुला सकते हैं। पहले राज्यपाल के अनुमति के अनुसार, ही बैठक बुलाई जाती थी। इतना ही नहीं बैठक को बुलाने के लिए कुलपति को पहले शिक्षा विभाग से विचार विमर्श भी करनी होगी।

पहले विश्वविद्यालय से मानद उपाधि देने के लिए जिन लोगों की सूची तैयार की जाती थी उसे पहले राज्यपाल के पास भेजा जाता था और आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल उस तालिका में बदलाव करने की क्षमता रखते थे, लेकिन जो नया नियम बनाया जा रहा है उसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्य के शिक्षा विभाग को सूची भेजेंगे उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। राज्यपाल उस सूची में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। केवल उन्हें जानकारी दी जाएगी।

अब शिक्षा विभाग चुनेगा कुलपति : पहले यह भी नियम था कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के जरिये तीन लोगों के नाम की सूची तैयार कर शिक्षा विभाग राज्यपाल के पास भेजता था। उन तीन लोगों में से किसी एक को राज्यपाल कुलपति के तौर पर नियुक्त कर सकते थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग सीधे तौर पर कुलपति का चुनाव करेगा और एक ही व्यक्ति का नाम राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसे अनुमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होंगे। किसी भी कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में राज्यपाल की अगर कोई शिकायत रहेगी तो सीधे तौर पर वह कोई फैसला नहीं ले सकेंगे, बल्कि शिक्षा विभाग को बताना होगा। शिक्षा विभाग उसकी जांच करेगा और उसी के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकेगा।

दीक्षा समारोह में भी हस्तक्षेप नहीं : दीक्षा समारोह को लेकर भी विश्वविद्यालय के कुलपति जो निर्णय लेंगे उसमें राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर सीधे तौर पर राज्य का शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों से संवाद करेगा और किसी भी तरह के बदलाव का सीधा अधिकार राज्य शिक्षा विभाग के पास होगा।

विस में तृणमूल ने किया राज्यपाल का विरोध

जागरण संवाददाता, कोलकाता

जगदीप धनखड़ फाइल

- बंगाल में लगातार बढ़ रही है राजभवन और राज्य सरकार के संबंधों में खटास
- जगदीप धनखड़ पर एससी–एसटी विधेयक रोक कर रखने का लगाया आरोप
- राज्यपाल का पलटवार, कछुए की गति से बढ़ रही है सरकार

बंगाल में राजभवन और राज्य सरकार के संबंधों में लगातार खटास बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को दोनों पक्ष के बीच तल्खी और बढ़ गई। विधानसभा में पहली बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने एससी-एसटी बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया और अजीबो-गरीब तरीके से गो बैक के नारे लगाए। वहीं, राज्यपाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं देश के संविधान के अनुसार काम करूंगा। मुझे राजनीति के अखाड़े में नहीं खींचा जा सकता, यदि सरकार मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में कछुए की गति से बढ़ती है तो यह मेरी गलती नहीं है और ऐसा कर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

मंगलवार सुबह सत्तारूढ़ दल के एससी-एसटी विधायकों ने विधानसभा परिसर में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हाथों में तख्तियां लिए राज्यपाल का विरोध किया। इस विरोध में कई मंत्री भी शामिल हुए। विधायकों ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति के हित में उक्त विधायक पर राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कहने पर हस्ताक्षर नहीं किया। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा कि राज्यपाल ने एससी- एसटी आयोग विधेयक के अलावा मॉब लिंचिंग विधेयक व अन्य कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है।

राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजी चिट्ठी

इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने छह पन्ने की चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को भेजी और इसे सदन में पढ़ कर सुनाने को कहा लेकिन तब तक सदन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली है।

राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस ने किया हंगामा और बहिर्गमन

संसद भवन परिसर में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने बंगाल के राज्यपाल पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक विधेयक को लटकाए रखने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। सदन में बाकी विपक्षी दलों का समर्थन न मिलने की दशा में शोर शराबा कर रहे सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कोई सूचना या नोटिस दिए बगैर वेल में आकर प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने के लिए समय मांगने पर सख्त नाराजगी जताई।

राज्यसभा में शून्यकाल समाप्त होने और प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। वे सभापति वेंकैया नायडू से अपनी बात रखने की मांग करते हुए वेल में आ गए। बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के इस तरह के प्रदर्शन पर नायडू ने सख्त नाराजगी जताते हुए एक मिनट देने से भी मना कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य वेल में बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नायडू ने मना किया, लेकिन तृणमूल नेता वेल में हंगामा करते रहे। सभापति शोर शराबा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और अपनी सीट लौटने का आग्रह करते रहे। तृणमूल के सदस्य 'राज्यपाल को वापस बुलाओ' और एससी-एसटी विधेयक उनके हक में, उन्हें वंचित मत करो' जैसे नारे लगा रहे थे। शोर शराबा के बीच प्रश्नकाल चलता रहा। तृणमूल कांग्रेस के सदन में नेता डेरेक ओब्रायन राज्यपाल की भूमिका पर अपनी बात रखने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन सभापति ने उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद तृणमूल सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद नायडू ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि सदस्यों को सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बिना किसी नोटिस के इस तरह की हरकत करना उचित नहीं है। नायडू ने कहा कि सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी का भी विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन नियमों के अनुसार सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए व्यवहार करना चाहिए।

23 दिन बाद भी मंजूर नहीं हुआ सरयू राय का इस्तीफा

महासमर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019

- भाजपा दिखा चुकी है बाहर का रास्ता, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने पर की कार्रवाई
- सरयू ने विधानसभा की सदस्यता से भी दिया था त्यागपत्र, उसकी भी अब तक स्वीकृति नहीं

प्रदीप सिंह, रांची

मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से ताल ठोकने वाले भाजपा के बागी और निष्कासित नेता सरयू राय अभी भी रघुवर मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। 17 नवंबर को सरयू राय ने रघुवर कैबिनेट से इस्तीफा राजभवन को भेजा था, लेकिन 23 दिनों से उनका त्यागपत्र राजभवन में ही पड़ा हुआ है। अभी तक उनके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सरयू राय रघुवर दास के कैबिनेट में खाद्य आपूर्ति मंत्री के पद पर थे। इधर झारखंड प्रदेश भाजपा ने दल के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वजह से सरयू राय को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही मंत्री सरयू राय ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा राजभवन को भेज दिया था। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र संबंधी आवेदन भी विधानसभा अध्यक्ष को भेजा था। इस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

यह है नियम : मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद राजभवन मुख्यमंत्री सचिवालय को इस संबंध में सूचित करता है। मुख्यमंत्री सचिवालय से अनुशंसा मिलने के बाद इस्तीफे की स्वीकृति दी जाती है। राजभवन के स्तर से इस बाबत संबंधित लोगों को भी सूचित किया जाता है। इसके बाद इसका बकायदा गजट नोटिफिकेशन होता है।

राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा : सरयू राय ने इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राजभवन पर दबाव बनाया है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात का भी वक्त मांगा है। संभव है कि गुरुवार को वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि इस्तीफा फैक्स एवं ईमेल के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया था। अब वे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि मंत्री पद से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। इसके अलावा वे विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार करने की विनती करेंगे।

> मैने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने के पहले राज्यपाल को मंत्री पद और विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भेज दिया था। अब सरकार को उसे स्वीकार करना है या नहीं, यह वे लोग जानें। –सरयू राय

तीसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म, मतदान कल

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत तीसरे चरण की रांची, हटिया, कांके, खिजरी, सिल्ली सहित 17 सीटों पर मंगलवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए। इससे पहले, इन सीटों पर मंगलवार को धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ। इन सभी सीटों पर 12 दिसंबर को सुबह सात बजे से मतदान होगा। इसमें कुल 309 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 32 महिला और 99 निर्दलीय शामिल हैं। चूंकि रांची, हटिया, कांके, रामगढ़ तथा बरकट्ठा में शाम पांच बजे तक मतदान होगा, इसलिए इन विधानसभा क्षेत्रों में मंगलवार को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ। वहीं, अन्य 12 विधानसभा क्षेत्रों कोडरमा, बरही, बड़कागांव, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, धनवार, गोमिया, बेरमो, ईचागढ़, सिल्ली तथा खिजरी में शाम तीन बजे ही चुनाव प्रचार खत्म हो गया, क्योंकि इन विधानसभा क्षेत्रों में शाम तीन बजे तक ही मतदान होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से मतदान का यह समय निर्धारित किया गया है।

भाजपा नहीं, जदयू है राजद का दुश्मन नंबर वन : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना

- राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोले नेता प्रतिपक्ष, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश में है जदयू

पटना में मंगलवार को राजद के अधिवेशन में तेजस्वी यादव (दाएं) को चांदी का मुकुट पहनाते तेज प्रताप यादव। जागरण

राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक एवं खुला अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को तीन बातें साफ-साफ समझा दीं। पहली, राजद की दुश्मन नंबर वन भाजपा नहीं, बल्कि जदयू है। दूसरी कि जदयू उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश में है और तीसरी, मकर संक्रांति के बाद विधानसभा चुनाव में जीत के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। पटना के बापू सभागार में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन तेजस्वी यादव ने किया। अध्यक्षता रघुवंश प्रसाद सिंह ने की और संचालन डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने किया। तेजस्वी ने अपने आधे घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा हर लाइन में की।

नागरिकता संशोधन बिल पर तेजस्वी ने कहा कि भाजपा से ज्यादा नीतीश दोषी हैं। पूरे भाषण में वह नीतीश की तुलना लालू यादव से करते नजर आए। कहा कि नीतीश को सबसे ज्यादा लालू से डर लगता है। अब वह भाजपा और आरएसएस से भी डरने लगे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश ने नागरिक संशोधन बिल का समर्थन किया, उससे जनता अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। भाजपा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कोई अपराधी या भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहा ले तो उसका पाप धुल जाता है। देश में अब केवल लालू प्रसाद और राजद ही भ्रष्ट है। बाकी सब पवित्र हो गए।

लालू फिर बने राजद प्रमुख

11वीं बार लालू प्रसाद को राजद का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजद के राष्ट्रीय सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने लालू के पार्टी प्रमुख चुने जाने की विधिवत घोषणा की। लालू की अनुपस्थिति में निर्वाचन प्रमाणपत्र तेजस्वी यादव एवं तेजप्रताप यादव को सौंपा गया।

आदिवासियों के समर्थन में मेवाणी ने विधेयक जलाया

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संबंध में लाए गए विधेयक को विधानसभा के बाहर जलाकर विरोध जताया। आदिवासियों के समर्थन में मेवाणी ने विधेयक का विरोध किया। मेवाणी को सत्र के पहले ही दिन सदन से निलंबित कर दिया गया था। विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र के पहले दिन संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान जब सीएम विजय रूपाणी सदन को संविधान दिवस मनाए जाने की जानकारी दे रहे थे उसी दौरान मेवाणी ने सरकार पर संविधान विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए कई घटनाओं का उल्लेख किया था। सदन में असभ्य व्यवहार करने व वेल में हंगामा करने पर विस अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेवाणी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं तो उन्हें बाकी दिन सत्र की कार्यवाही में शामिल होने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इन्कार कर दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी के आठ शब्द बने 'गोल्डन ट्वीट'

- आम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर किया था ट्वीट
- खेल की दुनिया में धौनी को जन्मदिन की बधाई वाला कोहली का ट्वीट शीर्ष पर रहा

इस साल आम चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया ट्वीट। सौजन्य– ट्विटर

नई दिल्ली, एजेंसियां : इस साल आम चुनाव में भाजपा की शानदार सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया आठ शब्दों वाला विजयी ट्वीट साल 2019 का 'गोल्डन ट्वीट' बन गया है। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को सबसे ज्यादा री-ट्वीट और लाइक किया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ने मंगलवार को इसकी घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत पर 23 मई को हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आठ शब्द लिखे थे, 'सबका साथ+सबका विकास+सबका विश्वास=विजयी भारत'। इस ट्वीट को एक लाख से ज्यादा लोगों ने री-ट्वीट किया, जबकि चार लाख से ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया था।

खेल की दुनिया में ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सबसे लोकप्रिय रहे। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के लिए कोहली द्वारा किया गया ट्वीट सबसे ज्यादा बार री-ट्वीट और लाइक किया गया। कोहली ने बहुत भावनात्मक बधाई संदेश लिखा था। उन्होंने धौनी के बारे में लिखा था, 'आप हम सभी के बड़े भाई हैं और मेरे लिए हमेशा प्रेरणा और मेरे कप्तान बने रहेंगे।'

फिल्मी दुनिया में ट्विटर पर दक्षिण भारत का दबदबा कायम रहा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता विजय ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी फिल्म 'बिगिल' के पोस्टर को शेयर किया था। मनोरंजन के क्षेत्र में इस ट्वीट को सबसे ज्यादा री-ट्वीट और लाइक मिले। कमेंट के साथ भी री-ट्वीट वाले श्रेणी में भी यह शीर्ष पर रहा।

हैशटैग मामले में भी आम चुनाव सबसे ज्यादा लोकप्रिय : हैशटैग के मामले में, हैशटैग लोकसभाइलेक्शंस2019 सबसे ज्यादा ट्वीट किया जाने वाला हैशटैग था। उसके बाद हैशटैग चंद्रयान2, हैशटैग सीडब्ल्यूसी19, हैशटैग पुलवामा और हैशटैग आर्टिकल370 सबसे ज्यादा ट्वीट किए जाने वाले हैशटैग हैं।

स्मृति ईरानी फाइल फोटो

सबसे चर्चित महिला नेता

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म पर राजनीति के क्षेत्र में ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चित महिला हस्तियों में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शीर्ष पर रहीं। उनके ट्विटर हैंडल को सबसे ज्यादा बार टैग किया गया। उनके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं।

हैशटैग चंद्रयान पर दुनिया की नजर

हैशटैग श्रेणी में सबसे रोमांचक पल और समारोह में हैशटैग चंद्रयान2 सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। चंद्रयान2 की हर गतिविधि पर दुनियाभर की नजर रही। लोग उसके बारे में पल–पल की जानकारी लेते और शेयर करते रहे। चंद्रयान 2 मिशन ने भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान को रेखांकित किया। इस मिशन के प्रत्येक गतिविधि पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया मिली।

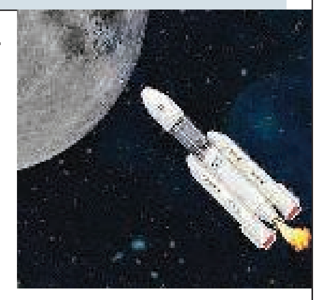

प्रतीकात्मक

99 मामले दर्ज किए गए हैं आर्थिक अपराध के पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआइ, ईडी और सीबीआइसी द्वारा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

तैयारी ▸ राज्य सरकार सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है

मप्र में अवकाश नकदीकरण के बाद अब कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति होगी बंद

स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने पर तीन हजार रुपये सालाना मिलने वाली इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। लेकिन, इसके अमल में आने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली तीन हजार रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि बंद हो जाएगी। बीमा योजना में आने वाला प्रीमियम भी कर्मचारियों को अपने वेतन से वहन करना होगा। कर्मचारियों का आरोप है कि एलटीसी (लीव ट्रेवल इनकैशमेंट) व लीव इनकैशमेंट (अवकाश नकदीकरण) बंद करने के बाद पेंशन भी समाप्त कर दी गई और अब सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार निरंतर अपने उत्तरदायित्व कम करती जा रही है और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं धीरे-धीरे कम की जा रही हैं। 1995-96 में लीव इनकैशमेंट, एलटीसी जैसी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी गईं। 2005 से पेंशन बंद कर उसे शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया। अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई। अब इलाज की जिम्मेदारी से भी सरकार मुक्त हो जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों को सालाना तीन हजार रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है। मामूली रूप से बीमार पड़ने पर कर्मचारी को डॉक्टर के पर्चे और दवाई के बिल के आधार पर अधिकतम तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

कमलनाथ। फाइल

आला अफसरों के लिए अलग नियम

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए बीमा योजना लागू है, परंतु उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बंद नहीं की गई है। मतलब दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चल रही हैं। अपनी सुविधानुसार किसी एक का लाभ ले सकते हैं।

हमारा कर्मचारी वर्ग प्रस्तावित बीमा योजना को इसी शर्त पर स्वीकार करेगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था यथावत जारी रहे। सभी कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से मप्र मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इस बारे में बात भी कर रहा है।

-सुधीर नायक, अध्यक्ष मप्र राज्य मंत्रालयीन कर्मचारी संघ

सरकार बचाएगी डेढ़ सौ करोड़ रुपये

अब नई स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के डेढ़ सौ करोड़ रुपये बचा लेगी। अब तक लगभग पांच लाख कर्मचारियों पर सरकार यह रकम खर्च करती है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी हो जाए, उन्हें मेडिकल बोर्ड के परामर्श के आधार पर जितनी भी राशि खर्च हो, उतना भुगतान किया जाता है। नई स्वास्थ्य योजना के बाद यह सुविधा छीन ली जाएगी।

पदोन्नति में आरक्षण मामले में बदला वकीलों का पैनल

नईदुनिया, भोपाल : सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों से लंबित चल रहे पदोन्नति में आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने वकीलों का पूरा पैनल बदल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन 'अजाक्स' के दबाव में पैनल में कुछ वकीलों को रखवाया था। उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान भी कराया गया था, लेकिन इसका कोई प्रभावी नतीजा नहीं आया। अब संभवतः शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मप्र हाई कोर्ट ने अप्रैल 2016 में मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया था। उसके बाद से राज्य में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। राज्य सरकार ने इसी कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी।

देश में शोध को लेकर बढ़ा रुझान, पांच वर्षों में दोगुने

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शोध के क्षेत्र में देश ने बड़ी छलांग लगाई है। पांच वर्षों में पीएचडी करने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके पीछे सरकार के प्रयासों को काफी अहम माना जा रहा है। 2014 के बाद से लगातार इसे बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का शोध प्रतिष्ठान खोलने की घोषणा की थी, जिस पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा शोधार्थियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी भी एक बड़ी पहल थी। जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के मानदेय को 28 हजार से बढ़ाकर 31 हजार किया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, शोध को लेकर यह रुझान हालांकि पूरे देश में एक समान नहीं है। असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले पांच वर्षों में शोध (पीएचडी) के मामले बढ़े हैं, वहीं दिल्ली, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इसमें कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2014-15 में जहां कुल 21 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, वहीं 2018-19 में यह संख्या बढ़कर करीब 41 हजार हो गई है। संसद को दी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, पीएचडी के मामले में यह बढ़ोतरी कोई अचानक नहीं, बल्कि यह साल-दर साल के हिसाब से हुई है। 2014-15 में जहां देश भर में कुल 21 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई, वहीं 2015-16 में 24 हजार, 2016-17 में करीब 28 हजार, 2017-18 में करीब 34 हजार और अब 2018-19 में करीब 41 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई है।

गौरतलब है कि शोध को बढ़ावा देने की यह पहल सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की मुहिम के साथ ही शुरू की थी। इसके साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत पर जोर दिया था।

बड़ी छलांग

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आई जानकारी
- दिल्ली, बिहार और झारखंड में शोध के मामलों में आई गिरावट

किस राज्य में कितने हुए शोध (2014-15 और 2018-19 में तुलनात्मक)

उत्तर प्रदेश	2625	3996
उत्तराखंड	408	1013
आंध्र प्रदेश	292	2615
बिहार	874	856
झारखंड	608	360
दिल्ली	1718	594

आइटी कानून में संशोधन से पहले की शिकायत पर चलाया जा सकता है केस

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून में 2009 में संशोधन होने से पहले के मानहानि के लिए गूगल इंडिया जैसी कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले के कानून में इस तरह की जवाबदेही से छूट हासिल नहीं थी। उच्चतम न्यायालय का फैसला गूगल इंडिया की याचिका पर आया है, जिसने आइटी कानून में संशोधन से पहले शुरू की गई मानहानि की शिकायत रद करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि शिकायत जनवरी 2009 में की गई, जबकि कानून की धारा 79 को 27 अक्टूबर, 2009 को बदला गया। हालांकि, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पहले के प्रावधानों के तहत छूट नहीं मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक कंपनी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री डालने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत को खारिज करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और केएम जोसफ की पीठ ने कहा कि यह मुकदमे का विषय है कि क्या गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वास्तविक कंपनी थी, जिसने एसबेस्टस शीट बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को अपनी वेबसाइट पर डाला था।

बिहार में जेलों की हालत पर हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट ने जेल आइजी को 16 दिसंबर तक बिहार के सभी जेलों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। इसके पहले हाई कोर्ट ने केवल छपरा जेल में असुविधा को लेकर तीन वकीलों की जांच कमेटी गठित की थी। अदालत ने जेल आइजी को शपथपत्र दायर कर जेलों की संख्या, कैदियों को रखने की क्षमता और सुविधाओं के बारे में बताने को कहा है। सरकार को यह भी बताना है कि क्षमता से अधिक कैदी किस जेल में रखे गए हैं। हाई कोर्ट ने प्रमोद कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने छपरा जेल की दयनीय स्थिति और वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर यह लोकहित याचिका दायर की थी।

लालू की संपति को ले सुनवाई : पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं उनके परिवार से जुड़े सम्पत्ति विवाद को दिल्ली भेजे जाने पर आपत्ति की है। यह केस सगुना मोड़ पर बन रहे मॉल से संबंधित है। यह जमीन विजय कोचर, विनीत कोचर, अखिल कोचर सुजाता होटल एवं अजय कोचर व अन्य लोगों द्वारा लालू परिवार को दी गई थी। अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले को दिल्ली भेजा जा रहा था। लारा ग्रुप द्वारा इनकम टैक्स फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने की।

लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मामले में केंद्र को नोटिस

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या राज्य सरकार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। केंद्र को यह बताना है कि किस नियमावली के तहत राज्य सरकार ने लोहार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई की।

संविधान के मुताबिक चले देश : नायडू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर छिड़ी बहस के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सब कुछ संविधान के मुताबिक ही होना चाहिए। मीडिया से लेकर न्यायपालिका सभी को इस पर साथ चलने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि तत्काल न्याय जिस तरह से देश के लिए ठीक नहीं है, वैसे ही न्याय में देरी भी ठीक नहीं है।

उपराष्ट्रपति नायडू मंगलवार को अंबेडकर सेंटर में आयोजित लोकमत संसदीय पुरस्कार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र में संविधान का पालन किया जाना चाहिए। देश में इन दिनों तत्काल न्याय की बात हो रही है। लेकिन, आप तत्काल न्याय नहीं कर सकते हैं। न ही न्याय में देरी ही ठीक है। आपको केस रजिस्टर करना होगा। जांच पूरी करनी होगी और न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यही सिस्टम का सही तरीका है।

नायडू ने इसके साथ ही मीडिया को ब्रेक्रिंग न्यूज की आपाधापी से बचने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मीडिया को टीआरपी रेस से बचते हुए न्यूज और व्यूज के अंतर को समझना होगा। आमलोगों को भी ऐसे समाचारों से सतर्क रहना चाहिए।

संसद के दोनों सदनों में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (राज्यसभा) और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव (लोकसभा) को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित आठ लोगों को संसदीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। लोकमत समाचार पत्र समूह की ओर से हर साल संसद के दोनों सदनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को पुरस्कृत किया जाता है। इस क्रम में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार तिरुचि शिवा (राज्यसभा) और सौगत राय (लोकसभा) को दिया गया है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार विप्लव ठाकुर (राज्यसभा) और सुप्रिया सुले (लोकसभा) को दिया गया है। पहली बार संसद पहुंचीं सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार कहकशां परवीन (राज्यसभा) और डॉ. भारती प्रवीण पवार (लोकसभा) को दिया गया है।

नई दिल्ली में मंगलवार को लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (दाएं) और राकांपा प्रमुख शरद पवार। जागरण

पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

- कई जगह सुरक्षा बलों के साथ टकराव
- त्रिपुरा में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित
- सड़क जाम के कारण दो माह के बीमार बच्चे की मौत

गुवाहाटी, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में छात्र संगठन मंगलवार को सड़क पर उतर आए। त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर जाम लगाने के कारण दो माह के बीमार बच्चे को ले जा रही एंबुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी जिससे उसकी मौत हो गई। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और नार्थ ईस्ट स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन (एनईएसओ) के प्रदर्शन के कारण असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन थम गया। त्रिपुरा में दोपहर दो बजे से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया। वामपंथी संगठनों एसएफआइ, डीवाईएफआइ, एआइडीडब्ल्यूए, एआइएसएफ और एआइएसए ने भी बंद का आह्वान किया था।

गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सचिवालय और विधानसभा भवन के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भी हुआ। डिब्रूगढ़ में बंद समर्थकों और सीआइएसएफ कर्मियों के बीच टकराव हुआ। तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बंद के कारण विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की नई तारीख घोषित की है।

त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों ने बाजार में लगा दी आग

त्रिपुरा में रेल सेवा ठहर गई और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे प्रदर्शनकारियों ने धलाई जिले में बाजार में आग लगा दी। यहां ज्यादातर दुकानें गैर आदिवासियों की हैं। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में बंद के कारण सड़क से निजी वाहन गायब रहे। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति शून्य रही। मणिपुर छात्र संगठन ने तीन बजे भोर से छह बजे शाम तक बंद का आयोजन किया। मेघालय में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया।

यूनियनों से जुड़े 50 हजार कर्मियों पर रेलवे की नजर टेढ़ी, वीआरएस देने पर विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूनियनों से जुड़े रेलवे के हजारों पदाधिकारियों के लिए नौकरी का सफर आगे कठिन हो सकता है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित परिवर्तन संगोष्ठी में यूनियन पदाधिकारियों के पर कतरने पर सहमति बनी है। संगोष्ठी में यह बात सामने आई कि रेलवे के हर डिवीजन में विभिन्न यूनियनों के करीब ढाई सौ पदाधिकारी हैं। उनका कर्मचारी के रूप में योगदान नगण्य, जबकि सुविधाएं जबरदस्त हैं। पूरे देश में ऐसे पदाधिकारियों की संख्या करीब 50 हजार है। मंत्रालय का आकलन है कि ये रेलवे पर बोझ बने हुए हैं और इनसे काम कराना दुष्कर है। इनकी वजह से रेलवे की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लिहाजा, इनकी सुविधाओं में कटौती के अलावा 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके पदाधिकारियों को वीआरएस देने पर विचार किया जाना चाहिए। खासकर उन सुपरवाइजरों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो किसी यूनियन के पदाधिकारी हैं। इन्हें यूनियन का पद या सुपरवाइजरी में से किसी एक को चुनना होगा, अन्यथा वीआरएस लेना होगा। इससे रेलवे की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा कर्मचारियों का बोझ कम होने से खर्चों पर अंकुश लगेगा।

30 फीसद घटाने होंगे कर्मचारी : परिवर्तन संगोष्ठी में रेलवे कर्मियों के वेतन व पेंशन के खर्च में लगातार बढ़ोतरी का मुद्दा छाया रहा। कहा गया कि रेलवे का कर्मचारियों पर होने वाला खर्च कुल आय के 60 फीसद से ज्यादा है, जो किसी भी प्रतिष्ठान के लिए अत्यधिक है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती आवश्यक हो गई है। हालांकि, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पहले चरण में तीन साल के अंदर 10 फीसद कर्मचारी कम किए जाने चाहिए। इसके बाद धीरे-धीरे इसे 30 फीसद तक ले जाना चाहिए। खासकर, अकुशल कर्मचारियों की संख्या तो बेहद कम होनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या 50 फीसद तक घटाने का प्रस्ताव भी सामने आया।

कारखानों की उत्पादकता पर जताई गई चिंता : रेलवे कारखानों व कार्यशालाओं की कम उत्पादकता पर भी चिंता प्रकट की गई। मंत्रालय का प्रस्ताव था कि उत्पादन इकाइयों और वर्कशॉप में जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम भुगतान किया जाता है। इसमें कटौती की जरूरत है। इसके अध्ययन के लिए बाहरी एजेंसियों से उत्पादकता और ओवरटाइम की समीक्षा कराई जानी चाहिए। रेलवे में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खर्चों में कटौती के लिए की गई थी, लेकिन न्यूनतम वेतन भुगतान के कारण खर्च घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या की जगह उनकी उत्पादकता के आधार पर भुगतान की कोई प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

प्रस्तावों पर रेलवे यूनियन ने जताई नाराजगी

रेलवे की सबसे प्रमुख यूनियन एआइआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, 'इन प्रस्तावों को देखकर लगता है कि उक्त संगोष्ठी रेलवे की 'परिवर्तन संगोष्ठी' न होकर 'समापन संगोष्ठी' थी। कारण है कि यदि प्रस्तावों को लागू किया गया तो परिवर्तन हो न हो, लेकिन रेलवे बंद जरूर हो जाएगी।

आइपीएस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामला एजेंसी को सौंपने से इन्कार

- सुप्रीम कोर्ट ने किसी केंद्रीय एजेंसी को मामला स्थानांतरित करने की महिला की अपील ठुकराई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा पश्चिम बंगाल कैडर के आइपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाने के मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो एफआइआर दर्ज की थी।

पहली एफआइआर महिला ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए गए थे कि फेसबुक पर दोस्त बने आइपीएस अधिकारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, वहीं दूसरी एफआइआर आइपीएस अधिकारी की मां ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि महिला और उसके परिवार के सदस्य उन पर 15 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म एवं अन्य आपराधिक मामले दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'ऐसा कुछ भी ठोस' दिखाने के लिए नहीं है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है या किसी विशिष्ट दिशा में जांच नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा, 'हमारा मानना है कि आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस चरण में यह कहा जा सकता है कि अगर कोई भी वीडियो या आडियो रिकार्डिंग याची के पास है तो उसे आज से दो दिनों के अंदर एसआइटी को सौंपा जा सकता है। यह एसआइटी पर छोड़ा जाता है कि वह विचार करे कि इस हिस्से को पूरक आरोपपत्र में शामिल करना है या नहीं जिसे दायर करने पर विचार किया जा रहा है।'

कोर्ट ने कहा, 'उपरोक्त परिस्थितियों में हमें कोई कारण नहीं दिखता कि दोनों प्राथमिकियों की जांच इस चरण में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए।' जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ ने उस महिला को भी नोटिस जारी कर पूछा कि गलत बयान देने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और गलत बयान देने के लिए उसके खिलाफ आदेश क्यों न पारित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के लिए दर्ज किया जाए और इस आदेश की प्रति महिला को भेजी जाए। साथ ही कोर्ट ने महिला को 14 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

24 साल से कैद में गंगा

मोक्षदायिनी हैं गंगा मैया। सब मैया के तारे ही तरते हैं। लेकिन, उनकी ही मुक्ति फंस जाए तो? कानपुर में ऐसी ही उल्टी गंगा बहाई जा रही है। 24 बरस पहले कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ को जोड़ने वाला गंगा बैराज बना तो गंगा प्रतिमा भी लाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती एक सितंबर 1995 को पुल चालू कर गईं, लेकिन प्रतिमा सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के स्टोर रूम से बाहर न आ सकी। वर्ष 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में चौधरी अजित सिंह ने यहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगवा दी, लेकिन...। अब 14 दिसंबर को गंगा का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या मैया को अब मुक्ति मिल सकेगी? संजय यादव

परिवार का 40 लाख कर्ज चुकाने के लिए हरप्रीत ने चुराए हथियार

- पांच दिसंबर को मध्य प्रदेश स्थित सेना प्रशिक्षण केंद्र से चोरी की थी दो राइफलें और तीन मैग्जीन

जागरण संवाददाता, होशियारपुर

सेना से फरार हरप्रीत सिंह ने 40 लाख रुपये कर्ज में डूबे परिवार को बाहर निकालने के लिए मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी स्थित सेना के प्रशिक्षण केंद्र से दो इंसास राइफलें, तीन मैगजीन और 20 कारतूस चोरी किए थे। इन हथियारों के दम पर उसने होशियारपुर के दोसड़का के एक ज्वेलर को लूटने की साजिश बनाई थी। इसके लिए उसने चार साथियों की गैंग भी तैयार कर ली थी। ज्वेलर के अलावा क्षेत्र के छह और अमीर लोग गैंग के निशाने पर थे। पैसे की व्यवस्था कर हरप्रीत अपनी प्रेमिका से शादी भी करना चाहता था।

डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने मंगलवार शाम को बताया कि छह दिसंबर को को सेना प्रशिक्षण केंद्र के कर्नल मनोज धंधपाल ने एडीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी आरएन ढोके को सूचना दी कि गांव मियाणी (होशियारपुर) का रहने वाला हरप्रीत उर्फ राजा पुत्र हरबंस सिंह सेना का जवान था। उसने अपने एक साथी जगतार सिंह जग्गा के साथ मिलकर पांच दिसंबर को सेना प्रशिक्षण केंद्र से दो इंसास राइफल, तीन मैग्जीन और 20 कारतूस चोरी किए हैं। जगतार भी गांव मियाणी का रहने वाला है। एसएसपी ने दोनों आरोपितों को पकड़ने के लिए तीन डीएसपी की स्पेशल टीम बनाई। टीम ने सोमवार रात को करीब 11 बजे गांव कंधाली नारंगपुर में गन्ने के खेत के पीछे बने पोल्ट्री फार्म में छापामारी कर हरप्रीत सिंह, जगतार सिंह जग्गा, कर्मजीत सिंह उर्फ मोनू, गुरजिंदर सिंह उर्फ काका (सभी निवासी मियाणी) और सर्बजीत सिंह उर्फ साईं (निवासी गांव चौटाला) को पकड़ लिया। आरोपितों के पास से चोरी की दोनों इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए गए।

केरल के बिलिवर्स चर्च ने विदेशी फंड से झारखंड के कई जिलों में खरीदी जमीन

दिलीप कुमार, रांची

केरल की बिलिवर्स चर्च ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010 (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का दुरुपयोग कर झारखंड में अरबों रुपये की जमीन खरीदी है। अधिकांश जमीन रांची, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, चतरा व चाईबासा जिले में खरीदी गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से ब्योरा मिलने के बाद झारखंड सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) को जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले पत्र में बताया गया है कि केरल की बिलिवर्स चर्च ऑफ इंडिया ने झारखंड में कई जगहों पर जमीन खरीदी है।

सामान्य रूप से खरीदी गई जमीन

रांची : कांके में 11.33 डिसमिल। नामकुम के नचलदाग में एक जगह पर 3.50 एकड़ व दूसरी जगह पर 2.05 एकड़। नामकुम में एक अन्य जगह पर 13.50 डिसमिल। सदर थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव में 15 डिसमिल। इटकी में 20 डिसमिल। नगड़ी के सांबो में 12 डिसमिल।

खूंटी जिला : तोरपा एक एकड़। कर्रा के हेसला गांव में 20 डिसमिल, इथेटोली में 98 डिसमिल व मेहा गांव में 82 डिसमिल। रनिया में एक एकड़। खूंटी में 24 डिसमिल।

चतरा जिला : सिमरिया के बकचोना गांव में 20 डिसमिल। गिद्धौर के सलगा में 34 डिसमिल। रामानुजगंज में 0.10 हेक्टेयर।

गुमला : कामडारा के तुरुंडू गांव में 65 डिसमिल। रायडीह में एक जगह दो एकड़, दूसरी जगह एक एकड़ व तीसरी जगह 1.20 एकड़। भरनो में एक एकड़। डुमरी में एक जगह 0.25 एकड़ व दूसरी जगह 0.75 एकड़। गुमला में 1.36 एकड़।

सिमडेगा : ठेठईटांगर में 1.68 एकड़। कोलेबिरा में एक एकड़।

पारिश चर्च बनाने के नाम पर खरीदी गई जमीन

रांची : इटकी के मकुंदा में 20 डिसमिल। बेड़ो के हरिहरपुर जामटोली में 28 डिसमिल। नामकुम के उलातू में 07 डिसमिल। जगन्नाथपुर के हेसाग में आठ डिसमिल।

खूंटी : हेसाग में 1.80 एकड़। रनिया के रायकेरा में 40 डिसमिल। तोरपा के कुंडी गांव में 19 डिसमिल।

गुमला : थुकाई में 60 डिसमिल। रायडीह में 0.25 एकड़। बिशुनपुर के राहे गांव में 69 डिसमिल।

लोहरदगा : भंडरा के भैसमुंडो में 20 डिसमिल।

ट्रेन में पबजी खेलते हुए पानी की जगह पी गया केमिकल, मौत

- कारोबारी ने अपने साथ बोतल में रखा था चांदी साफ करने का केमिकल

जागरण संवाददाता,आगरा

जानलेवा साबित हो रहे पबजी गेम ने मंगलवार को एक और युवक की जान ले ली। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में मोबाइल पबजी गेम खेला रहा युवक पानी की जगह केमिकल पी गया। चिकित्सीय मदद मिलने से पहले उसकी मौत हो गई।

ग्वालियर में चंद्रवनी नाका, थाना झांसी रोड के रहने वाले चांदी कारोबारी 20 वर्षीय सौरभ यादव पुत्र पीतम यादव अपने दोस्त पड़ोस में रहने वाले संतोष शर्मा के साथ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से आगरा आ रहे थे। संतोष के मुताबिक उनको आगरा के सराफा बाजार में काम था। सौरभ भी उनके साथ आ गया। सौरभ के पास एक बैग था। बैग में एक बोतल में चांदी साफ करने का केमिकल और एक बोतल में पानी था। दोनों ग्वालियर से जनरल बोगी में बैठ गए। सौरभ नीचे सीट पर बैठ गया। संतोष ने बताया कि सौरभ कान में लीड लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था और चने खा रहा था। थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए उसने बैग से बोतल निकाली। उसके हाथ में पानी की जगह केमिकल की बोतल आ गई, जिसे वह बिना देखे पी गया। थोड़ी देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उल्टी करने लगा। मुरैना स्टेशन पर चिकित्सीय सहायता नहीं मिल सकी। ट्रेन में ही युवक की मौत हो गई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची। जीआरपी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने शव को उतारा। सौरभ के स्वजनों को सूचना दी गई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि संतोष ने युवक के गेम खेलते समय केमिकल पीने की बात बताई है। केमिकल की बोतल को जब्त कर लिया है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। देर शाम सौरभ के स्वजन भी आगरा पहुंच गए हैं।

10,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा कश्मीर को पांच अगस्त के बाद से कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक। इसकी बड़ी वजह इंटरनेट बंद किया जाना बताया गया है।

सियासी कैदियों की रिहाई पर प्रशासन लेगा फैसला

दावा ▶ अमित शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह सामान्य हैं हालात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कश्मीर में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस खुद घिर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपने तो शेख अब्दुल्ला को 11 साल तक कैद में रखा था और चार महीने में ही हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। उन्होंने साफ किया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। उसे तय करना है कि कब किसे छोड़े। अब देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, जो हस्तक्षेप करे। जमीनी स्तर पर हालात के आकलन के आधार पर स्थानीय प्रशासन राजनीतिक कैदियों की रिहाई का फैसला करेगा। इसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है।

प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पर एक सवाल और उसके जवाब के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के ठप होने का मुद्दा उठाया। अधीर रंजन ने अमित शाह से जानना चाहा कि जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां कब शुरू होंगी? सामान्य हालात को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़े जाने पर शाह ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ राजनीतिक गतिविधि ही हालात सामान्य होने का मानदंड नहीं है। शाह के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में कहीं भी कर्फ्यू नहीं है और कुछ जगहों में रात को छोड़कर कहीं धारा 144 भी लागू नहीं है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और सभी कार्यालयों में हो रहे कामकाज का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं।

प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में जवाब देते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

शाह ने जम्मू-कश्मीर में किस तरह से स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, इसके लिए उन्होंने 40 हजार सरपंचों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव का हवाला दिया।

इससे पहले लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये मंजूर किया है। इसके साथ ही 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय अनुदान और करों में राज्य के हिस्से के रूप में संयुक्त जम्मू-कश्मीर को 14,559 करोड़ रुपये मिलने थे। अब इसे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को अलग-अलग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक इसमें से जम्मू-कश्मीर को कुल 2,977 करोड़ रुपये और लद्दाख को 1,276 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ शाह फैजल के वकील ने कहा, केंद्र की एकतरफा कार्रवाई असंवैधानिक

▶ इस मामले पर बहस बुधवार को भी जारी रहेगी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई। बहस की शुरुआत पूर्व आइएएस और अब नेता बन चुके शाह फैजल की ओर से हुई। उनके वकील ने कहा कि केंद्र सरकार का एकतरफा रूप से अनुच्छेद 370 हटाना गलत और असंवैधानिक है। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की मंजूरी के बगैर एकतरफा बदलाव नहीं कर सकती। बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के संबंध में कुल 14 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जिसमें ज्यादातर में राष्ट्रपति के छह अगस्त के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए रद किए जाने की मांग की गई है। शुरुआत में कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया था। मंगलवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर सुनवाई शुरू की। पीठ की अगुआई सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के वरिष्ठतम न्यायाधीश एनवी रमना कर रहे हैं। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एसके कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं। शाह फैजल की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने राष्ट्रपति के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन के अस्थायी आवरण की आड़ में संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य के संबंधों में कोई ऐसा स्थायी बदलाव किया जा सकता है जिसे बाद में बदला न जा सकता हो। रामचंद्रन ने अपनी बहस की रूपरेखा बताते हुए कहा कि वह इस पर भी बहस करेंगे कि जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों की सहमति के बगैर ऐसा एकतरफा बदलाव कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 में ही उसे बदलने का तंत्र दिया गया है, सवाल यह है कि स्थायी बदलाव करते वक्त क्या उसकी अवहेलना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव के लिए राज्य की संविधान सभा की मंजूरी चाहिए थी। राज्य की ओर राज्यपाल से सहमति लेना ठीक नहीं है क्योंकि राज्यपाल केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है।

अनुमति के बावजूद साजिशन जामा मस्जिद नहीं जा रहे मीरवाइज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ मस्जिद न जाकर देना चाहते हैं हालात खराब होने का संदेश

▶ हुर्रियत चेयरमैन को भड़काऊ भाषण पर है पीएसए लगने का डर

मीरवाइज मौलवी उमर फारूक। फाइल

एतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज-ए-जुमा पर कोई पाबंदी नहीं और न ही वहां जाने पर किसी पर रोक है। बावजूद इसके कश्मीर के प्रमुख मजहबी नेता और उदारवादी हुर्रियत कांफ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक कथित तौर पर मस्जिद में नमाज अदा करने से बच रहे हैं। दरअसल, बदले हालात और नए कश्मीर में मीरवाइज अपना अलगाववादी एजेंडा चलाने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि कोई भी भड़काऊ भाषण या एक भी गलती उन्हें जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाकर राज्य से बाहर किसी जेल में भिजवा सकती है। इसके साथ ही मीरवाइज लोगों का सामना करने से भी बच रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन से अनुमति के बावजूद मीरवाइज जामिया मस्जिद नहीं जा रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों को कहना है कि वह साजिशन ऐसा कर रहे हैं। ताकि संदेश जाए की कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं।

श्रीनगर स्थित डाउन-टाउन के की एतिहासिक जामिया मस्जिद कश्मीर घाटी की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक इस मस्जिद के प्रमुख हैं। कश्मीर में अधिकांश लोग उन्हें अपना मजहबी नेता भी मानते हैं। इसी मस्जिद के बाहर पांच अगस्त से पहले हर शुक्रवार को नमाज-ए-जुमा के बाद हिंसक प्रदर्शन होते थे। पाकिस्तान समर्थकों की भीड़ आतंकी कमांडरों के पोस्टर, पाकिस्तान के ध्वज लहराती हुई नारेबाजी करती थी।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे अलगाववादी : पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन विभिन्न नेताओं व अलगाववादियों को हिरासत में लेने या नजरबंद बनाने के अलावा निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। हालात में बेहतरी पर अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ही प्रशासन ने पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जामिया मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। लगातार 17 शुक्रवार को जामिया में नमाज नहीं हुई है, जिसे लेकर अलगाववादी और राष्ट्रविरोधी तत्व भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि सुरक्षाबल लोगों को मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने दे रहे हैं। मीरवाइज को भी नमाज के लिए घर से बाहर नहीं आने दिया जाता।

बेनकाब हो चुका एजेंडा

कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपना नाम न छापने पर कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाते हुए जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया है, उससे मीरवाइज और उनके साथियों का एजेंडा बेनकाब हो चुका है। इन लोगों ने आजादी के नाम पर यहां सैकड़ों लड़कों को बंदूक उठाकर मौत के रास्ते पर धकेला है और खुद आरामदायक जिंदगी का मजा लिया। लोगों में इनके प्रति गुस्सा है। मीरवाइज जानते हैं कि अगर मस्जिद में उन्होंने अपने खुतबे में कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो उनके समर्थक ही उनके खिलाफ नारा लगाएंगे। वहीं, अगर अलगाववादी एजेंडे की बात करेंगे तो सीधे जेल जाएंगे। ऐसे में खामोश रहने में ही उनकी भलाई है।

साजिश का हिस्सा है मस्जिद में न आना

राज्य पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासन की तरफ से जामिया मस्जिद में नमाज पर बीते एक माह के दौरान किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रही है। हालांकि शरारती तत्वों को रोकने के लिए सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त रहता है। करीब एक पखवाड़े पहले भी प्रशासन ने मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को संदेश भेजकर पूछा था कि जामिया मस्जिद में शुक्रवार को नमाज-ए-जुमा क्यों नहीं हो रही है? इस पर मीरवाइज ने बताया कि वह अस्वस्थ हैं। जबकि सूत्रों ने बताया कि मीरवाइज पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन वह नहीं चाहते कि उन्हें किसी तरह से आम लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़े। इसलिए वह चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समय तक घर में ही नजरबंद रखा जाए। वहीं, इससे यह संदेश जाएगा कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं।

न्यूज गैलरी

पांचवें दिन भी श्रीनगर की सभी उड़ानें रद

श्रीनगर : कश्मीर में घनी धुंध के चलते मंगलवार को लगातार पांचवें दिन भी श्रीनगर एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को रद कर दिया गया। महज सौ से पांच सौ मीटर की दृश्यता रहने के चलते न तो कोई उड़ान यहां से गई और न ही कोई विमान उतारा जा सका। उड़ान भरने और उतरने के लिए दृश्यता एक हजार मीटर से 1200 मीटर होनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार को श्रीनगर से कुल 27 फ्लाइट रवाना होनी थी। इनमें कुछ फ्लाइट सेना के जवानों के लिए थी। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के अधिकारियों ने सभी फ्लाइट रद होने की पुष्टि की है। (जेएनएन)

पंजाब में तैनात जवान ने खुद को मारी गोली, मौत

फाजिल्का : भारत-पाकिस्तान सीमा की अंतरराष्ट्रीय चौकी महार सोना पर तैनात एक जवान ने मंगलवार सुबह अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोलियां मारकर जान दे दी। उसकी पहचान त्रिपुरा के जिला गोमती निवासी 52 वर्षीय खुर्शीद मियां के रूप में हुई है। एएसआइ मंजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे फोन पर इसकी सूचना मिली। उन्हें बताया गया कि जवान की तारबंदी के गेट के पास रात 12 से लेकर सुबह छह बजे तक ड्यूटी थी। इस दौरान उसने सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर अपने आप को अपनी ही राइफल से गोलियां मार ली। गोली की आवाज सुनकर आसपास के जवान जब मौके पर पहुंचे, उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को मौके पर गोलियों के चले हुए आठ खोल भी बरामद हुए। उन्होंने बताया कि जवान को कितनी गोलियां लगी हैं, इसकी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। (जासं)

उत्तराखंड में आसानी से लीज पर नहीं मिलेगी सरकारी जमीन

नैनीताल : राज्य में अधिकारियों व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिलीभगत कर सरकारी जमीनों को गुपचुप तरीके से लीज पर लेना आसान नहीं होगा। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को सरकारी जमीन की लीज प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से टेंडर जारी कर पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में एकलपीठ का आदेश सही ठहराते हुए विशेष अपील निरस्त कर दी है। 15 जुलाई 2016 को मसूरी के कैंम्पटी फाल में बंगलो की कंडी को भाव सिंह को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया था। जिसे मसूरी निवासी सुंदर सिंह, रमेश सिंह समेत अन्य द्वारा याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा जमीन की लीज गलत तरीके से दी गई है, लिहाजा इसे निरस्त किया जाए। इसी साल 22 अक्टूबर को हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सरकार द्वारा दी गई लीज को गलत ठहराते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया था। (जासं)

हाई कोर्ट ने दो बंदियों से पीएसए हटाया रिहाई के आदेश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: राज्य उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाए गए दो लोगों को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों पर लागू पीएसए को रद कर दिया है।

उच्च न्यायालय में जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने गत सोमवार को मोहम्मद अशरफ गनई निवासी सोपोर और इम्तियाज अहमद पहलू निवासी श्रीनगर के मामलों की सुनवाई की थी। इन दोनों को पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। दोनों ने पीएसए को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अशरफ गनई को जंगल में पेड़ों के अवैध कटान और इमारती लकड़ी की तस्करी में संलिप्तता के आधार पर पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। वहीं, इम्तियाज पर पत्थरबाजी और देश विरोधी हिंसक घटनाओं में संलिप्तता के आधार पर बंदी बनाया गया था। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने दलीलों को सुनने के बाद दोनों पर पीएसए के आधार को खारिज कर दिया। साथ ही दोनों पर लागू पीएसए को हटाने का आदेश दिया। इसके अलावा आदेश किया कि अगर पुलिस को किसी अन्य मामले में इनकी तलाश नहीं है तो इन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।

ईयू ने कश्मीर के हालात को चिंताजनक बताया भारत-पाकिस्तान तनाव खत्म करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ यूरोपीय संघ के राजदूत ने भारत, पाकिस्तान से बातचीत की राह पर लौटने को कहा

▶ सीमा पार से आतंकी घटनाओं को मिल रहे बढ़ावा को लेकर भी चिंता जताई

जर्मनी समेत कई देशों की तरफ से कश्मीर मामला उठाए जाने के बाद अब नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूत ने भी कश्मीर के हालात को चिंताजनक बताया है। उन्होंने वहां जल्द से जल्द सामान्य हालात बहाल करने की उम्मीद जताई है। यूरोपीय संघ के नए राजदूत यूगो अस्तुतो ने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्तों में तनाव खत्म करने के लिए बातचीत की राह पर जल्द लौटने की भी बात कही है। नागरिकता संशोधन विधेयक पर अस्तुतो ने कहा कि भारत का संविधान कानून के समक्ष बिना किसी भेदभाव के बराबरी की गारंटी देता है। मुझे उम्मीद है कि समानता के इस सिद्धांत को बरकरार रखा जाएगा।

अस्तुतो ने कहा कि हम कश्मीर के हालात को लेकर चिंतित हैं। यह जरूरी है कि वहां हालात सामान्य किए जाएं और लोगों को घूमने-फिरने की आजादी हो। कश्मीर को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने के बावजूद वहां पर हालात को सामान्य करना जरूरी है। उन्होंने धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में आए बदलाव और खास तौर पर संचार व लोगों के आजादी से घूमने-फिरने पर लगी पाबंदी को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि भारत सरकार को इससे अवगत भी कराया गया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि कश्मीर को लेकर ईयू की पारंपरिक नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

वैसे उन्होंने सीमा पार से आतंकी घटनाओं को मिल रहे बढ़ावा को लेकर भी अपनी चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान को इन पर लगाम लगाना होगा। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निर्देशों को मुताबिक पाकिस्तान सरकार को आतंकी संगठनों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं, उनका समाधान बातचीत से करने की कोशिश होनी चाहिए।

सांसदों के कश्मीर दौरे को निजी बताया

अस्तुतो ने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में कश्मीर के दौरे पर गए यूरोपीय संघ के कुछ सांसद बतौर संघ के प्रतिनिधि नहीं गए थे, बल्कि वे अपने निजी दौरे पर थे। यह दौरा किसी भी सूरत में ईयू की राजकीय नीति को नहीं दर्शाती है। सनद रहे कि यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के 23 सांसदों ने एक भारतीय एनजीओ के आमंत्रण पर कश्मीर का दौरा किया था। इनमें से अधिकतर सांसद दक्षिणपंथी पार्टियों के हैं, जो अपने ही देश में बेहद अल्पमत में हैं। इस मामले को विपक्षी दलों ने जोर-शोर से उठाया था। सरकार ने कहा था कि इस दौरे से भारत के व्यापक राष्ट्रीय हित को लाभ हुआ है।

लोकसभा में उठी 'पानीपत' पर प्रतिबंध की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजस्थान के दो लोकसभा सदस्यों ने बॉलीवुड फिल्म 'पानीपत' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सांसदों ने दावा किया है कि ऐतिहासिक तथ्यों से परे जाकर इस फिल्म में भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल की खराब छवि दिखाई गई है।

शून्यकाल के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि फिल्म में राजस्थान और हरियाणा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने मांग की कि या तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रतिबंध लगाया जाए या संबंधित दृश्य हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले सेंसर बोर्ड द्वारा 15 फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

भाजपा के सुमेधानंद सरस्वती ने भी फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को दूसरे रूप में दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि फिल्म के खिलाफ हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। जयपुर के कई सिनेमा घरों में फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया गया है।

जयपुर के एक सिनेमाहाल के बाहर 'पानीपत' का पोस्टर जलाते लोग। एएनआइ

राजस्थान में जारी है 'पानीपत' पर विवाद

राज्य ब्यूरो, जयपुर: राजस्थान में निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत को लेकर विवाद मंगलवार को भी जारी रहा। जयपुर सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए और नेताओं की बयानबाजी भी जारी रही। इसके साथ ही ज्यादातर शहरों में फिल्म का प्रदर्शन रोक दिया गया है। फिल्म पानीपत में भतरपुर के महाराजा सूरजमल के चित्रण को लेकर राजस्थान में जाट समाज ही नहीं बल्कि सभी समाजों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजपूत समाज इसका विरोध कर चुका है। मंगलवार को राजपूत करणी सेना ने जाट समाज के नेताओं के साथ मिल कर जयपुर के प्रसिद्ध राजमंदिर सिनेमा के बाहर फिल्म के पोस्टर जलाए और फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने भी फिल्म का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ की जा रही छेड़छाड़ पूरी तरह गलत है। सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। फिल्म के विरोध में जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा समेत राज्य में अलग-अलग जगह प्रदर्शन किए गए। कोटा के सभी सिनेमाघरों से पानीपत मूवी को हटा दिया गया। वहीं मंगलवार को यहां लोगों ने सड़को पर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई।

दांत का इलाज करते डॉक्टर से फिसली सुई पेट में पहुंची

जागरण संवाददाता, संगरूर

दांतों में दर्द की समस्या से परेशान होकर इलाज के लिए संगरूर शहर के निजी क्लीनिक में जांच करवाने पहुंची लड़की के इलाज के दौरान डॉक्टर के हाथ से फिसली सुई उसके पेट में जा पहुंची। संगरूर के बाद पटियाला व फिर पीजीआइ में लड़की को भर्ती कराया गया है। पेट से सुई को निकालना डाक्टरों के लिए मुसीबत बन चुका है। एक्सरे में सुई लड़की के पेट में दिखाई दे रही है, लड़की पीजीआइ में तीन दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़ित लड़की के परिवार ने थाने में दांतों की डॉक्टर के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं, डॉक्टर ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि गलती किसी से भी हो सकती है।

संगरूर निवासी सोहन सिंह पुत्र बचन सिंह की बेटी रमनदीप कौर ने आठ दिसंबर को शहर के एक निजी दांतों के क्लीनिक में इलाज करवाने पहुंची थी। इस दौरान डॉक्टर एक सुई से रमनदीप कौर के दांतों का इलाज कर रही थी। अचानक ही डॉक्टर के हाथ से सुई फिसल गई और रमनदीप के गले से नीचे उतर गई। इससे रमनदीप कौर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रमनदीप की हालत बिगड़ने लगी तो उसके परिवार रमनदीप कौर को तुरंत ही शहर के एक निजी ईएनटी डाक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने लड़की के एक्स-रे करवाया तो पाया कि सुई छाती तक पहुंच गई है। फिर उसे पटियाला के राजिंदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टरों ने सलाह दी कि इंडोस्कापी की मदद से सुई को निकाला जा सकता है, लेकिन राजिंदरा में इसके लिए उचित प्रबंध न होने के कारण पीजीआइ रेफर कर दिया। सोहन सिंह ने बताया कि आठ दिसंबर की रात से पीजीआइ में उपचाराधीन है, लेकिन अभी तक डाक्टर सुई को पेट से निकाल नहीं पाए हैं। सुई को इंडोस्कापी की मदद से निकालने में भी डाक्टरों ने असमर्थता जाहिर कर दी है।

सिविल सर्जन से की शिकायत

सोहन सिंह ने डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन संगरूर को शिकायत सौंपी है। थाना सिटी संगरूर के एसएचओ गुरभजन सिंह ने कहा कि मामला सेहत विभाग से संबंधित है, वही कार्रवाई करेगा।

एक और महिला पत्रकार ने अकबर के खिलाफ बयान दिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ एक और महिला पत्रकार ने मंगलवार को अदालत में बयान दर्ज कराया। पत्रकार प्रिया रमानी की तरफ से पेश हुई महिला पत्रकार ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में कहा कि उसके साथ अकबर ने अगस्त-सितंबर 1997 में यौन शोषण किया था। महिला पत्रकार ने अदालत को बताया कि वह एक अंग्रेजी अखबार में काम करती थी और एमजे अकबर का दफ्तर उनके डेस्क के एकदम सामने था। अकबर उसे अपने दफ्तर से देखते रहते थे। कुछ समय बाद अकबर ने उन्हें निजी तौर पर संदेश भेजना शुरू कर दिया।

संदेश उनके पहनावे के बारे में होते थे और दफ्तर के आंतरिक पोर्टल से भेजे जाते थे। इस बारे में जब अपनी ब्यूरो प्रमुख को बताया तो उनसे कहा गया कि जो भी करना है, खुद तय करें और किसी तरह की मदद नहीं की जा सकती। महिला पत्रकार ने अदालत को बताया कि वह सिर्फ 26 साल की थी और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। क्योंकि दफ्तर में यौन शोषण की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। महिला पत्रकार ने कहा कि अकबर के बड़े ओहदे के भय में वह कुछ नहीं कर पाई।

लंका ही नहीं, अयोध्या में भी अशोक वाटिका

मान्यता

त्रेतायुगीन विरासत के नए सिरे से सुसज्जित होने की उम्मीद, माना जाता है कि इस वाटिका में भगवान राम विहार के लिए आते थे

नवनीत श्रीवास्तव, अयोध्या

सिर्फ लंका ही नहीं, अयोध्या में भी त्रेतायुगीन अशोक वाटिका है। दरअसल, रामजन्मभूमि के आग्नेय कोण पर सीताकुंड में स्थापित अशोक वाटिका को त्रेतायुगीन माना जाता है। मान्यता है कि इस वाटिका में भगवान राम विहार के लिए आते थे। पौराणिक ग्रंथ रुद्रायमल में भी इसका जिक्र है। हालांकि अब यह बदहाल है।

भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब यह उम्मीद जगी है कि जन्मभूमि के साथ ही इस त्रेतायुगीन विरासत को सरकार नए सिरे से सुसज्जित करेगी। पौराणिक ग्रंथों में त्रेतायुग में अयोध्या की अशोक वाटिका में चंदन, अशोक, नारियल, देवदारु, चंपक आदि दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष शोभा होते थे। तिलोदकी नदी समीप स्थित अशोक वाटिका में अब न तो त्रेतायुगीन आकर्षण है और न ही दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष। वाटिका में अशोक के चंद पेड़ों के अतिरिक्त वह शिलालेख मौजूद है, जो उसकी पौराणिकता की तस्दीक करता है।

वाटिका का हिस्सा था सीताकुंड: किसी काल में सीताकुंड अशोक वाटिका परिसर का हिस्सा था। मान्यता है कि सीताकुंड को स्वयं माता जानकी ने ही उद्घाटित किया था। भगवान राम ने कुंड को अनेक वरदान से गौरवान्वित किया। हालांकि कुंड का अस्तित्व तो है लेकिन अब अशोक वाटिका से अलग। कुछ वर्ष पूर्व एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा के अध्यक्ष व रामवल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमार दास व महासचिव महंत रामदास की अगुवाई में कुंड की साफ-सफाई भी की गई थी। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक अयोध्या की त्रेतायुगीन विरासत को संजोने-संवारने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अशोक वाटिका को पौराणिक स्वरूप दिलाने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जाएगा।

अयोध्या को गौरव से भरती त्रेतायुगीन विरासत

जासं, अयोध्या : एक ओर त्रेतायुगीन विरासत का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है वहीं जनौरा स्थित गिरिजाकुंड व मंत्रेश्वर महादेव मंदिर आस्था का केंद्र बने हैं। स्थानीय लोगों के संकल्पसिद्धि के रूप में गिरिजाकुंड और मंत्रेश्वर महादेव मंदिर त्रेतायुगीन विरासत को पूरी शिद्दत से संभाले हैं। यह कुंड वर्षभर पानी से लबालब भरा रहता है। बतख और अन्य पक्षी अठखेलियां करते दिखते हैं। दोनों स्थानों का जिक्र पौराणिक ग्रंथ रुद्रायमल में भी आता है। मान्यता है कि मंत्रेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। इसीलिए यह मंदिर बेहद प्रतिष्ठित है। भगवान राम की कालदेव से महाप्रस्थान के संबंध में मंत्रणा भी यहीं हुई थी। इसी मंदिर से सटा हुआ गिरिजाकुंड भी है।

उपग्रह रीसैट-2बीआर1 की उल्टी गिनती शुरू, प्रक्षेपण आज

चेन्नई, प्रेट्र : भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रीसैट-2बीआर1 के प्रक्षेपण से 24 घंटे पहले मंगलवार को उल्टी गिनती शुरू हो गई। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से पीएसएलवी-सी48 के जरिये इसे बुधवार को प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया कि पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) का 50वां मिशन- पीएसएलवी-सी48 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लांचपैड से बुधवार को दोपहर बाद 3:25 बजे उड़ान भरेगा। यह प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। यह पीएसएलवी की 50वीं उड़ान होगी और श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 75वां उपग्रह होगा। रीसैट-2बीआर1 को कृषि, वन एवं आपदा प्रबंधन में मदद के लिए तैयार किया गया है। इसका वजन 628 किलोग्राम है। इस मिशन की उम्र पांच वर्ष है। यह अपने साथ नौ छोटे उपग्रहों को भी ले जाएगा।

इनमें इजरायल, इटली और जापान के एक-एक और अमेरिका के छह उपग्रह शामिल हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 4:40 बजे रीसैट-2बीआर1 की उल्टी गिनती शुरू हुई। उसने कहा कि इन उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए व्यावसायिक करार के तहत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रीसैट-2बीआर1 से पहले 22 मई को रीसैट-2बी का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है।

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 और नौ विदेशी उपग्रहों को लेकर रवाना होने को तैयार पीएसएलवी-सी48। प्रेट्र

10 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज बांटे गए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस वर्ष पहली नवंबर तक। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आठ अप्रैल, 2015 को की गई थी। इसके माध्यम से गैर-कॉरपोरेट व गैर-कृषि क्षेत्र के स्मॉल व माइक्रो इंटरप्राइजेज को छोटे कर्ज दिए जाते हैं।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में खत्म हुआ फिरोज प्रकरण

विवाद खत्म ▶ कला संकाय के संस्कृत विभाग में लगाई पहली हाजिरी

परीक्षा के चलते कक्षाएं रहीं बंद, मिलेगी परीक्षा की ड्यूटी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में नियुक्ति के बाद से ही विरोध झेल रहे डॉ. फिरोज खान ने इस्तीफा देकर विश्वविद्यालय के ही कला संकाय स्थित संस्कृत विभाग में पदभार संभाल लिया है। फिरोज का संस्कृत विभाग के अलावा आयुर्वेद संकाय में भी चयन हुआ था। उन्होंने मंगलवार को विभाग में पहली हाजिरी लगाई। हालांकि परीक्षा के चलते उनको कक्षाएं नहीं मिल पाई। उधर, छात्रों ने फिरोज के इस्तीफे के बाद धरना समाप्त कर दिया है।

छात्रों ने किया विरोध-प्रदर्शन: डा. फिरोज की नियुक्ति सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में हुई थी। हालांकि इसे लेकर संकाय के छात्रों ने कई दिनों तक विरोध-प्रदर्शन किया। इसके बाद डा. फिरोज ने बीएचयू के ही कला संकाय के साथ ही आयुर्वेद संकाय में साक्षात्कार दिया। शनिवार को नई दिल्ली में हुई कार्यकारिणी की बैठक में डा. फिरोज को आयुर्वेद एवं कला दोनों ही संकायों में पढ़ाने के लिए हरी झंडी मिल गई। कला संकाय प्रमुख अशोक सिंह ने बताया कि फिरोज ने सोमवार शाम कला संकाय के संस्कृत विभाग में ज्वाइन कर लिया है। वह मंगलवार सुबह कला संकाय में संस्कृत विभाग में दो छात्रों के साथ गए। वहां प्रो. यूपी सिंह की देखरेख में उन्होंने पहली हाजिरी लगाई।

डॉ. फिरोज खान। फाइल

कुछ देर विभाग में रहे डॉ. फिरोज

प्रो. सिंह ने बताया कि डा. फिरोज रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद कुछ देर तक विभाग में मौजूद रहे। इसके बाद चले गए। प्रो. सिंह ने बताया इन दिनों परीक्षा चल रही है। इसलिए फिरोज को क्लास नहीं मिली। एक-दो दिन में परीक्षा में ड्यूटी लगाई जाएगी।

05 नवंबर को संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय हुई नियुक्ति

07 नवंबर से धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों का धरना शुरू

22 नवंबर को आश्वासन पर धरना समाप्त। पर, आंदोलन जारी

02 दिसंबर को छात्रों ने प्रशासन से जवाब मांगा

02 दिसंबर से अस्पष्ट जवाब के विरोध में दोबारा धरना शुरू

09 को फिरोज ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में इस्तीफा दिया

10 को कला संकाय के संस्कृत विभाग में किया ज्वाइन

दुष्कर्म पीड़िता की बहन से लिया नौकरी का आवेदन पत्र

जागरण टीम, उन्नाव : जिंदा जलाई गई दुष्कर्म पीड़िता के आक्रोश को देख प्रशासन अब उनकी मांगें पूरी कराने में जुट गया है। मंगलवार को प्रशासन ने पीड़िता की बहन से नौकरी का आवेदन लिया।

पीड़िता के परिवार ने सोमवार को सरकारी नौकरी, दो आवास और शस्त्र लाइसेंस की मांग पूरी हुए बिना समाधि स्थल पक्का न होने देने का एलान किया था। उन्होंने निर्माण के लिए पहुंचे कर्मियों को लौटा दिया था। पीड़िता की बहन ने एक सप्ताह में मांगें पूरी न होने पर कब्र से शव निकालकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासन कोई ऐसी चूक नहीं करना चाहता जिससे पीड़ित परिवार को विरोध का मौका मिले।

बीघापुर तहसीलदार चंद्रशेखर मंगलवार को पीड़िता के घर पहुंचे और उसकी बहन से नौकरी के लिए आवेदन पत्र और शैक्षिक, जाति, निवास प्रमाणपत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों का सहमति पत्र लिया। तहसीलदार ने बताया कि नौकरी का आवेदन पत्र डीएम के जरिए शासन को भेजेंगे। किस पद और किस विभाग में नौकरी मिलेगी यह निर्णय शासन से ही होगा। पीड़िता के भाई की आयु अधिक होने से पिता ने छोटी बेटी को नौकरी की इच्छा जताई थी। इस पर प्रशासन ने नौकरी का आवेदन लिया। इधर पंचायत राज विभाग भी सजग है। एडीओ पंचायत हरिओम तिवारी, ग्राम विकास अधिकारी शशि मोहन मिश्र के साथ दोपहर में गांव पहुंचे।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में 16 को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

उन्नाव के माखी दुष्कर्म मामले में तीस हजारी अदालत ने 16 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर और महिला शशि सिंह आरोपित हैं। तीस हजारी कोर्ट में गत 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी और 9 अगस्त को दोनों आरोपितों पर आरोप तय किए गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए थे। वही, सह आरोपित उसकी सहयोगी शशि सिंह पर षड्यंत्र रचने व अपहरण के आरोप तय किए गए थे।

अदालत ने इस मामले में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) की धारा 3 व 4 (नाबालिग से दुष्कर्म) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (दुष्कर्म) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। अदालत ने आरोपपत्र के आधार पर कहा था कि 4 जून 2017 को नौकरी दिलाने के नाम पर शशि सिंह के साथ मिलकर कुलदीप सेंगर ने साजिश रचने और परिजनों की सहमति के बगैर 16-17 साल की किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अपराध किया। इसके लिए अलावा किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और उसके परिजनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप तय किया गया था।

यह है उन्नाव कांड : आरोप है कि नौकरी देने का वादा करके पीड़िता के साथ विधायक सेंगर ने अपने आवास पर 4 जून 2017 को दुष्कर्म किया था। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया था, जब पीड़िता और उसकी मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता के खिलाफ 3 अप्रैल 2018 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस हिरासत में अत्यधिक पिटाई के कारण उनकी मौत हो गई थी। इसी साल 28 जुलाई को चाचा से मिलकर वापस लौटने के दौरान रायबरेली में पीड़िता, उसकी चाची, मौसी व वकील की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इसमें उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता व उसके वकील घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव कांड से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित किया था।

पीड़िता की हालत को देखते हुए एम्स में भी लगी थी अदालत

सुशील गंभीर, नई दिल्ली

दुष्कर्म के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जा रही हैं। ऐसे में तीस हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने जिस तरह उन्नाव दुष्कर्म केस की हर दिन सुनवाई कर मामले को फैसले के करीब तक पहुंचाया है, वह उदाहरण स्थापित करता है। इसी साल 5 अगस्त को पहली बार तीस हजारी अदालत में यह केस सुना गया था। तब से लेकर अब तक लगभग हर दिन इस मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता की नाजुक हालत को देखते हुए तीन दिन तक एम्स में भी अदालत लगी। ऐसा अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही होता है कि अदालत खुद पीड़ित को सुनने के लिए उसके पास जाए। प्रतिदिन देर शाम तक सुनवाई होती थी, जबकि कई बार सरकारी छुट्टी के दिन भी केस सुना गया। उन्नाव कांड से जुड़े सभी केस बंद कमरे में सुने जा रहे हैं और इस केस को भी इसी प्रक्रिया के तहत सुना गया। केस से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी अदालत में जाने की अनुमति नहीं थी। खबरें प्रकाशित और प्रसारित करने पर भी कई तरह की पाबंदियां अदालत ने लगाई थीं।

हड़ताल की वजह से रुक गई थी सुनवाई : तीस हजारी अदालत में 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल के बाद सभी अदालतों के वकील हड़ताल पर चले गए थे। 12 दिन तक चली हड़ताल के कारण इस मामले की सुनवाई भी अटक गई थी, जो करीब दो सप्ताह के बाद फिर से शुरू हो सकी।

न्यूज गैलरी

चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित की जमानत मंजूर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपित विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिया है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता बीएन मिश्र, आरबी मिश्र व सचिन मिश्र ने बहस की। शाहजहांपुर के याची पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करके पांच करोड़ रुपये मांगे हैं। मामले में आरोपी 20 सितंबर 2019 से जेल में बंद है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सह अभियुक्त सचिन का चचेरा भाई है। इस अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है, फिर भी उसे फंसाया गया है। इससे पहले दुष्कर्म पीड़िता और सचिन की जमानत मंजूर हो चुकी है। उसके आधार पर याची की भी जमानत मंजूर कर ली गई है। (विसं)

इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौ नए न्यायाधीश नियुक्त

प्रयागराज : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौ नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार के विधि और न्याय विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में अधिवक्ता बिपिन चंद्र दीक्षित, समित गोपाल, शेखर कुमार यादव, रविनाथ तिलहरी, दीपक वर्मा, गौतम चौधरी, शमीम अहमद, दिनेश पाठक व मनीष कुमार शामिल हैं। इन सभी न्यायाधीशों की अगले दो साल के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। इनमें से सात हाई कोर्ट की प्रधानपीठ व दो लखनऊ पीठ के हैं। नई नियुक्ति होने से हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 109 हो जाएगी। इससे मुकदमों की सुनवाई व निस्तारण की प्रक्रिया तेज होगी। हाई कोर्ट में मौजूदा समय नौ लाख से अधिक मुकदमें लंबित हैं। (विसं)

मध्य प्रदेश में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने दी जान

होशंगाबाद : मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दो दिन पहले दुष्कर्म का शिकार एक पीड़िता ने मंगलवार को जान दे दी। उसका शव कमरे में लटका मिला। दो दिन पहले पीड़िता ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोपित जेल में हैं। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उल्लेख है कि वह घटना के बाद से ही परेशान थी। इसके अलावा अन्य कई बातें भी लिखी हुई हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त कर लिया है। एसडीओपी मोहन सारवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजन ने आरोप लगाया है कि घटना से दुखी होकर ही नाबालिग ने आत्मघाती कदम उठाया है। (नईदुनिया)

समानता के अधिकार के विजन पर क्या समाज खरा उतर सका : कोविंद

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में महिलाओं के खिलाफ हाल में हुए अपराधों का जिक्र करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या समाज सभी के लिए समान अधिकारों के विजन पर खरा उतर सका है।

मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर को यादगार बनाने का आदर्श तरीका यही होगा कि पूरी दुनिया इस बात पर आत्मनिरीक्षण करे कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) की भावना पर खरा उतरने के लिए क्या और किया जाना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने यूडीएचआर के निर्माण में भारतीय सुधारक हंसा जीवराज मेहता के योगदान को भी याद किया। उन्हें खासतौर पर यूडीएचआर मसौदे के अनुच्छेद एक के वाक्य 'सभी पुरुष समान और स्वतंत्र जन्म लेते हैं' को बदलवाने का श्रेय दिया जाता है। उनके ही प्रयासों से यूडीएचआर में उक्त वाक्य को बदलकर 'सभी मानव समान और स्वतंत्र जन्म लेते हैं' कर दिया गया था।

कोविंद ने कहा कि मेहता जैसी दूरदर्शी नेताओं को याद करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हम खुद से यह सवाल करके शुरुआत कर सकते हैं कि क्या हम समान अधिकारों और समान गरिमा के उनके विजन पर खरे उतरे हैं। दुर्भाग्य से हाल में हुई कई घटनाओं ने हमें फिर से यह सोचने पर मजबूर किया है। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों की खबरें देश के कई हिस्सों से आई हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक स्थान या एक देश तक ही सीमित नहीं हैं। दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के अधिकार खतरे में हैं और उनका उल्लंघन किया जा रहा है।'

- बोले, महिलाओं के खिलाफ हालिया जघन्य अपराधों ने सोचने पर किया मजबूर
- कहा, ऐसी घटनाएं सिर्फ एक स्थान या एक देश तक ही सीमित नहीं हैं
- मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के एक कार्यक्रम में की शिरकत

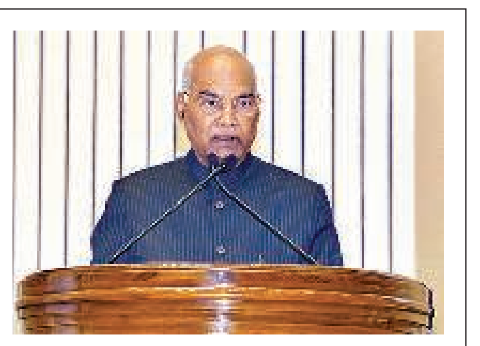

नई दिल्ली में मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एनएचआरसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रेट्र

शादी के बाद भी प्रेमी संग रहने की जिद पर पिता ने की थी हत्या

जागरण संवाददाता, बक्सर : बिहार में बक्सर में युवती की गोली मारकर हत्या के बाद शव को पुआल से जलाने की गुत्थी सुलझ गई है। मामला ऑनर किलिंग का निकला। मृत युवती की पहचान इंदू देवी के रूप में हुई है। पिता और भाई ने ही तीन रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या का कारण प्रेम-प्रसंग बताया जाता है। शादी के दूसरे दिन ही वह ससुराल से भागकर मायके आ गई थी और प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी थी। इससे समाज के लोग ताना मारते थे। पुलिस ने हत्यारोपित पिता महेंद्र प्रसाद, भाई मुकेश कुमार और माता शर्मिला देवी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित अन्य तीन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताते चलें कि 3 दिसंबर की सुबह बक्सर के कुकुढ़ा गांव के बाहर खेत में युवती का अधजला शव मिलने से सनसनी मच गई थी। युवती को पहले सिर में गोली मारी गई थी, इसके बाद उसे जला दिया गया था। पैर को छोड़ पूरा शरीर जल गया था।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के नंबर सर्विलांश में लगाकर उन्होंने घटना का राजफाश किया।

अमरोहा में एक युवक से शादी को अड़ी दो बहनें, छोटी से हुआ निकाह

जागरण संवाददाता, अमरोहा

- 24 घंटे बाद परिजनों के समझाने पर निकला हल
- बड़ी बहन ने छोटी बहन के साथ निकाह कराए जाने की सहमति दी

सोमवार शाम घर से फरार होते प्रेमी युगल को लोगों ने दबोच लिया लेकिन, मामले में देर रात उस समय नया मोड़ आ गया, जब प्रेमिका की छोटी बहन भी उसी युवक के साथ शादी की जिद पर अड़ गई थी। देर शाम पंचायत में प्रेमी का निकाह छोटी बहन से कराए जाने का फैसला लिया गया। देर रात दोनों का निकाह करा दिया गया।

यह मामला उप्र के अमरोहा स्थित डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। सोमवार शाम को गांव का युवक पड़ोस में रहने वाली प्रेमिका को बाइक पर लेकर जा रहा था। गांव के कुछ युवकों ने डॉयल-112 को सूचना देकर उन्हें पकड़वा दिया। पुलिस दोनों को कोतवाली ले गई। वहां पर दोनों के परिजनों को बुला लिया गया। थाने में युवती प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ गई लेकिन, युवक उससे शादी करने से इन्कार करता रहा। रात में दो बजे के बाद इस मामले में नया मोड़ उस समय आया, जब प्रेमिका की छोटी बहन भी कोतवाली पहुंच गई। वह भी बहन के प्रेमी को अपना प्रेमी बताते हुए शादी की जिद पर अड़ गई। हालांकि रात में पुलिस ने दोनों बहनों को परिजनों की सुपुर्दगी में घर भेज दिया और आरोपित हिरासत में ले लिया। मंगलवार को परिजनों व गांव के लोगों ने दोनों बहनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन, दोनों टस से मस नही हुईं। देर शाम तक इस मामले गांव में ही चली पंचायत में बड़ी बहन को पीछे हटना पड़ा। उसने प्रेमी का निकाह छोटी बहन से कराने की रजामंदी दे दी। उसके बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे तथा पुलिस को समझौते की बाबत जानकारी दी। देर रात ग्रामीणों ने छोटी बहन के साथ प्रेमी का निकाह करा दिया है। प्रभारी निरीक्षक शरद मलिक ने बताया कि बड़ी बहन ने छोटी बहन के साथ निकाह कराए जाने की सहमति दे दी है। समझौता होने पर आरोपित को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। मंगलवार देर रात दोनों के परिजन उनका निकाह कराने का हलफनामा देकर चले गए।

वन भूमि मामले में हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को झटका

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▶ 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के जंगलों को वन की परिभाषा से बाहर करने के आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के मामले में अहम आदेश पारित करते हुए सरकार के 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले जंगल को वन के दायरे से बाहर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को दो जनवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि 21 नवंबर 2019 को उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण अनुभाग द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में जहां 10 हेक्टेयर से कम या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले जंगल हैं, उनको वनों की श्रेणी व वन की परिभाषा के दायरे से ही बाहर कर दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह कार्यालय आदेश है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कहा कि यह न शासनादेश है, न ही कैबिनेट से पारित है। सरकार द्वारा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा से इस आदेश को जारी किया गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अनुसार प्रदेश में 71 प्रतिशत वन क्षेत्र घोषित है, जिसमें वनों की श्रेणी को भी विभाजित किया गया है। इसके अलावा ऐसे भी क्षेत्र हैं, जिनको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार इन क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र की श्रेणी में भी शामिल करते हुए इनके दोहन या कटान पर रोक लगाई जाए।

नैनीताल हाई कोर्ट। फाइल

अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों पर केस की सुनवाई 17 जनवरी को

जासं, मुजफ्फरपुर : उन्मादी भीड़ की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाली अभिनेत्री अपर्णा सेन सहित 49 बुद्धिजीवियों के मामले पर मंगलवार को सुनवाई फिर टल गई। अब इस पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा की ओर से सीजेएम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। जिसमें उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना की है कि तत्कालीन एसएसपी व मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर रखा है। इस परिवाद की सुनवाई 17 जनवरी को मुकर्रर है। यह परिवाद इसी मामले से संबंधित है। इसलिए दोनों मामले की सुनवाई एक तारीख को ही की जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने कोर्ट में अंतिम प्रपत्र दाखिल किया था। इसमें आरोपों को असत्य बताते हुए अधिवक्ता के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा-182 व 211 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति देने की कोर्ट से प्रार्थना की गई थी। इसके विरुद्ध अधिवक्ता ने कोर्ट में विरोध पत्र दाखिल किया था। इसमें पुलिस पर अनुसंधान में भेदभाव करने का आरोप लगाया गया।

डीआरआइ ने जब्त किया 42 किलो सोना, 10 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ कोलकाता, रायपुर व मुंबई में अलग-अलग जगहों से जब्त किया गया सोना

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की कोलकाता जोनल यूनिट की टीम ने सोने की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 42 किलोग्राम सोना जब्त किया है। डीआरआइ के कोलकाता जोनल यूनिट के अंतर्गत इस साल पूर्वी क्षेत्र से 219 किलो सोना जब्त किया जा चुका है।

पूरे देश की बात करें तो डीआरआइ और सीमा शुल्क विभाग की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक विदेशों से तस्करी कर लाया गया करीब 1400 किलोग्राम सोना जब्त किया जा चुका है। डीआरआइ की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में बताया गया कि तस्करी के सोने की यह खेप 8 दिसंबर को कोलकाता, रायपुर व मुंबई में तीन अलग-अलग ऑपरेशन में छापेमारी के दौरान जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 16.5 करोड़ रुपये है। इस सिलसिले में डीआरआइ ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सोने को बांग्लादेश से अवैध तरीके से तस्करी कर लाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से भारत में तस्करी कर लाए गए सोने को गोविंद मालवीय उर्फ गोविंद लाल लोहार के कोलकाता में एक फ्लैट में छिपाकर रखा गया है। इसके साथ उनके सहयोगी फिरोज मुल्ला के कोलकाता स्थित फ्लैट और उनके दुकान में भी सोना रखा हुआ है। इसके बाद डीआरआइ अधिकारियों ने तीनों जगहों से 26.650 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। यहां से जब्त सोने की कुल कीमत करीब 10.57 करोड़ रुपये आंकी गई है। पूछताछ में पता चला कि मुख्य आरोपित गोविंद मालवीय ने समरसता एक्सप्रेस और एलटीटी कुर्ला एक्सप्रेस से तस्करी के सोने की दो और खेपों को भेजा है। इसके बाद डीआरआइ ने रायपुर और मुंबई में सोने के वाहक को पकड़ लिया और उनके पास से विदेशी मूल के क्रमशः आठ किलोग्राम व सात किलोग्राम सोना बरामद किया गया। वहीं, तीन आरोपितों गोपीराम, मिलन और साहिल जैन को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी बोर्ड : इंटर में फेल होने पर दे सकेंगे कंपार्टमेंट परीक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी बोर्ड की वर्ष 2020 की इंटरमीडिएट परीक्षा में दो विषयों में फेल होने पर परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकेंगे। यह सुविधा अभी तक यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में एक विषय में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को ही मिलती है। मार्कशीट पर यह नहीं लिखा जाएगा कि विद्यार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा देकर पास हुआ है।

यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने दी। लोक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कंपार्टमेंट परीक्षा की सुविधा देने के इस प्रस्ताव पर जल्द शासन की मुहर लगाई जाएगी। यूपी बोर्ड में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठ्यक्रम लागू करने के बाद अब परीक्षा के पैटर्न में भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) व काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआइएससीई) की तर्ज पर बदलाव किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा सिर्फ 14 दिनों में खत्म होगी। पहले एक विषय के दो-दो पेपर थे, अब इसे एक-एक किया गया है। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में नए सत्र से ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाई जाएंगी।

तैयारी

भारतीय वायुसेना पिछले तीन दिन से मनाली-लद्दाख में सुरंगों की संभावनाओं को तलाशने के लिए ट्रायल कर रही थी

मनाली से लेह-लद्दाख के बीच बनेंगी तीन सुरंगें

संवाद सहयोगी, कुल्लू

अब मनाली से लेह-लद्दाख का सफर और भी सुहाना हो जाएगा क्योंकि इस सड़क मार्ग पर तीन सुरंगों का निर्माण होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना बुधवार से कुल्लू-मनाली से लेकर लेह-लद्दाख के पहाड़ों पर इन सुरंगों के निर्माण की संभावना तलाशेगी। भारतीय वायुसेना पिछले तीन दिन से मनाली-लद्दाख में सुरंगों की संभावनाओं को तलाशने के लिए ट्रायल कर रही थी। मंगलवार को यह प्रक्रिया पूर्ण होने की अधिकारियों ने पुष्टि की है।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड एवं भारतीय वायुसेना द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश लेह-लद्दाख से जोड़े जाने को लेकर मनाली से वहां तक तीन सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए भुंतर एयरपोर्ट से वायुसेना का एमआई-17 का हेलीकॉप्टर पिछले तीन दिन से कुल्लू-मनाली के आसपास के एरिया में घूमा और इसकी पूरी जानकारी जुटाई। ट्रायल पूर्ण हो गया है और अब बुधवार से वायुसेना इसका सर्वेक्षण करेगी और पहाड़ों के ऊपर से इन तीनों टनलों के निर्माण को लेकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

पहली बार हो रहा ऐसा सर्वेक्षण : बताया जा रहा है कि भारत में पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण पहली बार हो रहा है। इसके लिए एक विदेशी एंटीना की सहायता ली जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना भारत में पहली बार इस तरह से हवाई सेवा के माध्यम से सर्वेक्षण कर रही है।

सुरंगों के निर्माण से सफर होगा कम : इन तीन सुरंगों के बनने से मनाली और लेह-लद्दाख का सफर भी कम होगा और साथ ही सर्दी में बर्फबारी के दौरान भी ये सुरंगे सहायक सिद्ध होंगी।

वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सहमे लोग

जागरण संवाददाता, मंडी : हिमाचल व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जोड़ने के लिए सुरंग निर्माण से पूर्व उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए मंगलवार को भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया। लोग हेलीकॉप्टर के नीचे लटके कैमरों और एक जालनुमा एंटीना से इतने घबराए कि कुछ लोग इसकी जानकारी लेने कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे पहुंच गए। दोपहर के समय जब कुल्लू-मनाली हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो औट से लेकर बजौरा के बीच लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो एक जालनुमा चीज को हेलीकॉप्टर उठाकर ले जा रहा था। इससे लोग भयभीत हुए और एक दूसरे को संपर्क करने लगे कि आखिर क्या चीच उठाकर ले जाई जा रही है। जब इस बारे कुल्लू-मनाली हवाई अड्डा प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने देर शाम सारी स्थिति स्पष्ट की।

प्रतीकात्मक

- ट्रायल पूर्ण हो गया है और अब बुधवार से वायुसेना इसका सर्वेक्षण करेगी
- बर्फबारी के दौरान ये सुरंगे सहायक सिद्ध होंगी

इस अभियान में पिछले तीन दिन से भुंतर हवाई अड्डे से टीम भारतीय वायुसेना का सहयोग कर रही है। यदि मौसम साफ रहा तो बुधवार से भारतीय वायुसेना सुबह सात से साढ़े सात बजे के बीच में सर्वे शुरू करेगी। यह सर्वे 21 दिसंबर तक चलेगा। **-नीरज कुमार, निदेशक भुंतर एयरपोर्ट अथॉरिटी।**

छत्तीसगढ़ के रायपुर में नर्सिंग की दो छात्राओं की हत्या

नईदुनिया, रायपुर

▶ रायगढ़ की चचेरी बहनें रायपुर में किराए का मकान लेकर कर रही थीं कोर्स

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंगलवार को नर्सिंग की दो छात्राओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई। एडिशनल एसपी सिटी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदावरी नगर में के निजी गर्ल्स हॉस्टल में घटना सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच की है। मूलतः रायगढ़ जिले के बेलादुला, विनोबा नगर निवासी मनीषा सिदार (20) पुत्री जालंधर सिदार रावतपुरा नर्सिंग कालेज में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। सोमवार को मनीषा की रिश्ते की बहन नर्सिंग छात्रा मंजूलता सिदार उसके कमरे में आकर रुकी थी। मंगलवार की सुबह मनीषा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर खाना खाने के लिए बैठी थी, तभी कमरे में दो दोस्त मिलने आए। किसी बात को लेकर दोस्तों के बीच बहनों का विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने रोटी बनाने वाले लोहे के तवे से मनीषा के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। बहन को बचाने, तवा छीनने की कोशिश के दौरान मंजूलता पर भी युवकों ने वार कर दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान शोर सुनकर हॉस्टल के अन्य कमरे में रहने वाली छात्राओं ने घटना की जानकारी हॉस्टल मालिक बंटी साहू को दी। बंटी मौके पर पहुंचे तो दो हमलावर उस समय कमरे में ही मौजूद थे। बंटी को देखते ही वे दरवाजा खोलकर धक्का मारकर भाग निकले।

सीसीटीवी कैमरे में भागते कैद हुए हमलावरः पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे दर्जन भर से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो तीन जगहों से दोनों आरोपितों के फुटेज मिले। आरोपित हॉस्टल से भागते हुए गली में पैदल मोबाइल पर बात करते जाते कैमरे में कैद हुए हैं।

दैनिक जागरण

असल दोष यह है कि दोषों को सुधारने की कोशिश ही न की जाए

शरारत भरा दुष्प्रचार

यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि लोकसभा से पारित नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी आपत्ति जता रहे हैं। जो देश धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले में दुनिया भर में कुख्यात हो और जहां अल्पसंख्यक एक तरह से अंतिम सांसें गिन रहे हों वह आखिर किस मुंह से भारत को नसीहत दे सकता है? नागरिकता विधेयक पर इमरान खान की शरारत भरी टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी है। यह सहज ही समझा जा सकता है कि इमरान खान यह धृष्टता इसलिए कर सके, क्योंकि हमारे कई विपक्षी दल यह दुष्प्रचार करने में जुटे हुए हैं कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है। आखिर जिस विधेयक का देश के किसी भी मजहब के नागरिकों से कहीं कोई लेना-देना ही नहीं उसे लेकर यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि वह भारतीय मुसलमानों के हित में नहीं? नागरिकता विधेयक को लेकर जानबूझकर दुष्प्रचार तब किया जा रहा है जब विपक्ष की आपत्तियों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि इस कानूनी कवायद का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है। जो भी इस दुष्प्रचार में लिप्त हैं उन्हें बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि कोई इस विधेयक को जिन्ना के विचारों के अनुरूप बता रहा है तो कोई भारतीय मूल्यों के प्रतिकूल? क्या भारत का हित इसमें है कि दुनिया भर के लोगों को देश में बसने की इजाजत दे दी जाए?

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि नागरिकता विधेयक को लेकर दुष्प्रचार करने वाले सब कुछ जानते हुए भी इस तथ्य की अनदेखी करना पसंद कर रहे हैं कि यदि इसमें कुछ विसंगतियां होंगी तो उच्चतम न्यायालय के पास उन्हें दूर करने का अधिकार होगा। यह अच्छा हुआ कि भारत ने नागरिकता विधेयक पर एक अमेरिकी आयोग की टिप्पणी का प्रतिवाद करने में देर नहीं की। इस आयोग की टिप्पणी अनावश्यक ही नहीं, अज्ञानता से भी भरी है। उसे इससे परिचित होना चाहिए कि खुद अमेरिकी प्रशासन अपने हिसाब से यह तय करता रहा है कि किन देशों के नागरिक स्वीकार्य हैं और किन देशों के नहीं? उसके ऐसे कई फैसलों को वहां की अदालतों ने सही भी ठहराया है। अमेरिका या फिर अन्य किसी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं मिल सकता कि भारत के नागरिकता संबंधी नियम-कानून कैसे हों? यह आवश्यक है कि भारत सरकार पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दे कि वह उसके आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने से बाज आए। यह भी उचित होगा कि भारत की ओर से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मामले को उठाया जाए।

बहुरंगे दिन

कोलकाता के चटकल उद्योग से यूपी-बिहार समेत कई राज्यों का गहरा नाता है। जूट मिलों की बदहाली ने रोजगार के लिए बंगाल को ठिकाना बनाने वालों के सपनों पर पहरे बिठा दिए। कुछ लौट गए तो कुछ दूसरे धंधों से जुड़ गए। रोजगार की तलाश में आने वाली नई खेप की आमद भी कम हुई। अब उम्मीद की रोशनी दिखाई पड़ी है। जूट मिलों में रोजगार की नई संभावना दिखने लगी है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनाजों की पैकेजिंग में 100 फीसद जूट की बोरियों के इस्तेमाल का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में केंद्र सरकार ने अनाजों और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री बंगाल की नब्ज जानते हैं और उनके इस फैसले से सर्वाधिक प्रभावित यही राज्य होगा। यह फैसला 2021 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां दशकों से रह रहे मजदूर वर्ग का इससे सीधा वास्ता है। कोलकाता की दर्जनों जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। जूट उद्योग पर अभी तक आफत के ही बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब अनाजों की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों की मांग बढ़ेगी। यह मांग निःसंदेह जूट मिलों को पुनर्जीवित करने में सहायक सिद्ध होगी। केंद्र सरकार ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल एक्ट, 1987 के तहत जूट पैकेजिंग को बरकरार रखा है। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने प्रयास भी किया है। इस फैसले से करीब पौने चार लाख मजदूरों और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। सिर्फ बंगाल, यूपी और बिहार ही नहीं, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य भी इससे प्रभावित होंगे। मोदी के इस फैसले की सर्वत्र सराहना हो रही है। भारतीय जूट मिल्स एसोसिएशन ने भी मोदी सरकार के इस कदम की सराहना की है। इस फैसले से जहां एक तरफ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। सरकार ने प्लास्टिक की बोरियों पर रोक लगा दी है। प्लास्टिक की बोरियों पर रोक लगाए जाने पर मोदी ने खास जोर दिया है। अभी तक जूट बोरियों की अनुपलब्धता के चलते फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्लास्टिक की बोरियों के इस्तेमाल की छूट मिली हुई थी, लेकिन सरकार ने जूट को महत्व और प्लास्टिक पर रोक लगाकर दोहरे लाभ की भूमिका रची है। निःसंदेह यह फैसला उम्मीदों को परवान चढ़ाने वाला होगा। भविष्य में जूट मिलों के खुलने और नई मिलों की नींव पड़ने से रोजगार की तलाश पूरी होगी और खाली हाथों को काम मिलेगा।

उचित आधार वाला नागरिकता विधेयक

अद्वैता काला

इस दलील की अनदेखी नहीं होनी चाहिए कि नागरिकता विधेयक का मकसद विभाजन के बाद के हालात से निपटना है

नागरिकता संशोधन विधेयक पर संसद के भीतर और बाहर बहस गर्म है। यह बहस मीडिया में भी है और सोशल मीडिया में भी। हर कोई इस या उस पक्ष में अपनी राय रख रहा है। आलोचक इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो विधेयक के विरोध में नहीं हैं वे उसका समर्थन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यह कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी है। वे तो इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह पड़ोसी देशों के उन सताए गए अल्पसंख्यकों के पक्ष में है जिनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं।

1947 में जब देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ तब भारत ने अपनी हिंदू मान्यताओं के चलते धर्म आधारित देश बनना पसंद नहीं किया। हिंदू मान्यताएं सेक्युलरिज्म के अनुकूल हैं और उनका किसी भी पंथ के साथ कहीं कोई टकराव भी नहीं। भारतीय इतिहास इस तरह के दृष्टांतों से भरा पड़ा है कि भारत ने विभिन्न पंथों के धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों के लिए अपने द्वार किस उदारता के साथ खोले। इस मौके पर देश की पहली मस्जिद का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए जो केरल में बनी। अगर भारत ने किसी धर्म को अपना राजकीय धर्म नहीं घोषित किया तो यह किसी विवाद या दुविधा के कारण नहीं, लेकिन भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। उसने ऐसा तब किया जब वहां अच्छी-खासी संख्या में धार्मिक अल्पसंख्यक रह रहे थे। इन धार्मिक अल्पसंख्यकों ने इस उम्मीद में भारत की ओर पलायन नहीं किया कि नए देश में उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। वक्त ने उन्हें गलत साबित किया। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसने भी खुद को इस्लामिक देश घोषित किया। समय के साथ इन दोनों देशों में बलात मतांतरण और उत्पीड़न के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या घटनी शुरू हो गई। इसके विपरीत भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई। आज यह बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा जिस तीसरे देश अफगानिस्तान का उल्लेख है वहां भी लगातार चले युद्ध और तालिबान के दमनकारी शासन के चलते सिखों और हिंदुओं का सफाया हुआ। इस सफाए को दुनिया ने भी देखा। वास्तव में इसी कारण नागरिकता विधेयक में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। म्यांमार में भी मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोधी यह तर्क दे रहे हैं कि इन तीनों देशों के साथ-साथ निःसंदेह अनदेखी नहीं की जा सकती।

पाकिस्तान में अहमदिया और शिया सताए जा रहे हैं। यह तब है जब इस्लाम वहां का राजकीय धर्म है। चूंकि ये समुदाय पाकिस्तान के निर्माण में सहायक बने और उसकी आंतरिक संरचना का अंग हैं इसलिए उनकी देख-रेख करना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी के लिए उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में लोगों का उत्पीड़न इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां के लोग आत्मनिर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। वहां की समस्या को धार्मिक आधार पर किए जाने वाले उत्पीड़न की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

म्यांमार के अराकान इलाके में रोहिंग्या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उनके उत्पीड़न पर आंग सान सू को अंतरराष्ट्रीय अदालत के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है। अराकान में रह रहे हिंदू भी रोहिंग्या आतंकियों के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब वहां एक कब्र में दफनाए गए करीब सौ हिंदुओं के शव मिले थे।

चूंकि नागरिकता संशोधन विधेयक में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं और मुसलमानों को भी शामिल नहीं किया गया है इसलिए सरकार की इस दलील में दम है कि इस विधेयक का मकसद विभाजन के पहले और बाद के हालात से निपटना है। अफगानिस्तान इस विधेयक का हिस्सा है तो वहां के युद्ध जैसे असामान्य हालात के कारण। अफगानिस्तान के विपरीत म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश है और वहां एक विधिवत सरकार है। यह सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अपने लोगों और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह है। म्यांमार सरकार ने रोहिंग्याओं से देश लौटने को कहा भी है। इसकी संभावना है कि उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा।

एक आदर्श विश्व में हमें किसी सीमा की जरूरत नहीं, लेकिन आज के खतरनाक माहौल में देशों को अपनी सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी गंभीरता से लेना पड़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में विशाल आबादी की अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर हम और कितने शरणार्थियों को स्वीकार कर सकते हैं। आज तो यूरोप के समृद्ध देश भी इसके प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ब्रिटेन में इस पर बहस छिड़ी है कि खुली सीमा उनके हित में नहीं है। ब्रेक्जिट इसी की देन है। हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। दशकों से वहां से लोग बेहतर जीवन की उम्मीद में भारत में प्रवेश कर रहे हैं। वे उस क्षेत्र की आबादी के साथ घुलमिल गए हैं। इससे वहां की आबादी का संतुलन बिगड़ गया है। संसाधनों पर उनका कब्जा हो गया है। इसके अलावा वे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। दोष बेहतर जीवन की चाह रखने वाले गरीबों का नहीं, बल्कि स्वार्थी नेताओं का है जो वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए घुसपैठ को बढ़ावा देते रहे।

बेलगाम घुसपैठ से देश की सुरक्षा के लिए पैदा हो रहे खतरे की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब खुफिया एजेंसियां यह कह रही हों कि हूजी सरीखे आतंकी संगठन घुसपैठ को बढ़ावा देने के साथ ही घुसपैठियों के बीच पैठ भी बना रहे हैं। इन संगठनों का मकसद भारत में हिंसा और आतंक फैलाना ही है। इसका कोई मतलब नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल की चिंता करने में संकोच बरता जाए। चूंकि विपक्षी दलों की ओर से नागरिकता विधेयक का विरोध किया जा रहा है इसलिए यह एक भावनात्मक मसला भी बन रहा है। हैरत नहीं कि भारतीय मुस्लिम इस विधेयक को भेदभाव करना वाला समझें, जबकि सच यह है कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं। चूंकि धारणा का महत्व होता है इसलिए, सत्ताधारी दल और सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों तक पहुंच बढ़ाए और यह स्पष्ट करे कि इस विधेयक को ऐसा स्वरूप क्यों दिया गया? इस विधेयक पर संसद की मुहर लगने के आसार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता का उन मुद्दों से परिचित होना चाहिए जिनके बारे में उसका यह मानना हो कि वे उस पर असर डाल सकते हैं। पारदर्शिता और खुला संवाद भरोसे को बढ़ाने में सहायक ही बनता है।

(लेखिका ब्लॉगर एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

दोराहे पर खड़ा ब्रिटेन

ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमंस की 650 सीटों के लिए 12 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी हर पांच वर्ष में आम चुनाव होते हैं, लेकिन ब्रेक्जिट की अनिश्चितता के चलते वहां हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता इस कदर बढ़ी कि 2015 के बाद से यह ब्रिटेन का तीसरा संसदीय चुनाव है। ब्रिटेन के आधुनिक इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके नतीजे उसकी आगे की राह तय करेंगे। अभी ब्रिटेन दोराहे पर खड़ा है। दरअसल 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन के बहुसंख्यक 52 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय आर्थिक संघ से बाहर निकलने का विवादास्पद निर्णय लिया, लेकिन वह फैसला अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इस दौरान ब्रिटेन की राजनीतिक और सामाजिक खाई काफी चौड़ी हो गई, जिसका दुष्प्रभाव चुनाव में नजर आ रहा है। मैं 1983 से यहां के चुनावों का विश्लेषण कर रहा हूं, पर चुनावों में ऐसी कड़वाहट, इतना क्रोध और इतने आरोप-प्रत्यारोप पहले कभी नहीं देखे। देश विभाजित है। जनता भ्रमित है। व्यापारी चिंतित हैं। युवा आक्रोशित हैं और अल्पसंख्यक अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं।

2008 की आर्थिक मंदी के बाद से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा में लगातार कटौतियां होती रही हैं। कमजोर तबके के लोगों का वेतन बढ़ा नहीं है। गरीबों और अमीरों के बीच की खाई भी बढ़ी है। अपनी इन विफलताओं को छिपाने के लिए ब्रिटेन के बहुत से राजनीतिज्ञों ने इन आर्थिक कठिनाइयों के लिए यूरोपीय संघ को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ब्रिटेन प्रतिवर्ष यूरोपीय संघ को भारी अनुदान देता है। उदाहरण के लिए 2018 में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के बजट में 8.9 अरब पाउंड का अतिरिक्त अनुदान दिया। ब्रेक्जिट के पक्षधर नेताओं का मानना है कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद 8.9 अरब पाउंड की इस भारी भरकम रकम को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी स्थानीय सेवाओं पर खर्च किया जा सकेगा।

सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ब्रेक्जिट विधेयक को क्रिसमस से पहले संसद में पास कराया जाएगा और 30 जनवरी से पहले ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ जाएगा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता यूरोपीय संघ में बने रहना चाहती हैं। वहीं प्रमुख

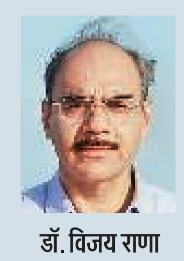

डॉ. विजय राणा

ब्रेक्जिट के चलते ब्रिटेन की राजनीतिक–सामाजिक खाई काफी चौड़ी हो गई है और उसका दुष्प्रभाव चुनाव में भी दिख रहा है

विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन का कहना है कि पहले तो वे यूरोपीय संघ के साथ ब्रेक्जिट के लिए एक नया समझौता करेंगे। फिर उस समझौते पर एक नया जनमत संग्रह कराएंगे। यदि जनता ने इस नए समझौते का समर्थन किया तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ को छोड़ देगा और यदि समझौते को खारिज कर दिया तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ में बना रहेगा। लेबर पार्टी की इस नीति को लेकर ब्रेक्जिट से उकताए मतदाताओं के मन में दो आशंकाएं हैं। एक तो यह कि अंतिम फैसला होने में महीनों लग सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि जेरेमी कोर्बिन को स्पष्ट बहुमत न मिले। उन्हें स्कॉटलैंड की आजादी की समर्थक स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ सकती है। एसएनपी पहले ही यह कह चुकी है कि यदि ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट का फैसला किया तो वह स्कॉटलैंड की आजादी के लिए जनमत संग्रह कराना चाहेगी, क्योंकि स्कॉटलैंड की जनता यूरोप में रहना चाहती है। ब्रिटेन के बहुत से मतदाता मानते हैं कि यदि एसएनपी और लेबर पार्टी की साझा सरकार बनती है तो भविष्य में ब्रिटेन टूट सकता है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो सकता है।

ब्रिटिश राजनीति का एक और निराशाजनक पक्ष है जनता में तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं के प्रति अविश्वास का भाव। बोरिस जॉनसन के बारे में माना जाता है कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने अमीर समर्थकों की चिंता है। जेरेमी कोर्बिन अपने धुर-वामपंथी विचारों के कारण हमेशा विवादास्पद रहे हैं। वह ब्रिटेन की राजशाही में यकीन नहीं रखते। वह अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक ब्रिटेन के सैनिक अभियानों के विरोधी रहे हैं। उन पर यहूदी विरोधी होने के गंभीर आरोप हैं। वह कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के समर्थक हैं। वह पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करते है कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। कोर्बिन के भारत विरोधी रुख के कारण भारतीय मूल के मतदाता लेबर पार्टी से नाराज हैं। 15 अगस्त को जब भारतीय मूल के लोग भारत के उच्चायोग के सामने जश्न माना रहे थे तो हजारों पाकिस्तान समर्थकों की एक भीड़ ने वहां हिंसक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में लेबर पार्टी के कई सांसदों ने भारत विरोधी भड़काऊ भाषण दिए। सितंबर में लेबर पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध और कश्मीर की आजादी के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान समर्थक गुटों ने कंजरवेटिव पार्टी के उन सांसदों को हराने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिन्होंने भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी। मस्जिदों में लेबर पार्टी के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर देखे जा सकते हैं।

ब्रिटिश चुनाव में जारी इस सांप्रदायिक खेल का विरोध करने के लिए भारतीय मूल के संगठनों ने भी ब्रिटिश हिंदू वोट मैटर्स नामक एक लेबर विरोधी अभियान चलाया है। रोचक यह है कि इस्लाम और कुरान का वास्ता देकर मुस्लिम वोट को प्रभावित करने वाले लेबर नेता अब यह शिकायत कर रहे हैं कि भारत ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। ब्रेक्जिट की विवादास्पद राजनीति ने ब्रिटेन के सहिष्णु समाज को गहरी चोट पहुंचाई है। भारतीय और पाकिस्तानी समुदाय हिंदू-मुस्लिम प्रतिद्वंद्विता के आधार पर मतदान का मन बना चुका है। दक्षिणपंथियों और वामपंथियों के बीच मानो तलवारें खिंची हैं। मीडिया में उग्र बहस जारी है। जनता की कुंठा बढ़ती जा रही है। यदि अगले शुक्रवार की सुबह कंजरवेटिव पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो सामाजिक तनाव की यह स्थिति अनिश्चित काल तक बनी रहेगी।

(लेखक लंदन में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सद्बुद्धि

विकास और विनाश की जड़ सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि को माना गया है। सद्बुद्धि मानव मस्तिष्क में सकारात्मक सोच की उपज करने वाली ईश्वर प्रदत्त औषधीय शक्ति है। इससे अवरोधों से भरे मार्ग पर भी रास्ता तैयार करने की क्षमता विकसित होती है और लक्ष्य तय कर लिया जाता है। सद्बुद्धि को जीवन में धारण करने के कारण ही व्यक्ति का विकास होता है। वहीं दुर्बुद्धि-ग्रस्त होने से मनुष्य का हर तरह से पतन हो जाता है।

भक्ति की प्रगाढ़ता जब बढ़ती है तो परमात्मा वरदान के रूप में भक्त को सद्बुद्धि के रूप में दैवी संपदा प्रदान करते हैं, जिससे उसे नाना प्रकार के लौकिक सुख, संपत्ति, धन दौलत, यश-कीर्ति, पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहती है। वहीं ईश्वर के प्रति नास्तिकता का भाव होने के कारण दुर्बुद्धि-ग्रस्त व्यक्ति को पग-पग पर ठोकर अपकीर्ति, दुख, संताप, पीड़ा, कष्ट प्राप्त होते हैं। ईश्वर के प्रति नास्तिकता के कारण ही उसकी मति क्षीण हो जाती है और समस्त संपदा नष्ट हो जाती है, जबकि सद्बुद्धि के कारण असहाय व्यक्ति भी अपना जीविकोपार्जन कर लेता है। किसी के समक्ष उसे हाथ फैलाने, भिक्षा मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती है।

सद्बुद्धि के जागरण से ही जीवन की समस्त अनसुलझी समस्याओं का समाधान किया जाना संभव है। प्राचीन समय में समस्त ऋषि-महर्षि और देवगण सद्बुद्धि के जागरण के लिए नित्य गायत्री उपासना किया करते थे। यही अंतर्दृष्टि के जागरण का भी मूल है। इसके बिना तो व्यक्ति मूढ़, मूर्ख, पशु-तुल्य निज जीवनयापन करता है। आत्मिक प्रगति और जीवन की सार्थकता का स्वर्णिम अवसर तो सद्बुद्धि के जागरण से ही संभव होता है। ऋषि-मुनि जीवन को संस्कारित एवं बंधन मुक्त बनाने के लिए बाल्य काल से ही सद्बुद्धि के जागरण का अभ्यास कराते थे। जिससे बच्चों में उत्कृष्ट सोच, स्वभाव, कर्म का जन्म होता था और इसके कारण उनका जीवन मनुष्यता को पाकर सुखी संपन्न, नैतिक प्रधान बनकर गौरवशाली एवं महान बन जाता था।

मुकेश ऋषि

मोबाइल फोन ने बदली दुनिया

सुधीर कुमार

लोगों को तकनीक से जोड़ने तथा उनमें तकनीकी समझ विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय मोबाइल फोन को ही जाता है

3 अप्रैल, 1973 को जब मोटोरोला कंपनी के मालिक मार्टिन कूपर ने दुनिया के सामने एक किलो वजनी पहला मोबाइल फोन प्रस्तुत किया था तो शायद उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि विज्ञान का यह चमत्कारिक ईजाद एक दिन पूरी दुनिया को ही सम्मोहित कर लेगा! मोबाइल फोन के आगमन के बाद न सिर्फ पूरी दुनिया तकनीक के मामले में बड़ी तेजी से परिवर्तित हुई है, अपितु 'विकेंद्रीकृत तकनीक' की अवधारणा को साकार करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लोगों को तकनीक से जोड़ने तथा उनमें तकनीकी समझ विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय मोबाइल को ही जाता है। कभी सिर्फ फोन करने और संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल अब अपने परंपरागत दायरे से बहुत आगे निकल चुका है। स्मार्टफोन के आगमन के बाद ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया महज पांच-छह इंच की स्क्रीन में समा गई है। बहुद्देशीय प्रकृति होने की वजह से मोबाइल ने आधुनिक जीवन को अत्यंत सरल और सुगम बना दिया है।

एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 80 करोड़ मोबाइल फोन धारक हैं। आश्चर्य की बात है कि इस सूची में 50 से 60 लाख फोन प्रतिवर्ष जुड़ भी रहे हैं! हालांकि कुछेक दशक पूर्व ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भारत में मोबाइल फोन का आगमन 1995 में हुआ, जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम से मोबाइल फोन के जरिये बात करके देश में मोबाइल के आगमन का श्रीगणेश किया था। मोबाइल फोन खरीदना तब बहुतों के लिए एक बड़ा सपना था। स्थिति यह थी कि तब इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने होते थे।

बहरहाल मौजूदा समय में देश तकनीक के मामले में भारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में डिजिटल क्रांति को नई दिशा मिली है। सच्चाई भी यही है कि आज के इस तकनीकी दौर में जो व्यक्ति मोबाइल, सर्च इंजन और सोशल मीडिया से दूर है, वह निश्चय ही तकनीक के मामले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है! देश को डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर रखना उचित कदम तो है। किंतु हमें यह भी ध्यान में रखकर चलना होगा कि देश में बिजली किल्लत, सुस्त इंटरनेट, डाटा की महंगी दर जैसी समस्याएं डिजिटल भारत की योजना के लिए बाधक बन सकती हैं। इसलिए डिजिटलीकरण के साथ-साथ बुनियादी मुद्दों पर भी काम करने की आवश्यकता है। तकनीक का प्रयोग बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण होगा। सरकारी विभागों में पेपरलेस कार्य तथा ई-शिक्षा को व्यवहार की जमीन पर उतारते ही कागज के कारण होने वाले पेड़ों की बहुसंख्य कटाई पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

कहा जाता है कि एक तकनीक आपको दूसरी तकनीक से जोड़ती है। ऐसे में अगर हम तकनीक से जुड़े नहीं रहते हैं तो नई-नई तकनीकें भी हमारी पहुंच से दूर रह जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम तकनीक से जुड़े रहें और उसका सीमित तथा सार्थक प्रयोग भी करते रहें।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

समान नागरिक संहिता वक्त की मांग

समान नागरिक संहिता में बेवजह की देरी शीर्षक से लिखे अपने लेख में नाइश हसन ने समान नागरिक संहिता को लागू करना हर धर्म के लोगों के लिए हितैषी बताया है। सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय से देश में समान नागरिक संहिता लाने की बात करता रहा है। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो यह हमारे देश की एकता और अखंडता को और मजबूत करने का काम करेगी। मोदी सरकार को जल्द ही इसे लाने का फैसला करना चाहिए। जब संविधान में हर धर्म-जाति के लोगों को एक समान अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान है तो फिर समान नागरिक संहिता लागू करने में किसी को क्या हर्ज? जो मुस्लिम इसका विरोध करते हैं, उनसे यह सवाल है कि कितने मुस्लिम देशों या अन्य देशों में हर धर्म के नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून हैं? कानून का कोई धर्म नहीं होता। फिर एक देश में अलग-अलग धर्म के नागरिकों के लिए अलग-अलग कानून क्यों?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

कौन है मौतों का जिम्मेदार

दिल्ली के रिहाइशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्ट्रियां कब तक मजदूरों की जान लेती रहेंगी? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिसके सहारे परिवार खड़ा था वह आज दुनिया से चला गया। अलग-अलग वजहों से समय-समय पर लोगों को असमय मौत के मुंह में डाल रहीं ये फैक्ट्रियां किसी काल से कम नहीं हैं। इसमें हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है, जो इस समय एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। इसमें राजनीति करने से अच्छा है कि उस स्थिति को ठीक किया जाए। इन सत्तर वर्षों में हमने न जाने कितनी तकनीक का विकास किया, लेकिन आज भी हमारे होटल, स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्री बिना सुरक्षा उपकरण के संचालित हो रहे हैं। आनाज मंडी में लगी आग बहुत ही दुखद है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए और त्वरित गति से सभी फैक्ट्रियों की जांच होनी चाहिए। वहीं अवैध रूप से चल रही इन इकाइयों को बंद करना होगा। इसके अलावा पुरानी दिल्ली की गलियों में फैले बिजली के तारों के जाल को भी सुधारा जाए।

आशीष, दिल्ली विश्वविद्यालय

मेलबाक्स

जन्मसिद्ध अधिकार है मानवाधिकार

संविधान ने सभी मनुष्यों तथा जीवों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनको जन्म से ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे- जीवन, आजादी, सम्मान, बराबरी का अधिकार हम सभी को है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन करता है तो न्याय प्रणाली द्वारा आरोपी को दंडित किया जाता है। क्या आज मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? दिल्ली अग्निकांड हो या महिलाओं पर होते अत्याचार ये सब मानव अधिकारों का हनन हैं। मात्र कागजों में अधिकारों की बातें करने से हम आम नागरिकों तक उसका अधिकार नहीं पहुंचा सकते। इनका पालन सरकारों का दायित्व बनता है। दिल्ली अग्निकांड में निर्दोष लोग दम घुटने तथा जल कर बेमौत मर गए। उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हर दूसरे दिन महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार कर हत्या करने की दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं इन सबका जिम्मेदार कौन है? मानवाधिकार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

आचार्य रामकुमार बघेल, पलवल

स्थानीय संस्कृति को बचाने की कवायद

यह पत्र 'नागरिकता विधेयक' के संदर्भ में है। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जैसा माहौल खड़ा किया गया वह वोट बैंक की राजनीति से ओतप्रोत है। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको अपनी सोच बड़ी और सही करने की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं। वहां के मुसलमानों को भारत में रियायत देने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। इसके अतिरिक्त अन्य धर्म के लोग जो 2014 के पहले से भारत में आकर बस गए हैं उनको कैसे भारत की नागरिकता देनी है यह विधेयक उसके संदर्भ में है। अवैध तरीके से बांग्लादेश से आए लोगों ने असम के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का नक्शा ही बदल दिया है। स्थानीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस पर कदम उठाने का समय आ गया है।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

230 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तार है राजस्थान में सांभर झील का, जबकि इसका जलग्रहण क्षेत्र करीब 4,700 वर्ग किमी में फैला है। इस झील का दायरा राजस्थान के तीन जिलों की सीमा तक है।

आजकल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

अस्तित्व में आता नागरिकता निर्धारण कानून

नागरिकता (संशोधन) विधेयक के कानूनी रूप में आ जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान होगा। इसमें प्रवासी मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत में घुसपैठियों के रूप में आसान आजीविका के संसाधन प्राप्त करने के लिए आए हैं। जबकि अन्य धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक होने के कारण प्रताड़ित कर पलायन को मजबूर किया गया। ऐसे में इन तीनों देशों के मुस्लिम प्रवासियों को इस व्यवस्था से वंचित रखना अनुचित नहीं कहा जा सकता है

संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह। फाइल फोटो

नागरिकता (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां सरकार की असल परीक्षा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध के बीच कहा, 'विधेयक अल्पसंख्यकों की बजाय घुसपैठियों के खिलाफ है। यह संविधान के किसी भी अनुच्छेद की अवज्ञा नहीं करता है। ना ही यह धर्म के परिप्रेक्ष्य में भेदभाव करता है। देश के मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने की कोशिश इस कानून के जरिये नहीं की गई है।'

गृह मंत्री ने कांग्रेस को इस मामले पर जवाब देते हुए कहा, 'धर्म के आधार पर देश का विभाजन तो कांग्रेस ने किया था। इस विभाजन को खत्म करने के लिए 130 करोड़ लोगों के हित संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है।' मालूम हो कि यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा। लोक-संपदा व संस्कृति के संरक्षण के लिए मणिपुर को ईनर लाइन परमिट में शामिल किया गया है। इसके बावजूद विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है जिसके लिए वहां के निहित स्वार्थी तत्व जिम्मेदार हैं।

किसे दी जाए भारत की नागरिकता, तय कर सकती है केंद्र सरकार : यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया गया है। इसमें अनेक नए प्राविधान किए गए हैं। दरअसल विपक्षी दल धर्म और पंथनिरपेक्ष आधार पर भेदभाव के रूप में नागरिकता विधेयक की आलोचना कर रहे हैं। इसमें श्रीलंका और नेपाल के घुसपैठिये मुस्लिमों को भी शामिल करने की मांग उठ रही है। खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1971 में जब इंदिरा गांधी के प्रयास से बांग्लादेश वजूद में आया था, तब बांग्लादेश से आए लोगों को तो नागरिकता दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान से आए लोगों को नहीं दी गई थी। लिहाजा देश किसे नागरिकता दे और किसे नहीं दे, यह संविधान सम्मत है। इस नाते समानता का सिद्धांत उन्हीं पर लागू हो सकता है, जिन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास सुरक्षित है कि वह किसे शरण दे और किसे भारतीय नागरिकता प्रदान करे। गोया, इस विधेयक पर वोट या तुष्टिकरण की राजनीति करना देशहित में कतई नहीं है।

दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऐसे मुस्लिम बहुल देश हैं, जिनमें गैर-मुस्लिम नागरिकों पर अत्याचार और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं। चूंकि ये देश एक समय अखंड भारत का हिस्सा थे, इसलिए इन तीनों देशों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी बड़ी संख्या में रहते थे। वर्ष 1947 में जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान नया देश बना था, तब वहां लगभग 20 प्रतिशत गैर-मुस्लिमों की आबादी थी, जो अब घटकर दो प्रतिशत रह गई है। पाकिस्तान से अलग होकर जब बांग्लादेश वजूद में आया था, तब वहां बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति संग्राम के जवानों ने गैर-मुस्लिम स्त्री व पुरुषों के साथ ऐसे दुराचार व अत्याचार किए कि वे भारत की ओर पलायन करने को मजबूर हुए। बांग्लादेश के समाजशास्त्री इस्माइल सादिक, रॉबिन डिसूजा व पुरंदर देवरॉय बहुत पहले लिख चुके हैं कि 'वहां के समाज का बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यकों की आजादी को पसंद नहीं करता है। इन समुदायों के पर्व-त्योहारों पर वह इसलिए आक्रामक हो उठता है, ताकि वे अपने पर्वों को मनाने से डरें।'

अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने इस सदी के आरंभ में बामियान में बड़े-बड़े पहाड़ी चट्टानों को तराशकर बनाई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोप के गोलों से केवल इसलिए उड़ा दिया था, क्योंकि वे इतर धर्म से संबंध रखती थीं। इससे पता चलता है कि इन देशों में बहुसंख्यक धर्मावलंबी दूसरे धार्मिक समुदायों को पसंद नहीं करते हैं। इस मानसिकता के चलते ही इन देशों में यदि कोई उदार मुस्लिम नेता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता गैर-मुस्लिमों के प्रति थोड़ी-बहुत भी सहानुभूति जताता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है।

इन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने की दृष्टि से गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में घोषणा की है कि 'पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लागू करेंगे।' गृह मंत्री की यह घोषणा बेहद महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से बड़ी संख्या में मुस्लिम घुसपैठियों ने आकर देश में आजीविका के संसाधनों पर तो कब्जा कर लिया है। साथ ही देश के जनसंख्यात्मक घनत्व को बिगाड़ा है और पूर्वोत्तर राज्यों में मूल निवासियों के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। असम में कुछ समय पहले जारी एनआरसी सूची के बाद बवाल मचा हुआ है, क्योंकि यहां 19.6 लाख लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं आए। नतीजन अब इन्हें अपनी अपील पर न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई किए जाने का इंतजार है। दरअसल असम में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों का मसला राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को लंबे समय से झकझोर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी चुनौती : इसमें कोई दो राय नहीं कि विधेयक को लेकर सरकार के सामने पूर्वोत्तर भारत बड़ी चुनौती के रूप में पेश आ सकता है। क्योंकि इसके लोकसभा से पारित होने के साथ ही असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों व पश्चिम बंगाल में विरोध शुरू हो गया है। इस विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का कहना है कि सरकार ने उन्हें भरोसे में नहीं लिया। दरअसल भाजपा और असम गण परिषद को छोड़ यहां ज्यादातर राजनीतिक दल कांग्रेस और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में हैं। गोया, भाजपा जानती थी कि इनसे बातचीत का कोई अनुकूल अर्थ निकलने वाला नहीं था? ये दल यह भी कह रहे हैं कि इस विधेयक के जरिये भाजपा हिंदू वोट बैंक इस क्षेत्र में मजबूत करना चाहती है। लेकिन समझा जा रहा है कि भाजपा की मंशा यह है कि एनआरसी में जो 19 लाख से ज्यादा लोग छूट गए हैं, उनमें 12 लाख बंगाली हिंदू हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद ये भारतीय नागरिक बन जाएंगे। इससे शरणार्थी और अवैध प्रवासियों की स्थिति में बदलाव आएगा।

अमेरिकी आयोग का अनावश्यक दखल

रामहित नंदन

यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआइआरएफ) ने भारतीय लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होते ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयोग का कहना है, 'इस विधेयक में प्रवासियों की नागरिकता के लिए जो रास्ता चुना गया है वह विशेष कर मुसलमानों को अलग करता है जिसे नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर तैयार किया गया है। यह गलत दिशा में उठाया गया खतरनाक कदम है। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष बहुलवाद और संविधान के खिलाफ है जो धर्म से परे हर व्यक्ति को कानून के सामने समान मानता है। भारत सरकार देश की नागरिकता के लिए एक ऐसा पैमाना तैयार कर रही है जो लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा।'

हालांकि इस आयोग की सिफारिशें अमेरिकी सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन लोकसभा में नागरिकता विधेयक के पारित होते ही आयोग द्वारा भारत के गृह मंत्री और 'प्रमुख नेताओं' पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देना भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के समान है। 'प्रमुख नेतृत्व' से इस आयोग का क्या आशय है? आयोग की इस रिपोर्ट के बारे में नरेंद्र मोदी सरकार और उससे पहले की मनमोहन सिंह सरकार का भी मत रहा है कि किसी भी विदेशी ताकत को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। जिस त्वरित गति से इस अमेरिकी आयोग ने प्रतिक्रिया या कहें चेतावनी दी है, उससे यह जरूरी हो गया है कि इसके पीछे बैठी ताकतों को उजागर किया जाए। आखिर यह है क्या? इसमें कौन लोग बैठे हैं? यूएससीआइआरएफ असल में अमेरिकी सरकार की एक संस्था है जिसका निर्माण इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, 1998 के तहत किया गया है। इसमें दस सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदनों के नेताओं द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष तिब्बती मूल के तेनजिन दोरजी हैं। इसमें वामपंथी और ईसाई सदस्यों की भरमार है। इसकी सदस्य और भारतीय मूल की महिला अरूणिमा भार्गव का उल्लेख करना यहां पर जरूरी है जो वामपंथी रुझानों वाली एक संस्था 'एंथम ऑफ अस' की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये वामपंथी विचारों वाले 'द ट्रूमैन नेशनल सिक्योरिटी प्रॉजेक्ट' नामक थिंक टैंक की सदस्य रह चुकी हैं। वैसे इस थिंक टैंक को डेमोक्रेटिक पार्टी का पिछलग्गू माना जाता है।

यूएससीआइआरएफ में अरूणिमा भार्गव की नियुक्ति तेनजिन दोरजी की सिफारिश पर सदन की नेता नैंसी पेलोसी ने की है। नैंसी पेलोसी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं और अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं। उनकी नियुक्ति करते समय तेनजिन दोरजी ने जो वक्तव्य जारी किया उसके अनुसार, 'एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि व अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की वकालत के प्रति मुखर समर्थन के साथ अरूणिमा आयोग के काम में महत्वपूर्ण नया आयाम जोड़ेंगी जो आयोग के काम को बेहतर बनाएगा, खास तौर से लोकतांत्रिक भारत को लेकर जिसके साथ अमेरिका का दीर्घकालिक और गौरवशाली रिश्ता है।'

भारत सरकार भले ही यूएससीआइआरएफ के वक्तव्य को यह कह कर नकार दे कि वह किसी भी बाहरी संस्था का अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन उसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बाहरी तत्व ही नहीं अंदरूनी लोग भी शामिल हैं। इस आयोग में कट्टर ईसाइयों का अच्छा खासा वर्चस्व है। आश्चर्य नहीं कि ये मुसलमानों के हितों की रक्षा का बहाना बना कर 'हिंदूवादी' के तौर पर प्रचारित की गई नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे और उसे नुकसान पहुंचाने की हरसंभव कोशिश करेंगे। भारत सरकार भले ही कूटनीतिक अनुशासन के कारण शायद अमेरिकी वामपंथियों को आईना ना दिखा सके, लेकिन एक भारतीय नागरिक के नाते हम तो कह ही सकते हैं कि भारत पर उंगली उठाने से पहले ये लोग अपने भीतर भी झांक कर देखें। पहले वहां जो रंग भेद और नस्लीय घृणा फैली है, उसे समाप्त करें, फिर भारत पर उंगली उठाएं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

खरी-खरी

मंदी खोजन मैं चला..!

डॉ. पिलकेंद्र अरोरा

मंदी का शोर सुन मुझसे रहा न गया और एक दिन मैं मंदी की खोज में निकल पड़ा। सोचा, क्यों न पहले अभियान की सफलता के लिए देवदर्शन कर, आशीर्वाद प्राप्त करूं। मंदिर पहुंचा तो देखा वहां नवनिर्माण जारी था। फर्श पर मार्बल और ऊपर स्वर्ण शिखर लगाए जा रहे थे। कन्फर्म हो गया कि भगवान के दरबार में तो मंदी का सवाल ही नहीं! दर्शन कर बाहर निकला तो लड्डू का प्रसाद बांटते हुए पड़ोसी डॉ. गुप्ता मिल गए। बोले, कल ही नई मर्सडीज गाड़ी ली है। तुम भी लो शुद्ध घी का है। मुझे लगा कि गुप्ताजी से मंदी-चर्चा ठीक नहीं! प्रसाद ग्रहण कर मैं आगे बढ़ गया!

पहली बार शहर को एक खोजी दृष्टि से देखा। बदला-बदला नजर आया। जहां पुरानी इमारतें थीं, वहां बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे। सड़कों पर साइकिलें कम और नए ब्रांड के दोपहिया-चौपहिया दौड़ रहे थे। जहां पुरानी सराय थी, वहां आलीशान होटल दिखा। बाहर काफी भीड़ थी। पता चला, वे ग्राहक हैं। अंदर हॉल फुल है और वे वेटिंग में बेहाल खड़े हैं। कहीं मंदी इस भीड़ में तो नहीं छुपी है? पर निराश हुआ। कदम आगे बढ़ाए, जो एक चाय की दुकान पर स्मार्ट युवक-युवतियों का झुंड देख ठिठक गए। सोचा क्यों न एकाध कट मैं भी मारूं और उनकी बातचीत सुनूं, ताकि किसी युवा-मंदी का कोई सुराग मिले। दुकान पर पहुंचा और बोला- आधी कप चाय देना भाई!

उसने छूटते ही कहा- यहां आधी कप नहीं मिलती! पूरी मिलती है। ये रहा मीनू! उसने (हिकारत से) कहा।

मीनू देख मेरे होश फाख्ता! अलग-अलग फ्लेवर की 30 से 40 रुपये तक की चाय! अपन तो हक्का-बक्का रह गए! अपन ने तो अब तक रुपये वाली चाय ही पी है। मैंने चाय पीने का इरादा बदल दिया और वहां से निकल लिया।

हाट बाजार पहुंचा, मगर वहां तो हाट की जगह ब्रांडेड चीजों का मॉल था। सुना था, मॉल में सब मिलता है तो मंदी भी मिल जाएगी। इस भरोसे के साथ वहां गया। पांव रखने की जगह नहीं। जगमगाते शोरूम! झिलमिलाते स्टोर्स! डिजाइनर वस्त्रों में लोग, जिन्हें जेन्ट्री कहने का रिवाज है, एक्सीलेटर्स से ऊपर-नीचे हो रहे थे! भव्यता देख मेरी सांसें भी एक्सीलेटर हो गईं। लंबी कतार देख पूछा! पता चला फिल्म की लाइन है, 200 रुपये की टिकट है। टिकट के दाम सुन मैं मॉल से बाहर निकल गया। मंदी-खोज अभियान फ्लॉप हो गया था। मैं अब घर की ओर निकल रहा था।

ट्वीट-ट्वीट

शिवसेना का नया ढकोसला। सरकार से नागरिकता बिल पर स्पष्टता मांगी। बिल की कॉपी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। खुद पढ़िए। जो गलत है उसे गलत कहिए। अच्छा लगे तो अच्छा कहिए। ऐसा लगता है मन में कुछ है, और जुबान पर कुछ और।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

नागरिकता संशोधन बिल उनके लिए है जो किसी 'धार्मिक देश' में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में मुस्लिमों का धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं होता, क्योंकि वे वहां बहुसंख्यक हैं। वैसे भी मुस्लिम पहले की तरह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। कानूनी रास्ते से यहां सबका स्वागत है।

अदनान सामी@AdnanSamiLive

यदि नागरिकता संशोधन बिल पड़ोस में धार्मिक आधार पर पीड़ित लोगों के लिए है तो इसमें हमारे नौ पड़ोसी देशों में से सिर्फ तीन का ही नाम क्यों है?

सुहासिनी हैदर@suhasinih

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या लोकसभा और विधानसभाओं में एससी-एसटी के साथ एंग्लो इंडियन के लिए भी आरक्षण जारी रहना चाहिए?

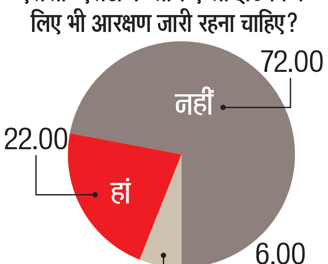

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कुछ विपक्षी दलों द्वारा यह कहना सही है कि नागरिकता संशोधन बिल संविधान विरोधी है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ऐरे–गैरे बस गए कहां–कहां से आय,
उनकी खातिर बन गया भारत एक सराय।
भारत एक सराय बढ़ाएं वे आबादी,
और नागरिक मूल झेलते हैं बर्बादी।
जब बनता कानून कि छोड़ें देश लखेड़े,
करने लगें विरोध यहां तब ऐरे–गैरे!

– ओमप्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

आलोक मिश्रा
राज्य संपादक, नई दुनिया, छत्तीसगढ़

लगता है वाकई तनाव है छत्तीसगढ़ में

देश में प्याज के ठाठ, हैदराबाद में मुठभेड़, उन्नाव कांड, झारखंड के चुनाव, मंदी की बहस के बीच छत्तीसगढ़ भी खासी चर्चा में आ गया है। नक्सलियों से मुकाबले के लिए तैनात जवानों की बंदूकें उन पर चलने के बजाए अपनों पर चल रही हैं। सप्ताह भर में तीन जगह गोलियां चलीं और छत्तीसगढ़ में तैनात नौ जवानों की जानें चली गईं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अपनों पर इस तरह गोलियां चल चुकी हैं जिसकी वजह है तनाव। तनाव इनमें ही नहीं है। यह इस समय हर जगह दिख रहा है। सरकार के लिए अभी धान तनाव है। कांग्रेस व भाजपा के लिए निकाय चुनाव तनाव है और जनता में इनके तनाव से तनाव है।

नारायणपुर शहर से 30 किमी दूर नक्सली क्षेत्र कड़ेनार में चार दिसंबर की सुबह अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आसपास के आदिवासी सहम गए यह सोचकर कि कहीं नक्सली हमला हुआ है। थोड़ी देर में साफ हो गया कि गोलियां चली हैं इंडो-तिब्बत सीमा बल के कैंप में जिसमें एक जवान ने साथी की एके-47 छीनकर पांच जवानों को मार डाला। वह भी जिंदा नहीं बचा। पहले बात आई कि उसने खुद को गोली मार ली, लेकिन सीने व कमर में लगी गोलियों ने बताया कि खुद मारना संभव नहीं। हालांकि अधिकारी यह कहकर अभी बोलने से बच रहे हैं कि यह जांच में ही स्पष्ट हो सकेगा। इस तड़तड़ाहट की गूंज थोड़ी ही देर में देश भर में सुनाई दे गई। लेकिन यह गूंज अभी थम भी नहीं पाई थी कि झारखंड चुनाव कराने गई कांकेर जिले में तैनात सीएएफ की 10वीं बटालियन के एक जवान ने सोमवार को सुबह-सुबह अपने कमांडर को गोली मार दी और खुद को भी। जवान इतने गुस्से में था कि 20 गोलियों से भरी मैग्जीन खाली कर दी। दूसरी घटना ने सभी को हैरान कर दिया, लेकिन यहीं बस नहीं

नारायणपुर में घटनास्थल का निरीक्षण करते आइटीबीपी के अधिकारी। फाइल फोटो

हुआ। दोपहर को दंतेवाड़ा में बस में सवार होकर आ रहे जवान जब एक होटल पर रुके तो एक ने अपनी बंदूक खुद पर ही चलाकर जान दे दी। इन घटनाओं की वजह उनमें व्याप्त तनाव के रूप में सामने आ रही है। परिवार से दूर जंगली जीवन, कम संख्या होने के कारण छुट्टियों के लिए तरसना और रूखा व्यवहार ऐसे कदम उठाने को मजबूर कर रहा है। इसे दूर करने के लिए माहौल बनाने की भी कोशिश जारी है, लेकिन इन घटनाओं ने बता दिया कि वह नाकाफी है।

इधर गांवों में धान की खरीदी और शहर में निकाय चुनाव भी तनाव का कारण बने हुए हैं। ढाई हजार रुपये में धान खरीदी का नारा देकर सत्ता में आई कांग्रेस के लिए यह वादा ही दिक्कत का कारण बन गया है। मोदी साथ दे नहीं रहे और बेहतर दाम देख कोटा अलग बढ़ गया। बची रकम बाद में देने का आश्वासन देकर केंद्र के मूल्य पर लेट धान खरीदी शुरू हुई तो भीड़ के आगे व्यवस्था चरमरा गई। प्रतिदिन खरीद का कोटा कम किया गया और लाइन लगवा दी गई। टोकन बांटे गए जो डेढ़ महीने बाद की तारीख तक चले गए। परिणति, कहीं चक्का जाम तो कहीं खरीद केंद्र पर किसानों ने जड़ दिया ताला। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने में जुटी है जबकि भूपेश हालात संभालने में। खुद कमान थामे किसानों को समझाने में तो वह जुटे ही हैं, केंद्र के अड़ियल रवैया को निशाना भी बनाए हैं और मुख्य सचिव सहित अधिकारियों को हालात संभालने दौड़ाए भी हैं।

सरकार और विपक्ष अगर धान में उलझा है तो निकाय चुनाव में दल उलझ गए हैं। लोकसभा और विधानसभा में जो माथापच्ची नहीं हुई, वह इस चुनाव में सभी झेल रहे हैं। पहले टिकट को लेकर आफत, एक अनार और सौ बीमार वाला हाल। कांग्रेस हो या भाजपा दोनों के लिए नाम फाइनल करना पापड़ बेलना जैसा हो गया। किसी तरह नामांकन के आखिरी दिन भोर तक सूची फाइनल की। जिसका नाम दिखा वह खुश, जिसे नहीं मिला वह बागी हो गया। वार्ड का चुनाव है, जिसकी अहमियत दल भी जानते हैं। वे जानते हैं कि अगर बागी मैदान में रहे तो इसमें चुनाव चिन्ह तो नैया पार लगाने से रहा। इसलिए शुरू हुई बागियों को मनाने की कोशिश, जो अभी तक जारी है। नाम वापसी की तिथि निकल गई है। कुछ तो मान गए हैं लेकिन अधिकांश डटे हैं। दल इस आस में हैं कि चलो मैदान में भले ही रहें, अंत तक समर्थन हासिल कर ही लिया जाएगा। इस बीच कुछ को टिकट थमाने के बाद छीना भी गया, वे अलग कलप रहे हैं। इससे भी माहौल में तनाव का रंग छाया है। दिसंबर बीत रहा है, लेकिन ठंड का नामोनिशान नहीं हैं। इसमें अगर देखा जाए तो मौसम की कम तनाव की भूमिका ज्यादा है।

चिंताजनक

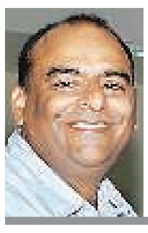

पंकज चतुर्वेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रवासी पक्षियों के लिए काल बनती सांभर

राजस्थान के तीन जिलों में विस्तृत सांभर झील में 25 हजार से अधिक पक्षियों की मौत चिंता का विषय है। प्राकृतिक संतुलन और जीवन–चक्र में प्रवासी पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका इस तरह से मारा जाना अनिष्टकारी है

वे हजारों किमी दूर से जीवन की उम्मीद के साथ यहां आए थे, क्योंकि उनकी पिछली कई पुश्तें सदियों से इस मौसम में यहां आती थीं। इस बार वे जैसे ही इस खारे पानी की झील पर बसे, उनके पैरों और पंखों ने काम करना बंद कर दिया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में उनकी लाशें बिछने लगीं। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहे जाने वाली राजस्थान की सांभर झील में पिछले डेढ़ माह में 25 हजार से ज्यादा प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं। शुरू में तो पक्षियों की मौत पर ध्यान ही नहीं गया, लेकिन जब हजारों लाशें दिखीं, और दूर-दूर से पक्षी विशेषज्ञ आने लगे तब यह पता चला कि उनके प्राकृतिक पर्यावास में लगातार हो रही छेड़छाड़ व बहुत कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है।

हर वर्ष भारत आने वाले पक्षियों में साइबेरिया से पिनटेल डक, शोवलर, डक, कॉमनटील, डेल चिक, मेलर्ड, पेचर्ड, गारगेनी टेल तो उत्तर-पूर्व और मध्य एशिया से पोचर्ड, कॉमन सैंड पाइपर के साथ-साथ फ्लेमिंगो जैसे कई पक्षी आते हैं। भारतीय पक्षियों में शिकरा, हरियल कबूतर, दर्जिन चिड़िया आदि प्रमुख हैं। यात्रा के दौरान पक्षी अपने हिसाब से उड़ते हैं और उनकी ऊंचाई भी अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं।

सांभर झील कभी समुद्र का हिस्सा था। धरती में हुए लगातार परिवर्तनों से रेगिस्तान विकसित हुए और इसी क्रम में भारत की सबसे विशाल खारे पानी की झील 'सांभर' अस्तित्व में आई। यह झील करीब 230 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है, जबकि इसका जलग्रहण क्षेत्र इससे कई गुना अधिक है। अरावली पर्वतमाला की आड़ में स्थित यह झील राजस्थान के तीन जिलों- जयपुर, अजमेर और नागौर तक विस्तारित है। भले ही इस झील का अतंरराष्ट्रीय महत्व हो, लेकिन समय की मार इस झील पर भी पड़ी। वर्ष 1996 में 5,700 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र वाली यह झील 2014 में 4,700 वर्ग किमी में सिमट गई। चूंकि यहां पर बड़ी मात्रा में नमक उत्पादन किया जाता है, लिहाजा नमक माफिया भी यहां की जमीन पर कब्जा करता रहता है। इस विशाल झील के पानी में खारेपन का संतुलन बना रहे, इसके लिए इसमें मैया, रूपनगढ़, खारी, खंडेला जैसी छोटी नदियों से मीठा पानी लगातार मिलता रहता है तो उत्तर में कांतली, पूर्व में बांदी, दक्षिण में मासी और पश्चिम में लूनी नदी में इससे बाहर निकला पानी जाता रहा है।

प्रतीकात्मक

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवंबर के शुरू में सांभर झील में विदेशी पक्षियों के झुंड आने शुरू हो गए। वे नए परिवेश में खुद को व्यवस्थित कर पाते, उससे पहले ही उनकी गर्दन लटकने लगी। वे ना तो चल पा रहे थे और ना उड़ पा रहे थे। लकवा जैसी बीमारी से ग्रस्त पक्षी तेजी से मरने लगे। जब तक प्रशासन चेतता दस हजार से अधिक पक्षी मारे जा चुके थे। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की टीम सबसे पहले पहुंची। फिर एनआइएचएसएडी यानी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइ सिक्योरिटी नेशनल डिजीज भोपाल का दल आया व उसने सुनिश्चित किया कि ये मौतें बर्ड फ्लू के कारण नहीं हैं।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) बरेली के दल ने जांच कर बताया कि मौत का कारण 'एवियन बॉट्यूलिज्म' नामक बीमारी है। यह बीमारी क्लोस्ट्रिडियम बॉट्यूलिज्म नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। यह बीमारी आमतौर पर मांसाहारी पक्षियों को होती है। इसके बैक्टीरिया से ग्रस्त मछली खाने या इस बीमारी का शिकार हो कर मारे गए पक्षियों का मांस खाने से इसका विस्तार होता है। मारे गए सभी पक्षी मांसाहारी प्रजाति के थे।

हालांकि अधिकांश पक्षी वैज्ञानिकों की राय में पक्षियों के मरने का कारण एवियन बॉट्यूलिज्म ही है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इसके पीछे 'हाईपर न्यूट्रिनिया' को भी मानते हैं। नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने पर पक्षियों के तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वे खानापीना छोड़ देते हैं व उनके पंख और पैर में लकवा हो जाता है। कमजोरी के चलते उनके प्राण निकल जाते हैं।

सांभर झील लंबे समय से लापरवाही का शिकार रही है। यहां नमक निकालने के ठेके कई कंपनियों को दिए गए हैं। ये मानकों की परवाह किए बगैर गहरे कुएं और झील के किनारे दूर तक नमकीन पानी एकत्र करने की खाई बना रहे हैं। फिर परिशोधन के बाद गंदगी को इसी में डाल दिया जाता है। विशाल झील को छूने वाले किसी भी नगर-कस्बे में घरों से निकलने वाले गंदे पानी को परिशोधित करने की व्यवस्था नहीं है और हजारों लीटर गंदा-रासायनिक पानी हर दिन इस झील में मिल रहा है। इस साल औसत से करीब 46 फीसद ज्यादा पानी बरसा। इससे झील के जल ग्रहण क्षेत्र का विस्तार हो गया। झील में नदियों से मीठे पानी की आवक और अतिरिक्त खारे पानी को नदियों में मिलने वाले मार्गों पर अतिक्रमण हो गए हैं, सो पानी में क्षारीयता का स्तर नैसर्गिक नहीं रह पाया। भारी बरसात के बाद यहां तापमान फिर से 27 डिग्री के पार चला गया। इससे पानी का क्षेत्र सिकुड़ गया व उसमें नमक की मात्रा बढ़ गई जिसका असर झील के जलचरों पर पड़ा। हो सकता है कि इस कारण मरी मछलियों को पक्षियों ने खा लिया हो व उससे उन्हें एवियन बॉट्यूलिज्म हो गया हो। वैसे आइवीआरआइ की जांच में अच्छी बरसात के चलते पानी में नमक घटने व पानी में ऑक्सीजन की मात्रा महज चार मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम रह जाने के चलते यह त्रासदी उपजने की बात कही गई है।

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पक्षी अपने पर्यावास में अत्यधिक मानव दखल, प्रदूषण, भोजन के अभाव से भी परेशान है। लिहाजा प्रवासी पक्षियों की घटती संख्या हमारे लिए भी चिंता का विषय है।

14 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश कैबिनिट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के चलते उठाया गया है। एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत 1.25 करोड़ रुपये होगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 11 दिसंबर 2019

डाटागीरी

बीते महीनों में बढ़ी हैं हवाई यात्रियों की परेशानियां

फ्लाइट के रद होने, लेट होने या ऐन मौके पर बोर्डिंग से रोके जाने से यात्रियों को तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हाल के महीनों में इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। इस वर्ष मई से अक्टूबर तक करीब 10,000 ऐसे यात्री रहे जिन्हें बोर्डिंग से वंचित रखा गया। साथ ही फ्लाइट रद होने से प्रत्येक माह 15 से 48 हजार यात्रियों को परेशान होना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से ये बाते सामने आई हैं।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

इस साल मई से अक्टूबर के बीच 10,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न एयरलाइनों द्वारा बोर्डिंग से वंचित रखा गया। ये मामले सबसे ज्यादा जून में सामने आए। जून में 3,834 यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित किया गया। इसी अवधि के दौरान फ्लाइट रद होने से 15000 से 48000 यात्री प्रत्येक महीने प्रभावित हुए, जबकि फ्लाइट में दो घंटे या उससे अधिक समय की देरी होने से प्रत्येक माह 1.2 लाख से 2.5 लाख यात्री प्रभावित हुए।

ये आंकड़े नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बीते दिनों संसद में दो अलग-अलग सवालों के जवाब में उपलब्ध कराए गए थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा बताया गया है कि जब किसी यात्री को बोर्डिंग से वंचित किया जाता है और उसे एक घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान का विकल्प नहीं दिया जाता है तो एयरलाइन को यात्री की परिस्थिति को देख 10,000 से 20,000 रुपये का भुगतान करना होता है।

उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि सितंबर और अक्टूबर में 2100 यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित रखा गया, जिसमें से 1400 के लिए एयर इंडिया जिम्मेदार थी। इन छह महीनों में फ्लाइट रद होने के कारण प्रभावित यात्रियों की अधिकतम संख्या जुलाई में 48,272 थी, जिसमें दो घंटे से ज्यादा फ्लाइट लेट होने से प्रभावित होने वाले यात्रियों की संख्या 2.5 लाख थी। सितंबर और अक्टूबर दोनों माह में कुल 49,000 यात्रियों को फ्लाइट रद होने की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इसमें 20,000 से अधिक इंडिगो के यात्री थे।

प्रतीकात्मक

फ्लाइट रद होने से प्रभावित यात्री

एयर लाइन	यात्री	
	सितंबर	अक्टूबर
एयर इंडिया	3,050	6,485
पवन हंस	9	9
स्पाइसजेट	4,723	6,885
गो एयर	345	106
इंडिगो	11,366	9,526
एयर एशिया	345	1,176
विस्तारा	488	465
स्टार एयर	187	57
ट्रुजेट	2826	980
एयर डेक्कन	2	10
एयर हेरिटेज	-	77
कुल	23,341	25,776

बोर्डिंग से वंचित करने वाली एयरलाइन

एयरलाइन	सितंबर 2019		अक्टूबर 2019	
	यात्री	सुविधाएं और मुआवजा (लाख में)	यात्री	सुविधाएं और मुआवजा (लाख में)
एयर इंडिया	582	26.14	822	37.51
स्पाइसजेट	347	10.6	226	6.50
इंडिगो	17	1.40	35	2.68
एयर एशिया	12	0.43	14	0.33
विस्तारा	2	0.03	5	0.30
ट्रुजेट	17	1.05	-	-
एयर हेरिटेज	33	0.18	-	-
कुल	1,010	39.29	1,102	47.32

लोहा नगरी की बदली आबोहवा मिटा प्रदूषित शहर होने का दाग

रंग लाए प्रयास ▸ अब रोजाना हवा में नहीं घुलती एक हजार क्विंटल जहरीली गर्द

खन्ना और मंडी गोबिंदगढ़ की 92 में से 88 लोहा भट्ठी में लगे हवा प्रदूषण कंट्रोल यंत्र ने काले धुएं से दिलाई निजात

धरमिंदर सिंह, फतेहगढ़ साहिब

करीब चार साल पहले भारत की प्रसिद्ध लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ पर सबसे प्रदूषित शहर होने का दाग लगा। दुनिया के टॉप 25 शहरों में यह शहर 22वें स्थान पर रहा। इससे सटे एशिया की सबसे प्रसिद्ध अनाज मंडी का शहर खन्ना 16वें स्थान पर था। इन दोनों शहरों का सबसे प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण यहां की इंडस्ट्री थी, जो इन्हें 24 घंटे काले धुएं के बादलों में लपेटकर रखती थी। अब दिनों-दिन हुए प्रयासों से लोहा नगरी ने सबसे प्रदूषित शहर होने का दाग मिटा लिया। मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना में लगी करीब 92 लोहा भट्ठी यूनिट में से 88 लोहा भट्ठी में हवा प्रदूषण कंट्रोल यंत्र (साइड हुड) लग चुके हैं। इसी का नतीजा है कि मंडी गोबिंदगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) इस वर्ष औसतन 200 से 225 तक रहा। गत वर्ष का एक्यूआइ 300 से 325 तक रहा था। करीब 88 लोहा भट्ठी में 32 से 35 लाख रुपये का यंत्र साइड हुड लगा है। इससे मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना की लोहा भट्ठी से हवा में घुलने वाली रोजाना करीब एक हजार क्विंटल जहरीली गर्द से छुटकारा मिला है।

साइड हुड का ये फायदा : पहले प्रत्येक लोहा भट्टी की भट्ठी में जलने वाले ईंधन की 20 से 25 किलो जहरीली राख ही इकट्ठी होती थी। बाकी की राख गर्द के रूप में हवा में घुल जाती थी। साइड हुड लगने के बाद एक लोहा भट्ठी के अंदर करीब 125 किलो राख इकट्ठी हो जाती है। इसी कारण एक्यूआइ में एक तिहाई गिरावट दर्ज की गई है।

25 फीसद लोहा भट्टी इकाइयां भी हुईं बंद : मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना में पहले सवा सौ से अधिक लोहा भट्ठी इकाइयां होती थीं। शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के मकसद से इकाइयों पर शिकंजा कसा गया। बिजली के बढ़े दामों और टैक्सों की मार ने करीब 25 फीसदी फर्नेंस इकाइयां बंद हो गईं।

20 हजार पौधे लगाए, 57 जगहों को किया पक्का : प्रदूषण का दाग मिटाने के लिए करीब डेढ़ वर्ष में 20 हजार के करीब पौधे लगाए गए। 57 ऐसी जगहों को ढूंढ़ा गया, जहां से दिनभर गर्द उड़ती रहती थी। जहां पर ट्रक खड़े किए जाते थे। इन जगहों को भी पक्का करके इलाके के लोगों को धूल के कणों से छुटकारा दिलाया गया।

वरदान साबित होगी पीएनजी : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का टारगेट अब रोलिंग मिल हैं। इन मिलों को 31 मार्च 2020 तक का समय दिया हुआ है। इसके बाद बिना पीएनजी (पाइपड नेचुरल गैस) कोई भी मिल नहीं चलेगी। इसके लागू होने के बाद शहर में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होगा।

मंडी गोबिंदगढ़ की एक फर्नेस में भट्ठी पर लगे साइड हुड पर काम करता मजदूर। साइड हुड के कारण राख इकट्ठी हो जाती है। पहले राख आसमान में उड़ जाती है, जिससे प्रदूषण फैलता था। जागरण

साइंस सिटी में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीके खोजेंगे वैज्ञानिक

हरनेक सिंह जैनपुरी, कपूरथला : पृथ्वी के लगातार बढ़ रहे तापमान और इसके कारण पर्यावरण में हो रहे बदलाव (ग्लोबल वार्मिंग) की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के करीब 45 साइंस सेंटरों के वैज्ञानिक साइंस सिटी कपूरथला में जुटेंगे। 13 से 15 दिसंबर तक साइंस सिटी कपूरथला में 19 वीं राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने और विज्ञान व तकनीक के प्रचार व प्रसार को बढ़ाने पर चर्चा होगी।

तीन दिवसीय कन्वेंशन में सभी साइंस सेंटरों के निदेशकों की ओर से व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि वह क्या कर रहे हैं। नई तकनीक क्या आई है। उनकी आगे की योजना क्या है। प्रदूषण के कारण बढ़ता तापमान दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। इस चुनौती से विज्ञान और तकनीक की मदद से कैसे बचा जा सकता है। देश में 65 साइंस सेंटर हैं। इनमें से करीब 45 के निदेशक इस कन्वेंशन में शामिल होंगे। कन्वेंशन में विशवरिया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम बेंगलुरू के निदेशक एसके मंडल गोपाल, मणिपुर साइंस सेंटर के निदेशक अलिंगडंम भाईबोचा सिंह, बिरला म्यूजियम पनाली के निदेशक डॉ. वीएन धौलाखंडी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम केरला के निदेशक जी अरुल ब्रिलाड प्रकाश और बिरला म्यूजियम कोलकाता के निदेशक एस चौधरी भी शामिल होंगे।

बिहार में आरटीआइ के जरिये पता कर रहे वर का स्टेटस, पति की सैलरी

दीनानाथ साहनी, पटना

शैक्षणिक योग्यता, पदनाम और तनख्वाह के बारे में सूचना का अधिकार के तहत मांगी जा रही जानकारी

2005 में जब सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम अस्तित्व में आया, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका उपयोग शादी से पहले वर का स्टेटस पता करने में होगा। यह रोचक ही है कि बिहार में बेटियों के पिता इस कानून के जरिये लड़कों (जिनसे विवाह की बात चल रही है) के चाल-चलन के अलावा क्रेडिट स्कोर के बारे में भी जानकारी मांग रहे हैं। हद तो यह है कि पति की सैलरी पता करने में पत्नियां इस कानून का सहारा ले रही हैं।

बिहार के कई महकमों के दफ्तरों में ऐसी अर्जियां पड़ीं हैं, जिनमें लड़के की शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, नौकरी के स्थायित्व व सैलरी का पता लगाने के लिए जानकारियां मांगी गई हैं। लोक सूचना पदाधिकारियों के मुताबिक, कई अर्जियां बेहद ही दिलचस्प होती हैं।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जिला प्रबंधक के रूप में पदस्थापित एक युवा की शादी रांची के एक कारोबारी परिवार में तय हुई है। लड़की के कारोबारी पिता ने वर की सैलरी, नौकरी स्थायी है या अस्थायी एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में आरटीआइ की अर्जी देकर जानकारी मांगी है। सवाल पूछा है कि एमबीए की डिग्री कहां की है। इसी तरह की कई अर्जियां शिक्षा विभाग में आई हैं, जिनमें लड़कों से जुड़ी कई जानकारियां मांगी गई हैं। भागलपुर के एक व्यक्ति ने आरटीआइ की अर्जी शिक्षा विभाग में दी है। पूछा है, लड़का नियोजित शिक्षक है पर उसका वेतन क्या है? भविष्य में उसे प्रोन्नति मिलेगी या नहीं, सैलरी बढ़ेगी या नहीं? इसी तरह सारण के एक कारोबारी ने अर्जी देकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के एक कॉलेज में कार्यरत लेखा पदाधिकारी के बारे में वेतन और उम्र के बारे में सूचना मांगी है। औरंगाबाद के एक व्यक्ति ने लड़के के व्यवहार के बारे में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जानकारी मांगी है, जबकि आरा के निवासी ने वर की सैलरी की सूचना मांगी है। एक सूचना अधिकारी ने बताया कि वर की आर्थिक हैसियत की सही सूचना पाने के लिए लड़की पक्ष द्वारा क्रेडिट इनफॉरमेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल) की मदद ली जा रही है। सिबिल की सहायता से किसी भी व्यक्ति के कर्ज का विस्तृत ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है।

60 फीसद को सूचना देने से इन्कार : इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आरटीआइ के जरिये 1423 लोगों ने सूचनाएं मांगीं। इनमें 645 मामलों में निजी जानकारियां मांगी गई थीं। इनमें 60 फीसद आवेदक को सूचना देने से इन्कार कर दिया गया।

विवाद की स्थिति में पत्नियां ले रहीं आरटीआइ का सहारा

आरटीआइ के जरिये पत्नियां भी पतियों की जानकारियां हासिल कर रही हैं। मसलन श्रम संसाधन विभाग में एक महिला ने आरटीआइ की अर्जी देकर पति को मिलने वाली पेंशन की जानकारी मांगी है। उसने पूछा है कि पति की पेंशन कितनी है और वह किस बैंक खाते में जाती है। दरअसल, यह मामला पति-पत्नी के बीच कोर्ट केस से जुड़ा है। एक अन्य महिला ने श्रम संसाधन विभाग में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि पति खर्च के लिए कुछ नहीं दे रहा है। उसे बताया जाए कि पति की सैलरी कितनी है? किस खाते में आती है?

रुपहले पर्दे पर खनन माफिया के खिलाफ गरजेंगी दुर्गा

धर्मेंद्र चंदेल, ग्रेटर नोएडा

वर्ष 2013 में खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बाद समूचे देश में चर्चा में आईं आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की कहानी अब रुपहले पर्दे पर दिखाई देगी। केसरी और बदला फिल्म के निर्माता सनीर खेत्रपाल दुर्गा शक्ति नागपाल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में दुर्गा शक्ति नागपाल की खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई को इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह राजनीतिक दबाव से जूझते हुए उन्होंने खनन माफिया के नेटवर्क पर प्रहार कर उसे ध्वस्त कर दिया था। दुर्गा शक्ति की इस कार्रवाई के बाद देशभर में अवैध खनन समाचार पत्रों एवं चैनलों की सुर्खियां बन गया था।

उत्तर प्रदेश में बालू और रेत का बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता रहा है। 22 जिलों में इसकी सीबीआइ जांच चल रही है। कई जिलों के डीएम खनन के आरोप के लपेटे में हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान 2013 में गौतमबुद्ध नगर में भी बड़े पैमाने पर बालू और रेत का खनन हुआ था। खनन माफिया का जिले में बोलबाला था। उसी दौरान आइएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति की गौतमबुद्ध नगर में एसडीएम के पद पर तैनाती हुई थी। उन्होंने आते ही खनन माफिया की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। एक-एक कर माफिया पर उनका डंडा चला। उनकी इस कार्रवाई ने अधिकारियों से लेकर राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी थी।

दुर्गा शक्ति नागपाल जागरण आर्काइव

लेडी सिंघम

- 2013 में उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में खनन माफिया पर चला था डंडा
- लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हुई थीं आइएएस दुर्गा शक्ति नागपाल

खनन का खेल रुका था, करवा दिया गया था निलंबित : दुर्गा शक्ति की सख्ती और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खनन के अवैध कारोबार पर उस वक्त लगाम लग गई। वहीं, दूसरी तरफ खनन का खेल रुकने से शासन में बैठे माफिया के करीबी नेता परेशान हो गए और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करवा दिया। सरकार का यह कदम उसके ही खिलाफ चला गया और पूरा देश दुर्गा शक्ति के समर्थन में खड़ा हो गया।

फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं

दुर्गा शक्ति रातों रात लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन गईं। मशहूर फिल्म निर्माता सनीर खेत्रपाल अब दुर्गा शक्ति नागपाल की खनन माफिया के खिलाफ इस कार्रवाई को रुपहले पर्दे पर उतारने जा रहे हैं। हालांकि, अभी फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका नाम दुर्गा शक्ति होगा। दुर्गा शक्ति नागपाल ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि गौतमबुद्ध नगर में अवैध खनन रोकना बड़ी चुनौती थी। बिना किसी दबाव के मैंने इस धंधे पर लगाम लगाकर माफिया को जेल भेजा। इस फिल्म को लेकर उत्साहित हूं।

ताजमहल में पर्यटकों की सुरक्षा करेगी वुडन रेलिंग

जागरण संवाददाता, आगरा : ताजमहल में पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य मकबरा पर वुडन रेलिंग लगाई जाएगी। इससे मुख्य मकबरा की संगमरमरी जाली के नजदीक जाकर नीचे झांकने पर रोक लग सकेगी। वर्तमान में यहां रस्सी बांधकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है।

ताजमहल में मुख्य मकबरा पर चारों ओर संगमरमरी जाली लगी हुई है। इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है। पर्यटक जाली के किनारे पर आकर नीचे की ओर झांकते हैं। इससे पर्यटकों के नीचे गिरने का खतरा रहता है। एएसआइ ने पर्यटकों को रोकने के लिए यहां पर जाली से पहले रस्सी बांधकर व्यवस्था की है। इसके बावजूद कई बार पर्यटक रस्सी क्रॉस कर जाली तक पहुंच जाते हैं। इसे देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने मुख्य मकबरा पर चारों तरफ संगमरमरी जाली से एक मीटर पहले वुडन रेलिंग लगाने को टेंडर जारी किया है।

इस पर करीब 35.31 लाख रुपये व्यय होंगे। मुख्य मकबरे के संगमरमरी फर्श से रेलिंग मिलती-जुलती नजर आए, इसीलिए मार्बल के ब्लॉक में साल की लकड़ी की बीम फिक्स की जाएंगी। बीम में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। वुडन रेलिंग पर्यटकों को संगमरमरी जाली के नजदीक जाने से रोकने में सहायक होगी। इसमें करीब तीन माह का समय लगेगा। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि ताज में पर्यटकों की सुरक्षा को वुडन रेलिंग लगाई जाएगी। इसका काम शीघ्र शुरू होगा।

पूर्व में भी लगाई जा चुकी हैं इसी तरह की रेलिंग

ताजमहल में पूर्व में भी इसी तरह वुडन रेलिंग लगाई जा चुकी हैं। मुख्य मकबरे में शहंशाह शाहजहां व मुमताज के कब्रों वाले कक्ष, पच्चीकारी को पर्यटकों को छूने से रोकने को मुख्य मकबरे की आर्च, चमेली फर्श पर पर्यटकों की लाइन लगाने की व्यवस्था को इसी तरह की रेलिंग लगाई जा चुकी हैं।

नैनीताल में खुला देश का पहला काई संरक्षण व शोध सेंटर

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी

- हिमालयी काई पर रिसर्च शुरू
- प्रदूषण इंडिकेटर के तौर पर है पहचान
- औषधीय गुणों से भी भरपूर काई प्रजाति

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद अहम माने जाने वाले काई और इसके विविध प्रजातियों पर किया जाएगा शोध। प्रतीकात्मक

नैनीताल में संरक्षण सेंटर बनाकर वन विभाग ने काई की प्रजातियों पर रिसर्च की शुरुआत की है। सबसे पुरानी वनस्पतियों में शामिल इस प्रजाति को आमतौर पर बेकार समझा जाता है, लेकिन पारिस्थितिकीय तंत्र में इसका खासा महत्व है। प्रदूषण का सबसे बड़ा इंडिकेटर मानी जानी वाली काई में एंटीसेप्टिक व एंटी बैक्टीरिया जैसे औषधीय गुण शामिल हैं। यह देश का पहला काई संरक्षण एवं शोध सेंटर है। वनाधिकारियों के मुताबिक, देश में पहली बार शुरू हुए शोध में हिमालयी काई प्रजातियों को भी शामिल किया जाएगा।

वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से एक ही प्रजाति की काई के रंग में बदलाव आ सकता है। औषधीय महत्व के कारण ही हिमालयी क्षेत्र पिंडारी में लोग चोट लगने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, किसी भी तरह का शोध नहीं होने के कारण इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं मिल सकी थी, जिस वजह से संरक्षण व शोध दोनों एक साथ शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे क्षेत्र में मिलने वाली प्रजातियों को ट्रांसप्लांट कर लाया गया है। मार्च तक बेसिक काम पूरा हो जाएगा। हालांकि, रिसर्च पूरे पांच साल तक चलेगा।

खुर्पाताल में एक हेक्टेयर में काम : कालाढूंगी रोड से नैनीताल की तरफ जाते वक्त शहर से ठीक पहले खुर्पाताल में एक हेक्टेयर जमीन पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सेंटर 1700-1800 मीटर ऊंचाई पर है। अनुसंधान सलाहकार समिति में प्रस्ताव पास होने पर कैंपा योजना के तहत काम किया जा रहा है।

धूल व चटक धूप से दिक्कत : वन अनुसंधान केंद्र के अफसरों के मुताबिक, काई को प्रदूषण का इंडिकेटर इसलिए माना जाता है, क्योंकि यह धूल व गंदगी के बीच नहीं पनपती। चटक धूप व सूखी पत्तियां इसे पनपने में दिक्कत करती हैं।

21 प्रजातियों का हो चुका संरक्षण : खुर्पाताल में शुरुआती दौर में 21 प्रजातियों का संरक्षण हो चुका है। इसमें होफिला, फिसीडेंस, फोलिया, ब्रोथरा, स्टीरियोफिलम, लिकोडन आदि शामिल हैं। लोगों को इनका महत्व पता चल सके, इसलिए हर प्रजाति का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

दुश्मन पर बरसने वाली गोलियां ले रही हैं अपनों की जान

नईदुनिया, रायपुर

दुश्मन पर बरसने वाली गोलियां इन दिनों अपनों की ही जानें ले रही हैं। सप्ताहभर में ऐसी तीन घटनाएं हुई हैं, जिनमें नौ जवानों की जान चली गई। इनमें दो घटनाएं साथियों को गोली मारने की है तो एक खुद को। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 12 वर्षों में करीब 150 से अधिक जवानों ने खुदकशी की है। जवानों की आत्महत्या की सर्वाधिक 36 मामले 2017 में हुए थे। इनमें राज्य पुलिस के 76 तथा अर्धसैनिक बलों के 39 जवान शामिल थे। वहीं, लगभग दो दर्जन से अधिक जवान साथियों की गोली से मारे गए।

जिन घटनाओं ने दहला दिया दिल : हाल में हुई ऐसी घटनाओं में पहली छह दिन पहले नारायणपुर जिले की है। आइटीबीपी के जवान ने अपने ही पांच साथियों को गोलियों से भून दिया और खुद को भी गोली मार ली। दूसरी और तीसरी घटना गत सोमवार को और दंतेवाड़ा में हुई। चुनाव ड्यूटी में रांची (झारखंड) गए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के एक जवान ने अपने अफसर को गोली मार दी। घटना में जवान की भी गोली लगने से मौत हो गई। इधर सोमवार दोपहर दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान 15 दिन की छुट्टी मनाकर लौटा था।

- एक हफ्ते में हुई तीन घटानाएं, गई नौ जवानों की जान
- 12 वर्ष में 150 से अधिक जवानों ने की खुदकशी
- मनोवैज्ञानिकों की राय, समय-समय पर जवानों की जांच और काउंसिलिंग होनी चाहिए

लंबे समय तक घरों से दूर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं जवान। प्रतीकात्मक

कोई व्यक्ति दो तरह की मनोस्थिति में आत्महत्या या हत्या जैसा घातक कदम उठाता है। एक होता है क्षणिक आवेश, जिसमें किसी तत्कालिक घटना की प्रतिक्रिया में ऐसा हो जाता है। दूसरा कारण है अवसाद या मानसिक बीमारी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जवान बेहद विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। महीनों परिवार से दूर रहते हैं। इन सबका असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ही तैनात जवान परिवार से दूर रहते हैं। सीमा पर तैनात जवान और दूसरी सर्विस के लोग भी महीनों परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। मेरी राय में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की दो-तीन महीने के अंतराल में जांच होनी चाहिए, जो संभवत: नहीं हो रही है। जांच के बाद आवश्यकता अनुसार काउंसिलिंग या उपचार किया जा सकता।

-डॉ. मनोज साहू, विभागाध्यक्ष मनोचिकित्सा विभाग डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल

तनाव और हालात बना रहे आक्रामक

जवानों खुदकशी के पीछे मुख्य रूप से तीन वजहें बताई जा रही हैं। इनमें घर-परिवार से दूरी और तैनाती क्षेत्रों के कठिन हालात शामिल हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार, खुदकशी की यह वजह हो सकती है, लेकिन दूसरों की हत्याएं असमान्य घटनाएं हैं। कोई भी ऐसा सामान्य स्थिति में नहीं कर सकता।

अनुशासन के नाम पर जुबान पर ताला

दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कुछ जवानों और अफसरों से फोन पर संपर्क किया और उनसे डिप्रेशन की वजह जानने का प्रयास किया। इनमें से कुछ ने तो बात टाल दी, लेकिन नाम न छापने की शर्त पर कई जवानों ने पूरे सिस्टम पर अपनी भड़ास निकाली। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों की शिकायत थी कि अनुशासन के नाम पर उनकी जुबान पर ताला लगा दिया जाता है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो समस्या बताने पर मजाक उड़ाते हैं या डांट कर भगा देते हैं। जवान कहते हैं कि फोर्स की पहचान अनुशासन है, इस वजह से अनुशासन रहना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर आवाज नहीं दबानी चाहिए। कई अधिकारी ऐसे हैं जो बड़े अफसरों से बात करने तक नहीं देते। साथ ही कई जवानों ने घर परिवार से जुड़ी कई तरह की समस्याएं भी गिनाईं।

काम से ज्यादा पारिवारिक तनाव वजह

नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल चुके राज्य पुलिस के एक आला अफसर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों और उनके कमांडिंग अफसरों को संयम बरतने की सलाह देते हैं। इस वरिष्ठ आइपीएस अफसर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के पीछे काम से ज्यादा पारिवारिक कारण जिम्मेदार होते हैं। फोर्स की जिम्मेदारी है, सभी को छुट्टी तो नहीं मिल सकती। ऐसे में छुट्टी नहीं मिलने के कारण घातक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। कमांडिंग अफसरों को भी संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जिसे वास्तव में छुट्टी की जरूरत हो, उसे स्वीकृति देनी चाहिए।

कुछ बड़ी घटनाएं

दिसंबर 2016 : भेच्ची थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ के 219वीं बटालियन के आरक्षक रोशन एक्का ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली। एक्का रांची के रहने वाले थे।

जनवरी 2017 : कांकेर जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथी को गोली मार दी। दोनों जवानों के बीच आपसी बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई थी।

मई 2018 : बस्तर में तैनात 222वीं बटालियन के जवान सुखविंदर सिंह ने खुद को गोली मार ली। वह पंजाब के रहने वाले थे।

सितंबर 2018 : सीआरपीएफ के जवान करण सिंह अपनी सर्विस रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले करण की खुदकशी की वजह पारिवारिक कारण बताई गई।

जून 2019 : बीजापुर में सीएएफ के एक आरक्षक ने अपने ही दो साथियों को गोली मार दी। दोनों ही आरक्षकों की मौके पर ही मौत हो गई।

15 से 54 आयुवर्ग में चार में से एक पुरुष (एक लाख में 23.2 प्रतिशत) किसी न किसी रूप में एनीमिया का शिकार है भारत में। यह बात 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

पहाड़ से पलायन रोकेगी हिमालयी उपज कुटकी

चंद्रशेखर द्विवेदी, बागेश्वर

- दर्जनभर गांवों में करीब पांच लाख पौधों का रोपण जगा रहा नई उम्मीद
- समूहों के माध्यम से भेषज संघ करा रहा कुटकी का उत्पादन
- बाजार में 500 से 800 रुपये प्रति किलो तक है कीमत

पलायन के चलते खाली हो रहे पहाड़ के गांवों के लिए हिमालयी उपज कुटकी बड़ी उम्मीद ला रही है। हिमालय से सटे उत्तराखंड के सीमांत बागेश्वर जनपद से कुटकी के बेहतर उत्पादन का सफल प्रयोग हो रहा है। यहां इस जड़ी के उत्पादन को उत्तराखंड भेषज संघ प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रहा है।

बागेश्वर जिले में कपकोट ब्लाक के मल्ला दानपुर क्षेत्र के बदियाकोट, तीख, सोरांग, कर्मी तोली, कीमू आदि गांवों की 203 नाली भूमि पर इस हिमालयी औषधीय उपज का उत्पादन शुरू हो रहा है। इस वर्ष इन गांवों में कुटकी के करीब पांच लाख पौधों का रोपण किया गया है। इसकी देखरेख का सारा काम स्वयं सहायता समूह हिमालयन जैविक कृषि उत्पादन, एकता, मां भगवती, अलखनाथ, महाकाली, जय मां संतोषी, गोलू देवता, शेरावाली आदि कर रहे हैं। कुटकी उत्पादन से गांवों के 208 लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तीन साल में उपज के लिए पर्याप्त बाजार भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। उत्पादन के लिहाज से अनुकूलता का आकलन हो जाने के बाद अब अन्य जगहों पर भी इस औषधीय पौध के उत्पादन के लिए योजना तैयार की जा रही है।

गरीबी उन्मूलन

चार हजार किलो उत्पादन का लक्ष्य : कुटकी बाजार में 500 से 800 रुपये प्रति किलो तक आसानी से बिक जाती है। जिन जगहों में इस वर्ष कुटकी की फसल लगाई गई है, वह 2022 तक बाजार में भेजने लायक हो जाएगी। 203 नाली भूमि पर करीब चार हजार किलो कुटकी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बाजार भाव के अनुसार 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार आसानी से हो जाएगा।

> हिमालय की ठंडी आबोहवा के चलते जड़ी-बूटी उत्पादन की पूरे जिले में अपार संभावनाएं है। दुर्लभ हिमालयी जड़ी-बूटी का रोपण दूरदराज गांवों तक कराया गया है। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मुहैया कराने के साथ-साथ यह मुहिम प्रदेश में जड़ी-बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा कदम है।
> –रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी बागेश्वर, उत्तराखंड

औषधीय गुणों से भरपूर : कुटकी का वानस्पतिक नाम पनिकम एंटीडोटेल है। औषधीय गुणों से भरपूर कुटकी लिवर टॉनिक के रूप में काम करती है। बुखार दूर करने के अलावा रक्तशोधन में इसका प्रयोग दवा के रूप में होता है। आयुर्वेद में इसका खासा महत्व है। पर्वतीय इलाकों में लोग पेट दर्द, बुखार, खांसी सहित तमाम व्याधियों में कुटकी का ही सेवन करते रहे हैं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

उत्तराखंड के सीमांत बागेश्वर जनपद स्थित एक गांव में कुटकी के पौधों की देखभाल में जुटा किसान। जागरण

दानिश संग कदमताल करता नए कश्मीर का जवां ख्वाब

जागरण विशेष ▶ 'कश्मीर का रोनाल्डो' एक बार फिर घरेलू दर्शकों के सामने जलवा बिखेरने को तैयार

फुटबॉलर दानिश भट। जागरण

आइ-लीग में स्टार फुटबॉलर दानिश भट की टीम 'रियल कश्मीर' के श्रीनगर में होने वाले मुकाबले को लेकर जोश चरम पर

रजिया नूर, श्रीनगर

दानिश भट ! एक नाम जिसने कश्मीर को सब कुछ भूल आगे बढ़ने का जज्बा दे दिया। फिर से खुशी से थिरकना, जोश से झूमना और मस्ती में खो जाना सिखा दिया। वह फुटबॉल के साथ कदमताल करते हुए विरोधी खेमे की ओर आगे बढ़ता है, तो कश्मीर की धड़कनें उफान मारने लगती हैं। वह गिर जाए तो सांसें थम जाती हैं। पर वह फिर उठकर दौड़ता है, चूंकि जानता है कि कश्मीर की उम्मीदें उसके साथ ही दौड़ेंगी।

'कश्मीर का रोनाल्डो' नाम से मशहूर कश्मीर का स्टार फुटबॉलर दानिश भट एक बार फिर घरेलू दर्शकों के सामने जलवा बिखेरने को तैयार है। आइ-लीग में दानिश की टीम 'रियल कश्मीर' का एक मुकाबला 26 को उनके होम टाउन श्रीनगर में होना है। पूरे कश्मीर में इस मुकाबले को लेकर जोश उफान पर है। यह फुटबॉलर आज कश्मीर की उम्मीदों का नया चेहरा बन चुका है और वादी में अपनी प्रतिभा का जादू बिखेर कश्मीरी युवाओं को नई प्रेरणा से भर दे रहा है।

राज्य के पुनर्गठन के बावजूद बंदिशों और बंद की धमकियों के बावजूद दानिश और उसके साथी निरंतर अभ्यास का मौका तलाश ही लेते और घंटों अभ्यास में जुटे रहते। दानिश ने दैनिक जागरण को बताया कि तड़के अंधेरे में ही वह और उनके साथी अभ्यास में जुट जाते और पौ फटने से पहले ही अपना अभ्यास पूरा कर लौट आते। कुछ दिन उन्हें राज्य से बाहर भी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ा। बहरहाल, अब मुश्किलें कुछ कम हो चली हैं और दानिश की टीम आइलीग टूर्नामेंट में बाजी मारने को आतुर है। आज रियल कश्मीर और दानिश एक-दूसरे की पहचान बन चुके हैं।

श्रीनगर में फुटबॉल खेलते बच्चे। जागरण

> शुक्र है कि कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं और श्रीनगर में घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का सपना फिर पूरा होने जा रहा है। चाहत है कि पूरा कश्मीर इस मुकाबले के दौरान हमारा हौसला बढ़ाए।
> –दानिश भट, स्टार फुटबॉलर, रियल कश्मीर टीम

26 को अपने होम टाउन में होने वाले मुकाबले के बारे में दानिश कहते हैं कि घरेलू मैदान पर खेलना एक अलग तरह का अनुभव होगा। इस मुकाबले के लिए हम तैयार हैं। निश्चित तौर पर उम्मीदों का दबाव रहेगा, लेकिन समर्थकों का प्यार हमें ऊर्जा भी देता है। कश्मीर में फुटबॉल के प्रति दीवानगी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उम्मीद है कि पूरा कश्मीर इस मुकाबले का भरपूर मजा लेगा...।

विरासत में मिली फुटबॉल, संघर्ष भी लंबा... : श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के रहने वाले 23 वर्षीय दानिश नंबर 10 जर्सी में खेलते हैं और इस नंबर को पाने के लिए पसीना भी खूब बहाया है। दानिश के अनुसार फुटबॉल का खेल विरासत में मिला, क्योंकि पिता और दो चाचा स्थानीय क्लबों के लिए खेलते थे। पापा और अंकल जब खेलने जाते थे तो मैं साथ जाता था। लोग उनके लिए तालियां बजाते तो मैं भी खुशी से झूमता था। इन्हीं तालियों की गूंज ने मुझे भी फुटबॉलर बना दिया। मैंने स्कूल का क्लब ज्वाइन किया। जल्द ही जम्मू कश्मीर बैंक की टीम में मौका मिल गया। वर्ष 2016 में रियल कश्मीर फुटबॉल टीम बनी और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मौका मिला।

कश्मीर में टेलेंट की कमी नहीं... : दानिश ने कहा, कश्मीर में टेलेंट की कमी नही है। अच्छा प्लेटफार्म मिले तो खिलाड़ी न केवल फुटबॉल बल्कि क्रिकेट और अन्य खेलों में भी सफलता के आयाम गढ़ सकते हैं। वादी में सुविधाएं मिलें तो युवा असामान्य स्थिति में भी सर्वश्रेष्ठ देने की क्षमता रखते हैं।

मुकाबले का इंतजार... : ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंतर्गत आइ-लीग प्रतियोगिता में देश के नामी क्लब हिस्सा ले रहे हैं। 30 नवंबर से शुरू हुई प्रतियोगिता चार अप्रैल को समाप्त होगी। रियल कश्मीर टीम 26 दिसंबर से अगले कुछ मुकाबले श्रीनगर में खेलेगी। खेल प्रेमियों ने टीम के स्वागत की तैयारी की ही है, खिलाड़ी भी होम ग्राउंड पर प्रतिभा दिखाने को बेकरार हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

उत्तराखंड में जंगली सूअर मारने पर फिर प्रतिबंध

गोविंद बिष्ट, हल्द्वानी

- केंद्र की ओर से दी गई छूट का समय खत्म, अब काश्तकारों पर दर्ज हो सकता है मुकदमा
- पहाड़ में फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं जंगली सूअर

उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक के किसी खेत में घुसकर अगर जंगली सूअर आतंक मचा रहे हैं तो काश्तकार अब भूलकर भी उन्हें मारने की कोशिश न करें, वरना उन्हें वन विभाग के मुकदमे या अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर खेतों में आकर फसल को चौपट करने वाले जंगली सूअरों को मारने पर फिर से प्रतिबंध लग चुका है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई छूट नवंबर में खत्म हो चुकी है। ऐसे में काश्तकारों की परेशानी बढ़ना लाजिमी है।

उत्तराखंड के काश्तकार जंगली जानवरों की वजह से सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। जंगली सूअर व बंदरों से फसल को बचाना पहाड़ में सबसे बड़ी चुनौती है। यहीं वजह है कि कई इलाकों में लोगों ने खेती करना तक छोड़ दिया है। इस परेशानी को देखते हुए नवंबर 2018 में केंद्र सरकार ने एक साल के लिए सूअरों को मारने की छूट दी थी। हालांकि, यह नियम वन्यजीवों के आरक्षित क्षेत्र से बाहर खेतों में पहुंचने पर लागू था, लेकिन पिछले माह 12 नवंबर को यह अस्थायी समय सीमा समाप्त हो गई। अब काश्तकार द्वारा सूअर को मारने पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अनुसूची पांच का वन्यजीव होने के कारण डीएफओ जुर्माना लगाकर छोड़ सकते हैं या फिर आरोपित को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।

> जंगली सूअरों को मारने की छूट खत्म हो चुकी है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रस्ताव भेज फिर से अनुमति मांगी है। उम्मीद है कि फिर से परमिशन मिल जाएगी।
> –राजीव भरतरी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उत्तराखंड वन विभाग

हर माह बीस हेक्टेयर फसल प्रभावित : प्रदेश का 71 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जंगल का हिस्सा है। हाथी, बंदर, जंगली सूअर और अन्य वन्यजीव लगातार खेतों में धमककर नुकसान करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में हर माह करीब बीस हेक्टेयर खेती को वन्यजीव नुकसान पहुंचाते हैं।

दस साल में नौ हजार यूनिट रक्तदान

विनोद श्रीवास्तव, हरिद्वार

बचा रहे जीवन

- हरिद्वार का ब्लड वालंटियर्स ग्रुप एक दशक से जुटा है अभियान में
- ब्लड बैंक हरिद्वार, एम्स ऋषिकेश और देहरादून के अस्पताल को भी देता है रक्त
- जरूरत पड़ने पर जिले के बाहर भी मरीजों की जान बचाने को तत्पर रहता है ग्रुप

दस वर्ष पूर्व 'रक्तदान से जीवनदान' के संकल्प को साकार करने के लिए हरिद्वार में ब्लड वालंटियर्स ग्रुप की ओर से छेड़ी गई मुहिम आज एक विशाल वृक्ष का आकार ले चुकी है। दस साल में इन ब्लड वालंटियर्स ने नौ हजार यूनिट रक्त विभिन्न अस्पताल के ब्लड बैंकों को देकर हजारों मरीजों की जान बचाई है। जरूरत पड़ने पर इनका ग्रुप जिले की सीमाओं से बाहर भी गंभीर मरीजों के जान बचाने को चौबीसों घंटे तत्पर रहता है।

ब्लड वालंटियर्स हरिद्वार की टीम में जिला अस्पताल के स्टाफ से लेकर सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं की सहभागिता भी है। टीम का अभियान अब बड़े शिविर, जिसमें 350 यूनिट तक ब्लड डोनेट किया जाता है, तक पहुंच गया है। बीते दस वर्षों में टीम नौ हजार यूनिट रक्त एकत्र कर जिला अस्पताल हरिद्वार के ब्लड बैंक के अलावा एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ऋषिकेश और देहरादून में संचालित ब्लड बैंक को दान दिया है।

प्लेटलेट्स देने में भी आगे: साल के पूरे 365 दिन सक्रिय रहने वाले ब्लड वालंटियर्स की टीम ने इस वर्ष कई डेंगू पीड़ितों को प्लेटलेट्स देकर उनका जीवन बचाया। आज सोशल नेटवर्किंग के जरिये ब्लड वालंटियर्स पूरे देश में अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं।

> ब्लड वालंटियर्स 29 उत्साही युवकों समेत लगभग 400 समर्पित लोगों की टीम है, जो रक्तदान कर दूसरों की जान बचाने को हर समय तत्पर रहती है। इस टीम से लगातार दूसरे भी प्रेरणा ले रहे हैं और टीम के साथ जुड़ रहे हैं।
> –अनिल अरोड़ा, संस्थापक सदस्य, ब्लड वालंटियर्स, हरिद्वार

हरिद्वार के ब्लड वालंटियर्स ग्रुप (आगे दाएं से) विशाल अनेजा, के एस पाण्ड़े, सुमित बंसल और शेखर सतीजा एवं (पीछे की पंक्ति में दाएं से) चीकू कालरा, अनिल अरोड़ा, मनीष लखानी व अंकित नेगी। साभार : वालंटियर्स ग्रुप

टूट गई पीएम के हाथों मिली चप्पल दुखी रत्नीबाई सहेज रहीं स्मृतियां

पी रंजन दास, बीजापुर

रत्नीबाई की बेशकीमती संपत्ति में शुमार वह चप्पल, जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट की थी, वह अब टूट गई है। रत्नीबाई इससे खासी दुखी हैं। दो महीने पहले किसी कार्यक्रम में जाते वक्त उनकी चप्पल टूटी थी। चप्पल तो टूट गई, लेकिन परिवार ने उस तस्वीर को सहेज कर रखा है, जिसमें प्रधानमंत्री रत्नीबाई को चप्पल पहनाते नजर आ रहे हैं। अब रत्नीबाई के लिए उस अवस्मरणीय क्षण की वह तस्वीर और स्मृतियां ही शेष हैं।

भैरमगढ़ के बंडपाल की रहने वाली उम्रदराज रत्नी बाई तब चर्चा में आई थीं जब 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजापुर के जांगला आए थे उन्होंने यहां से देश को आयुष्मान भारत योजना की सौगात दी थी, तब पीएम ने तेंदूपत्ता संग्राहक रत्नी बाई को चप्पल भेंट की थी। जनसभा को संबोधित करने के बाद बारी जब तेंदूपत्ता संग्राहकों को चप्पल भेंट करने की आई, तब प्रधानमंत्री अपनी जगह से उठे और अचानक झुककर अपने हाथों से रत्नीबाई के पावों में चप्पल पहना दी।

नंगे पांव उदास बैठीं रत्नी बाई। नईदुनिया

उस वक्त रत्नी बाई के पास उनकी कुटिया और चार बेटे-बहुओं, नाती-पोती से भरे-पूरे परिवार को छोड़कर दूसरी कीमती संपत्ति नहीं थी, लेकिन पीएम के हाथों मिला चप्पल एकाएक रत्नीबाई के लिए बेशकीमती सामान बन गया। भले ही वह चप्पल थी, लेकिन पीएम के हाथों भेंट मिलने से उसकी कद्र में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। चोरी के डर से वह उसकी बराबर निगरानी करती थी।

अपनी मिट्टी की कुटिया के एक कमरे में वह अनाज के बोरे में उसे छिपाकर रखती थी। और तो और कमरे में कोई बगैर उनकी इजाजत के प्रवेश न कर सके इसलिए दरवाजे की कुंडी पर ताला लगाकर चाबी 24 घंटे उनके गले में एक सूत से बंधी होती थी। चप्पल के प्रति उसका लगाव भी सुर्खियों में रहा। वह कभी कभार किसी आयोजन में ही चप्पल पहनती थी। चप्पल टूटने से दुखी रत्नी बाई बताती हैं कि उन्हें ताउम्र इस बात का मलाल रहेगा।

जीपीएस की मदद से होगी रेल ट्रैक की निगरानी

जागरण संवाददाता, आगरा

- रेलवे ने सभी गैंगमैन को दिए जीपीएस ट्रैकर, गड़बड़ी मिलने पर कंट्रोल रूम को देंगे जानकारी

कोहरे में ट्रैक की निगरानी को रेलवे ने इस बार हाईटेक प्रणाली अपनाई है। गैंगमैन की पुश ट्रॉली को विभाग ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) ट्रैकर से लैस किया है। इसकी मदद से गैंगमैन की निगरानी के साथ पटरियों में आने वाली दिक्कत की जानकारी कंट्रोल रूम को तुरंत दी जा सकेगी।

कोहरे में पटरियों पर फ्रैक्चर होने के मामले बढ़ जाते हैं। इसके लिए गैंगमैन लाइन पर पेट्रोलिंग करते हैं। अब पटरियों की देखरेख करने वाले गैंगमैन की पुश ट्रॉली को जीपीएस ट्रैकर से जोड़ दिया गया है। इस ट्रैकर की मदद से दिक्कत की जानकारी गैंगमैन तुरंत कंट्रोल रूम को दे सकते हैं।

ऐसे काम करता है जीपीएस ट्रैकर

पुश ट्राली में तीन बटन होते हैं। यह बटन कंट्रोल, इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े रहते हैं। ट्रैक पर कोई भी गड़बड़ी मिलने पर गैंगमैन संबंधित विभाग का बटन दबाकर उसे सूचना भेजता है। जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से लोकेशन देखकर टीम वहां पर पहुंच जाती है।

कोहरे में बढ़ जाती है परेशानी। प्रतीकात्मक

> सभी गैंगमैन को जीपीएस ट्रैकर दे दिए गए हैं। ट्रैकर की मदद से रेल की सुरक्षा और मजबूत होगी। साथ ही गैंगमैन की मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी।
> –एसके श्रीवास्तव, पीआरओ आगरा रेल मंडल

'मेरा नाम मुहम्मद फैज खान है और मैं गो सेवक हूं'

सुनील राणा, जालंधर

30 महीने से पदयात्रा पर छत्तीसगढ़ के फैज, जून 2017 में लेह से शुरू हुई यात्रा कन्याकुमारी होते हुए आज होगी पंजाब में दाखिल

भगवा वस्त्र पहने इस शख्स को नमाज पढ़ते देख हर कोई हैरान होता है। हैरानी उस वक्त और बढ़ जाती है, जब वह गीता के श्लोकों का उच्चारण करने के साथ कुरान की आयतें सुनाने लगते हैं। मौका मिलने पर गो कथा भी करते हैं। पहचान पूछने पर कहते हैं, 'मेरा नाम मुहम्मद फैज खान है और मैं एक गो सेवक हूं। इंसानियत मेरा मजहब है।' हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुहम्मद फैज खान की, जो 24 जून, 2017 से पदयात्रा पर हैं। मकसद गो सद्भावना का संदेश देना। लेह से शुरू हुई इस पदयात्रा का पहला पड़ाव कन्याकुमारी में खत्म हुआ। इसके बाद कन्याकुमारी से शुरू हुई यह पदयात्रा 11 दिसंबर को पंजाब में दाखिल होगी। इसका समापन एक जनवरी को जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी में होगा।

38 साल के फैज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नया पारा के रहने वाले हैं। वह रायपुर के सूरजपुर डिग्री कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता थे। बात 2012 की है। एक दिन गिरीश पंकज का लिखा उपन्यास 'एक गाय की आत्मकथा' पढ़ा तो मानो जिंदगी बदल गई। नौकरी छोड़ गोसेवा में लग गए। देश के कई हिस्सों में गो कथा की। गो सद्भावना का संदेश देने के लिए 24 जून, 2017 को लेह से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा शुरू की। विभिन्न राज्यों से होते हुई यात्रा 28 सितंबर, 2018 को कन्याकुमारी पहुंची। इसके बाद 15 नवंबर, 2018 को यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू किया। पहले यात्रा का समापन अमृतसर में करना था, लेकिन जम्मू-कश्मीर के अलग राज्य बनने के बाद समापन वैष्णो देवी में करने का फैसला किया। 11 दिसंबर को यात्रा पंजाब में दाखिल हो रही है। यात्रा मार्ग में आने वाला पंजाब 22वां राज्य है। अब तक वह 13500 किमी की पदयात्रा कर चुके हैं। करीब 500 किमी यात्रा बाकी है। यात्रा के दौरान वह त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नहीं जा पाए।

पदयात्रा के दौरान फैज खान। सौजन्य : फेसबुक

गाय का दूध शिफा

फैज खान का कहना है कि कुछ लोगों ने गोमांस को मुस्लिम धर्म के साथ जोड़ दिया है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। पैगंबर हजरत मुहम्मद साहिब ने कहा है कि गाय का दूध शिफा (स्वास्थ्यवर्धक) है। उसका मक्खन दवा है और गोश्त बीमारी है। उनका कहना है कि हमारे देश में गाय सबसे जरूरी है। गाय से हमें स्वास्थ्यवर्धक दूध, दही, घी के साथ ही उपयोगी गोबर और गोमूत्र मिलता है।

नानक-बुद्ध से ली यात्रा की प्रेरणा : फैज ने बताया कि उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से लेकर महात्मा बुद्ध तक के बारे में पढ़ा है। पता चला कि इन महापुरुषों ने भी पद यात्रा की है। इन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा से आज वह 14 हजार किमी की यात्रा के समापन के करीब हैं। यात्रा में उत्तर प्रदेश के बलिया से पीयूष राय, गाजीपुर से किशन राय, छत्तीसगढ़ से बाबा परदेसी राम साहू और चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कैलाश वैष्णव लगातार यात्रा में सहयोग बनाए हुए हैं।

सामान लेकर साथ चलता है 'कार रथ' : फैज ने बताया कि राजस्थान के एक गो सेवक ने यात्रा के लिए उन्हें कार भेंट की थी। इसी को रथ का नाम दिया गया। इसमें उनकी जरूरत का पूरा सामान रहता है। कैलाश वैष्णव पूरी यात्रा के दौरान इसे चला रहे हैं।

अनूठा मामला

झारखंड में सड़क किनारे रखे सैकड़ों टन क्वाट्र्ज और क्वार्टजाइट जब्त, स्मोकी क्वाट्र्ज में पायराइट, चालकोपायराइट के अंश देखे गए

गए थे अवैध खनन की जांच को, मिल गया सोने का खनिज भंडार

सुधीर पांडेय, चाईबासा

झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के पोटका में क्वाट्र्ज और क्वार्टजाइट के अवैध खनन की जांच करने पहुंची भूतत्व विभाग की टीम को उक्त क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने (गोल्ड) के खनिज भंडार का पता चला है।

विभाग के निदेशक फैज अक मुहम्मद मुमताज ने इस क्षेत्र को अपने अधीन में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग के उपनिदेशक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पोटका में ओडिशा सीमा से सटे तिरिंग गेट के पास राघवडीह, किशनडीह व मरांगमाली वन क्षेत्र में सड़क किनारे भारी मात्रा में क्वाट्र्ज और क्वार्टजाइट का अवैध खनन किया जा रहा है।

इस तरह बढ़ी सोना होने की संभावना : पिछले दिनों इसकी जांच के लिए जमशेदपुर के खनन पदाधिकारी नदीम शरीफ और सहायक निदेशक करुण कुमार को लेकर वे पोटका गए थे। जांच के क्रम में पाया कि उक्त क्षेत्र में तीन जगह करीब 690 टन, 1150 टन और 345 टन के क्वाट्र्ज और क्वार्टजाइट को तोड़कर भंडारित किया गया है। निरीक्षण में बहुतायत मात्रा में स्मोकी क्वाट्र्ज और फुंसीटाइट क्वार्टजाइट भी पाया गया। स्मोकी क्वाट्र्ज में पायराइट, चालकोपायराइट के अंश देखे गए। यहां स्मोकी क्वाट्र्ज मिलने से यह संभावना बनी कि निश्चित रूप से यहां पर सोना खनिज भी मौजूद होगा, क्योंकि स्मोकी क्वाट्र्ज में ही सोना खनिज होने की प्रबल संभावना रहती है।

किया जा रहा सर्वे: उपनिदेशक ने बताया कि नदी नाला एवं स्मोकी क्वाट्र्ज में रासायनिक विश्लेषण में सोने के अंश लगभग 2.17 पीपीएम पाया गया है। यह एक उच्च गुणवत्ता का मानक है। रांची स्थित जीएसआइ (जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जनार्दन प्रसाद की ओर से जानकारी दी गई है कि भू वैज्ञानिक अन्वेषण दल यहां सोना खनिज के लिए भूतत्व सर्वे का कार्य कर रहा है।

ऐसे निकलता है सोना

सोने को क्वाट्र्ज पत्थरों से निकाला जाता है। सोने के छोटे-छोटे टुकड़े इन पत्थरों में होते हैं। ऐसे पत्थर रांची और पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। खोदाई के बाद पत्थर की पिसाई कर तेज पानी के बहाव में छाना जाता है। भारी धातु नीचे बैठ जाती है। फिर गोल्ड अट्रैक्टर मैग्नेटिक नीडल से सोना पत्थर से अलग किया जाता है।

प्रतीकात्मक

कुंदरकोचा व लावा में हो रहा अभी सोने का खनन

पूर्वी सिंहभूम के कुंदरकोचा और लावा में दो जगह पहले से ही सोने का खनन हो रहा है। चाईबासा के परडीहा और परासी में सोने की खान की नीलामी हो चुकी है। यहां अभी खनन नहीं शुरू हो पाया है। जमशेदपुर के भीतरडारी में सोने की खान की मात्रा का पता लगाने का काम चल रहा है।

बैंक ऑफ इंडिया समेत चार बैंकों ने सस्ता किया कर्ज

नई दिल्ली : मंगलवार को बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर में कटौती की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वर्ष की एमसीएलआर 0.05 परसेंट घटाकर 8.25 परसेंट कर दी है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्ष की एमसीएलआर 8.3 परसेंट से घटाकर 8.2 परसेंट कर दी है। यूको बैंक ने अलग-अलग अवधि की एमसीएलआर में 10 आधार अंक तक की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पांच से लेकर 10 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है। (प्रेट्र)

भारत में निवेश का बड़ा हिस्सा बैंकों का है। हालांकि सतत विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए ह्यूमन कैपिटल में निवेश की जरूरत है।

– कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल
40,239.88	11,856.80	₹ 38,460	₹ 44,607	₹ 70.92	$ 63.92
▼ 247.55	▼ 80.70	▼ ₹ 95	▼ ₹ 128	▼ ₹ 0.12	

डूबने के कगार पर विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब वैश्विक व्यापार विवादों के निपटारे में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकेगा। अपनी हालिया नीतियों और बयानों से दुनिया के कई देशों को नाराज कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय में नई नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है। साथ ही बजट रोकने की भी धमकी दी है। इससे 2020 में डब्ल्यूटीओ के पतन की आशंका भी जताई जा रही है। दुनिया के बहुत से देशों के साथ ही यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत के कई मामले डब्ल्यूटीओ में लंबित हैं।

592
25 सालों में डब्ल्यूटीओ में पहुंचे मामले

ऐसे निपटाता है विवाद

विवादों का निपटारा करना डब्ल्यूटीओ का महत्वपूर्ण कार्य है। एक सदस्य जब दूसरे सदस्य देश के खिलाफ डब्ल्यूटीओ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाता है तो यह प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद विवाद के निपटारे के लिए डब्ल्यूटीओ सभी पक्षों को परामर्श देता है और स्वयं विवाद सुलझाने के लिए कहता है। यदि परामर्श से हल नहीं निकलता तो शिकायत एक पैनल को भेज दी जाती है। पैनल सभी पक्षों से चर्चा करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। यदि पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ कोई पक्ष अपील करता है तो विवाद पर अपीलीय निकाय फैसला सुनाता है।

ऐसे जानिए डब्ल्यूटीओ

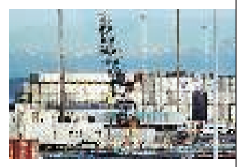

डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य व्यापार के सुचारु और निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करना है। यह संगठन 1995 में अस्तित्व में आया और फिलहाल 164 देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय जिनेवा में है और यह विश्व व्यापार के करीब 23 अरब डॉलर को नियंत्रित करता है। डब्ल्यूटीओ से पहले इस भूमिका में जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ (जीएटीटी) काम कर रहा था। जीएटीटी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में बनाया गया था। दुनिया के 23 देशों ने जीएटीटी पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि जीएटीटी का क्षेत्र वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। 25 सालों में कुल 592 मामलों में से डब्ल्यूटीओ ने 118 मामले आपसी सहमति से निपटाए हैं।

अब यह है दिक्कत

डब्ल्यूटीओ के शक्तिशाली अपीलीय निकाय के दो जज 10 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ एक जज बचे हैं। डब्ल्यूटीओ के नियमानुसार किसी भी मामले को सुनने के लिए कम से कम तीन जज होने चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने अपीलीय संस्था में पदों की भर्ती पर 2018 से रोक लगा रखी है। विशेष बात यह है कि डब्ल्यूटीओ सदस्य नियुक्तियों को लेकर एकमत होने चाहिए, तभी पदों को भरा जा सकता है। अपीलीय निकाय में स्वीकृत पदों की संख्या सात है। फिलहाल जजों के रिटायर होने के बाद पदों को नहीं भरा गया और नौबत यहां तक पहुंच गई है।

बजट में अमेरिका का योगदान

अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ के बजट में कटौती की धमकी भी दी है। डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर मौजूद साल 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, उस साल संस्था का 19.55 करोड़ स्विस फ्रेंक (करीब 1406 करोड़ रुपये) का बजट था। इसमें सबसे ज्यादा 11.31 फीसद हिस्सेदारी अमेरिका की थी। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जिसने 8.61 फीसद का सहयोग किया। भारत का हिस्सा 2.14 फीसद था।

भारत के लिए चिंता

डब्ल्यूटीओ में भारत के कई मामले चल रहे हैं। यदि अपीलीय निकाय नहीं रहता है तो यह परेशान करने वाली स्थिति होगी। अमेरिका और जापान आयात शुल्क बढ़ाने को लेकर भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ पहुंचे हैं। वहीं भारत ने अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम शुल्क के साथ ही एच-1बी वीजा सहित अन्य मामलों में घेरा है।

डब्ल्यूटीओ में भारत के मामलों की स्थिति

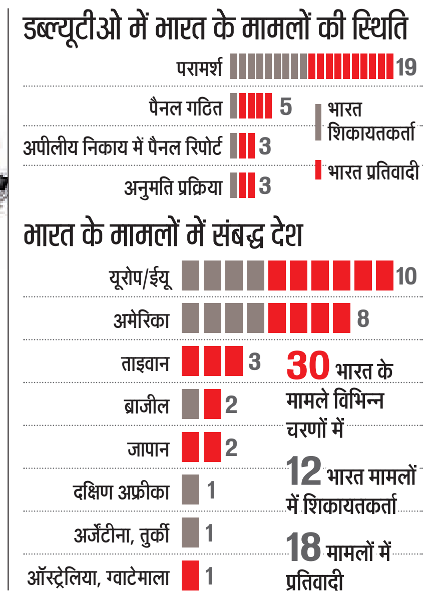

जीएसटी रेवेन्यू पर बढ़ी चिंता, दरें बढ़ाने पर विचार

जटिल हालात ▶ कंपनसेशन फंड से राज्यों के राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति भी केंद्र सरकार के लिए हो रही मुश्किल

केंद्र व राज्यों के अधिकारियों की समिति ने कई विकल्पों पर किया विमर्श

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेवेन्यू की धीमी होती रफ्तार बढ़ाने को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मौजूदा दरों में संशोधन पर विमर्श की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंगलवार को इस संबंध में गठित केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के एक समूह की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विकल्पों पर विचार हुआ। अभी समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है लेकिन जिन विकल्पों पर विचार हुआ उनमें तंबाकू उत्पादों पर सेस की दर में वृद्धि करने का सुझाव भी शामिल है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में कई विकल्पों पर विचार हुआ। इनमें एक विकल्प जीएसटी की पांच परसेंट की दर को बढ़ाकर अधिकतम आठ परसेंट और 12 परसेंट को बढ़ाकर अधिकतम 15 परसेंट करने का सुझाव भी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक सुझाव जीएसटी की दरों को 10 और 20 परसेंट के दो स्लैब निर्धारित करने का भी बैठक में विचार के लिए आया। बैठक में एक विकल्प पांच परसेंट के स्लैब को बढ़ाकर छह परसेंट करने का भी आया। एक सुझाव यह भी आया है कि ग्राहकों को खरीदारी के वक्त रसीद लेने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए लॉटरी सिस्टम शुरू किया जाए।

जल्दी ही अधिकारियों की यह समिति रेवेन्यू सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद रिपोर्ट पर विचार विमर्श और फिटमेंट और लॉ कमेटी के सुझावों के साथ यह जीएसटी काउंसिल के पास जाएगी। इसके बाद ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर जीएसटी काउंसिल में प्रस्तुत किया जाएगा। काउंसिल ही जीएसटी की दरों के पुनर्गठन के संबंध में अंतिम फैसला लेगी। अभी जीएसटी के चार स्लैब पांच, 12, 18 और 28 परसेंट लागू हैं। 28 परसेंट जीएसटी के दायरे में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर सेस भी वसूला जाता है।

जीएसटी की दरों के पुनर्गठन पर विचार ने ऐसे समय में जोर पकड़ा है, जब जीएसटी से मिलने वाला रेवेन्यू अपेक्षित रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। यहां तक कि केंद्र के लिए कंपनसेशन फंड से राज्यों के रेवेन्यू में कमी की क्षतिपूर्ति करना भी मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 19 महीने के न्यूनतम पर चला गया था। इसके बाद ही जीएसटी काउंसिल ने रेवेन्यू में सुधार पर विचार करने के लिए अधिकारियों की समिति का गठन किया था। 12 सदस्यों वाली इस समिति में पांच सदस्य केंद्र से और पांच राज्यों से हैं। समिति में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के एसजीएसटी कमिश्नर को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इनके अलावा जीएसटी काउंसिल में संयुक्त सचिव और जीएसटीएन के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।

स्थायी समिति ने जताई चिंता : वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने रेवेन्यू के लक्ष्य के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन धीमा रहने पर चिंता जताई है। मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि लांच के दो साल बाद सरकार ने जीएसटी की दरों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की है। समिति ने सरकार से अपेक्षा की है कि वह जल्दी ही इस दिक्कत का समाधान निकालेगी ताकि रेवेन्यू बढ़ाने के अपेक्षित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। समिति ने रेवेन्यू विभाग को इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने की दिशा में सतर्क रहने की हिदायत भी दी है।

समिति के समक्ष प्रस्ताव

- पांच फीसद की स्लैब को आठ और 12 फीसद को 15 किया जाए
- जीएसटी के लिए 10 और 20 फीसद की दो स्लैब बनाई जाए
- पांच फीसद वाली स्लैब को बढ़ाकर छह फीसद कर दिया जाए
- ग्राहकों को बिल के लिए प्रोत्साहित करने को लॉटरी सिस्टम शुरू हो
- तंबाकू उत्पादों पर सेस की दरों में वृद्धि से हो रेवेन्यू की भरपाई

जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा दरों में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला। प्रतीकात्मक

प्रत्यक्ष कर संग्रह की रफ्तार भी धीमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह की स्थिति तो खराब है ही, लेकिन प्रत्यक्ष कर संग्रह की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले आठ महीनों के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में महज 1.6 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सरकार के लिए राजकोषीय संतुलन साधने को लेकर नई चिंताएं पैदा होने के संकेत हैं।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में प्रत्यक्ष कर संग्रह के जो आंकड़े दिए हैं, वह पहली बार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। अप्रैल से नवंबर, 2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,56,490 करोड़ रुपये का रहा, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष (2018-19) की समान अवधि में यह संग्रह 5,47,711 करोड़ रुपये रहा था। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में व्यक्तिगत आयकर के लिए 5,59,000 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट टैक्स के लिए 7,66,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था। जाहिर है कि शेष बचे चार महीनों में सरकार को निर्धारित लक्ष्य का 60 फीसद से ज्यादा संग्रह करना है।

रणनीतिक विनिवेश में देरी पर कैग ने उठाए सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंच सकी सरकार
- डिविडेंड के मामले में खजाने को 9417 करोड़ का नुकसान

सरकार की तरफ से सरकारी कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के लक्ष्य की प्राप्ति में ढिलाई पर कैग ने सवाल खड़े किए हैं। कैग का मानना है कि 2017-18 में सार्वजनिक उपक्रमों के चयन के बावजूद कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश के लक्ष्य के नजदीक भी नहीं पहुंचा जा सका। साथ ही कैग ने कहा है कि डिविडेंड के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का पालन नहीं होने से 2017-18 में खजाने को 9471 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

संसद में मंगलवार को सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि विनिवेश के लिए जिम्मेदार विभाग दीपम व सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपसी समन्वय और ज्यादा बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। इससे बाकी बचे उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा। 2017-18 में रणनीतिक विनिवेश के लिए 24 उपक्रमों का चयन किया गया था। लेकिन 2018-19 तक इनमें से केवल चार उपक्रमों का ही रणनीतिक विनिवेश हो पाया। सरकार ने इस बीच आरईसी के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन कैग का मानना है कि यह इस सूची से बाहर का विनिवेश था।

एचपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यद्यपि एचपीसीएल-ओएनजीसी सौदा सीसीईए द्वारा निर्धारित रणनीतिक बिक्री के मानकों के अनुरूप हुआ है। लेकिन इसके ऑडिट को इस रोशनी में देखा जाना चाहिए कि एक सरकारी कंपनी में से सरकार की इक्विटी दूसरी सरकारी कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई।

कंपनी के विनिवेश से संबंधित पूछताछ के मामले में दीपम से मिली जानकारी पर भी कैग ने असंतोष जाहिर किया है। कैग के मुताबिक कंपनी के फ्री कैश फ्लो, डेट इनवेंट्री और रिफाइनरी मार्जिन के अनुमानों के संबंध में दीपम और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पर्याप्त सपोर्टिंग शीट उपलब्ध नहीं कराई। इसके अलावा कंपनी की फाइनल वैल्यूएशन रिपोर्ट के संबंध में पूछे गए सवालों पर दीपम ने तथ्यात्मक जवाब नहीं दिए।

डिविडेंड के मसले पर कैग ने कहा है कि सरकारी नियमों के मुताबिक मुनाफा अर्जित करने वाले पीएसयू को 20 परसेंट लाभांश का एलान करना होता है। लेकिन 53 कंपनियों ने इन नियमों का पालन नहीं किया। इसके चलते सरकार को 9471 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

मुद्रा योजना में अब तक 21 करोड़ कर्ज मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अक्टूबर, 2019 तक कुल 9.87 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित
- कुल कर्ज में सामान्य वर्ग के आवेदकों की हिस्सेदारी 65 फीसद
- सरकारी बैंकों के 2.43 करोड़ लोन में से 12.3 लाख लोन हुए हैं एनपीए

प्रतीकात्मक फोटो

छोटे कारोबारियों मसलन रेहड़ी-पटरी वाले, खोमचे और सब्जी भाजी से लेकर नाई, मैकेनिक आदि को कर्ज देकर व्यवसाय के विस्तार के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब तक 20.65 करोड़ कर्ज मंजूर किए जा चुके हैं। इसके तहत सरकार ने अक्टूबर, 2019 तक 9,86,816.91 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए हैं।

सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि अकेले वित्त वर्ष 2019-20 में अब तक 1,20,301.3 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए। इस अवधि में कर्ज के 2.40 करोड़ आवेदनों को मंजूरी दी गई। वित्त वर्ष 2018-19 में मुद्रा कर्ज के 5,98,70,318 आवेदन मंजूर किए गए थे। इनके तहत 3,11,811.4 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए थे।

राज्यसभा में दिए अपने लिखित जवाब में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अक्टूबर, 2019 तक वितरित कुल कर्ज राशि में करीब 65 फीसद हिस्सेदारी सामान्य वर्ग के आवेदकों की रही है। कुल 9,86,816.91 करोड़ रुपये की राशि में से सामान्य वर्ग के आवेदकों को 6,42,393.74 करोड़ रुपये की राशि वितरित हुई है। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को 2,10,254.99 करोड़ रुपये की राशि कर्ज के तौर पर मिली। यह कुल वितरित राशि का करीब 22 फीसद है। वहीं, अनुसूचित जाति के 3.5 करोड़ आवेदकों को 1,00,460.31 करोड़ रुपये की राशि का कर्ज अक्टूबर, 2019 तक वितरित किया जा चुका है। यह कुल वितरित राशि के 10 फीसद से कुछ अधिक बैठता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 33,707.04 करोड़ रुपये की राशि वितरित हुई है।

जहां तक मुद्रा लोन के एनपीए में तब्दील होने का सवाल है, सरकार ने राज्यसभा में जून, 2019 तक सार्वजनिक बैंकों की तरफ से बांटे गए कर्ज का ब्योरा रखा है। इसके तहत सरकारी बैंकों ने 2.43 करोड़ लोन वितरित किए थे, जिनमें से 12.3 लाख लोन एनपीए बने हैं। इस बीच, बढ़ते एनपीए का हवाला देकर तृणमूल कांग्रेस ने मुद्रा लोन योजना को बंद करने की मांग की है।

नहीं बंद हो रहे 2000 रुपये के नोट : वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें 2000 रुपये के नोट बंद करने का दावा किया जा रहा था। राज्यसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा, 'यह चिंता आजकल सामने आई है। मेरे विचार से इस तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।' इससे पहले सपा सांसद विशंभर प्रसाद ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट से कालाधन बढ़ा है। लोगों के बीच धारणा है कि सरकार 2000 रुपये का नोट बंद कर फिर 1000 रुपये का नोट लाने पर विचार कर रही है।

यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : मांग में कमी के चलते यात्री वाहनों की बिक्री में नवंबर में 0.84 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में इन वाहनों की बिक्री में सुधार देखा गया था।

वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में कुल 2,63,773 यात्री वाहन बिके। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2,66,00 यात्री वाहन बिके थे। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि के दौरान घरेलू कारों की बिक्री में 10.83 परसेंट की गिरावट आई। इस दौरान कुल 1,60,306 कारें बिकी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,79,783 कारों की बिक्री हुई थी। इस वर्ष नवंबर में कुल 10,728 वैन बिकीं, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16,333 वैन बिकीं थी।

लगातार सिकुड़ रहा है चीन का ऑटो मार्केट

बीजिंग, रायटर : चीन में लगातार 17वें महीने वाहन बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने वाहन बिक्री में 3.6 परसेंट की गिरावट देखी गई। इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के बाद चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई है।

'आरसेप के मौजूदा स्वरूप में भारत की चिंताओं को अनदेखा किया गया'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में रखा सरकार का पक्ष
- कहा, जिन देशों के साथ एफटीए हुआ, उनसे देश का आयात बढ़ता चला गया

आरसेप का वर्तमान स्ट्रक्चर न केवल अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों बल्कि भारत के कई मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने में असमर्थ रहा। इसलिए भारत के लिए आरसेप पर आगे बढ़ना बेहतर विकल्प नहीं था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को राज्यसभा में यह बात कही।

आरसेप से अलग रहने के मुद्दे पर दिए अपने वक्तव्य में गोयल ने कहा कि आसियान समेत कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भी भारत के लिए उपयोगी नहीं रहे। उन्होंने कहा, 'हमारे अनुभव से यह पता चला है कि इनसे भारत को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इसलिए सरकार आसियान देशों से हुए एफटीए की समीक्षा करने जा रही है।'

गोयल ने कहा कि जिन देशों के साथ पूर्व में विदेश व्यापार संबंधी करार हुए उनसे भारत के आयात में वृद्धि हुई। इन देशों में आसियान के अलावा दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया शामिल हैं। वाणिज्य मंत्री के मुताबिक इन समझौतों में भारत ने इन देशों को अपने बाजार में अत्यधिक पहुंच उपलब्ध कराई, जबकि भारत को इसके बदले दूसरे देशों में कम पहुंच प्राप्त हुई। आसियान के साथ हुए एफटीए का उदाहरण देते हुए गोयल ने कहा कि भारत ने 74.4 फीसद टैरिफ लाइनों पर टैरिफ समाप्त कर दिया, जबकि कुछ आसियान देशों ने केवल 50.1 और 69.7 फीसद लाइनों पर ही टैरिफ समाप्त किया।

पीयूष गोयल। फाइल

बढ़ता गया व्यापार घाटा : वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इन देशों के साथ हुए द्विपक्षीय कारोबार की तुलना बताती है कि करार लागू होने के बाद की तारीख से भारत के व्यापार घाटे में लगातार वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक आसियान के साथ व्यापार घाटा पांच अरब डॉलर से चार गुना बढ़कर 21.8 अरब डॉलर हो गया। आरसेप देशों के साथ व्यापार घाटा 2003-04 में 7.1 अरब डॉलर से नौ गुना बढ़कर 2013-14 में 65.1 अरब डॉलर हो गया। अकेले चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2003-04 के 1.1 अरब डॉलर से 33 गुना बढ़कर वर्ष 2013-14 में 36.2 अरब डॉलर हो गया।

पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि बढ़ते आयात के इस रुख के बावजूद तत्कालीन सरकार 2006 में चीन के साथ व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली व्यापार और आर्थिक संबंध समिति को चीन के साथ इस तरह का करार करने की सिफारिश की गई। हालांकि व्यापार घाटा अधिक हो जाने की चिंता व्यक्त करते हुए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया।

दबाव में टूटे

पावर, ऑयल एंड गैस और आइटी स्टॉक्स में दिखा दबाव, सेंसेक्स 248 अंक और निफ्टी 81 अंक गिरकर हुआ बंद

शुरुआती मजबूती के बाद गिरकर बंद हुए शेयर बाजार

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सत्र में सकारात्मक बढ़त के बाद मंगलवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने शुरुआती मजबूती दर्ज की लेकिन पावर, ऑयल एंड गैस और आइटी सेक्टर के शेयरों में दबाव के चलते जल्द ही इसने अपनी बढ़त खो दी। सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 40,588.81 के मजबूत स्तर से की थी। बाद में लय खोते हुए 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 247.55 अंक यानी 0.61 परसेंट की गिरावट के साथ 40,239.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 80.70 अंक की गिरावट देखी गई। यह 11,856.80 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 10.5 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, आइटीसी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयरों में 2.66 परसेंट तक की गिरावट आई। वहीं दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और बजाज ऑटो के शेयर 1.06 परसेंट तक उछाल के साथ बंद हुए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक महंगाई का दबाव और आर्थिक चिंताओं के चलते शेयर बाजारों में बिकवाली का माहौल रहा। इसके अलावा अमेरिका के फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रखने से भी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। एशिया के अन्य शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख रहा। हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर और जकार्ता के शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। हालांकि शंघाई के शेयर बाजार मामूली बढ़त दर्ज करने में सफल रहे।

मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे सुधार के साथ बंद हुआ। इस दौरान एक डॉलर की कीमत 70.92 रुपये दर्ज की गई।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

पीसी ज्वैलर्स : रेटिंग एजेंसी क्रिसिल द्वारा कंपनी के बैंक लोन की रेटिंग गिराए जाने का असर इसके शेयरों पर देखा गया। मंगलवार को कंपनी के शेयरों में आठ परसेंट तक की गिरावट देखी गई। बीएसई में इसके शेयर 8.08 परसेंट की गिरावट के साथ 22.75 रुपये पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 8.06 परसेंट गिरकर 22.8 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके।

यस बैंक : मंगलवार को बीएसई में बैंक के शेयर 10.05 परसेंट की गिरावट के साथ 50.55 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए। वहीं एनएसई में यह 10.40 परसेंट की गिरावट के साथ 50.40 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। बैंक शेयरों में यह गिरावट बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले देखी गई है।

जेएसडब्ल्यू स्टील : पिछले महीने कंपनी के क्रूड स्टील आउटपुट में कमी का असर इसके शेयरों पर देखने को मिला। मंगलवार को बीएसई में इसके शेयर 2.96 परसेंट फिसलकर 251.1 रुपये के स्तर पर बंद हुए। वहीं एनएसई में इसके शेयरों में 2.97 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले सोमवार को कंपनी ने बताया था कि पिछले महीने इसके क्रूड आउटपुट में सात परसेंट की गिरावट आई है।

म्यूचुअल फंड में खातों की संख्या 8.65 करोड़ पहुंची

पिछले महीने म्यूचुअल फंड कारोबार में 2.6 लाख नए खाते जुड़े। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल खातों की संख्या 8.65 करोड़ हो गई है। इससे पहले अक्टूबर के दौरान छह लाख नए खाते इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े थे। म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ने के लिए खोले जाने वाले इन खातों को फोलियो कहा जाता है। एक निवेशक के एक से अधिक फोलियो हो सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक नवंबर के अंत तक 44 फंड हाउसेज के साथ कुल 8,65,18,585 खाते जुड़ चुके थे।

खराब सिग्नल से राहत देगी एयरटेल की वाई-फाई कॉलिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग सुविधा लेकर आई है। इसकी मदद से घर और ऑफिस जैसी जगहों पर कमजोर सिग्नल की चिंता किए बगैर बेहतर कॉलिंग सुविधा का आनंद उठाया जा सकेगा। एयरटेल का दावा है कि यह अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फोन कॉल की गुणवत्ता में इजाफा किया जा सकेगा।

एयरटेल वाई-फाई कालिंग के जरिये स्मार्टफोन धारक अपने फोन कॉल को एलटीई से वाई-फाई आधारित कॉल में बदल सकेंगे। इससे बंद जगहों पर कमजोर सिग्नल की समस्या से निजात पाई जा सकेगी। कंपनी ने कहा कि ऑफिस और घरों में जहां फोन सिग्नल कमजोर रहते हैं, एयरटेल वाई-फाई कालिंग की मदद से सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से किसी तरह का एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी और इसमें डाटा भी बहुत कम खर्च होगा। हालांकि यह सुविधा सभी स्मार्टफोन में उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए स्मार्टफोन यूजर एयरटेल की वेबसाइट के वाई-फाई-कॉलिंग सेक्शन में जाकर अपने मोबाइल फोन में वाई-फाई कॉलिंग की स्थिति जांच सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा आइफोन 6एस सीरीज और इसके बाद के सभी आइफोन में उपलब्ध है। इसके साथ ही वन प्लस-7 सीरीज और सैमसंग जे-6 जैसे मॉडल में भी यह सुविधा दी गई है। कंपनी ने बताया कि अभी वाई-फाई कॉलिंग दिल्ली-एनसीआर में शुरू की जा रही है। जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में किया जाएगा।

ऐसे करेगा काम : यूजर को पहले अपने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना होगा। इसके बाद सेटिंग में जाकर वाई-फाई कॉलिंग को ऑन करना होगा। इससे सिग्नल को एलटीई से वाई-फाई आधारित कॉलिंग सिस्टम में बदला जा सकेगा।

38 लोगों के साथ लापता हो गया है चिली की सेना का एक विमान। चिली की वायुसेना ने बताया है कि चार इंजन वाले एसी-130 हरक्युलिस विमान ने पुंटा एरेनास शहर से स्थानीय समयानुसार शाम चार बजकर 55 मिनट पर अंटार्कटिका बेस के लिए उड़ान भरी थी।

पहली बार सीसीपीआइ में शीर्ष दस देशों में भारत

भगीरथ प्रयास ▸ देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में नौवें स्थान पर

▸ देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग का मौजूदा स्तर उच्च श्रेणी में

▸ अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल

मैड्रिड, प्रेट्र : भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआइ) में शीर्ष दस देशों में शामिल हुआ है। यह भारत के कार्बन उत्सर्जन से उबरने के लिए किए गए भगीरथ प्रयासों का ही नतीजा है। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। यहां तक कि कोयला उद्योगों के दम पर अब भी अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब भी अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हैं।

स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 'कॉप 25' जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मंगलवार को सीसीपीआइ रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा इस्तेमाल का मौजूदा स्तर 'उच्च श्रेणी' में नौवें स्थान पर है। हालांकि यह अभी तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि, अपनी जलवायु नीति के प्रदर्शन के लिए उच्च रेटिंग के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को अभी जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए रूपरेखा बनानी होगी। इसके परिणामस्वरूप कोयले पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी।

कार्बन उत्सर्जन कम करने में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत नासिर्फ अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो रहा है बल्कि लक्ष्य पाने की दिशा में उसका काम 15 फीसद से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 57 उच्च उत्सर्जन वाले देशों में से 31 में उत्सर्जन का स्तर कम होने के रुझान दर्ज किए गए हैं। ये देश 90 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मनवॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के संयुक्त रूप से पेश सूचकांक के विश्लेषकों में से एक उर्सुला हेगन ने कहा, 'नए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से कोयले की खपत में कमी समेत उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं।' इस सूचकांक में स्वीडन चौथे और डेनमार्क पांचवें स्थान पर है। सबसे बड़े वैश्विक उत्सर्जक चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार करते हुए 30वां स्थान हासिल किया है। केवल दो जी20 देशों ब्रिटेन (7वें) और भारत (नौवें) को 'उच्च' श्रेणी में स्थान दिया गया है जबकि जी20 के आठ देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी (बहुत निम्न) में बने हुए हैं।

ऑस्ट्रेलिया (61 में से 56वां), सऊदी अरब और खासकर अमेरिका खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में हैं। अमेरिका पहली बार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश में शामिल हुआ है। सूचकांक के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की अगुआई में अमेरिका विभिन्न श्रेणियों में पहली बार 'निम्न' और 'बेहद निम्न' में आते हैं।

वैश्विक निवेशकों की पर्यावरण के लिए कार्रवाई की अपील

वैश्विक निवेशकों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी25) में शामिल होने वाली सरकारों से अपील की है कि वह पर्यावरण के वैश्विक संकट का हल निकालने का प्रयास करें और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोयले से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को बंद करेंगे। साथ ही कार्बन से होने वाले प्रदूषण की कीमत भी बढ़ाएंगे। जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी बंद करने की भी सिफारिश की गई है। कुल 37 अरब डॉलर के संस्थानों को चलाने वाले निवेशकों ने विभिन्न सरकारों से यह अपील की है।

जलवायु परिवर्तन पर जो वादा किया वह निभा रहे : जावडेकर

मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

मैड्रिड, प्रेट्र : पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत ने 'जो कहा है, वह कर रहा है'। साथ ही देश ने अपनी जीडीपी के 21 फीसद तक उत्सर्जन तीव्रता को कम किया है। उन्होंने कहा कि 2015 के पेरिस शिखर सम्मेलन में किए गए वादे के मुताबिक कार्बन उत्सर्जन में 35 फीसद कमी लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए काम जारी है।

मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) सीओपी-25 की उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भारत का रुख पेश किया और कहा कि देश ने 'जो कहा, वह किया है।' उन्होंने कहा कि केवल छह देश इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत इस सूची में सबसे ऊपर है। टिकाऊ व सतत जीवनशैली भारतीय लोकाचार का हिस्सा है। भारत सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उन्होंने देश में पर्यावरण परिवर्तन की रोकथाम के लिए किए जा रहे सभी उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस समझौते के तहत 175 गीगावॉट परिवर्तनीय ऊर्जा के लक्ष्य की घोषणा की है। हम पहले ही 83 गीगा वॉट का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट एक्शन समिट में 450 गीगा वॉट का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। हमने कोयला उत्पादन पर प्रति टन छह डॉलर की दर से कार्बन कर लगा दिया है।

स्पेन में दिल्ली के वायु प्रदूषण का अहसास

मैड्रिड, प्रेट्र : स्पेन की राजधानी में हो रहे सीओपी-25 पर्यावरण सम्मेलन में विश्व के नेता और अन्य आगंतुक भारत की राजधानी दिल्ली के वायु प्रदूषण के गंभीर हालात का अहसास कर रहे हैं। मैड्रिड में वायु प्रदूषण के खिलाफ एक कलात्मक मुहिम के तहत कई पॉड बनाए गए हैं। इसमें एक या दो मिनट रह कर लोग किसी देश के किसी शहर के वायु प्रदूषण को महसूस कर सकते हैं।

लंदन के कलाकार माइकल पिंक्सकी ने कई पॉल्यूशन पॉड बनाए हैं। इन गोलाकार पॉड में आकर लोग सांस में लेने में दिक्कत का अनुभव करते हैं। पिंक्सकी ने बताया कि हर पॉड में एक खास शहर की वायु की नकल तैयार की गई है। इन हवाओं से पूरे शरीर पर अलग संवेदनाओं का अहसास होता है। उदाहरण के तौर पर साओ पालो में ताजातरीन हवा के चलते किसी वन या सैंचुरी में रहने का अहसास होता है। जबकि भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हुए आंखें नम हो जाती हैं जबकि टॉट्रा की वायु अत्यधिक शुद्ध और ताजा है।

न्यूज गैलरी

पाक में महिला पोलियोकर्मी की गोली मारकर हत्या

पेशावर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने एक महिला पोलियोकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रांत के बन्नू जिले में ऑटो से जा रहीं पोलियोकर्मी बिस्ताज बीबी पर सोमवार को इस गोलीबारी में ऑटो ड्राइवर अब्दुर रऊफ भी बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। (प्रेट्र)

जापान में यूरेनियम की खरीद-फरोख्त में तीन गिरफ्तार

टोक्यो : जापान में यूरेनियम की ऑनलाइन खरीद-फरोख्त में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 24 साल के एक शख्स ने याहू की वेबसाइट पर यूरेनियम की बोली लगाई थी। जिसे 61 साल के फार्मासिस्ट और 17 साल के एक छात्र ने खरीदा था। यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा के लिए उन्होंने तीस हजार येन (करीब 20 हजार रुपये) चुकाए थे। (रायटर)

सूडान से आज आ सकते हैं 14 भारतीयों के शव

खारतूम : अफ्रीकी देश सूडान की एक फैक्ट्री में पिछले सप्ताह लगी आग में जान गंवाने वाले 14 भारतीयों के शव बुधवार को भारत पहुंच सकते हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि जिन शवों की पहचान हो गई है उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। गत तीन दिसंबर को राजधानी खारतूम में स्थित सीला सिरेमिक फैक्ट्री के एलपीजी टैंकर में हुए विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से 16 भारतीय लापता बताए गए थे। (प्रेट्र)

'तालिबान को पनाह नहीं दे पाक तो खत्म हो जाएगा अफगान युद्ध'

वाशिंगटन : अमेरिका के शीर्ष सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपने यहां तालिबान को पनाह देना बंद कर दे, तो अफगानिस्तान में जारी युद्ध कुछ हफ्तों में ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त करने के लिए तालिबान के बजाय पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। दक्षिणी कैरोलिना से सीनेटर ग्राहम ने 'फॉक्स चैनल' को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के साथ बातचीत कर मुझे लगता है, हम गलती कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें जो करना चाहिए वह पाकिस्तान से बातचीत है। (प्रेट्र)

उत्तर कोरिया पर यूएन सुरक्षा परिषद में अहम बैठक आज

संयुक्त राष्ट्र, रायटर : चेतावनी के बावजूद उत्तर कोरिया द्वारा लगातार किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। इसके मद्देनजर अमेरिका के आग्रह पर बुधवार को 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अहम बैठक होने जा रही है। उत्तर कोरिया ने हाल में दावा किया था कि उसने एक अहम सामरिक उपलब्धि हासिल की है। जानकार इसे एक और मिसाइल का परीक्षण बता रहे हैं। (रायटर)

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में भिड़े रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स

आरोप-प्रत्यारोप ▸ डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

रिपब्लिकन नेता बोले, महाभियोग की जांच महज प्रचार पाने का तरीका

शीर्ष रिपब्लिकन नेता, डग कॉलिंस। एएफपी

डेमोक्रेट्स के वकील डेनियल गोल्डमैन। एपी

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही सोमवार को नए चरण में पहुंच गई। संसद की न्यायिक समिति के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी डेमोक्रेट्स और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पक्ष रखा। डेमोक्रेट्स ने जहां ट्रंप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा करार दिया। वहीं रिपब्लिकन ने ट्रंप पर लगाए गए आरोप को खारिज करते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया।

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को फोन कर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की होड़ में शामिल पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ जांच के लिए दबाव बनाया था। डेमोक्रेट्स के वकील डेनियल गोल्डमैन ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप का किसी देश पर चुनाव जीतने और धोखा देने में मदद के लिए दबाव बनाना, निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।' आरोप को खारिज करते हुए शीर्ष रिपब्लिकन नेता डग कॉलिंस ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स का यह कदम महज प्रचार पाने का तरीका है। ट्रंप ने खुद भी इस जांच को 'फर्जी' कहा है। लेकिन डेमोक्रेट्स का मानना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सुबूत हैं कि ट्रंप ने अपने निजी राजनीतिक हितों को देश पर तरजीह दी।

एफबीआइ ने मेरी सरकार गिराने का प्रयास किया : ट्रंप

▸ न्याय विभाग के महानिरीक्षक की रिपोर्ट का स्वागत किया

वाशिंगटन, प्रेट्र : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच पर न्याय विभाग के महानिरीक्षक की रिपोर्ट का यह कहते हुए स्वागत किया है कि इससे पता चलता है कि एफबीआइ अधिकारियों ने 2016 के उनके चुनाव अभियान की जांच कर सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। अमेरिकी चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की जांच संबंधी न्याय विभाग की महानिरीक्षक रिपोर्ट का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया। उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा है कि इससे पता चलता है कि एफबीआइ अधिकारियों ने सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी।

न्याय विभाग के पुलिस महानिरीक्षक माइकल होरोविट्ज की रिपोर्ट सोमवार को जारी हुई। इसमें कहा गया है कि जांच करने वाले एफबीआइ एजेंट राजनीतिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित नहीं थे। हालांकि रिपोर्ट में जांच के तरीके को लेकर कई त्रुटियां पाई गईं हैं। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि यह सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास था। एफबीआइ जांच पर रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग हैं जो इस जांच में शामिल थे और वे पकड़े गए हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया कि न केवल इन लोगों ने सुबूत गढ़े, बल्कि अदालतों से भी झूठ बोला। जांच के दौरान कुछ ऐसा हुआ है, जिसे हम भविष्य में कभी नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि जब आप रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें इतनी बुरी बातें हैं, जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये लोग सफल हो सकते थे, अगर मैंने इसके खिलाफ कदम नहीं उठाए होते।

पहली बार मिले पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की

पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (बाएं), फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (मध्य में) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रायटर

पेरिस, एएफपी : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमिर जेलेंस्की की सोमवार को पहली बार पेरिस में मुलाकात हुई। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ जारी सैन्य संघर्ष को खत्म करने की दिशा में हुई इस वार्ता को पुतिन ने जहां महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं जेलेंस्की ने इस मसले के निपटारे के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत बताई।

मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की अगुआई में यह बैठक पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद देर रात मीडिया से मुखातिब पुतिन ने कहा, 'बातचीत सही दिशा में रही। संघर्ष खत्म करने के लिए रूस पूरी तरह तैयार है।' जबकि जेलेंस्की ने कहा, 'इमानदारी से कहूं तो यह बैठक अच्छी पहल थी, लेकिन मुझे इससे ज्यादा उम्मीद थी।' इस अहम वार्ता में यूक्रेन के अशांत पूर्वी क्षेत्र से सैनिकों की वापसी के जरिये अगले वर्ष मार्च तक संघर्षविराम के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया गया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कैदियों की रिहाई को लेकर भी सहमति जताई। बैठक में क्रीमिया पर रूसी कब्जे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई।

जंगलों में लगी आग के धुएं से घुटा सिडनी का दम

जंगलों में लगी आग के धुएं से ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी का दम घुटने लगा है। मंगलवार को सिडनी के कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर (200) से 11 गुना ज्यादा दर्ज किया गया। शहर के कुछ हिस्सों में आवागमन रोक दिया गया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से यथासंभव घरों में ही रहने और सांस के मरीजों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। न्यू साउथ वेल्स में एंबुलेंस सेवा के प्रमुख ब्रेंट आर्मिटेज ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग सांस संबंधी शिकायतों के कारण सहायता मांग रहे हैं। सिडनी रेलवे पहले ही चेतावनी दे चुका है कि घने धुएं के कारण स्टेशनों पर खराब स्थिति पैदा हो सकती है। यूनियन नेता थॉमस कोस्टा ने कहा, ऐसी हालत में श्रमिकों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शहर में हवा बहुत जहरीली है। उत्तर से आने वाली हवा के कारण धुआं तेजी से शहर में आ रहा है। उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में पिछले माह 50 से ज्यादा जगहों पर आग लगी थी। (एपी)

अमेरिका के और नागरिकों को मुक्त करने को ईरान तैयार

तेहरान, आइएएनएस : ईरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद जरीफ ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि उनका देश अपने यहां कैद अमेरिकी नागरिकों को आजाद करने को तैयार है। बीते शनिवार को दोनों देशों द्वारा अपने यहां कैद एक-दूसरे के एक-एक नागरिकों को मुक्त करने से उत्साहित जरीफ ने कहा कि ईरान ने अपनी तरफ से पहल कर दी है। इस पर अब अमेरिका द्वारा कदम बढ़ाने की जरूरत है।

ज्ञात हो कि बीते शनिवार को ईरान ने अपने यहां जासूसी के मामले में कैद अमेरिकी नागरिक शियुए वांग को रिहा किया था। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी जेल में बंद ईरानी प्रोफेसर मसूद सुलेमानी को रिहा किया था। जरीफ के सोमवार वाले बयान से कुछ देर पहले ईरान प्रशासन के प्रवक्ता ने कहा था कि उनका देश अमेरिका में कैद अपने सभी नागरिकों को वापस लाने को तैयार है। प्रवक्ता ने सुलेमानी को रिहा करने के अमेरिकी कदम को सही बताते हुए स्विट्जरलैंड की सराहना की। स्विट्जरलैंड ने दोनों देशों के बीच कैदियों की हुई अदला-बदली में मध्यस्थता की थी।

हांगकांग कोर्ट ने फेस मास्क पर से प्रतिबंध हटाया

▸ मुख्य कार्यकारी ने लोकतंत्र समर्थकों को रियायत देने से इन्कार किया

कैरी लैम। फाइल

हांगकांग, आइएएनएस/एएफपी : हांगकांग कोर्ट ने फेस मास्क पर से प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक पाए जाने की पूर्व की व्यवस्था को निलंबित करने का आग्रह ठुकरा दिया।

उधर देश की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने अपनी बीजिंग यात्रा से पहले लोकतंत्र समर्थकों को किसी तरह की रियायत देने से इन्कार कर दिया। लोकतंत्र समर्थकों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन के सोमवार को छह महीने हो गए। शुरुआत में प्रत्यर्पण कानून को लेकर शुरू हुआ आंदोलन बाद में चीन के शासन के विरोध में बदल गया।

हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जेरेमी पून शिउ और कोर्ट ऑफ अपील के वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन लैम ने मंगलवार को कहा कि वे संतुष्ट हैं कि सरकार की अपील सुनवाई के योग्य है, लेकिन यह भी पाया गया है कि अधिकारी निचली अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने को निलंबित करने की जरूरत साबित करने में विफल रहे।

उधर, लैम ने कहा कि हम केवल मांगों को पूरा करने के लिए कानून के शासन को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हम सभी समस्याओं की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब वह शनिवार को बीजिंग यात्रा पर जाएंगी तो राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात में घटनाओं का पूर्ण विवरण पेश करेंगी। नवंबर के अंत में शहर के लोकतंत्र समर्थकों को स्थानीय चुनावों में शानदार जीत मिली थी। इस जीत को समर्थकों ने आंदोलन के बारे में जनमत संग्रह के रूप में वर्णित किया था।

मुस्लिम समाज में शांति एवं सुधार के लिए अबू धाबी में सम्मेलन

जेएनएन, नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में फोरम फॉर प्रमोटिंग पीस इन मुस्लिम सोसाइटी की छठवीं वार्षिक सभा का आयोजन हो रहा है। फोरम का उद्देश्य दुनिया भर में शांति की मूल अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के 500 से ज्यादा विद्वान, उदारवादी मौलाना और नेता हिस्सा ले रहे हैं। भारत की तरफ से इस्लाम के जानकार और चिंतक रामिश सिद्दीकी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी शिरकत कर रहे हैं। तीन दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन नौ दिसंबर को शुरू हुआ था।

बुधवार को इसके समान पर 'न्यू अलायंस ऑफ वर्च्यू' चार्टर जारी किया जाएगा। इस फोरम की प्राथमिकता विश्व में शांति स्थापना के लिए संघर्ष को खत्म करना, संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना और अतीत के मतभेदों और वर्तमान की लड़ाइयों का समाधान निकालना है। दुनिया में शांति स्थापना के लिए काम करने वाले व्यक्ति को इमाम हसन इब्न अली पीस अवॉर्ड दिया जाता है।

ब्रिटेन चुनाव

पिछली बार के मुकाबले इस बार युवा दिखा रहे ज्यादा उत्साह, आवास, जलवायु परिवर्तन और ब्रेक्जिट के बारे में नेताओं से पूछे गए कई सवाल

बहस में राजनेताओं ने दिए युवाओं के सवालों के जवाब

▸ 2017 के चुनाव में 18 से 20 आयुवर्ग के सिर्फ 40 से 50 फीसद वोटरों ने ही किया था मतदान

▸ ब्रिटेन में गुरुवार को की जानी है वोटिंग

ब्रिटेन में मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कुछ इस अंदाज में नजर आए। रायटर

लंदन, आइएएनएस : चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनेताओं ने टीवी पर एक बहस में युवा मतदाताओं के आवास, जलवायु परिवर्तन और ब्रेक्जिट से जुड़े सवालों के खुलकर जवाब दिए। यह बहस सोमवार को बीबीसी टीवी पर प्रसारित की गई। ब्रिटेन के पिछले कुछ चुनावों में युवाओं ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। वर्ष 2015 और 2017 के चुनाव में 18 से 20 आयुवर्ग के सिर्फ 40 से 50 फीसद वोटरों ने ही मतदान किया था। जबकि बीती सदी के सातवें दशक में यह आंकड़ा अस्सी फीसद तक था। ब्रिटेन में गुरुवार को मतदान होना है।

दर्शकों ने पैनल में शामिल राजनेताओं से पूछा कि जब उन्होंने अपना पहला घर खरीदा था तो उनकी उम्र क्या थी? इस पर ब्रेक्जिट पार्टी के निगेल फराज ने बताया कि उस समय वह 22 साल के थे। पैनल में शामिल वेल्स के नेता एडम प्राइज एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे अधिक 30 साल की उम्र में अपना घर खरीदा था। जब फराज ने आवास से जुड़ी समस्याओं के लिए जनसंख्या वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया तो एसएनपी के यूसुफ हमजा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ब्रेक्जिट नेता देश में होने वाली किसी भी समस्या के लिए आप्रवासियों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के रॉबर्ट जेनरिक ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटी तो वह घर खरीदने के लिए लोगों को मदद प्रदान करेगी।

मीट खाने पर नहीं लगाएंगे प्रतिबंध : कंजरवेटिव : एक युवा ने सवाल किया कि सरकार यह कैसे कह सकती है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर है जबकि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले मीट की खपत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही। इस पर कंजरवेटिव पार्टी के रॉबर्ट जेनरिक ने कहा, हमारी पार्टी लोगों के मीट खाने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी। इसके बजाय पार्टी लोगों को सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा बचाने के उपायों के लिए प्रेरित करेगी। इस जवाब पर लिबरल डेमोक्रेट जो स्विनसन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने तो जलवायु परिवर्तन विभाग ही समाप्त कर दिया और पवन ऊर्जा के लिए दी जा रही सब्सिडी को भी रोक दिया है।

न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी से मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हुई

व्हाकटाने, रायटर : ज्वालामुखी के फिर से सक्रिय होने के भय के कारण तलाशी दल न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड पर जाने में असमर्थ है। अभी तक आठ लोग लापता हैं और मरने वालों की संख्या छह हो गई है। सोमवार को इस द्वीप पर ज्वालामुखी सक्रिय हो गया था। पुलिस ने बताया कि निर्जन द्वीप पर विस्फोट होने के बाद लावा की चपेट में आने से 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डर्न ने कहा कि टोही विमानों से राख से भरे द्वीप पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने संसद में कहा, 'यह त्रासदी विनाशकारी है। जिन लोगों ने परिवार और मित्र खोए हैं या लापता हैं, हम उनके दुख को समझ रहे हैं।' पुलिस ने कहा कि जिस समय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उस समय व्हाइट द्वीप पर 47 लोग थे। इनमें आस्ट्रेलिया के 24, अमेरिका के नौ, न्यूजीलैंड के पांच, जर्मनी के चार, चीन एवं ब्रिटेन के दो-दो और मलेशिया का एक व्यक्ति था।

यूएन की अदालत में म्यांमार से नरसंहार रोकने को कहा गया

▸ म्यांमार का पक्ष रखने के लिए द हेग पहुंची हैं आंग सान सू की

▸ 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में चलाया गया था सैन्य अभियान

द हेग, एएफपी : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के शीर्ष न्यायालय द हेग पहुंचीं नोबेल शांति विजेता आंग सान सू की को नरसंहार रोकने की अपील का सामना करना पड़ा। वह रोहिंग्या मुसलमानों पर दमन के खिलाफ म्यांमार का पक्ष रखने के लिए वहां गई हैं। बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ चलाए गए अभियान पर चुप्पी से उनकी अंतरराष्ट्रीय साख को धक्का लगा है।

मानवाधिकार समूहों ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में म्यांमार की नुमाइंदगी करने के उनके फैसले की आलोचना की है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गांबिया ने यह मामला उठाया है और आरोप लगाया है कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार समझौते का उल्लंघन किया है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ 2017 में सैन्य अभियान को लेकर म्यांमार को न्याय के कठघरे में लाने की यह पहली कोशिश है। मुस्लिम बहुल गांबिया 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से कदम उठा रहा है।

वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में चलाए गए सैन्य अभियान के बाद करीब सात लाख चालीस हजार रोहिंग्याओं ने भागकर बांग्लादेश में शरण ले ली थी। गांबिया के न्याय मंत्री अबूबकर तमबादोउ ने जजों से कहा, गांबिया और म्यांमार के बीच बहुत विवाद है। गांबिया आपसे म्यांमार से बर्बर कृत्यों को रोकने के लिए कहने का अनुरोध करता है। बर्बरता ने हमारी साझा अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उसे अपने ही लोगों के खिलाफ नरसंहार रोकना चाहिए। बता दें कि म्यांमार के परंपरागत परिधान पहने हुए सू की ने पहुंचने के बाद वहां मौजूद मीडिया से कोई बात नहीं की। वह कार से बाहर निकलीं और हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के परिसर में चली गईं।

ये भी जानिए
भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब तक तीन टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसमें भारत को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है, जबकि दो में हार का सामना करना पड़ा।

अब गलती मंजूर नहीं

- भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला आज
- पिछले मैच में क्षेत्ररक्षण की गलतियों को सुधारना चाहेगा भारत

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय टीम जब बुधवार को तीसरे और आखिरी टी-20 मुकाबले में यहां वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेगी, तो उसकी नजरें दूसरे टी-20 में की गई गलतियों को नहीं दोहराने पर होंगी, खासकर क्षेत्ररक्षण के क्षेत्र में। फिलहाल दोनों ही टीम सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं और दो बार की विश्व चैंपियन टीम ने दूसरे टी-20 में जबरदस्त वापसी करते हुए मेजबान टीम को शिकस्त दी थी।

भारत का फोकस एक बार फिर युवा स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और दबाव में चल रहे विकेटकीपर रिषभ पंत पर होगा। वानखेड़े में होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। सुंदर के मामले में यह देखना होगा कि टीम प्रबंधन उन पर ही भरोसा जताता है या फिर चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका देता है। सुंदर ने पिछले पांच टी-20 मुकाबलों में तीन विकेट ही लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 20 ओवर में 144 रन लुटा दिए हैं। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टी-20 मुकाबलों में तो उन्हें विकेट ही नहीं मिला था। सुंदर का क्षेत्ररक्षण भी सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से कप्तान विराट कोहली भी चिंतित हैं। पिछले मैच में उन्होंने लेंडल सिमंस का कैच टपका दिया था, जिसके बाद यही बल्लेबाज वेस्टइंडीज की जीत की वजह बना था। वहीं, कुलदीप ने अपना पिछला टी-20 मुकाबला फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेला था। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले दो मुकाबलों में कुलदीप को खेलने का मौका नहीं मिला। पंत के लिए चीजें लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। सारा ध्यान उन्हीं पर है और उनके लिए अपनी लय पाना आसान नहीं है, जिससे उनमें महेंद्र सिंह धौनी का उत्तराधिकारी नजर आ सके। पिछले मुकाबले में प्रशंसकों ने संजू-संजू के नारे लगाए थे, जिसके बाद सीमा रेखा पर खड़े कोहली ने प्रशंसकों से ऐसा करने से इन्कार कर दिया था। यह उस वक्त हुआ जब पंत ने विकेट के पीछे इविन लुइस का आसान सा कैच टपका दिया था। नंबर चार पर खेलते हुए पंत ने पिछली सात टी-20 पारियों में नाबाद 33, 18, 06, 27, 19 और 04 रन बनाए हैं। पंत ने पिछली बार अर्धशतक वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रोविडेंस में लगाया था।

कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं है। पिछले दो मुकाबलों में शांत रहने वाले रोहित शर्मा भी अपने घरेलू मैदान पर धमाका करना चाहेंगे। केएल राहुल और कोहली ने रन बनाए हैं। शिवम दुबे ने पिछले मैच में अपना पहला टी-20 अर्धशतक लगाया था। वह अपने घरेलू मैदान पर एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि वह लंबे छक्के लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही श्रेयस अय्यर के साथ है।

हालांकि, चिंता का विषय भारतीय गेंदबाजी है। भारतीय तेज गेंदबाजों भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर ने पहले दो मैचों में काफी रन लुटाए हैं। चाहर की बांग्लादेश के खिलाफ यादगार सीरीज रही थी, लेकिन वह वेस्टइंडीज के खिलाफ इसे दोहराने में कामयाब नहीं रहे हैं। मुहम्मद शमी की टीम में मौजूदगी के रहते चाहर को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण भी पिछले दो मुकाबलों में सवालों के घेरे में रहा है। टीम ने काफी खराब क्षेत्ररक्षण किया और कैच भी टपकाए। कोहली भी कह चुके हैं कि अगर क्षेत्ररक्षण में सुधार नहीं किया तो कोई भी लक्ष्य ज्यादा नहीं रहेगा। मेजबान टीम लक्ष्य का पीछा करने में माहिर है, लेकिन टीम को विश्व कप से पहले लक्ष्य बचाना भी सीखना होगा।

दूसरी ओर वेस्टइंडीज भी सीरीज में वापसी करने के बाद तीसरे टी-20 को जीतना चाहेगी। उसका शीर्ष क्रम खासकर सिमंस बेहतरीन फॉर्म में हैं। इसके साथ ही लुइस, निकोलस पूरन और शिमरोन हेटमायर भी रन बना रहे हैं और वे सभी इस फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। इसके अलावा ब्रेंडन किंग, जेसन होल्डर और कप्तान कीरोन पोलार्ड के रहते किसी भी टीम के लिए वेस्टइंडीज को हराना मुश्किल हो सकता है। उसके गेंदबाज भी खासकर शेल्डन कॉटरेल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ केसरिक विलियम्स, लेग स्पिनर हेडन वॉल्श जूनियर और होल्डर ने सही जगह पर गेंदबाजी करके रनों पर लगाम लगाई है। वेस्टइंडीज ने वानखेड़े से 2016 आइसीसी टी-20 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को हराकर ही फाइनल में प्रवेश किया था।

वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार को मुंबई में होने वाले तीसरे टी-20 से पहले मंगलवार को अभ्यास सत्र में भाग लेते टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा ● प्रेट्र

विश्व कप अभी दूर, विंडीज के खिलाफ जीतना लक्ष्य : रोहित

भारतीय टीम के उप कप्तान ने कहा, टीम को अपने बेसिक्स को बेहतर कर मैच जीतने की जरूरत

मुंबई, प्रेट्र: भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस समय उनका ध्यान बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले आखिरी टी-20 मैच पर है, जो तीन मैचों की सीरीज के विजेता का फैसला करेगा।

रोहित ने मंगलवार को यहां कहा कि मैं लगातार यह नहीं कह सकता कि हम टी-20 विश्व कप के लिए टीम बना रहे हैं। यह अभी दूर है। हमें इस समय सीरीज जीतने पर ध्यान देना है और यह हमें अच्छी स्थिति में रखेगी और आगे ले जाएगी। सीमित ओवरों में टीम के उप-कप्तान रोहित ने कहा कि इस समय टीम को अपने बेसिक्स को बेहतर कर मैच जीतने की जरूरत है, ताकि वह विश्व कप की तैयारी कर सके। अगर हम लगातार मैच जीतते रहें और लगातार अच्छी चीजें करते रहे तो टीम का संयोजन अपने आप बन जाएगा।

तीसरे टी-20 के लिए फिट नहीं कैरेबियाई ऑलराउंडर एलेन

मुंबई, प्रेट्र: वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फेबियान एलेन भारत के खिलाफ बुधवार को यहां तीसरे और आखिरी टी-20 में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह अभी भी घुटने की चोट से पूरी तरह से उबर नहीं सके हैं। वेस्टइंडीज के कोच फिल सिमंस ने मंगलवार को बताया कि एलेन अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। उन्होंने मैच से पूर्व कहा कि एलेन बुधवार को खेलने के लिए फिट नहीं है। हमें उनकी कमी खलेगी, क्योंकि वह शानदार क्रिकेटर हैं। एलेन को अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में पहले मैच के बाद ही घुटने की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था। वह भारत के खिलाफ दोनों टी-20 मैच नहीं खेल सके।

दोनों टीमों के पास सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन चुनौती है पिछली गलतियों से सीख कर निर्णायक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की। हैदराबाद में भारत ने कप्तान विराट कोहली की पारी के दम पर विशाल लक्ष्य को बौना साबित कर जीत हासिल की थी। लेकिन, तिरुअनंतपुरम में खेले गए दूसरे मैच में विंडीज ने हिसाब बराबर कर लिया। अभी तक भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण सबसे लचर रहा है। दोनों मैचों में क्षेत्ररक्षकों ने कैच छोड़े थे। तीसरे मैच में टीम इंडिया इस पर ध्यान देना चाहेगी। रोहित ने कहा कि कीरोन पोलार्ड के कप्तानी संभालने के बाद वेस्टइंडीज की टीम में काफी बदलाव आ गया है।

भारतीय टी-20 टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, रिषभ पंत (विकेटकीपर), मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, भुवनेश्वर और मुहम्मद शमी।

वेस्टइंडीज : कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फेबियान एलेन, ब्रेंडन किंग, दिनेश रामदीन, कॉटरेल, इविन लुइस, शेरफेन रदरफॉर्ड, शिमरोन हेटमायर, खारे पियरे, लेंडल सिमंस, जेसन होल्डर, हेडन वाल्श जूनियर, कीमो पॉल, केसरिक विलियम्स।

01 विकेट लेते ही टी-20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे युजवेंद्रा सिंह चहल। वह इस मामले में रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ देंगे

57 पारी में 1136 रन टी-20 क्रिकेट में बना कर इस वर्ष सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं कीरोन पोलार्ड। 55 रन बनाते ही वह टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर मौजूद ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ देंगे। टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने 13152 रन बनाए हैं

विराट को खल रही है बुमराह की कमी

के श्रीकांत
कलम से

दूसरे टी-20 मैच में वेस्टइंडीज को मिली जीत भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी की तरह है। अब दोनों टीमों को निर्णायक मुकाबले में भिड़ना है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुश्किल हालात किसी खिलाड़ी से उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम का भी हर खिलाड़ी आगे बढ़कर अपनी-अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। वेस्टइंडीज की मुंबई से सुखद यादें जुड़ी हैं, खासकर इस प्रारूप से। वहीं, भारतीय टीम भी ये दिखाने के लिए उत्सुक होगी कि उसकी गेंदबाजी की धार जसप्रीत बुमराह तक ही सीमित नहीं है। ये और बात है कि विराट कोहली बुमराह की सटीक गेंदबाजी और मारक गति को याद कर रहे होंगे।

सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले गेंदबाजों के लिए आसान नहीं रहे। सपाट पिच, ओस और खराब फील्डिंग ने उनके लिए हालात और मुश्किल कर दिए। वहीं भारतीय गेंदबाजी आक्रमण औसत दर्जे का नजर आया। इस लिहाज से जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जो परिस्थितियों को गणना से बाहर कर देते हैं। वह जिस तरह का कोण बनाते हैं और शानदार यॉर्कर फेंकते हैं, उनकी इसी खूबी ने उन्हें ऐसा गेंदबाज बनाया है, जैसे कि वह आज हैं। उनके पास विविधता है, जो उनका स्वाभाविक हथियार है। अगर आप गौर करें तो बुमराह एक छोर से रनों का प्रवाह रोककर दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे खिलाड़ियों की भी मदद करते हैं। कप्तान मैच के दौरान किसी भी पल उनके चार ओवरों का इस्तेमाल कर सकता है। कप्तान के पास यह विकल्प ही बुमराह को सबसे मूल्यवान गेंदबाज बनाता है, जिसकी कमी टीम को खल भी रही है।

पिच से भारतीय स्पिनरों को मदद नहीं मिल रही है, इसलिए टीम के पास विचारों की कमी हो गई है। वहीं दूसरी ओर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इस बार बेहतर तैयारी के साथ आए हैं। मुझे युजवेंद्रा सिंह चहल के खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर जाकर जगह बनाकर शॉट खेलने की मेहमान बल्लेबाजों की योजना अच्छी लगी। जहां तक बात भारतीय गेंदबाजी की है तो भले ही बुमराह और हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद हालात बदलेंगे, लेकिन अन्य गेंदबाजों को भी आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में यह मैच बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। प्रशंसकों की तरह मैं भी उतना ही उत्साहित हूं। उम्मीद है कि बेहतर टीम ही जीतेगी। **(टीसीएम)**

आज के मैच में ACC KAMAAL ka MOMENT कौन जीतेगा?
वोट करने के लिए, लॉग ऑन करें facebook.com/accind
ACC OFFICIAL PARTNER

एक नजर में

ओलंपिक, विश्व कप से बाहर करने से रूस खफा

लुसाने : विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने डोपिंग के गलत आंकड़े देने के आरोप में रूस में चार साल का प्रतिबंध लगा दिया है जिस पर राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लुसाने में वाडा की कार्यकारी समिति की बैठक में रूस पर चार साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया जिससे वह टोक्यो ओलंपिक 2020 और कतर विश्व कप 2022 नहीं खेल सकेगा। उसने रूस पर डोपिंग जांच प्रयोगशाला के गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया है। इस प्रतिबंध की वजह से रूसी सरकारी अधिकारी किसी बड़े टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वहीं रूस को किसी टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार भी नहीं होगा। पुतिन ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित और ओलंपिक चार्टर के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, 'रूसी ओलंपिक समिति की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है। रूस अपने झंडे तले खेलों में भाग लेगा।' रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने कहा, 'यह रूस विरोधी उन्माद का सिलसिला है और अब यह नासूर बन चुका है।' (एएफपी)

हरियाणा मजबूत स्थिति में

लाहली : शुभम रोहिल्ला के 142 रन के दम पर हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप-सी मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ दूसरे दिन मंगलवार को यहां पहली पारी में 401 रन बनाने के बाद महाराष्ट्र के चार बल्लेबाजों को 88 रन पर पवेलियन भेज दिया। हरियाणा ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 279 रन से की। रोहिल्ला और हिमांशु राणा (40) ने चौथे विकेट के लिए 81 की साझेदारी की। रोहिल्ला ने 285 गेंद की पारी में 17 चौकों की मदद से 142 रन बनाए। महाराष्ट्र के लिए अनुपम संकलेचा ने चार, जबकि सत्यजीत बाचव ने तीन विकेट लिए। महाराष्ट्र की टीम पहली पारी के आधार पर हरियाणा से अभी 313 रन पीछे है। (प्रेट्र)

सिंधू की नजर खिताब पर

ग्वांग्झू : विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के बाद से खराब दौर से जूझ रही भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू को उम्मीद है कि यहां बुधवार से शुरू हो रहे सत्र के आखिरी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में वह फॉर्म में लौटेंगी। सिंधू ने अगस्त में बासेल में विश्व चैंपियनशिप जीती, लेकिन उसके बाद से वह लगातार खराब फॉर्म में हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू जुलाई में इंडोनेशिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थीं। इसके बाद कोरिया ओपन और फुजोउ ओपन में पहले दौर से बाहर हो गईं, जबकि चाइना ओपन, डेनमार्क ओपन और हांगकांग ओपन के दूसरे दौर में हारीं। बीडब्ल्यूएफ रेस टू ग्वांग्झू रैंकिंग में सिर्फ शीर्ष आठ खिलाड़ी ही विश्व टूर फाइनल्स खेलते हैं। सिंधू इस साल के आखिर में 15वें स्थान पर होंगी, लेकिन विश्व चैंपियन होने के कारण उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। सिंधू ने विश्व फाइनल्स की तैयारी के लिए हांगकांग ओपन के बाद ब्रेक लिया था। वह 2017 व 2018 में फाइनल खेल चुकी हैं। (प्रेट्र)

धौनी कभी भी खुद को टीम पर नहीं थोपेंगे : शास्त्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय कोच रवि शास्त्री ने कहा कि अगर महेंद्र सिंह धौनी को लगता है कि वह अगले साल टी-20 विश्व कप खेलने की दौड़ में हैं तो इस पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व कप्तान कभी खुद को टीम पर नहीं थोपेंगे।

कोच शास्त्री ने से जब धौनी के भविष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह (धौनी) महान खिलाड़ी हैं। उन्हें जानने के कारण मुझे पता है कि वह खुद को कभी भारतीय टीम पर नहीं थोपेंगे। वह ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन वह आइपीएल खेलने जा रहे हैं। इंग्लैंड में खेले गए क्रिकेट विश्व कप के बाद से धौनी ब्रेक पर हैं। शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि धौनी वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा कि अगर आइपीएल के बाद उन्हें लगता है कि वह भारत के लिए खेल सकते हैं तो किसी को उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।

धौनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं पर चुप्पी बनाए रखने के बाद हाल ही में कहा था कि जनवरी तक कुछ भी मत पूछो। पिछले महीने धौनी को झारखंड की अंडर-23 टीम के साथ रांची में अभ्यास करते देखा गया था, जिसके बाद उनकी वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं।

गर्मी में कंगारू लेंगे कीवियों का टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच डे-नाइट टेस्ट कल से, टेस्ट के दौरान 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान

पर्थ, एएफपी : केन विलियमसन की अगुआई वाली न्यूजीलैंड की टीम जानती है कि यदि उन्हें तीन दशक से ज्यादा में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना है तो स्थानीय परिस्थितियों से जल्द अभ्यस्त होना होगा। दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट पर्थ में गुरुवार से खेला जाएगा, जो डे-नाइट होगा।

पहले टेस्ट से पूर्व मेहमान टीम को अभ्यास मैच नहीं मिला है। पहले टेस्ट के दौरान शुरुआती तीन दिन पर्थ में करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान है, जिसका सामना करना कीवी टीम के लिए आसान नहीं होगा। यहां से टीम बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए मेलबर्न का रुख करेगी। न्यूजीलैंड ने पिछले सप्ताह इंग्लैंड के खिलाफ 1-0 से सीरीज जीत के बाद जो लय हासिल की है, वह उनके लिए मददगार होगी। हालांकि यह जीत उन्हें न्यूजीलैंड के धीमे विकेट पर मिली थी। वहीं पर्थ में उन्हें तेज और उछाल वाले विकेट पर गुलाबी गेंद से खेलना होगा। न्यूजीलैंड ने पिछली बार डे-नाइट टेस्ट करीब दो साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेला था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया हाल ही में पाकिस्तान को एडिलेड में पारी और 48 रनों से हराकर अभ्यस्त है।

कीवी टीम को मिली अच्छी खबर : न्यूजीलैंड को मैच से पहले अच्छी खबर मिली है। हरफनमौला कोलिन डि ग्रैंडहोम फिट हो गए हैं। उन्हें पिछले माह इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद पेट की मांसपेशियों में समस्या हो गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट भी चोटिल हो गए थे। मगर अब वह फिट हैं। पर्थ की पिच पर वह साथी गेंदबाजों टिम साउदी और नील वैगनर के साथ टीम के लिए मैच विजेता साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लॉथम के अनुसार हम यहां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों से आशंकित नहीं हैं। हम उनके खिलाफ पहले भी खेल चुके हैं। इसलिए जानते हैं कि उनके खिलाफ क्या करना है। टिम पेन की ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रदर्शन में पिछले कुछ समय में निरंतरता नजर आई है। टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराते हुए एशेज पर कब्जा कायम रखा। फिर पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से जीत हासिल की। एडिलेड में 335 रनों की पारी खेलने वाले डेविड वार्नर तूफानी फॉर्म में हैं। वहीं, रोस टेलर को अभ्यास सत्र के दौरान दायें हाथ के अंगूठे में चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने अभ्यास सत्र छोड़ दिया। हालांकि, टीम प्रबंधन के अनुसार चोट गंभीर नहीं है और टेलर को वर्फ की सिकाई की जा रही है।

डे-नाइट टेस्ट

विलियम्स बेहतरीन बल्लेबाज हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी सीरीज में हम उन्हें खामोश रखेंगे।
स्टीव स्मिथ, बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया

डे-नाइट क्रिकेट मजेदार होगा। हमें इससे अभ्यस्त होना होगा। मैं इसकी उम्मीद करता हूं। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है। हम यात्रा करते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं और सीधे मैच में उतरते हैं। सही अभ्यास क्या होता है, यह समझना कठिन है।
केन विलियमसन, कप्तान, न्यूजीलैंड

मौका मिला तो शिवम ने घर पर बिताया वक्त

उमेश राजपूत ● नई दिल्ली

फुर्सत के पल
- मां ने बेटे को उसकी पसंद के मैथी के पराठे खिलाए
- पिता ने कहा, अब थोड़ा धैर्य रखकर खेलें शिवम

शिवम दुबे की एक पारी ने उन्हें भारत के चमकते सितारों की जमात में लाकर खड़ा कर दिया है। शिवम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 में कप्तान विराट कोहली के भरोसे को बनाए रखा और अर्धशतक जड़ा था। अब शिवम उस वानखेड़े स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं जहां उनका बचपन गुजरा है।

तीसरा टी-20 खेलने मुंबई पहुंचे शिवम ने थोड़ा समय अपने परिवार के साथ भी बिताया। शिवम के पिता राजेश दुबे ने कहा कि शिवम एयरपोर्ट सीधे घर आए और फिर परिवार के साथ समय गुजारने के बाद मंगलवार सुबह चले गए। शिवम की मां माधुरी दुबे ने उम्मीद जताई कि उनका बेटा आगे भी ऐसे ही खेलता रहे। शिवम को मैथी के पराठे खूब पसंद हैं और सोमवार को घर आने के बाद मां ने शिवम के लिए मैथी के पराठे बनाए।

पिता ने बताया कि शिवम घर पर आए, लेकिन उन्होंने अपनी वहां मौजूदगी के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था। वह आराम करना चाहते थे। मंगलवार सुबह शिवम अभ्यास के लिए वानखेड़े स्टेडियम चले गए। उनके साथ उनके पिता भी गए और उन्होंने दूर से शिवम को अभ्यास करते हुए देखा। शिवम ने बल्लेबाजी के साथ-साथ कैचिंग का भी अभ्यास किया। वह शिवम के अभ्यास से संतुष्ट नजर आए। शिवम लगातार तीन-चार छक्के मारने में माहिर हैं, लेकिन पिता चाहते हैं कि शिवम अब थोड़ा धैर्य रखकर खेलें।

राजेश ने कहा कि शिवम ने उन्हें बताया कि दूसरे टी-20 मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली शिवम को खुलकर खेलने को कहा। हालांकि, इसके बावजूद दूसरे छोर पर कोहली के होने की वजह से ही वह कुछ दबाव महसूस कर रहे थे। अब शिवम का पूरा परिवार और उनके तीन करीबी दोस्त बुधवार को तीसरा निर्णायक मुकाबला देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे। शिवम के ये तीनों दोस्त उन्हें बचपन से ही अभ्यास कराया करते थे।

आइसीसी प्रमुख के रूप में कार्यकाल नहीं बढ़ाना चाहते मनोहर

नई दिल्ली, आइएएनएस : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के चेयरमैन शशांक मनोहर का कार्यकाल मई 2020 में समाप्त हो रहा है। वह अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, उनके अनुसार अधिकांश निदेशक चाहते हैं कि वह अपना कार्यकाल आगे बढ़ाएं।

बीसीसीआइ के पूर्व प्रमुख मनोहर ने कहा, 'मैं आगे दो साल के कार्यकाल के लिए इच्छुक नहीं हूं। अधिकांश निदेशकों ने मुझसे निवेदन किया है कि मैं पद पर बना रहूं, लेकिन मैं उन्हें कह चुका हूं कि ऐसा करना नहीं चाहता। मैं करीब पांच साल से चेयरमैन हूं। मैं इस बारे में बेहद स्पष्ट हूं कि जून 2020 के बाद मैं कार्यकाल आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अगली मई में मेरे उत्तराधिकारी का पता चल जाएगा।' मनोहर को मई 2016 में आइसीसी के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के रूप में चुना गया था। उन्हें दो साल के लिए पुनः 2018 में चुना गया था। उनके आइसीसी प्रमुख रहते कई फैसले ऐसे रहे, जिससे बीसीसीआइ नाखुश रहा। आइसीसी द्वारा प्रस्तावित भविष्य दौरा कार्यक्रम पर भी संशय है क्योंकि इसमें हर साल टी-20 विश्व कप कराने और तीन साल में 50 ओवर का विश्व कप कराने की अनुशंसा है।

भारतीय शटलर ज्वाला ने घर बेचकर खोली खेल अकादमी

निखिल शर्मा ● नई दिल्ली

शुरुआत
- हैदराबाद में खोली गई अकादमी की दिल्ली में हुई लांचिंग
- बैडमिंटन के अलावा क्रिकेट, टेनिस, तैराकी की भी दी जाएगी ट्रेनिंग

ज्वाला का यह कदम सराहनीय है। ज्वाला की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं ज्वाला और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। **सुशील कुमार,** पहलवान

ओलंपियन और भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा की मौजूदगी में मंगलवार को यहां ज्वाला गुट्टा अकादमी ऑफ एक्सीलेंस लांच हुई। ज्वाला ने बताया कि हैदराबाद स्थित इस अकादमी को खोलने के लिए उन्हें बेहद संघर्ष करना पड़ा। कहीं से मदद नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपना एक घर बेचकर यह अकादमी खोली है। इस मौके पर दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय पहलवान सुशील कुमार और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह सहित सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे।

हैदराबाद में गाचीबौली इलाके के सुजाता हाई स्कूल में खोली गई इस अकादमी में विश्व स्तरीय 14 बैडमिंटन कोर्ट मौजूद हैं। बैडमिंटन के साथ ही यहां पर क्रिकेट, टेनिस, तैराकी जैसे खेलों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस अकादमी में 100 बच्चों के ठहरने लायक हॉस्टल भी मौजूद है। अकादमी में योगा सेंटर और सभी सुविधाओं से लेस जिम भी मौजूद है। ज्वाला ने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे वास्तव में अनुशासन और निरंतरता के महत्व का अहसास हुआ है, न केवल खेल में, बल्कि सामान्य जीवन में भी। मेरे मन में एक अकादमी बनाने की सोच थी। मैं उन लोगों में अनुशासन विकसित करने का प्रयास करूंगी, जो बैडमिंटन सीखने के लिए तैयार हैं।

उत्तरी भारत की जगह दक्षिणी भारत में अकादमी खोलने पर ज्वाला ने कहा कि मुझे पता है कि हैदराबाद में पहले से ही एक अकादमी मौजूद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उत्तरी भारत के खिलाड़ियों को भी यहां ट्रेनिंग मिले। मैं भारत सरकार से भी मांग करती हूं कि उत्तरी भारत में ही अकादमी खुलवाने में मेरा सहयोग करें।

ट्रायल दे सकता हूं, कैंप नहीं : विजेंदर

नई दिल्ली : पेशेवर मुक्केबाजी में लगातार सफलता हासिल कर रहे विजेंदर सिंह ओलंपिक में खेलने को तैयार हैं। विजेंदर ने कहा कि मैं ट्रायल देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बाद लगने वाले महीनों भर के कैंप बोझिल हो जाते हैं। कई समस्याएं आती हैं। नाडा द्वारा अभिनेता सुनील शेट्टी को ब्रांड एंबेसडर बनाने पर विजेंदर ने कहा कि यह फैसला तो समझ से बाहर है। हमारे देश में कई अच्छे एथलीट मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। उनकी जगह किसी अभिनेता को यह जिम्मेदारी देने पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

नासिर जमशेद स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी

लंदन, रायटर : पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद स्पॉट फिक्सिंग के मामले में ब्रिटेन के न्यायालय द्वारा अन्य खिलाड़ियों को प्रलोभन देने के मामले में दोषी पाए गए हैं। उन्होंने अपराध स्वीकार लिया है और उन्हें फरवरी में सजा सुनाई जाएगी।

30 साल के जमशेद को अगस्त 2018 में भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्युनल द्वारा 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। उन पर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को हिला देने वाले स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल होने का आरोप था। गत दिसंबर में उन पर रिश्वत देने का आरोप लगा था। जमशेद ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पाकिस्तान के लिए कुल 68 मैच खेले हैं। जमशेद ने पहले आरोप से इन्कार किया था, लेकिन इंग्लैंड के मैनचेस्टर में सुनवाई के दौरान अपनी याचिका बदल दी। जमशेद को ब्रिटिश नागरिक यूसुफ अनवर (36) और मुहम्मद एजाज (34) के साथ गिरफ्तार किया गया था। यूसुफ और एजाज रिश्वत देने की बात पहले ही मान चुके थे।

सरकारी वकील ने बताया कि एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी ने खुद को फिक्सिंग गिरोह का सदस्य बताते हुए इस नेटवर्क में जगह बनाई। उन्होंने 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फिक्सिंग के प्रयास और फरवरी 2017 में पीएसएल में फिक्सिंग का रहस्योद्घाटन किया। इन टी-20 टूर्नामेंट से जुड़े दोनों ही मामलों में एक ओपनर ने पैसे लेकर एक ओवर की पहली दो गेंद पर रन नहीं बनाने की सहमति दी थी। बांग्लादेश में पहली दो गेंद पर रन नहीं बनाने की योजना में फिक्सर के निशाने पर जमशेद थे।

चैंपियंस लीग बायर्न-टॉटनहम मैच में एल्फोंसो पर होंगी निगाहें, पहले ही अंतिम-16 में जगह बना चुका है जर्मन क्लब

शरणार्थी शिविर से निकल बायर्न में छाए डेविस

बर्लिन, एएफपी : अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक कनाडा के युवा एल्फोंसो डेविस का जीवन शरणार्थी शिविर में शुरू हुआ था, लेकिन अब वह जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के साथ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। इस दौरान डेविस बायर्न के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं।

पहले ही अंतिम-16 में जगह बना चुकी बायर्न म्यूनिख की टीम बुधवार को यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप-बी में इंग्लिश क्लब टॉटनहम से भिड़ेगी, जहां रॉबर्ट लेवांदोवोस्की की मौजूदगी के बीच डेविस भी आकर्षण के केंद्र में होंगे। अगर बायर्न यह मुकाबला जीत जाता है तो वह चैंपियंस लीग के सभी छह ग्रुप मुकाबले जीतने वाला पहला जर्मन क्लब बन जाएगा। हालांकि, उसके लिए यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नए मैनेजर जोस मौरिन्हो के मार्गदर्शन में टॉटनहम की टीम बिलकुल अलग नजर आ रही है। पिछले महीने 19 साल के हुए डेविस अक्टूबर में टॉटनहम पर मिली 7-2 की धमाकेदार जीत वाले मुकाबले में बेंच पर बैठे थे। हालांकि, निकलस सुइल और लुकास हर्नांडेज जैसे सेंटर बैक खिलाड़ियों के चोटिल होने से डेविस को शुरुआती लाइन-अप में जगह मिली है। आमतौर पर डेविस एक स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन डेविड अल्बा के सेंटर बैक में खेलने की वजह से उन्हें लेफ्ट बैक में खेलना पड़ रहा है, लेकिन इस भूमिका में भी वह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। वह बायर्न के पिछले सभी नौ मुकाबलों में पूरे समय तक मैदान में रहे हैं।

फिल्मी है डेविस का जीवन : घाना में जन्मे डेविस का बचपन शरणार्थी शिविर में बीता। इसके बाद बचपन में ही उन्हें अपने परिवार के साथ कनाडा आना पड़ा और यहीं उन्होंने फुटबॉल की बारीकियां सीखीं। आगे चलकर डेविस 16 साल की आयु में कनाडा की राष्ट्रीय टीम की ओर से पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उन्हें कनाडा की नागरिकता मिलते ही राष्ट्रीय टीम में जगह मिली थी।

10 गोल के साथ बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांदोवोस्की चैंपियंस लीग के मौजूदा सत्र में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं

05 मुकाबले ग्रुप-बी में जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने खेले हैं और इन सभी में उसने जीत हासिल करके पहले ही चैंपियंस लीग के अंतिम-16 में अपनी जगह पक्की कर ली है

आज के मुकाबले

मैच	समय
डायनमो जाग्रेब vs मैनचेस्टर सिटी	23:25
शाख्तर डोनेट्स्क vs अटलांटा	23:25
एटलेटिको मैड्रिड vs लोकोमोटिव मास्को	01:30
बायर लेवरकुसेन vs जुवेंटस	01:30
बायर्न म्यूनिख vs टॉटनहम	01:30
क्लब ब्रुग vs रीयल मैड्रिड	01:30
ओलंपियाकोस vs रेड स्टार बेलग्रेड	01:30
पीएसजी vs गालातसारी	01:30

समय (भारतीय समयानुसार) है।

एटलेटिको के लिए कड़ी परीक्षा की घड़ी

मैड्रिड, एएफपी : एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमोन मौजूदा सत्र को अपने क्लब के लिए बदलाव का समय बता चुके हैं। क्लब के हालिया प्रदर्शन ने मैनेजर के भविष्य के साथ क्लब के भविष्य पर भी संदेह खड़े कर दिए हैं। चैंपियंस लीग के ग्रुप-डी में एटलेटिको मैड्रिड का सामना बुधवार को लोकोमोटिव मास्को से होगा, जहां स्पेनिश क्लब के लिए यह एक कड़ी परीक्षा की घड़ी होगी। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना से 0-1 से हारने के बाद उसकी खिताबी उम्मीदें बिखरती नजर आई थीं। एंटोनी ग्रीजमैन, लुकास हर्नांडेज, डिएगो गोडिन, रोड्री, जुआनफ्रान और फिलिप लुइस के पिछले सत्र में जाने के बाद एटलेटिको की स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाई है। ग्रुप-डी से जुवेंटस पहले ही क्वालीफाई कर चुका है।

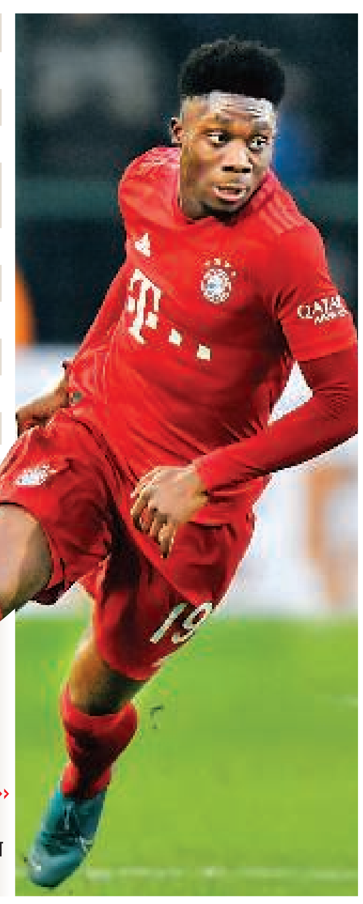
बायर्न म्यूनिख के एल्फोंसो डेविस ● फाइल फोटो, एपी

नॉटिंघमशायर का पाक गेंदबाज अब्बास से करार

लंदन, आइएएनएस : इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर ने 2020 सत्र के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मुहम्मद अब्बास के साथ करार किया है। अब्बास सत्र के पहले नौ मैचों के लिए नॉटिंघमशायर के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद वह इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। 29 वर्षीय अब्बास ने 2017 में पाकिस्तान के लिए टेस्ट में पदार्पण किया था।

संजू सैमसन को उनके घरेलू मैदान पर नहीं खिलाकर टीम इंडिया ने अपना ही नुकसान किया है।
– शशि थरूर, कांग्रेस नेता

दक्षिण एशियाई खेल ▶ कुल 309 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को भारत ने पीछे छोड़ा

रिकॉर्ड 312 पदकों के साथ शीर्ष पर

अंतिम दिन भारतीय मुक्केबाजों ने जीते छह स्वर्ण

काठमांडू, प्रेट्र : भारत ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का समापन रिकॉर्ड 312 पदकों के साथ शीर्ष पर रहते हुए किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 174 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य के साथ सर्वाधिक 312 पदक हासिल करते हुए दक्षिण एशियाई खेलों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इससे पहले भारत ने गुवाहाटी एवं शिलांग में 2016 में हुए पिछले दक्षिण एशियाई खेलों में कुल 309 पदक (189 स्वर्ण, 90 रजत और 30 कांस्य) हासिल किए थे जो इस प्रतियोगिता में किसी भी देश द्वारा हासिल सर्वाधिक कुल पदक थे। हालांकि पिछले आयोजन के मुकाबले भारत को इस बार 15 स्वर्ण पदक कम हासिल हुए। इस बार भारत ने 487 खिलाड़ियों का जत्था भेजा था। हालांकि 2016 के आयोजन में कुल 789 पदक दाव पर थे जिसमें 263 पदक स्पर्धाएं थीं लेकिन इस बार 338 पदक स्पर्धाओं में 1014 पदक दाव पर थे।

पदक तालिका में मेजबान नेपाल कुल 206 पदकों (51 स्वर्ण, 60 रजत, 95 कांस्य) के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि श्रीलंका 251 पदकों (40 स्वर्ण, 83 रजत और 128 कांस्य) के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 1984 से शुरू हुए दक्षिण एशियाई खेलों के हर आयोजन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

सैग गेम्स में मुक्केबाजी फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद जश्न मनाती पिंकी। आइएएनएस

अंतिम दिन मुक्केबाजों का जलवा : प्रतियोगिता के अंतिम दिन मंगलवार को भारत ने 18 पदक (15 स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य) जीते, जिसमें मुक्केबाजों ने छह स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया। बास्केटबॉल में भारत की पुरुष और महिला टीमों ने क्रमशः श्रीलंका (101-62) और मेजबान नेपाल (127-46) को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किए। स्क्वॉश में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण और पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। विकास कृष्ण (69 किग्रा) और पिंकी रानी (51 किग्रा) की अगुआई में भारत ने छह और स्वर्ण पदक जीते, जिससे भारतीय मुक्केबाजों ने अपने अभियान का अंत 16 पदक के साथ किया। पुरुष वर्ग में विकास के अलावा स्पर्श कुमार (52 किग्रा) और नरेंदर (91 किग्रा से अधिक) ने भी स्वर्ण पदक जीते, जबकि महिला मुक्केबाजों में सोनिया लाठेर (57 किग्रा) और मंजू बंबोरिया (64 किग्रा) ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने मुक्केबाजी में यहां 12 स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता विकास ने पाकिस्तान के गुल जैब को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। नरेंदर को भी नेपाल के आशीष दुवादी को 5-0 से हराने के लिए अधिक पसीना नहीं बहाना पड़ा। वहीं मंगलवार को फाइनल में उतरी भारत की सभी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते।

मारपीट मामले में हॉकी इंडिया ने 11 खिलाड़ियों को निलंबित किया

नई दिल्ली, आइएएनएस : हॉकी इंडिया (एचआइ) की अनुशासन समिति ने पिछले महीने 56वें नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पंजाब पुलिस और पंजाब नेशनल बैंक के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में हुई हाथापाई के कारण 11 खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही टीम के अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। यह लड़ाई पंजाब पुलिस के हरदीप सिंह और पंजाब नेशनल बैंक के सुमित टोप्पो के बीच हुई थी जिसमें बाद में कई और खिलाड़ी भी आ गए थे।

एचआइ ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि समिति ने पंजाब आर्म्ड पुलिस के हरदीप सिंह और जसकरन सिंह को 18 महीनों के लिए निलंबित कर दिया है जबकि दुपिंदरदीप सिंह, जगमीत सिंह, सुखप्रीत सिंह, सरवनजीत सिंह और बलविंदर सिंह को 12 महीनों के लिए निलंबित किया है। इन सभी को एचआइ की आचार संहिता के लेवल-3 के उल्लंघन के लिए निलंबित किया गया है। इन सभी का निलंबन 11 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पंजाब पुलिस के मैनेजर अमित संधू को भी लेवल-3 के उल्लंघन के चलते 18 महीनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही पंजाब पुलिस की टीम को तीन महीनों के लिए निलंबित करने और किसी भी अखिल भारतीय टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने देने की सिफारिश की गई है।

केरल के खिलाफ बिखरी दिल्ली

रणजी ट्रॉफी

मुंबई, प्रेट्र : कप्तान सचिन बेबी के शतक और सलमान निजार के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से केरल ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-ए मैच के दूसरे दिन मंगलवार को यहां नौ विकेट पर 525 रन पर पारी घोषित करने के बाद दिल्ली का स्कोर दो विकेट पर 23 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। केरल की टीम मंगलवार को तीन विकेट पर 276 रन से आगे खेलने उतरी। बेबी (155) और निजार (77) ने छठे विकेट के लिए 156 रन जोड़कर टीम का स्कोर 450 रन के पार पहुंचाया। सचिन ने अपनी पारी को 36 रन से आगे बढ़ाया। लेग स्पिनर तेजस बरोका ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। इसके जवाब में दिल्ली की शुरुआत खराब रही और 17 रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों अनुज रावत (15) और कुणाल चंदेला (01) के विकेट गंवा दिए। दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान ध्रुव शौरी छह रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। नीतिश राणा दूसरे छोर पर उनका साथ निभा रहे हैं जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला है। दिल्ली की टीम अभी 502 रन से पीछे है जबकि उसके आठ विकेट शेष हैं।

हिमाचल के खिलाफ सौराष्ट्र जीत की दहलीज पर

धर्मशाला, प्रेट्र : हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच ग्रुप-बी मैच के पहले दिन 17 विकेट गिरने के बाद मंगलवार को दूसरे दिन भी 16 विकेट गिरे, जिसके बाद मेहमान टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। सौराष्ट्र को दूसरी पारी में 162 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। चिराग जानी 14, जबकि प्रेरक मांकड़ आठ रन बनाकर खेल रहे हैं। सलामी बल्लेबाज हार्विक देसाई ने 46 रन की पारी खेली। सौराष्ट्र की टीम को जीत के लिए 66 रन की दरकार है, जबकि उसके सात विकेट शेष हैं। हिमाचल की ओर से वैभव अरोड़ा ने दो, जबकि ऋषि धवन ने एक विकेट चटकाया। इससे पहले सुबह सौराष्ट्र की टीम पहली पारी में सात विकेट पर 93 रन से आगे खेलने उतरी और उसने हिमाचल के पहली पारी के 120 रन के जवाब में 141 बनाकर 21 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। हिमाचल की ओर से अरोड़ा ने 48 रन देकर छह, जबकि पंकज जायसवाल ने 40 रन देकर तीन विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट के छह विकेट के दम पर दूसरी पारी में भी हिमाचल की शुरुआत खराब रही और टीम ने 31 रन तक ही पांच विकेट गंवा दिए।

पंजाब ने ली बढ़त

जयपुर, प्रेट्र : कप्तान मनदीप सिंह के शतक से पंजाब ने ग्रुप-ए मैच के दूसरे दिन मंगलवार को यहां राजस्थान के खिलाफ छह विकेट पर 290 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल कर ली। राजस्थान ने इससे पूर्व पहली पारी में 257 रन बनाए। पंजाब को 33 रन की बढ़त है जबकि उसके चार विकेट शेष हैं। पंजाब की शुरुआत खराब रही और उसने 31 रन तक ही सलामी बल्लेबाजों सनवीर (00) और शुभमन (12) के विकेट गंवा दिए।

त्रिपुरा ने झारखंड को फॉलोऑन खिलाया

अगरतला, प्रेट्र : राणा दत्त के चार विकेट और अभिजीत सरकार के तीन विकेट के दम पर त्रिपुरा ने ग्रुप-सी के मुकाबले के दूसरे दिन मंगलवार को झारखंड की पहली पारी को महज 136 रन पर समेट कर उसे फॉलोऑन के लिए मजबूर किया। फॉलोऑन मिलने के बाद झारखंड ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 91 रन बना लिए, जिससे वह अब भी त्रिपुरा की पहली पारी से 62 रन पीछे है। इससे पहले त्रिपुरा ने दिन की शुरुआत आठ विकेट पर 263 रन से की और उसकी पहली पारी 289 रन पर खत्म हुई। झारखंड की पहली पारी में सिर्फ तीन बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में पहुंच सके जिसमें विराट सिंह (47), विवेकानंद तिवारी (30) और कप्तान सौरभ तिवारी (11) शामिल हैं। फॉलोऑन मिलने के बाद हालांकि झारखंड के बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज के देवब्रत (25) और विकेटकीपर नाजिम (40) ने पहले विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की। दिन का खेल खत्म होने पर विराट (19) और राहुल (06) क्रीज पर मौजूद थे।

पुडुचेरी के खिलाफ बिहार का संघर्ष जारी

जागरण संवाददाता, पटना : पुडुचेरी के खिलाफ चल रहे मुकाबले में बिहार की टीम पारी की हार बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। दूसरे दिन मंगलवार को दिन का खेल खत्म होने तक बिहार ने दूसरी पारी में 61 रन पर चार विकेट गंवा दिए हैं और पारी की हार टालने के लिए अब भी उसे 66 रन चाहिए। मेजबान टीम पहली पारी में 173 रनों पर सिमट गई थी।

पंजाब पैंथर्स को मात दे गुजरात पहले स्थान पर

नई दिल्ली, आइएएनएस : अमित पंघल की कप्तानी वाली गुजरात जाएंट्स ने मंगलवार को यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कांप्लेक्स के केडी जाधव हाल में जारी बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में मेरी कॉम की कप्तानी वाली पंजाब पैंथर्स को 5-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही गुजरात ने अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। 15 लीग मैचों के इस टूर्नामेंट में इस जीत के बाद गुजरात के तीन मैचों में 14 अंक हो गए हैं और वह पहले स्थान पर पहुंच गई है। वहीं पैंथर्स के तीन मैचों में से 12 अंक हो गए हैं और वह दूसरे स्थान पर खिसक गई है।

पैंथर्स के लिए मैरी कॉम और अनुभवी मुक्केबाज मनोज कुमार मैच जीतने में सफल रहे लेकिन बाकी के खिलाड़ियों की हार के कारण पैंथर्स जीत नहीं सकी।

मेरी कॉम को उस समय झटका लगा जब 57 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में उनकी टीम के अब्दुलमलिक खलाकोव को गुजरात जाएंट्स के चिराग के हाथों चौंकाने वाली हार मिली। अनुभवी आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम भारवर्ग में युवा मोहित को हराकर गुजरात को पूरे अंक दिला दिए। इसके बाद कप्तान पंघल ने पुरुषों के 52 किलोग्राम भारवर्ग के मैच में पीएल प्रसाद को हरा गुजरात को 3-0 से आगे कर दिया।

इसके बाद मेरी कॉम और मनोज ने अपने-अपने मुकाबले जीत पैंथर्स की वापसी की संभावनाओं को बरकरार रखा। मेरी कॉम ने राजेश नरवाल को मात दी। वहीं दुर्योधन सिंह नेगी ने मनोज को पहले दौर में टक्कर दी लेकिन मनोज ने दूसरे और तीसरे दौर में वापसी कर मैच अपने नाम किया। पैंथर्स जानती थी कि उसके लिए यहां से भी राह आसान नहीं है।

10 साल बाद पाक में लौटेगा टेस्ट क्रिकेट

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से

रावलपिंडी, प्रेट्र : पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट क्रिकेट लौटना पड़ोसी मुल्क के लिए बहुत बड़ी घटना है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार से खेला जाएगा। यह 10 साल में पहला मौका होगा जब पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेला जाएगा। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली ने इसे भावुक क्षण बताया।

2009 में पाकिस्तान दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था। उस घटना के बाद से बड़ी टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इन्कार कर दिया था। पाकिस्तान को अपने घरेलू मैच तटस्थ स्थलों पर खेलने पड़ रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे और तीसरे दिन बारिश का खतरा है। पिच पर कवर ढंके हैं, इसलिए इसका मिजाज भांपना दोनों टीमों के लिए मुश्किल होगा। वर्तमान में दोनों ही टीमों में शामिल कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान में टेस्ट खेला हो। श्रीलंकाई टीम ने सिर्फ एक बार 2000 में रावलपिंडी में टेस्ट खेला था, जो दो विकेट से जीता था। पाकिस्तान के लिए शान मसूद और इमाम उल हक पारी की शुरुआत करेंगे। तेज गेंदबाजी आक्रमण का जिम्मा उस्मान शिनवारी के कंधों पर होगा। मध्यक्रम में फवाद आलम और हैरिस सोहेल के बीच होड़ रहेगी।

बुधवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले ट्रॉफी के साथ दोनों टीमों के कप्तान। एएफपी

इस टेस्ट सीरीज के लिए सभी खिलाड़ी बहुत भावुक हो रहे हैं। अपने घरेलू मैदान पर वापसी करना बहुत अच्छा है। मिकी ऑर्थर अब श्रीलंका टीम के साथ हैं। वे हमारे बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। ऑर्थर के होने से खास फर्क नहीं होगा।
–अजहर अली, कप्तान, पाकिस्तान

मिकी ऑर्थर पाकिस्तान की टीम के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इससे सीरीज की शुरुआत से पहले हमें आत्मविश्वास मिला है। पाकिस्तान टीम कभी भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होती।
–दिमुथ करुणारत्ने, कप्तान, श्रीलंका

विविध

उप्र में विधि अधिकारियों की अब प्रतिदिन लगेगी हाजिरी

विधि संवाददाता, प्रयागराज

▶ सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने सरकारी वकीलों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विभिन्न न्यायालयों में तैनात विधि अधिकारियों को प्रतिदिन अपनी हाजिरी देनी होगी। साथ ही जिन मुकदमों में पैरवी की है, उसका ब्योरा भी रखना पड़ेगा। राज्य विधि अधिकारियों को अपना बिल का अपने कोर्ट इंचार्ज से सत्यापन कराकर ही देने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट इंचार्ज अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ताओं को बनाया गया है। यदि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित कोर्ट इंचार्ज और राज्य विधि अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे। महाधिवक्ता द्वारा जारी निर्देश के अनुसार न्यायालयों में सूचीबद्ध मुकदमों की फाइलें संबंधित पटल के प्रभारी एक दिन पहले ही उस कोर्ट के इंचार्ज को देंगे। साथ ही कोर्ट इंचार्ज के जरिए वह फाइल विधि अधिकारियों को दी जाएगी। फाइलें वापस भी इसी तरीके से की जाएंगी।

कोर्ट इंचार्ज से होते हुए पटल अधिकारी तक जाएगी। महाधिवक्ता ने यह भी निर्देश दिया है कि जो विधि अधिकारी शहर छोड़ते हैं, उनको लिखित रूप से इसकी सूचना महाधिवक्ता कार्यालय को देनी होगी। इसी प्रकार से जो फाइलें विधि अधिकारियों को शपथ पत्र अपील आदि लिखवाने के लिए आवंटित की गई है। वह फाइलें लिखे जाने के बाद ही वापस की जाएगी।

यदि किसी वजह से बिना लिखे फाइल वापस की जाती है, तो उसका लिखित कारण बताना होगा। महाधिवक्ता ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन मुकदमों में सरकार के खिलाफ आदेश होता है अथवा सरकारी अधिकारियों को न्यायालय तलब करता है, उसकी सूचना महाधिवक्ता को ई-मेल के जरिए देनी होगी, ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके। इन सभी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। महाधिवक्ता के इस फरमान से सरकारी वकीलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तो उन्हें हर दिन अपनी हाजिरी देनी होगी और दूसरे जिन मुकदमों में पैरवी की गई है उसका ब्योरा भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिसकी जांच कभी भी की जा सकती है।

नक्सल कमांडर रमन्ना की मौत पर नक्सलियों की चुप्पी से गहराया रहस्य

नईदुनिया, जगदलपुर

▶ ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड है रमन्ना

▶ सोमवार को जंगल में अंतिम संस्कार की खुफिया सूचना

नक्सल कमांडर रमन्ना की मौत पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास यह सूचना है कि तेलंगाना से सटे बीजापुर जिले के जंगल सोमवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन नक्सली इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। रमन्ना अप्रैल 2010 में हुई अब तक की सबसे बड़ी नक्सल वारदात ताड़मेटला कांड का मास्टरमाइंड था। इसी घटना ने देश का ध्यान बस्तर की नक्सल समस्या की ओर खींचा था। ताड़मेटला में सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए थे।

रमन्ना की हार्टअटैक से मौत की खबर के बाद दो दिन से छत्तीसगढ़ व तेलंगाना पुलिस इसकी पुष्टि के लिए परेशान दिखी। हालांकि नक्सलियों ने अब तक न हां कहा है न ही इन्कार किया है। मंगलवार को सोशल मीडिया में खबर चलने लगी कि तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के एसपी सुनील दत्त ने रमन्ना की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि बाद में तेलंगाना पुलिस ने भी साफ कर दिया कि अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बस्तर आइजी सुंदरराज पी ने कहा कि रमन्ना नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। अगर उसकी मौत हुई है तो नक्सली इसे क्यों छिपाएंगे? दो दिन से रमन्ना की मौत की खबर चल रही है। अगर यह सच न होता तो अब तक नक्सलियों ने खंडन कर दिया होता। आइजी ने कहा कि हम उसका शव तो बरामद नहीं कर सकते कि तुरंत पुष्टि कर दें। खुफिया एजेंसियों को गांव से इनपुट आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि सोमवार को पामेड़, बासागुड़ा और जगरगुंडा के बीच ट्राइजंक्शन कहे जाने वाले नक्सलियों के कोर इलाके के किसी गांव शायद, पालागुड़म या जोड़ागुड़ा के आसपास के जंगल में रमन्ना का अंतिम संस्कार किया गया।

सुंदरराज ने कहा कि जो इनपुट मिल रहे हैं उससे 90 फीसद संभावना तो यही है कि रमन्ना की वास्तव में मौत हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो आश्चर्य की बात है कि नक्सली इसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं।

15 साल की उम्र से दक्षिण बस्तर के जंगलों में सक्रिय रहा रमन्ना : तेलंगाना के वारंगल जिले के रमन्ना उर्फ रावुलू श्रीनिवास ने 15 साल की उम्र में हथियार उठा लिया था। तभी से वह दक्षिण बस्तर के सुकमा व बीजापुर जिले के बीच के जंगलों में सक्रिय रहा। छह अप्रैल 2010 को सुकमा जिले के ताड़मेटला में उसने सीआरपीएफ की एक कंपनी पर हमला किया जिसमें 76 जवानों की मौत हो गई। 2005 से अब तक उस इलाके में हुई लगभग सभी बड़ी वारदातों का मास्टरमाइंड उसे माना जाता है। आंध्र, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने उसपर कुल ढाई करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा है।

पुलिस के पास नहीं है रमन्ना की कोई ताजा तस्वीर : रमन्ना इतना शातिर है कि पुलिस उसकी कोई हालिया तस्वीर तक हासिल नहीं कर पाई है। रमन्ना की मौत की खबरों के बाद रमन्ना की वही तस्वीर सामने आई जो बेहद पुरानी है। रमन्ना पर घोषित इनाम के साथ पुलिस इसी तस्वीर का इश्तहार जारी करती है पर वह पकड़ में नहीं आता। जबकि बस्तर में ही उसपर 40 लाख रुपये का नगद इनाम घोषित है।

सरकार से खफा संयुक्त सचिव ने ठुकराई अपर सचिव पद की प्रोन्नति

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जताई आपत्ति

▶ कहा, वेतन विसंगति दूर करने में सरकार नहीं ले रही दिलचस्पी, जान-बूझकर विलंब से दी जाती है प्रोन्नति

▶ सरकार की नीतियों से अपमानित महसूस कर रहा

योजना सह वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत अविनाश कुमार सिंह ने हाल ही में अपर सचिव पद पर मिली प्रोन्नति को ठुकरा दिया है। उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से सरकार की प्रोन्नति नीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा है कि अपर सचिव पद की वेतन विसंगति दूर करने में सरकार जहां दिलचस्पी नहीं ले रही है, वहीं इस पद पर जान-बूझकर विलंब से प्रोन्नति दी जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में प्रोन्नति देने में जान-बूझकर अघोषित नीति के तहत विलंब किया जाता है। इससे इतर गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को इस पद पर प्रोन्नत करने में अधिक रुचि दिखाई जा रही है। लिहाजा छह दिसंबर के प्रभाव से अपर सचिव के पद पर मिली प्रोन्नति को स्वीकार करने में वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं।

बताते चलें कि प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने वेतन विसंगति दूर करते हुए 8900 (13 ए) का वेतनमान देने के साथ-साथ समय पर प्रोन्नति देने की मांग की थी। यह मांग तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा के समय से ही चल रही है। इस मसले को लेकर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ (झासा) ने आंदोलन भी किया था, परंतु सरकार के आश्वासन के बाद उसने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। झासा ने बिहार समेत अन्य राज्यों में प्रभावी इस स्केल का प्रमाण भी दिया था। बहरहाल गैर प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को वर्ष 2017 के दिसंबर में प्रोन्नति दी जा चुकी है, वहीं वर्ष 2018 की भी फाइल बढ़ चुकी है। झासा का यह भी आरोप था कि जब बात आइएएस अफसरों की प्रोन्नति की होती है तो महीनों पूर्व से ही इसकी कवायद शुरू हो जाती है, जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की प्रोन्नति मामले में लेटलतीफी की जाती है। इसका नतीजा है कि अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के लगभग 200 और अपर समाहर्ता स्तर के तकरीबन 70 पद रिक्त हैं।

सरकार के इस रवैये से प्रशासनिक सेवा संघ नाराज है। फिलहाल संघ राज्य में प्रभावी आचार संहिता और निर्वाचन कार्यों को लेकर अपने दायित्वों से बंधा है। नई सरकार के गठन के बाद उग्र आंदोलन होगा।
–आरके सिन्हा, अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा संघ

ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर परिसर का सर्वेक्षण कराने की अपील

जागरण संवाददाता, वाराणसी

ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मंगलवार को अदालत से अपील की गई। ज्ञानवापी स्थित प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन- फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में प्रार्थना देकर यह अपील की गई है। विदित हो कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा मस्जिद भी है जिसके विवाद की सुनवाई स्थानीय अदालत में 1991 से चल रही है। अदालत ने विपक्षियों से आपत्ति तलब करने के साथ ही अग्रिम सुनवाई के लिए नौ जनवरी 2020 की तिथि मुकर्रर की है।

भगवान विश्वेश्वरनाथ के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास तथा अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर 1991 में मुकदमा दायर किया था। कहा गया था कि ज्ञानवापी विश्वेश्वरनाथ मंदिर का एक अंश है। वहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन आदि का अधिकार है। इसके निर्माण, मरम्मत, पुनरोद्धार आदि कराने का अधिकार है। मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा अन्य विपक्षी हैं। इस अधिकार को लेकर मुकदमा दाखिल करने वाले दो वादियों पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ. रामरंग शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। दिवंगत वादी पंडित सोमनाथ व्यास के स्थान पर प्रतिनिधित्व कर रहे वादमित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) विजय शंकर रस्तोगी ने प्रार्थना पत्र में कहा है कथित विवादित परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। यह देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। परिसर में ज्ञानवापी नाम का बहुत ही पुराना कुआं है और इसी कुएं के उत्तर तरफ भगवान विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है। मंदिर परिसर के हिस्सों पर मुसलमानों ने आधिपत्य कर मस्जिद बना दिया। 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था। जबकि विपक्षियों का दावा है कि उक्त तिथि को इसका स्वरूप मस्जिद का था। इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा परिसर विवादित है और इसका धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक भवन तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता।

भोपाल के स्कूल में युवक को जंजीर से बांधकर जिंदा जलाया

नईदुनिया, भोपाल

▶ दीवार पर लिखा है अनिल, 100 फीसदी जलने से नहीं हुई शिनाख्त

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पंचशील नगर स्थित सरदार पटेल स्कूल में मंगलवार सुबह एक युवक की जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव जंजीर से बंधी हुई हालत में था। वह 100 फीसदी जला हुआ था, इसलिए अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। जिस कमरे में शव मिला, उसकी दीवार पर पत्थर से खरोंचकर अनिल लिखा गया है।

भोपाल के एएसपी अखिल पटेल ने बताया कि प्राचार्य अभिषेक सिंह बैस ने सुबह पौने नौ बजे सूचना दी थी कि स्कूल के पीछे एक कमरे में एक जला हुआ शव देखा गया है। इसके बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। कमरे में शव बुरी तरह जली हालत में छाती से जंजीर से बंधा शव खिड़की से लटका था। आसपास लकड़ी और कोयले के अंश मिले हैं। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया और बारीकी से मुआयना कराया गया। इसके बाद शव को हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में रखवा गया।

तीन दिन से लापता है क्षेत्र का युवक : एएसपी पटेल का कहना है कि युवक को मारकर शव को जंजीर से बांधकर जलाया गया है। पंचशील नगर का एक युवक तीन दिन से लापता है, उसका नाम अनिल ठाकरे है। शव जहां जलाया गया है, उस कमरे की दीवार पर भी अनिल ही लिखा है। आशंका है कि हत्या के बाद आरोपितों ने यह नाम लिखा हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

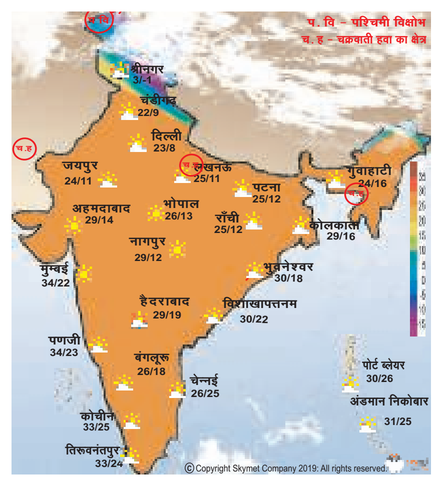

मौसम विशेष

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के तापमान में हल्की वृद्धि होने के आसार हैं। जम्मू-कश्मीर में एक नये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा व बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी छिटपुट वर्षा संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/21/आंबा	अहमदाबाद	28/12/आंबा
कोलकाता	29/17/सा	बड़ौदा	30/13/सा
चेन्नई	30/24/आंबा	नागपुर	29/11/आंबा
हैदराबाद	28/20/सा	इन्दौर	27/12/आंबा
बंगलूरू	27/17/आंबा	राँची	28/17/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/24/सा	पटना	27/16/आंबा
गुवाहाटी	24/16/सा	जमशेदपुर	29/17/आंबा
गंगटोक	07/-3/आंबा	पुणे	30/19/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

बुधवार 11 दिसंबर 2019

आजकल

16

www.jagran.com

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना हुई

1946 में आज ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की स्थापना की थी। 1965 में इसे दुनिया भर में बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए काम करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

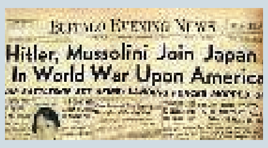

जर्मनी-इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की

1941 में आज ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर की गई बमबारी के बाद इटली के तानाशाह मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।

ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार को जन्मदिन मुबारक हो

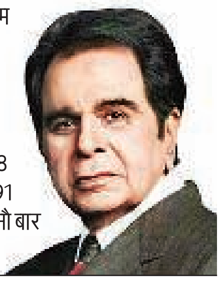

अभिनय का प्रतीक माने जाने वाले दिलीप कुमार का जन्म 1922 में आज ही पेशावर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। उनका असली नाम यूसुफ खान है। 1944 में आई ज्वार भाटा पहली फिल्म रही। इसके बाद 'मधुमति', 'नया दौर', 'देवदास', 'अंदाज', 'मुगल-ए-आजम', 'राम और श्याम', 'कर्मा' और 'सौदागर' जैसी उम्दा और सदाबहार फिल्में दीं। 1998 में प्रदर्शित 'किला' के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। 1991 में पद्मभूषण और 2015 में पद्मविभूषण अवार्ड से सम्मानित हुए। नौ बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला।

इधर-उधर की

खरीदा गिफ्ट, निकली राइफल

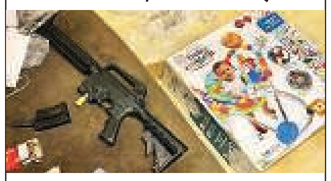

वाशिंगटन, एजेंसी : एक दंपती ने अपने दोस्त की बेटी के लिए गिफ्ट खरीदा, लेकिन गिफ्ट की जगह लोडेड सेमी ऑटोमेटिक राइफल निकली। दरअसल, वेरोनिका और उनके पति अपनी एक दोस्त के बेबी शॉवर समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में उन्होंने बच्चे के लिए एक स्टोर से 9.99 डॉलर (करीब 700 रुपये) में एक गिफ्ट खरीदा और उसे देखा बिना ही पैक कराकर निकल गए। समारोह में पहुंचने पर जब दंपती की दोस्त के पति ने गिफ्ट खोलकर देखा तो वह चिल्ला पड़े और वहां मौजूद मेहमान हंसने लगे। दरअसल, डिब्बे में गिफ्ट की जगह सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। वेरोनिका के पति यह देखकर स्तब्ध रह गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जांच में सामने आया है कि गिफ्ट की जगह मिली राइफल एक मोसबर्ग 715टी सेमी ऑटोमेटिक राइफल है।

10 वर्षों में कई ग्लेशियरों के गायब होने का खतरा

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर में हिमालय और दक्षिण में एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बचे हुए ग्लेशियर अगले 10 साल या इससे पहले ही गायब हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरों के प्रति आगाह करने वाले एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है। अमेरिका की ओहिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'सबसे पहले विलुप्त होने वाले ग्लेशियर इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के हो सकते हैं। दुनियाभर के बड़े ग्लेशियरों के लिए यह एक चेतावनी होगी।'

पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि न्यू गिनी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद ग्लेशियरों का पिघलना 2015-2016 में अल नीनो के कारण तेजी से बढ़ा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अल नीनो एक ऐसी घटना है जो उष्णकटिबंधीय महासागर के पानी और वायुमंडलीय तापमान को गर्म करने का कारण बनती है। हालांकि यह एक प्राकृतिक जलवायु प्रक्रिया है, लेकिन इसे ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ा दिया है।

मिलकर काम करने की जरूरत

इस अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का पानी के गर्म होने के साथ-साथ तीव्र तूफान आने की संभावना भी बढ़ गई है। शोधकर्ताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचने के लिए हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। केवल चर्चा आदि में समय नष्ट करने के बजाय प्रभावी कमद उठाने से इन खतरों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है।

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इंडोनेशिया के ग्लेशियर सबसे पहले विलुप्त हो सकते हैं। फाइल

शोधकर्ताओं के अनुसार, 'अगले 10 वर्षों में न्यू गिनी के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। इस दौरान सबसे मजबूत अल नीनो होने की संभावना है।'

इस अध्ययन के सह-लेखक : लोनी थॉम्पसन ने कहा, 'इसके बाद ऐसी संभावनाएं भी हैं कि अन्य उष्णकटिबंधीय ग्लेशियरों (तंजानिया के किलिमंजारो और पेरू के क्वेलकाया) पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।' उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पापुआ और इंडोनेशिया के ग्लेशियर पूरी दुनिया के लिए एक संकेतक हैं, जो यह बताएंगे कि दुनिया किस खतरे का सामना करने वाली है।

बढ़ गई है बर्फ पिघलने की दर : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ता वर्ष 2010 से ग्लेशियरों की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हालांकि ग्लेशियरों का पिघलना 150 साल पहले से शुरू हुआ था, पर पिछले कुछ दशकों में बर्फ पिघलने की दर बढ़ गई है। थॉम्पसन और उनकी शोध टीम ने अध्ययन के दौरान पाया कि ग्लेशियरों की बर्फ एक मीटर प्रतिवर्ष की वर्ष की दर से पिघल रही है और वर्ष 2010 से 2018 के बीच ग्लेशियरों की सतह 75 फीसद तक सिकुड़ गई है।

एआइ लगाएगी हार्ट फेल होने के खतरे का पता

लंदन, प्रेट्र : हार्ट फेल होने के खतरे का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) में अप्लाई किया जा सकता है और हार्ट फेल होने से पहले ही मरीज को जरूरी इलाज दिया जा सकता है।

लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हार्ट की एमआरआइ इमेजों का एआइ के जरिये विश्लेषण के दौरान पाया कि किसी भी व्यक्ति के जीन उसके हृदय के बाएं वेंट्रिकल स्थित अंगों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं और 22-39 फीसद उसके आकार के लिए जिम्मेदार होते हैं। वेंट्रिकल में ही दिल का पंपिंग चैंबर भी होता है। इसके आकार में वृद्धि या कमी के कारण अक्सर हार्ट फेल के मामले सामने आते हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मानव जीनोम के ऐसे 14 क्षेत्रों की पहचान की है, जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल के आकार और कार्यप्रणाली से संबंधित होते हैं।

तेजी से सिकुड़ते जा रहे हैं प्राकृतिक क्षेत्र

चिंताजनक ▸ 2030 तक शहरों में बदल सकता है तीन लाख वर्ग किमी का दायरा

लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण प्रभावित हो रही है जैव विविधता

टोरंटो : बढ़ते शहरीकरण के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने वाले एक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से लगभग तीन लाख वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक क्षेत्र तबाह होकर शहरों में तब्दील हो जाएंगे। इसका आकार पूरे ब्रिटेन से भी बड़ा होगा। शोधकर्ताओं ने 900 से ज्यादा अध्ययनों का सर्वेक्षण कर यह दावा किया है।

नेचर सस्टेनिबिलिटी नामक जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक रूप से 120 करोड़ अतिरिक्त लोग शहरी क्षेत्रों में बसने आ सकते हैं। कनाडा की एमसी गिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा, 'विकास की यह गति हर छह सप्ताह में न्यूयॉर्क के आकार का एक नए शहर का निर्माण कर सकती है।' इस अध्ययन के सह-लेखक और एमसी गिल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एंड्रयू गोंजालेज ने कहा, 'शहरों की बढ़ती आबादी के प्रभावों के बारे में हमारी समझ भविष्य की जैव विविधता के लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन हमें अपनी समझ और ज्ञान को दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो इससे शहरीकरण के बारे में नई और कारगर नीतियों को बनाने की हमारी क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।'

जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बढ़ता शहरीकरण नुकसानदेह हो सकता है। प्रतीकात्मक

तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक असर : अध्ययन ने बताया गया है कि जैव विविधता पर बढ़ते शहरीकरण का सीधा प्रभाव उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों जैसे-चीन, ब्राजील और नाइजीरिया में अधिक गंभीर होगा क्योंकि यहां जैव विविधता का स्तर काफी उच्च है।

और अध्ययन की बताई जरूरत : इस अध्ययन में लेखकों ने कहा है कि दरअसल, वैज्ञानिक सही स्थानों पर शहरी विकास के प्रभावों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण बढ़ते शहरीकरण की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि शहरीकरण के कारण हमारी प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों की पूरी और स्पष्ट तस्वीर देखने के लिए हमें और अधिक अध्ययन की जरूरत है।

कम आय वाले देशों की हालत चिंताजनक : शोधकर्ताओं ने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में कम आय वाले देशों में शहरों का विस्तार होने से प्राकृतिक आवासों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो कि गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावों का और अधिक आकलन के लिए विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के आसपास के क्षेत्र, जैसे- ब्राजील, पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करने की जरूरत है।

शहरीकरण पर लगाम लगाने की है सख्त जरूरत

अध्ययन में बताया गया है कि 72 फीसद शोध उच्च आय वाले देशों में हुए हैं, जहां शहरीकरण का जैव विविधता पर सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कम आय वाले देशों में यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 922 अध्ययनों में से केवल 34 फीसद ने जैव विविधता पर शहरी विकास के अप्रत्यक्ष प्रभावों की मात्रा निर्धारित की थी। उन्होंने कहा कि यदि हमें जैवविविधता को बनाए रखना है तो इसके लिए बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या पर भी लगाम लगानी होगी।

कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर गूंजी बेटी की किलकारी

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर मंगलवार को किलकारी गूंज उठी। उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने बेटी को जन्म दिया। कपिल ने खुद ट्वीट करके फैंस के साथ अपनी खुशी साझा की। कपिल ने लिखा, 'बेटी का जन्म हुआ है। आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। सभी को ढेर सारा प्यार। जय माता दी।' खास बात यह है कि कपिल और गिन्नी अपनी शादी की पहली सालगिरह से ठीक दो दिन पहले माता-पिता बने हैं। दोनों की शादी पिछले वर्ष 12 दिसंबर को हुई थी।

सुनील ग्रोवर, कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, रकुल प्रीत, एकता कपूर, कीकू शारदा, गुरु रंधावा, साइना नेहवाल समेत कई सितारों और फैंस ने कपिल को बधाइयां दी हैं। सुनील ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बधाई हो। प्यार और शुभकामनाएं'। कियारा आडवाणी ने लिखा, 'अभी गुड न्यूज सुनी। आपको और गिन्नी को बधाइयां। बेटी पर भगवान की कृपा बनी रहे।' गुरु रंधावा ने लिखा, 'बधाई हो पाजी। मैं अब ऑफिशियली चाचा बन गया।' रकुल प्रीत ने लिखा, 'बधाई। भगवान आपकी बेटी को सभी खुशियां दें।' टाइगर श्रॉफ ने लिखा, 'मुबारक हो सर। आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। भगवान की कृपा बनी रहे।'

बेटी को गोद में लिए कपिल शर्मा। मंगलवार सुबह बेटी के जन्म के बाद ट्विटर पर तस्वीर साझा कर उन्होंने खुशी का इजहार किया। यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सौ. : ट्विटर

परिवार संग छुट्टियां मनाने के लिए लगातार काम कर रहे कपिल : बेटी और परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए कपिल लगातार काम कर रहे हैं। वह बुधवार को दीपिका पादुकोण के साथ 'छपाक' फिल्म के लिए शूटिंग करेंगे। गुरुवार को 'गुड न्यूज' फिल्म की टीम उनके सेट पर पहुंचेगी। उसी दिन कपिल और गिन्नी की शादी की पहली सालगिरह भी है, लेकिन वह छुट्टी नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को एक और एपिसोड की शूटिंग करने के बाद कपिल दिसंबर मध्य से छुट्टी पर जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वह अगले साल के पहले हफ्ते तक छुट्टी पर रहेंगे।

शोध अनुसंधान

अल्जाइमर रोगियों के लिए फायदेमंद है कीटो डाइट

कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च वसा वाले आहार यानी कीटो डाइट का सेवन अल्जाइमर रोग से लड़ने में मदद कर सकता है। चूहों पर किए गए एक शोध से पता चला है कि जिस समय अल्जाइमर रोग बढ़ रहा होता है, उस दौरान इस तरह के आहार न्यूरांस (तंत्रिका कोशिकाएं) को मरने से बचाते हैं। न्यूरांस का काम मस्तिष्क से सूचना का आदान-प्रदान और विश्लेषण करना है। न्यूरोसाइंस सोसायटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक मनुष्य के शरीर में जिस समय अल्जाइमर रोग विकसित हो रहा होता है, उस समय मस्तिष्क अति उत्तेजित होता है। चूंकि इंटरन्यूरांस (विशेष न्यूरॉन) अन्य न्यूरांस के मुकाबले मस्तिष्क को ज्यादा सिग्नल भेजते हैं, ऐसे में अन्य न्यूरांस के मुकाबले उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि जब इंटरन्यूरांस अल्जाइमर के प्रोटीन एमोलाइड बीटा के संपर्क में आते हैं तो इनके मरने की संभावना अधिक होती है। -आइएएनएस

कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकती है एंटीबायोटिक खुराक

एंटीबायोटिक दवाओं को उन दवाओं के रूप में जाना जाता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को नष्ट या धीमा कर देती हैं। चूहों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक आम एंटीबायोटिक की एक खुराक देने से न केवल प्रतिरक्षा कोशिकाएं ट्यूमर (जिनका विकिरण के द्वारा इलाज किया जा रहा है) को खत्म करने में मदद करती हैं बल्कि कैंसर कोशिकाओं को भी मारती हैं। निष्कर्ष से उत्साहित शोधकर्ता अब इसका मानवीय परीक्षण करने जा रहे हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ क्लीनिकल इंवेस्टिगेशन में प्रकाशित हुआ था। ठोस ट्यूमर वाले सभी रोगियों में से आधे से अधिक अपने उपचार के दौरान किसी बिंदु पर रेडियो थेरेपी से गुजरते हैं। रोगियों को उपचार के दौरान रेडियो थेरेपी की उच्च खुराक देना मरीज में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। -एएनआइ

नोबेल शांति पुरस्कार...

यूरोपीय देश नार्वे की राजधानी ओस्लो में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनको पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। आधुनिक और सुधारवादी नेता के रूप में मशहूर 43 वर्षीय अबी ने इस मौके पर कहा, 'मैं इथियोपिया और इरिट्रिया की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण करता हूं।' गौरतलब है कि इथियोपिया इस समय जातीय हिंसा से जूझ रहा है। एपी

ब्रिटेन की 562 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार

यह जेट-प्रोपेल्ड ब्रिटिश ब्लडहाउंड एलएसआर (लैंड स्पीड रिकॉर्ड) कार है। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रांत में हाई स्पीड टेस्टिंग के दौरान इस कार ने करीब 562 मील प्रति घंटे (904 किलोमीटर प्रति घंटे) की रफ्तार दर्ज की। ब्रिटेन में निर्मित यह मशीन फॉर्मूला 1 कार, फाइटर जेट और अंतरिक्ष यान का मिश्रित रूप है। इंजीनियरों ने इसमें रोल्स रॉयस ईजे 200 के जेट इंजन का उपयोग किया है, जो कि आमतौर पर यूरोफाइटर टाइफून जेट में होता है। इससे इसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। निर्माता अब इसे हाइब्रिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन से लैस करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे इसकी गति 1,000 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

'छपाक' के ट्रेलर लांच पर भावुक हुईं दीपिका

मेघना गुलजार निर्देशित एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी से प्रेरित फिल्म 'छपाक' का ट्रेलर मंगलवार को मुंबई में लांच किया गया। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हुए इस लॉन्च पर मेघना गुलजार, दीपिका पादुकोण, विक्रांत मेस्सी मौजूद थे। ट्रेलर दिखाए जाने के बाद जब दीपिका स्टेज पर पहुंचीं तो वह भावुक हो गईं। दीपिका को संभलने में थोड़ा वक्त लगा। दीपिका का कहना है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब मेघना ने उन्हें सुनाई थी, तब दो पेज की नरेशन सुनने के बाद ही उन्होंने फिल्म के लिए हां कर दी थी। दीपिका ने बताया कि फिल्म की कहानी उस घटना पर नहीं, बल्कि उस घटना से बाहर निकलकर जिंदगी जीने की है। दीपिका बताती हैं कि ऐसे किरदार को निभाना मुश्किल है, जो आपके सामने मौजूद होता है। लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाना उनके लिए आसान नहीं था। प्रॉस्थेटिक मेकअप के बाद जब पहले दिन सेट पर दीपिका तैयार बैठी थीं, तब वह नर्वस थीं कि लक्ष्मी उनको देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगी। दीपिका ने बताया कि जब लक्ष्मी ने उन्हें देखा तो कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है, जैसे वह आईना देख रही हैं।

दीपिका कहती हैं कि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी मान्यता कोई और नहीं होगी कि जिसका किरदार वह निभा रही हैं, वह खुद यह बात कहे। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार का कहना है कि उनकी फिल्मों की कहानियों में महिला का किरदार सशक्त जरूर होता है, लेकिन वह केवल एक महिला की कहानी नहीं होती है। वह ऐसी कहानियां चुनती हैं, जो उन्हें समझ में आती हैं। वह किसी संवेदनशील कहानी को ढूंढ़कर उसे कमर्शियल बनाने की कोशिश नहीं करती हैं।

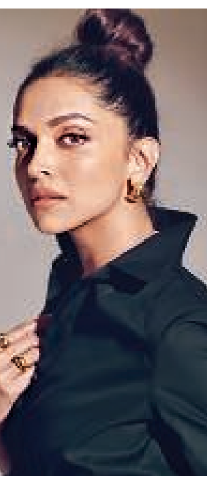

जॉन अब्राहम मेरे सुपरहीरो हैं : मिलाप जवेरी

कुछ निर्देशकों के अपने खास पसंदीदा अभिनेता होते हैं, जिनके साथ वे बार-बार फिल्म बनाना चाहते हैं। बात अगर निर्देशक मिलाप जवेरी की करें, तो उनके पसंदीदा अभिनेता जॉन अब्राहम हैं। जॉन के साथ 'सत्यमेव जयते' फिल्म का बना चुके मिलाप उनके साथ 'सत्यमेव जयते 2' लेकर फिर आ रहे हैं। मिलाप का कहना है कि जॉन अब्राहम उन्हें इतने पसंद हैं कि 'रॉकी' और 'रैम्बो' जैसी फिल्मों की तरह वह उनके साथ 80-90 की उम्र तक 'सत्यमेव जयते' की सीरीज बना सकते हैं। मिलाप बताते हैं कि जॉन ने उन्हें तब मौका दिया था, जब उनका करियर खत्म हो रहा था। उस वक्त जॉन उनके साथ फिल्म करने के लिए तैयार हुए थे। ऐसे में जॉन उनके रियल लाइफ हीरो हैं। 'सत्यमेव जयते' फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। मिलाप का कहना है कि जब तक जॉन उनके साथ

काम करते रहेंगे, तब तक वह भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। 'सत्यमेव जयते 2' की शूटिंग अगले वर्ष के प्रारंभ में शुरू होगी। फिल्म का पोस्टर पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें जॉन पुलिस की वर्दी को फाड़कर खड़े हुए हैं और उनकी छाती पर तिरंगा दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर को लेकर मिलाप बताते हैं, 'जिस तरह हनुमान जी अपनी छाती फाड़कर दिखाते हैं कि उनमें श्रीराम बसते हैं, ठीक उसी तरह जॉन का किरदार अपने दिल में तिरंगा लेकर घूमता है, जो देश के प्रति उसकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। फिल्म की टैग लाइन है 'तन मन धन से बढ़कर जन गण मन' यानी एक इंसान के दिल में उसका देश बसता है। मैं फिल्म की टीम का शुक्रगुजार हूं कि यह पोस्टर शूट करने की इजाजत उन्होंने मुझे दी।

यह पोस्टर कुछ-कुछ सुपरमैन की याद दिलाएगा, जिसमें सुपरमैन अपनी शर्ट फाड़ता है और उसकी छाती पर सुपरमैन का लोगो दिखाई देता है।' मिलाप का कहना है कि ठीक उसी तरह जॉन मेरे सुपरहीरो हैं। मिलाप के मुताबिक 'सत्यमेव जयते 2' के डायलॉग्स 'सत्यमेव जयते' और 'मरजावां' से भी ज्यादा भारी भरकम होंगे। 'सत्यमेव जयते 2' अगले वर्ष दो अक्टूबर को रिलीज होगी।

'अर्जुन रेड्डी' की अभिनेत्री 'जयेशभाई जोरदार' फिल्म में

दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी रीमेक बनने के साथ ही वहां के कलाकार भी बॉलीवुड का रुख भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 'अर्जुन रेड्डी' फिल्म के हीरो विजय देवराकोंडा ने हिंदी सिनेमा में काम करने की इच्छा जताई थी। अब उस फिल्म की हीरोइन शालिनी पांडे बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं। शालिनी का यह डेब्यू रणवीर सिंह के साथ यशराज की फिल्म 'जयेशभाई जोरदार' में होगा। शालिनी ने इसके लिए ऑडिशन दिया था। शालिनी का कहना है, 'प्रतिभा के आधार पर यशराज जैसे बैनर में काम मिलना सपने के सच होने जैसा है। मुझे हिंदी इंडस्ट्री में प्रतिभा दिखाने का बड़ा मौका मिला है।' रणवीर सिंह के साथ काम करने को लेकर भी शालिनी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उनके सामने काम करने के लिए उन्हें खूब तैयारी करनी होगी। 'जयेशभाई...' की कहानी महिला सशक्तीकरण की बात करेगी। निर्माता इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे, जो शालिनी पर जाकर पूरी हुई। शालिनी को जबलपुर में थियेटर करने के बाद तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' में काम करने का मौका मिला। शालिनी ने अपने रोल के लिए तेलुगु सीखी थी।

अध्ययन

सीएसआइआर-जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कहा- शरीर में एक्सोसॉम पुटिकाओं के स्राव को नियंत्रित करती है 'सिमवास्टेटिन'

गंभीर रोगों से बचाएगी कोलेस्ट्रॉल की दवा

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : जीवों की कोशिकाओं के बीच आणविक स्तर पर होने वाले संचार की भूमिका शरीर के अंगों के साथ-साथ कोशिकाओं एवं ऊतकों का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। कोशकीय संचार में होने वाले असामान्य बदलावों से मधुमेह, हृदय रोगों और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए उपयोग होने वाली दवा 'सिमवास्टेटिन' कोशकीय संचार को प्रभावित करने वाली एक्सोसॉम पुटिकाओं के स्राव को नियंत्रित कर सकती है, जो कोशकीय संचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती हैं। भारतीय शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में यह बात उभरकर समाने आई है।

नई दिल्ली स्थित सीएसआइआर-जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (आइजीआइबी) के शोधकर्ता अंकुर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि हमने अस्थमा के पूर्व नैदानिक मॉडलों में सिमवास्टेटिन को प्रभावी पाया है। एक्सोसॉम आधारित आणविक संचार के कारण उभरने वाले दूसरे रोगों से निपटने में भी इसी तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। विभिन्न जटिल बीमारियों में सिमवास्टेटिन का उपयोग मौजूदा उपचार रणनीतियों और जोखिम व लाभ के अनुपात जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

चूहों पर किया अध्ययन : कोलेस्ट्रॉल एक्सोसोम झिल्ली का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए शोधकर्ता यह मानकर चल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने वाले अणुओं की मदद से एक्सोसॉम को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए, शोधकर्ताओं ने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली दवा सिमवास्टेटिन का उपयोग एक्सोसॉम को बाधित करने के लिए किया है। चूहों पर किए गए परीक्षण से पता चला है कि सिमवास्टेटिन के उपयोग से एक्सोसॉम उत्पादन को कम किया जा सकता है।

संवाहक के रूप में करती हैं काम : एक्सोसॉम पैकिंग अणुओं के लिए उपयोग किए जाने वाली एक तरह की पुटिका है जो इस तरह के संचार के लिए आवश्यक मानी जाती है। कोशकीय संचार में सूचनाओं से लैस एक्सोसॉम नामक पुटिका संवाहक के रूप में कार्य करती है। इन पुटिकाओं में दर्ज सूचनाएं कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से ये पुटिकाएं स्रावित होती हैं तो इसे शरीर की रक्षात्मक प्रतिक्रिया के संकेत के रूप में देखा जाता है।

एक्सोसॉम का ज्यादा स्राव है घातक : शोधककर्ताओं का कहना है कि अधिक मात्रा में एक्सोसॉम का स्राव कई गंभीर बीमारियों के रूप में उभर सकता है। क्षतिग्रस्त कोशिका क्षेत्रों से होने वाले एक्सोसॉम स्राव को दवाओं के जरिये लक्ष्य बनाकर उसे बाधित करना गंभीर रोगों से बचाव की कारगर रणनीति हो सकती है।

शोधकर्ताओं ने बताया कि एक्सोसॉम के संश्लेषण में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका अहम होती है। यही कारण है कि एक्सोसॉम स्राव को नियंत्रित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने के लिए उपयोग होने वाली दवा का नए सिरे से उपयोग किया है। ऐसा करने पर पता चला है कि कोशिका रूपों में सिमवास्टेटिन एक्सोसॉम के संश्लेषण एवं उसके स्राव को बाधित कर सकती है। कई गंभीर बीमारियों में एक्सोसॉम आधारित आणविक संचार की भूमिका को ध्यान में रखकर शोधकर्ताओं ने अस्थमा के पूर्व-नैदानिक मॉडल में सिमवास्टेटिन को एक्सोसम के नियंत्रित करने में उपयोगी पाया है।